राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

अड़चनों पर बोले गडकरी– यहां तो सब काम रोकने के लिए हैं ›› 3

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 178
मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 6 दिसंबर 2019
www.jagran.com
पृष्ठ 16

सरोकार

30 सेकंड में जख्म से रक्तस्राव रोक देगा स्वदेशी पाउडर

दुर्गापुर : एनआइटी राउरकेला से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करने वाले साबिर के स्टार्टअप ने विकसित किया है किफायती-कारगर और एकदम नया नुस्खा। बाजार में उपलब्ध रक्तस्राव रोकने वाली विदेशी दवाओं से पांच गुना कम कीमत। (पेज-10)

जागरण पड़ताल

एक लाख घरों का सीवर बनी गंगा, कहां हैं शौचालय

कानपुर : प्रधानमंत्री नरेंद मोदी अपने दस केंद्रीय मंत्रियों और गंगा से संबंधित सभी पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित 14 दिसंबर को कानपुर, उप्र में नमामि गंगे परियोजना के कामों की समीक्षा करेंगे। लेकिन संशय यह कि क्या सच्चाई सामने होगी। (पेज-10)

विश्वास.News

घरेलू नुस्खे से कैंसर ठीक होने का दावा फर्जी ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल • पेज 10

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▸ पृष्ठ 4

महाराष्ट्र में आरएसएस से जुड़े संस्थान की स्टांप शुल्क छूट रद

मुंबई : महाराष्ट्र में राकांपा व कांग्रेस के सहयोग से बनी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के उस निर्णय को रद कर दिया है, जिसमें आरएसएस से जुड़े एक शोध संस्थान को स्टांप शुल्क में छूट प्रदान की गई थी। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया, 'स्टांप शुल्क में मिली छूट को रद करने का निर्णय महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने बुधवार को लिया।'

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 5

पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित

मुंबई : पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के प्रमुख अभियुक्त हीरा कारोबारी नीरव मोदी को विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर गुरुवार को विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया। पिछले साल अगस्त में भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून बनाए जाने के बाद वह दूसरा कारोबारी है, जिसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय ▸ पृष्ठ 13

अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर गोलीबारी में दो की मौत

लॉस एंजिलिस : अमेरिका का सैन्य बेस पर्ल हार्बर बुधवार को गोलीबारी से दहल उठा। एक नौसैनिक ने गोलियां बरसाकर दो नागरिकों की जान ले ली। हमलावर नौसैनिक ने बाद में खुद को भी गोली मार ली। यह घटना ऐसे समय पर हुई जब पर्ल हार्बर पर द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान हुए हमले की शनिवार को बरसी मनाने की तैयारी चल रही थी।

कैरेबियाई चुनौती

पहला टी-20
भारत vs वेस्टइंडीज
शाम 7:00 बजे से
स्थान : हैदराबाद
प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता को आरोपितों ने जिंदा जलाया, हालत गंभीर

- पीड़िता को एयर एंबुलेंस से सफदरगंज अस्पताल में कराया गया भर्ती
- पांचों आरोपित गिरफ्तार, जांच के लिए मंडलायुक्त ने गठित की टीम

जागरण टीम, लखनऊ

हैदराबाद में डॉक्टर बेटी से क्रूरता को लेकर देश का आक्रोश अभी कम नहीं हुआ था कि गुरुवार को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में दुष्कर्म का मुकदमा वापस न लेने पर आरोपितों व उनके परिजनों ने पीड़िता को जिंदा जला दिया। गंभीर रूप से झुलसी पीड़िता को एयर एंबुलेंस से दिल्ली भेजकर सफदरजंग अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। पीड़िता 95 फीसद तक झुलस चुकी है। इस वजह से हालत बहुत नाजुक है। पीड़िता को आइसीयू में वेंटिलेटर के सहारे रखा गया है।

घटना पर मुख्यमंत्री के सख्त रुख के बाद पुलिस ने पांचों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। मंडलायुक्त ने पूरी घटना की जांच के लिए पांच सदस्यीय टीम गठित की है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने डीजीपी से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। पीड़ित युवती जिले के बिहार थाना क्षेत्र के एक गांव की है। 25 वर्षीय इस युवती ने अपने ही गांव के शिवम त्रिवेदी और उसके साथी शुभम त्रिवेदी पर आरोप लगाया था कि 12 दिसंबर 2018 को उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट और महिला आयोग के निर्देश पर आरोपितों के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज हुए थे जिनकी जांच चल रही है। इसके बाद से आरोपित लगातार मुकदमा वापसी का दबाव बना रहे थे। गुरुवार सुबह पीड़िता बैसवारा रेलवे स्टेशन जा रही थी। गांव से लगभग तीन सौ मीटर दूर रास्ते में शिवम त्रिवेदी और उसके साथ कुछ लोगों ने उसे रोका और केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी और भाग निकले। लपटों से घिरी हुई पीड़िता बचाने की गुहार लगाते हुए दौड़ी और गैस एजेंसी के गोदाम के बाहर गिर गई। शोर सुन बाहर निकले गार्ड ने आग बुझाकर यूपी 112 पर सूचना दी। पुलिस युवती को सुमेरपुर सीएचसी ले गई, जहां से उसे जिला अस्पताल और वहां से लखनऊ ले जाकर सुबह साढ़े दस बजे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल (सिविल) में भर्ती कराया गया। इससे पहले पीड़िता ने उन्नाव के जिला अस्पताल में एसडीएम बीघापुर के समक्ष बयान दिया कि शिवम ने बात करने के लिए उसे रायबरेली चलने को बुलाया था। शिवम के साथ उसके पिता रामकिशोर, शुभम और उसके पिता हरिशंकर के साथ उमेश वाजपेयी भी थे। सभी उस पर दुष्कर्म का मुकदमा वापसी का दबाव बना रहे थे। इन्कार पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी।

पीड़िता के बयान के आधार पर पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें शुभम, हरि शंकर, उमेश व राम किशोर को उन्नाव पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि आरोपित शिवम ने ने खुद थाने आकर समर्पण किया। इस बीच उन्नाव के एएसपी विनोद पांडेय के नेतृत्व में गठित पांच सदस्यीय टीम ने जांच शुरू कर दी है।

घटना को लेकर राज्यसभा में हंगामा पेज>>5
विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर पेज>>5

लखनऊ में गुरुवार को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को सिविल अस्पताल से दिल्ली ले जाने के लिए एंबुलेंस में शिफ्ट करते स्वास्थ्यकर्मी। जागरण

एयरपोर्ट तक बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर

लखनऊ से शाम करीब साढ़े छह बजे पीड़िता को लेकर एयर एंबुलेंस ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इस दौरान सिविल अस्पताल से एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। वहीं रात करीब सवा आठ बजे एयर एंबुलेंस दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर पहुंची। एयरपोर्ट से कुछ ही मिनट बाद एंबुलेंस पीड़िता को लेकर सफदरजंग अस्पताल के लिए रवाना हुई। इस दौरान एयरपोर्ट से अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया।

महंगाई की चिंता में नहीं घटा रेपो रेट

उम्मीदों से इतर ▸ रिजर्व बैंक ने पांच फीसद किया विकास दर का अनुमान, नीतिगत दरें यथावत

आर्थिक सुस्ती के चलते कटौती की थी उम्मीद, गवर्नर बोले-मशीन की तरह हर बार नहीं घटा सकते ब्याज दर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

महंगाई की बढ़ती दर ने आमजन ही नहीं केंद्रीय बैंक को भी चिंतित कर दिया है। यही वजह रही कि पिछली पांच मौद्रिक नीति समीक्षाओं में रेपो रेट में कटौती करने वाले रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बार सबको चौंकाते हुए नीतिगत ब्याज दरों में कटौती से हाथ खींच लिया। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने तीन दिन की बैठक के बाद रेपो रेट 5.15 फीसद पर बनाए रखने का फैसला किया है। उद्योग जगत ने केंद्रीय बैंक के इस कदम से निराशा जताई है।

अर्थव्यवस्था में सुस्ती के माहौल को देखते हुए माना जा रहा था कि बाजार को गति देने के लिए केंद्रीय बैंक रेपो रेट में कटौती कर सकता है। रिजर्व बैंक ने भी माना है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति उसके पहले के अनुमान से खराब है, लेकिन केंद्रीय बैंक ने महंगाई थामने को तरजीह दी। आर्थिक चुनौतियों और विपक्ष के सवालों से घिरी सरकार के लिए आरबीआइ का इस बार रेपो रेट न घटाने का फैसला एक झटका है। इस बार रेपो रेट नहीं घटाने के सवाल पर गवर्नर दास ने कहा, 'आप हमसे मशीन की तरह रेट कटौती की उम्मीद नहीं कर सकते। वैसे फरवरी, 2019 से रेपो रेट में पांच बार जो कटौती की गई है उसका फायदा अब ग्राहकों को मिलने लगा है। इसका असर अब दिखना शुरू होगा। सरकार की तरफ से भी कुछ कदम उठाए गए हैं और उन सभी उपायों का असर होने की प्रतीक्षा है।'

पांच बार में हुई थी 1.35 फीसद की कटौती : पिछली पांच समीक्षाओं में रेपो रेट (होम लोन, ऑटो लोन जैसे कर्ज की दरों को प्रभावित करने वाली दर) में 135 आधार अंकों (1.35 फीसद) की कटौती की गई थी। इस बार महंगाई ने कटौती के इस क्रम को रोक दिया। अक्टूबर में महंगाई की दर 4.6 फीसद रही है, जो पहले के अनुमान से ज्यादा है। पूरे साल के लिए रिजर्व बैंक ने महंगाई की दर को 3.5-3.7 फीसद की रेंज से बढ़ाकर 4.7-5.1 फीसद कर दिया है।

चौथी बार घटाया गया विकास दर अनुमान : अर्थव्यवस्था के हाल पर चिंता जताते हुए रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष (2019-20) के लिए आर्थिक विकास दर के अनुमान को 6.1 फीसद से घटाकर पांच फीसद कर दिया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान यह चौथा मौका है जब केंद्रीय बैंक ने विकास दर अनुमान घटाया है। सबसे पहले सात फीसद का अनुमान लगाया गया था, जिसे अगस्त में 6.9 फीसद और अक्टूबर में 6.1 फीसद किया गया था। पिछले दिनों केंद्र सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों में बताया गया कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर, 2019) में देश की आर्थिक विकास दर लुढ़ककर 4.5 फीसद पर आ गई है। उसके बाद से देश-विदेश की कई एजेंसियों ने भारत के विकास दर अनुमान को घटाया है।

घरेलू मांग घटने से गिरी विकास दर : केंद्रीय बैंक ने विकास दर अनुमान घटाने के लिए घरेलू मांग में कमी के साथ ही वैश्विक स्तर पर छा रही सुस्ती को बड़ी वजह बताया है। आरबीआइ ने कहा है कि दूसरी तिमाही में अगर सरकारी खर्चे में हुई बढ़ोतरी को अलग कर दिया जाए तो जीडीपी की विकास दर 3.1 फीसद ही रह जाती है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि ब्याज दरों में पहले की गई कटौती का असर अब दिखाई दे सकता है।

(संबंधित खबरें पेज-12 पर)

आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को मुंबई में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद प्रेसवार्ता की। प्रेट्र

बिना कटौती के घटेगी ब्याज दर

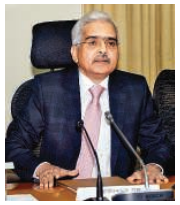

आरबीआइ ने इस बार रेपो रेट में कटौती भले ही नहीं की हो लेकिन गवर्नर दास का मानना है कि ब्याज दरों में कटौती इसके बिना भी हो सकती है। उन्होंने कारण यह बताया है कि पांच बार जो कटौती की गई है उसका फायदा अब बैंकों ने ग्राहकों को देना शुरू किया है। सितंबर-अक्टूबर, 2019 के आंकड़े बताते हैं कि बैंकों के लिए जमा स्कीमों पर लागत कम हो रही है यानी वह जमाकर्ताओं को पहले के मुकाबले कम ब्याज दे रहे हैं। आगे भी कर्ज की दरें कम होने की पूरी उम्मीद है।

कुछ शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं लेकिन यह कह पाना मुश्किल है कि ये कितने टिकाऊ हैं। वैसे सरकार व आरबीआइ ने मिलकर अर्थव्यवस्था की सेहत को सुधारने के जो कदम उठाए हैं, उनसे घरेलू मांग बढ़ाने में निश्चित तौर पर मदद मिलेगी।
- शक्तिकांत दास, गवर्नर, रिजर्व बैंक

क्या है रेपो रेट?

जिस दर पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। इस दर में कटौती से बैंकों को रिजर्व बैंक से कर्ज लेने में सहूलियत होती है और उनके पास नकदी बढ़ती है। बैंकों की ओर से दिए जाने वाले लोन की ब्याज दरें भी रेपो रेट से जुड़ी हैं, इसलिए इसमें कटौती से कंज्यूमर लोन भी सस्ते हो जाते हैं।

उत्तराखंड के छात्रवृत्ति घोटाले में मानवेंद्र स्वरूप गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, देहरादून

उत्तराखंड के छात्रवृत्ति घोटाले में हो रही कार्रवाई की आंच उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित दयानंद शिक्षण संस्थान तक पहुंच गई। संस्था के अधीन देहरादून के प्रेमनगर में संचालित एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में 4.31 करोड़ रुपये का घोटाला पकड़ में आया है। इस सिलसिले में एसआइटी ने संस्था के सचिव मानवेंद्र स्वरूप और एक दलाल को गिरफ्तार कर लिया। दलाल भाजपा से जुड़ा बताया जा रहा है। कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। बता दें कि मानवेंद्र स्वरूप राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं। उनके पिता जगेंद्र स्वरूप और बाबा वीरेंद्र स्वरूप लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के एमएलसी रहे हैं।

फर्जी छात्रों का प्रवेश दिखा छात्रवृत्ति हड़पी : एसआइटी ने फरवरी में प्रेमनगर थाने में एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में छात्रवृत्ति घोटाले का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि संस्थान ने शैक्षणिक सत्र 2012-13 से 2015-16 के मध्य समाज कल्याण विभाग की तरफ से दी जाने वाली छात्रवृत्ति में 4.31 करोड़ रुपये का घपला किया। बैंक डिटेल, पंजीकृत छात्रों और संस्थान से उत्तीर्ण छात्रों का ब्योरे की जांच के बाद सामने आया कि मैनेजमेंट संस्थान में सैकड़ों फर्जी छात्रों का प्रवेश दिखाकर छात्रवृत्ति के रूप में यह राशि हड़पी। यही नहीं, फेल छात्रों को भी पास दिखाकर उनके नाम पर छात्रवृत्ति का गबन किया गया।

एसआइटी ने जांच के बाद दयानंद शिक्षण संस्थान के सचिव मानवेंद्र स्वरूप को नामजद किया था। इसके साथ ही कोर्ट से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल किया। आरोपित मानवेंद्र स्वरूप मैनेजमेंट स्टडीज संस्थान के संयुक्त सचिव और अधिकृत हस्ताक्षरी भी हैं। एसआइटी ने आरोपित मानवेंद्र स्वरूप को कानपुर से गिरफ्तार कर बुधवार को देहरादून लेकर आई। यहां प्रेमनगर थाने में उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद एसआइटी ने इसी घपले में विकासनगर निवासी राकेश तोमर को भी गिरफ्तार कर लिया। तोमर एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का एजेंट था। वह दूरदराज के छात्रों के दस्तावेज लेकर उनके नाम पर छात्रवृत्ति निकालने का साजिश करता था।

देहरादून में एसआइटी ने छात्रवृत्ति घोटाले में दयानंद शिक्षण संस्थान के सचिव मानवेंद्र स्वरूप को गिरफ्तार किया। फाइल फोटो

छात्रवृत्ति घोटाले की जांच एसआइटी की दो यूनिटें कर रही हैं। जांच में स्पष्ट हो चुका है कि गिरोह बनाकर घोटाला किया गया है। इसमें जो भी शामिल है, उसकी गिरफ्तारी की जाएगी चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो।
- संजय गुंज्याल, आइजी, एसआइटी

विधानसभा के गेट पर खड़े रहे राज्यपाल

बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ का टकराव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत राज्यपाल गुरुवार को विधानसभा गए, लेकिन उनके लिए विधानसभा का वीआइपी गेट नहीं खुला। इसके बाद राज्यपाल ने दूसरे गेट से पैदल चल कर विधानसभा के अंदर प्रवेश किया। **(खबर पेज-4 पर)** एएनआइ

अयोध्या मामले पर आज दाखिल होगी पुनर्विचार याचिका

जागरण संवाददाता, अयोध्या : बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी महबूब के अनुसार छह दिसंबर को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा। पुनर्विचार याचिका पर हाजी महबूब सहित मो. उमर, मौलाना महफूजुर्रहमान, बादशाह खान जैसे स्थानीय पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं।

इससे पहले जमीयत उलेमा हिंद बीती नौ नवंबर को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर चुका है, जबकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से पक्षकार रहे इकबाल अंसारी फैसला आने के पूर्व से ही घोषित अपने रुख पर कायम हैं। इकबाल अंसारी से पहले पक्षकार रहे उनके पिता मरहूम हाशिम अंसारी भी सदैव कहते आए थे कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उन्हें मान्य होगा। इकबाल ने इस संबंध में बुलाई बैठकों से भी खुद को दूर रखा।

फैसला आने के बाद अपनी शुरुआती प्रतिक्रिया में हाजी महबूब ने भी पुनर्विचार याचिका दाखिल न करने की बात कही थी, लेकिन बाद में वह अपने बयान से पलट गए और कहा कि सबकी राय में उनकी राय भी शामिल है। हालांकि रामनगरी के अधिकतर लोग व संत धर्माचार्य इकबाल अंसारी के रुख पर खुशी का इजहार करते हुए उन्हें सौहार्द्र का दूत बताते हैं।

वकील को अवमानना की धमकी के लिए जस्टिस अरुण मिश्रा ने मांगी माफी

नई दिल्ली : भू-अधिग्रहण के एक मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन को अवमानना कार्यवाही की चेतावनी देने पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने गुरुवार को माफी मांग ली। उन्होंने कहा, 'अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मैं न सिर्फ माफी मांगता हूं बल्कि सौ बार दंडवत होकर भी माफी मांग लूंगा। अगर किसी को कुछ महसूस हुआ हो तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं।' (पेज-5)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सबरीमाला में महिलाओं को अनुमति का फैसला 'अंतिम' नहीं

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केरल के सबरीमाला अयप्पा मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने वाला उसका फैसला 'अंतिम' नहीं है। इसका कारण यह है कि इसे बड़ी पीठ को भेजा गया है। शीर्ष अदालत ने महिला श्रद्धालु बिंदू अम्मिनी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह की दलीलों पर यह टिप्पणी की। वकील ने आरोप लगाया कि कोर्ट के 2018 के फैसले का उल्लंघन हो रहा है। (पेज-7)

BYJU'S The Learning App | IAS
PRELIMS MASTER 2020
प्रिलिम्स पाठ्यक्रम का सम्पूर्ण कवरेज
@7,500/- STARTS 9TH DECEMBER 2019
कार्यक्रम की रूपरेखा
300+ घंटों की सामान्य अध्ययन और CSAT की विस्तृत कक्षाएं
निः शुल्क प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज (30 TESTS)
अभ्यास हेतु अतिरिक्त 3000+ बहु वैकल्पिक प्रश्नोत्तर
UPSC के विगत 10 वर्षों के प्रश्नपत्रों का विशिष्ट विश्लेषण
समसामयिक विषयों का सम्पूर्ण कवरेज (3 वर्षों का)
भारत-2020 (ईयर बुक), आर्थिक सर्वेक्षण, बजट और विभिन्न मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों का कवरेज
अद्यतन अध्ययन सामग्री
मैपिंग के लिए विशेष कक्षाएं
OFFICE : Shop No. 19, Vardhaman Central Mall, Nehru Vihar, Delhi
Call, SMS or WhatsApp — 9205881869

अहम कदम

खानपान पर सब्सिडी खत्म करने के प्रस्ताव पर सभी दलों ने लगाई मुहर, नया रेट जल्द होगा लागू, सालाना 17 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान

संसद की कैंटीन में अब नहीं मिलेगा रियायती खाना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संसद की कैंटीन में खाने पर मिलने वाली सब्सिडी हटाने का फैसला कर लिया गया है। सभी राजनीतिक दलों ने लंबे समय से सवालों के घेरे में चल रही इस सब्सिडी को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुआई में हुए इस फैसले के बाद अब संसद की कैंटीन का खाना महंगा हो जाएगा। इस कदम से सरकारी खजाने के सालाना 17 करोड़ रुपये बचेंगे।

संसद की कैंटीन में मिलने वाले रियायती खाने को लेकर माननीयों पर अक्सर सवाल दागे जाते रहे हैं। अभी जेएनयू फीस विवाद के दौरान भी सांसदों को रियायती खानपान की सुविधा पर निशाना साधा गया था। संसद की कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने के मसले पर पिछले कुछ समय से चर्चा चल रही थी। पिछली लोकसभा के दौरान 2017 में संसद की कैंटीन में खानपान की दर में इजाफा करते हुए सब्सिडी को काफी हद तक कम भी कर दिया गया था। अब इस दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए गुरुवार को कार्य मंत्रणा समिति में सभी प्रमुख दलों के नेताओं के साथ स्पीकर की बैठक में सब्सिडी को पूरी तरह खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बैठक में शामिल भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि सभी सांसदों का मानना था कि सब्सिडी जारी रखना उचित नहीं है।

लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने कहा कि इस फैसले के बाद सब्सिडी के मद में खर्च होने वाले 17 करोड़ रुपये की बचत होगी। इस सब्सिडी में तीन करोड़ रुपये ही सांसदों के खान-पान की सब्सिडी थी। बाकी 14 करोड़ रुपये की सब्सिडी संसद के स्टाफ और दूसरे लोगों पर खर्च होती थी। ताजा फैसले के बाद सांसदों ही नहीं तमाम लोगों को अब लागत के हिसाब से खानपान का मूल्य चुकाना होगा। संसद में कैंटीन का संचालन करने वाली रेलवे की एजेंसी आइआरसीटीसी जल्द ही खानपान का नया रेट लोकसभा स्पीकर को भेजेगी। सब्सिडी खत्म होने के बाद दरें दोगुनी तक होने का अनुमान है।

मौजूदा मेन्यू रेट लिस्ट

आइटम	कीमत (रुपये में)
ब्रेड और मक्खन	6
रोटी	2
खिचड़ी (प्रति प्लेट)	27
वेज कटलेट	23
इडली	17
दही-भात (प्रति प्लेट)	32
वेज थाली	35
चिकन करी	50
चिकन कटलेट, (प्रति प्लेट)	41
तंदूरी चिकन	60
कॉफी	5
सादा डोसा	12
फिश करी	40
हैदराबादी चिकन बिरयानी	65
मटन करी	45
चावल	7
सूप	14

पानी बोतल, जूस और मिठाई पहले से ही लागत मूल्य पर बेचे जाते हैं।

25 हेल्प डेस्क डीडीए ने शुरू की हैं अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख से अधिक लोगों को घरों का मालिकाना हक दिलाने के लिए। इन पर मालिकाना हक से संबद्ध प्रक्रिया से संबंधित सभी तरह की जानकारी मिलेगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 6 दिसंबर 2019

कृत्रिम तालाबों में कितनी मूर्तियां की गई विसर्जित : एनजीटी

जासं, नई दिल्ली : एनजीटी की ओर से नियुक्त यमुना मॉनिटरिंग कमेटी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) से पूछा कि त्योहारी सीजन में बनाए गए कृत्रिम तालाबों में कितनी मूर्तियों का विसर्जन किया गया और बाद में उनका निस्तारण कैसे किया गया। यह निर्देश डीपीसीसी के उस अध्ययन के बाद आया, जिसमें दिखाया गया कि गणेश चतुर्थी व दुर्गा पूजा के दौरान कृत्रिम तालाबों में मूर्तियों के विसर्जन से पिछले साल की तुलना में इस साल यमुना नदी में कम प्रदूषण हुआ।

मूर्ति विसर्जन की रिपोर्ट की पड़ताल करने पर पता चला कि इसमें से कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी गायब है। इसलिए अनुरोध किया गया है कि नदी में विसर्जित होने से रोकने वाली मूर्तियों की संख्या की जानकारी भी निगरानी समिति को उपलब्ध कराई जाए। एनजीटी की ओर से सेवानिवृत्त विशेषज्ञ सदस्य बीएस सजवान और दिल्ली की पूर्व मुख्य सचिव शैलजा चंद्रा सहित दो सदस्यीय पैनल ने भी डीपीसीसी से पूछा कि क्या तालाबों की संख्या और उनका भौगोलिक प्रसार पर्याप्त है।

वाया डीएनडी नोएडा से दिल्ली होगा जाम मुक्त, योजना हुई तैयार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

नोएडा व गाजियाबाद से दिल्ली और दिल्ली के अन्य हिस्सों से दक्षिणी दिल्ली आना-जाना अब जाम मुक्त होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने गुरुवार को आश्रम फ्लाईओवर की विस्तार योजना को मंजूरी दे दी। इसके तहत रिंग रोड पर आश्रम फ्लाईओवर को डीएनडी फ्लाई-वे तक विस्तार दिया जाएगा। यह छह लेन का होगा। तीन लेन जाने के लिए व तीन लेन आने के लिए। साथ ही आश्रम फ्लाईओवर से सराय काले खां जाने के लिए तीन लेन के डाउन रैंप का निर्माण होगा। इसके अलावा आइटीओ व सराय काले खां से साउथ दिल्ली जाने वाले वाहनों के लिए तीन लेन का अप रैंप डीएनडी लूप से इस फ्लाईओवर के लिए बनेगा।

गुरुवार को पत्रकार वार्ता में केजरीवाल ने बताया कि इस योजना पर कुल 128.95 करोड़ रुपये की लागत आएगी। साथ ही एक साल में निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्लाईओवर के विस्तार से आश्रम व महारानी बाग के पास लगने वाले जाम से मुक्ति मिल जाएगी। आश्रम फ्लाईओवर से डीएनडी लूप तक रिंग रोड पर व्यस्ततम घंटों के दौरान भारी भीड़ होती है। इससे आश्रम-डीएनडी के बीच जाम लग जाता है। इस विस्तार योजना से लोगों को इस जाम से मुक्ति मिलेगी।

किलोकरी से सड़क पार करने के लिए नहीं लगाना होगा चार किमी का चक्कर

आश्रम विस्तार फ्लाईओवर के निर्माण के बाद किलोकरी से सड़क पार करने के लिए चार किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब किलोकरी से रिंग रोड पर केवल डेढ़ सौ मीटर चलने के बाद यू टर्न लेकर वाहन चालक सड़क पार कर सकेंगे। साथ ही वह महारानी बाग या साउथ दिल्ली की ओर जा सकेंगे। इसी तरह महारानी बाग से सराय काले खां, नोएडा, आइटीओ व गाजियाबाद जाने के लिए एक किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना होगा। अब रिंग रोड पर डेढ़ सौ मीटर चलकर यू टर्न लेकर गंतव्य की ओर वाहन चालक जा सकेंगे।

- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने आश्रम फ्लाईओवर के विस्तार को दी मंजूरी
- 128.95 करोड़ की लागत से एक साल में होगा निर्माण, जल्द प्रारंभ होगी टेंडर प्रक्रिया

आश्रम फ्लाईओवर के विस्तार योजना का लेआउट प्लान। सौजन्य : दिल्ली सरकार

डीएनडी लूप से आश्रम चौराहे तक रिंग रोड पर लगता है लंबा जाम : अभी नोएडा व गाजियाबाद से दक्षिणी दिल्ली आने-जाने वाले वाहनों को डीएनडी लूप से आश्रम चौराहे तक जाने के लिए जाम से जूझना पड़ता है। साथ ही आइटीओ एवं सराय काले खां से दक्षिणी दिल्ली जाने वालों को जाम से दो-चार होना पड़ता है। लोगों को कई बार दफ्तर आने-जाने में देर हो जाती है। साथ ही ईंधन बर्बाद होता है। कई बार लोगों को इस चौराहे तक जाने में आधे घंटे का समय भी लग जाता है।

पैदल यात्रियों को जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी जान : अभी रिंग रोड पर सड़क पार करने के लिए महारानी बाग रेड लाइट का पैदल यात्री सहारा लेते हैं। इस योजना के बाद रेड लाइट को खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही वहां पैदल यात्रियों के लिए सब वे का निर्माण होगा, जिसके सहारे पैदल यात्री बगैर रुके सुरक्षित आ-जा सकेंगे।

इनका होगा निर्माण
- छह लेन का आश्रम विस्तार फ्लाईओवर
- तीन लेन रैंप साउथ दिल्ली से सराय काले खां जाने के लिए
- तीन लेन रैंप आइटीओ व सराय काले खां से साउथ दिल्ली जाने के लिए
- महारानी बाग रेड लाइट पर पैदल यात्रियों के लिए सब वे
- फ्लाईओवर पर एलईडी लाइट
- पिलर पर आर्ट वर्क
- रैंप समेत कुल लंबाई 1425 मीटर

यह भी होगा फायदा
- नोएडा व गाजियाबाद से एम्स, सफदरजंग, एस्कार्ट, अपोलो अस्पताल आने-जाने वाले यात्रियों को अभी जाम में जूझना पड़ता है। इस योजना के बाद लोग बगैर जाम में फंसे आ-जा सकेंगे।
- आइटीओ व सराय काले खां से साउथ दिल्ली आने-जाने वाले लोगों को भी जाम में नहीं जूझना होगा।
- प्रतिदिन हजारों लीटर ईंधन की बचत होगी।
- लोग समय से दफ्तर जा सकेंगे।

सभी बसों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

बड़ा कदम ▸ महिलाओं के बस का सफर सुरक्षित करने के लिए दिल्ली कैबिनेट ने लिया फैसला

पैनिक बटन और ऑटोमैटिक व्हीकल लोकेशन सिस्टम भी लगाया जाएगा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली में महिलाओं के लिए बसों का सफर सुरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा निर्णय लिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि दिल्ली में चल रही सभी डीटीसी एवं क्लस्टर बसों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पैनिक बटन और जीपीएस आधारित ऑटोमैटिक व्हीकल लोकेशन सिस्टम भी लगाया जाएगा। साथ ही महिलाओं में सुरक्षा भाव बढ़ाने के लिए बसों को वन एप से जोड़ा जाएगा। इससे बस की लाइव लोकेशन की जानकारी भी मिलेगी। योजना के तहत 100 बसों में इस माह के अंत तक ही सीसीटीवी, पैनिक बटन व जीपीएस आधारित ऑटोमैटक व्हीकल लोकेशन सिस्टम लग जाएगा। सभी बसों में सात माह के अंदर यह सिस्टम लग जाएगा। इसके लिए एक कमांड सेंटर भी बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सरकार के इस फैसले से दिल्ली में महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी। साथ ही वह एप से बस की सूचना भी ले सकेंगी।

5500 बसों में लगेगा सिस्टम : मुख्यमंत्री ने कहा कि हम काफी समय से इस योजना को लागू करने के प्रयास में थे। पहले के तीन टेंडर पिछले तीन-चार साल में फेल हो गए। अब टेंडरिंग प्रक्रिया सफल हो गई है। कैबिनेट ने इस पर कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के तहत दिल्ली में लगभग 5500 डीटीसी और क्लस्टर बसों में सीसीटीवी, पैनिक बटन (प्रत्येक बस में 10) और जीपीएस आधारित स्वचालित वाहन स्थान प्रणाली स्थापित की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति पैनिक बटन दबाता है तो तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट चला जाएगा और उसे तत्काल मदद दी जाएगी। पूरी प्रणाली को नियंत्रित करने और निगरानी करने के लिए एक केंद्रीकृत कमांड रूम होगा। इस परियोजना के दो प्रमुख लाभ हैं। पहला, सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन खतरों को रोकने और बसों में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेंगे। दूसरा, यात्रियों को जीपीएस आधारित स्वचालित वाहन स्थान प्रणाली द्वारा संचालित मोबाइल एप पर बसों के आगमन का स्थान और अपेक्षित समय की जानकारी मिल जाएगी। यह सुविधा नहीं होने की वजह से अभी तक यात्रियों को बसों के आगमन का समय और स्थान के बारे में सही पता लगा पाना मुश्किल था। अब यह दिल्ली के लोगों के लिए एक पुरानी बात हो जाएगी।

मार्शल की वजह से सुरक्षित हुआ बसों का सफर : केजरीवाल ने कहा कि बसों में मार्शल नियुक्त होने से बसों का सफर सुरक्षित हुआ है। मार्शलों की वजह से कई घटनाएं रुक गई हैं। साथ ही कई घटनाओं का पर्दाफाश बस मार्शलों की वजह से हुआ है।

बस में लगेंगी इतनी चीजें : तीन सीसीटीवी कैमरे, 10 पैनिक बटन, जीपीएस आधारित ऑटोमैटिक व्हीकल लोकेशन सिस्टम

दिल्ली सचिवालय में पत्रकारो से बात करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जागरण

150 करोड़ की लागत आएगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दिसंबर के अंत तक 100 बसों पर इन सुविधाओं को शुरू करने की योजना बना रहे हैं। 5500 बसों में परियोजना को पूरा करने और एप-आधारित स्वचालित वाहन स्थान प्रणाली को पूरी तरह कार्यात्मक बनाने में छह महीने लगेंगे। इस परियोजना की कुल लागत 150 करोड़ रुपये आंकी गई है। एप लगभग बन कर तैयार हो चुका है। एक बार पूरी व्यवस्था लागू होने के बाद, बसों की जानकारी, स्थान, आगमन का समय आदि शहर भर के बस स्टॉप पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

दिल्ली एयरपोर्ट पर 39 लाख रुपये के साथ चार कश्मीरी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के अधिकरियों ने 39 लाख रुपये से ज्यादा की नकदी के साथ चार कश्मीरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपित एयर इंडिया की उड़ान से जेद्दा से दिल्ली आए थे। बाद में उन्हें दूसरे विमान से जम्मू जाना था। सभी जम्मू-कश्मीर के पुंछ के रहने वाले हैं। इनमें से दो सगे भाई हैं। आरोपितों को गिरफ्तार कर कस्टम अधिकारी पता लगाने में जुटे हैं कि बरामद रुपये का किस काम में इस्तेमाल किया जाना था। आतंकी फंडिंग की आशंका के तहत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सहित अन्य एजेंसियां भी मामले पर नजर रखे हुए हैं।

आइजीआइ एयरपोर्ट के कस्टम विभाग के आयुक्त मनीष कुमार ने बताया कि तीन दिसंबर को जेद्दा से एयर इंडिया की उड़ान आइजीआइ एयरपोर्ट पर आई थी। मिलिटरी और सीआइएसएफ सर्विलांस से कस्टम को जानकारी मिली थी कि इस उड़ान से आए कुछ यात्रियों के पास बड़ी मात्रा में नकदी है। कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट पर संदिग्ध यात्रियों की सघन जांच की। इस दौरान चार यात्रियों के पास से 39 लाख 14 हजार रुपये बरामद हुए। उन्होंने अपने बैग और सामान के अंदर रुपये छिपा रखे थे। बरामद ज्यादातर नोट दो हजार, पांच सौ और दो सौ के हैं। उनके पास से 50, 20 और 10 रुपये के भी कुछ नोट मिले हैं।

35 और 40 वर्ष के बीच के उम्र के इन आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि वे छोटे-मोटे कारीगर हैं। जानकारी कम होने के कारण उन्होंने जेद्दा में अपनी कमाई हुई मुद्रा को भारतीय नोट में बदलवा लिया था, जबकि नियम के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय यात्री मात्र 25 हजार रुपये नकदी अपने साथ ला अथवा ले जा सकता है। कस्टम विभाग के अधिकारी आरोपितों के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। अधिकारियों के मुताबिक विदेश में कारीगरी कर रहे लोगों के पास से इतनी मोटी रकम मिलना संदेह पैदा कर रहा है। उधर, रुपये बरामद कर एजेंसियां इस कोण से मामले की छानबीन कर रही हैं कि कहीं इस रुपये का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में आतंक के लिए तो नहीं किया जाना था।

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कश्मीरी यात्री से बरामद नकदी। सौ. : कस्टम

मिड-डे मील में मिला मरा हुआ चूहा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पहाड़गंज के देश राज भाटिया मार्ग पर स्थित एसडी हरी मंदिर बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को मीड-डे मील के कंटेनर में मरा हुआ चूहा मिला। हालांकि किसी भी छात्रा को खाना परोसा नहीं गया था। स्कूल में मिड-डे मील की आपूर्ति सुमित नागपाल करते हैं।

विद्यालय की प्रधानाचार्य अनिता जैन ने बताया कि पिछले दो माह से मिड-डे मील का ठेका सुमित नागपाल को दिया गया था। कई दिनों से मीड-डे मील में कुछ ना कुछ गड़बड़ी मिल रही थी। कभी खाना अधपका होता था, तो कभी दाल बहुत पतली होती थी। इस संबंध में उन्होंने तीन दिसंबर को शिकायत भी की थी। इसी वजह से खाने को परोसने से पहले उसकी हर रोज अच्छे से जांच की जाती थी।

गुरुवार को छात्राओं को नमकीन दलिया और हलवा दिया जाना था। लेकिन जैसे ही दलिया का कंटेनर खोला तो उसमें मरा हुआ चूहा मिला। उन्होंने इसकी जानकारी मिड-डे मील ठेकेदार को दी। इसके बाद शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों को मामले से अवगत कराया।

मिड-डे मील की जगह छात्राओं को नमकीन, बिस्किट बांटा गया। साथ ही शिकायत में यह भी बताया गया कि शुक्रवार से सुमित नागपाल से मिड-डे मील का खाना नहीं लिया जाएगा। लिहाजा मजबूरन उन्हें स्कूल में मिड-डे मील को बंद करना पड़ेगा। इस संबंध में जब शिक्षा निदेशक बिनय भूषण से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

रफ्तार मंद पड़ते ही दमघोटू होने लगी दिल्ली की हवा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : हवा की रफ्तार मंद पड़ते ही दिल्ली-एनसीआर की हवा फिर से दमघोटू होने लगी है। वातावरण में स्मॉग के साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। शुक्रवार से हालात और बिगड़ने के आसार हैं।

सफर और मौसम विभाग के मुताबिक प्रदूषण से 11 दिसंबर से पहले राहत मिलने की संभावना नहीं है। दिसंबर के शुरुआती तीन दिनों में वायु प्रदूषण अपेक्षाकृत कम रहा था, लेकिन गुरुवार से हवा की गति (चार किमी प्रति घंटा) मंद पड़ जाने से पीएम 2.5 की मात्रा तेजी से बढ़ने लगी। सीपीसीबी द्वारा जारी एयर बुलेटिन के अनुसार एनसीआर के कई शहरों में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स गुरुवार को 382 दर्ज हुआ।

सुबह सात बजे ही यह 338 पहुंच गया था। बाद में इसमें तेजी से इजाफा होता चला गया। सर्वाधिक बुरा हाल गाजियाबाद का है, जहां इंडेक्स 432 पहुंच गया है। ग्रेटर नोएडा का 417, नोएडा का 414, बुलंदशहर का 404, बल्लभगढ़ का 372, गुरुग्राम का 328 और पलवल का 368 दर्ज हुआ। सफर का पूर्वानुमान है कि शनिवार तक हालात में सुधार नहीं होगा। उधर पराली का धुआं अभी भी दिल्ली पहुंच रहा है।

कोहरे ने दी दस्तक

दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ-साथ अब कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। गुरुवार को इस मौसम की सबसे सर्द सुबह रही। न्यूनतम तापमान महज 7 .6 डिग्री सेल्सियस पर सिमट गया। अधिकतम तापमान 23 .6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के मुताबिक इस सप्ताह हवा की गति मंद ही रहेगी। जिसकी वजह से शुक्रवार से स्मॉग और घना कोहरा रहने की संभावना है। गुरुवार को सफदरजंग में दृश्यता का स्तर महज 500 मीटर रहा। एनएच-9 पर चालकों को वाहनों की लाइट चलानी पड़ी। शुक्रवार को भी एक से दो स्थानों पर घना कोहरा छाने की संभावना है। जागरण

डीयू के तदर्थ शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के तदर्थ शिक्षकों को अब नहीं हटाया जाएगा। डीयू में स्थायी पदों के लिए नियुक्तियों की प्रक्रिया के पूरा होने तक तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएंगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के उच्च शिक्षण संस्थानों के सचिव आर सुब्रमण्यम ने डीयू शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद मंत्रालय की और से यह फैसला लिया। इससे अलावा डीयू की तरफ से 28 अगस्त को स्थायी नियुक्तियों की प्रक्रिया के पूरे होने तक अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करने के फैसले को भी मंत्रालय ने बदलते हुए निर्णय लिया है कि डीयू के कॉलेज व संस्थानों में अगले अकादमिक सत्र के शुरू होने से पहले स्थायी नियुक्तियां की जाएं। जब तक स्थायी नियुक्तियां नहीं होती हैं, तब तक तदर्थ शिक्षक, स्थायी शिक्षक, अनुबंध शिक्षक व अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएं।

बुधवार व गुरुवार को डूटा की तरफ से 28 अगस्त के पत्र को वापिस लेने की मांग समेत अन्य मांगों के लिए हड़ताल शुरू की गई थी। इसमें डीयू के शिक्षकों ने दिसंबर में हो रही परीक्षा मूल्यांकन का बहिष्कार कर दिया था। गुरुवार को डूटा के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष प्रो रजनीश जैन भी मौजूद थे। वहीं हड़ताल को खत्म करने को लेकर डूटा ने कहा है कि वह इस विषय में आज कोई फैसला लेंगे।

कमेटी ने हाई कोर्ट को बताई राजधानी के सरकारी अस्पतालों की बदहाली

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से गठित की गई विशेषज्ञों की समिति ने गुरुवार को अदालत के सामने सरकारी अस्तपालों की बदहाल तस्वीर पेश की। करीब पांच महीने तक दिल्ली के 35 सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करने के बाद कमेटी ने 250 से अधिक पेज की रिपोर्ट मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष पेश की। रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से लेकर जीबी पंत अस्पताल, लोकनायक अस्पताल, जीटीबी अस्पताल जैसे बड़े अस्तपालों में भी मूलभूत सुविधाएं एवं उपकरण नहीं हैं। कहीं उपकरण हैं तो डॉक्टर नहीं हैं। रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए मुख्य पीठ ने दिल्ली सरकार को एक संक्षिप्त रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य पीठ ने छह जून को दिल्ली के 35 सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पूर्व प्रधान सचिव डीएस नेगी की अध्यक्षता में सात सदस्यीय विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया था। साथ ही पीठ ने विशेषज्ञ कमेटी के कार्य में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा को मदद करने का निर्देश दिया था। कमेटी ने जीबी पंत अस्पताल, लोकनायक अस्पताल, जीटीबी अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल समेत 35 अस्पतालों व प्राथमिक केंद्रों का निरीक्षण किया।

अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा ने बताया कि पीठ के समक्ष दाखिल की गई रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से लेकर बड़े सरकारी अस्पतालों की हालत बेहद खराब है। बड़े अस्पतालों में समर्पित आइसीयू डायरेक्टर या प्रभारी नहीं है। अधिकांश अस्पतालों में करोड़ों की लागत से खरीदे गए उपकरण बिना इस्तेमाल के पड़े हैं। इतना ही नहीं दिल्ली सरकार के अधिकांश सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए पाइप्ड मेडिकल गैस सुविधा नहीं है। एनुअल मेंटेनेंस कान्ट्रैक्ट (एएमसी), कॉम्प्रीहेंसिव मेंटेनेंस कान्ट्रैक्ट (सीएमसी) उपलब्ध नहीं हैं। फर्जी कंपनियों के माध्यम से उपकरण की खरीद होती है और इसके कारण एएमसी व सीएमसी उपलब्ध नहीं है। जीटीबी, जीबी पंत, एलएनजेपी जैसे बड़े अस्पतालों में रखरखाव की स्थिति खराब है। जीटीबी अस्पताल का ऑपरेशन थियेटर चार साल से नहीं चल रहा है। किसी अस्पताल में मरीजों की संख्या के हिसाब से आइसीयू में बेड उपलब्ध नहीं हैं।

शाम चार बजे के बाद नहीं चलती इमरजेंसी : रिपोर्ट के अनुसार इमरजेंसी विभाग की स्थिति सबसे दयनीय है। यहां पर मरीजों की संख्या के हिसाब से डॉक्टरों, नर्सों की संख्या काफी कम है। अधिकांश अस्पतालों में 40 मरीज पर एक डॉक्टर है तो 23 मरीज पर एक नर्स। कर्मचारियों की कमी के कारण शाम चार बजे के बाद इमरजेंसी नहीं चलती। इतना ही नहीं कर्मचारियों की कमी के संबंध में डाटा तैयार करने का कोई उपयुक्त प्रक्रिया नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार अस्पतालों में ट्रांसफर करने की कोई पॉलिसी नहीं है। बगैर व्यवस्था किए डॉक्टर से लेकर नर्स और कर्मचारियों का तबादला कर दिया जाता है।

यह है मामला : नौ महीने की गर्भवती मधुबाला के बच्चे की मौत जीटीबी अस्पताल में ऑपरेशन थियेटर नहीं मिलने के कारण गर्भ में ही हो गई थी। इतना ही नहीं अस्पताल की लापरवाही के कारण तीन दिन तक उनका मृत बच्चा गर्भ में ही रहा तो उनकी जान पर बन आई। हालांकि वह किसी तरह बच गईं। इसके बाद मधुबाला ने अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा के माध्यम से जीटीबी अस्पताल समेत पांच बड़े सरकारी अस्पतालों के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी।

करीब पांच महीने तक 35 सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करने के बाद कमेटी ने 250 से अधिक पेज की रिपोर्ट पेश की

पहल

उत्तरी दिल्ली निगम और स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए दो दिवसीय महिला महोत्सव का हुआ आगाज

देर रात सड़क पर महिलाओं ने खुद को महसूस किया सुरक्षित

किशन कुमार, नई दिल्ली

रात में भी खुली सड़क पर महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए करोलबाग में गुरुवार को दो दिवसीय महिला रात्रि महोत्सव का आगाज हुआ। मोटर वाहनमुक्त (एनएमवी) अजमल खां रोड पर महोत्सव के पहले दिन बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचीं। खुली सड़क पर महिलाओं ने खाने-पीने के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद उठाया। सफेद रोशनी से नहाई सड़क और दोनों ओर झालरों से जगमग दुकानों का नजारा कुछ ऐसा था कि जैसे दिवाली लौट आई हो। देर रात बाजार में उत्सव का माहौल बना रहा। यह पहली बार है जब दिल्ली में महिलाओं के लिए रात में बाजार और महोत्सव का रंग जमा हो।

महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए उत्तरी दिल्ली निगम व स्वयंसेवी संस्थाओं की यह अनूठी पहल है, जो शाम सात बजे से रात्रि 11 बजे तक के लिए है। वैसे बाजार में मध्य रात्रि तक चहल-पहल रही। 'स्टेप आउट ऐट नाइट' नाम के इस महोत्सव में मनोरंजन के तमाम इंतजाम हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मंच से लेकर खेलकूद की गतिविधियां भी शामिल हैं। ऐसे में महिलाओं के साथ पहुंचे बच्चों ने भी खुली सड़क पर जमकर मस्ती की। कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने किया।

उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि महिलाएं सभी क्षेत्रों में अपनी भागीदारी रखें। महिला की सुरक्षा करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जब यहां की सड़कों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाएंगे तब जाकर देश सुरक्षित होगा। सभी को इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। आज हम अच्छे लोगों के साथ इस पर्व के लिए पहुंचे हैं, ताकि अधिकतर महिलाएं अपने घरों से निकलें और अपनी बंदिशों को खत्म करें। उत्तरी दिल्ली नगर की निगमायुक्त वर्षा जोशी ने भी महिलाओं को घरों से बाहर निकलकर इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए अपील की। कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं का कहना था कि महिलाएं यहां स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं। सरकार को ऐसी व्यवस्था दिल्ली में हर बाजार व विभिन्न इलाकों भी करनी चाहिए, ताकि आधी रात में निकलने में भी महिलाएं डर महसूस न करें।

चाट-पकौड़ी के स्टॉलों पर रही भीड़ : कार्यक्रम में जगह-जगह खाने पीने के स्टॉल लगाए गए हैं। ऐसे में सबसे अधिक भीड़ चाट-पकौड़ी के स्टॉलों पर देखने को मिली। लोगों ने पॉव भाजी, चीला, गोल-गप्पे व पकौड़ों आदि का स्वाद लिया। महिलाओं का कहना था कि पहली बार इस बाजार में इस तरह के खाने-पीने के स्टॉलों का लगना सराहनीय है।

भंगड़ा व घूमर नृत्य पर थिरके लोग : कार्यक्रम में लोगों को राज्यों की संस्कृति से भी रूबरू होने का भी मौका मिला। पंजाबी भांगड़ा से लेकर राजस्थानी घूमर पर लोग जमकर थिरकते दिखे। कोई परिवार के साथ तो कोई दोस्तों के साथ खुली सड़क पर झूमता दिख रहा था। मौज-मस्ती के मूड में डूबे लोग कार्यक्रम को अपने अंदाज से जी रहे थे।

करोलबाग की अजमल खां रोड पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में बैंड बाजे पर थिरकती युवतियां। ध्रुव कुमार

Umasankar

220 भ्रष्ट कर्मचारियों को समयपूर्व सेवानिवृत्ति दी गई है पिछले पांच वर्षों में। इनमें 96 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। कार्मिक मंत्रालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी।

यहां हर कोई काम रोकने की बात करता है : गडकरी

व्यथा ▸ सड़क परिवहन मंत्री ने परियोजनाओं में विलंब के कारण बताए

कहा, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और मध्यस्थता में देरी सबसे बड़ी बाधा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परियोजनाओं में होने वाली देरी पर अपनी व्यथा सामने रख दी। भूमि अधिग्रहण व पर्यावरण मंजूरियों के अलावा मध्यस्थता प्रक्रियाओं को कठघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा, 'यहां हर कोई काम रोकने की बात करता है। काम करने की बात कोई नहीं करता।' देश को विकास के प्रति सकारात्मक नजरिया एवं व्यवहार अपनाने की जरूरत है।

गुरुवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सड़क परियोजनाओं में विलंब के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में गडकरी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और विकास के कार्य साथ-साथ चलने चाहिए। उन्होंने आर्बिट्रेशन प्रक्रियाएं जल्द पूरी करने को लेकर सरकार की गंभीरता का जिक्र भी किया।

लोकसभा में गुरुवार को सवाल का जवाब देते केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (टीवी ग्रैब)। प्रेट्र

'भारतमाला' परियोजना की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने इस परियोजना के 5.35 लाख करोड़ रुपये लागत वाले पहले चरण को अक्टूबर, 2017 में मंजूरी दी थी। इसके तहत 10 हजार किमी नेशनल हाईवे समेत कुल 34,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होना है। परियोजना में नौ हजार किमी के आर्थिक गलियारे, छह हजार किमी के फीडर रोड तथा पांच हजार किमी के राष्ट्रीय गलियारे शामिल हैं। इसके अलावा इसमें दो हजार किमी सीमावर्ती सड़कों, इतनी ही तटीय सड़कों तथा 800 किमी एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है। गडकरी ने कहा कि राजमार्गों का निर्माण अलाइनमेंट, लागत एवं भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता, डीपीआर/फीजिबिलिटी अध्ययन, वित्तीय क्षमता तथा कोष की उपलब्धता इत्यादि के आकलन के बाद ही शुरू किया जाता है।

भारत में सड़क हादसों से सबसे ज्यादा मौतें : गडकरी ने कहा कि भारत में सड़क हादसों से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। जबकि, दुनिया में ऐसे भी देश हैं, जहां कोई सड़क दुर्घटना नहीं होती। हादसों पर काबू पाने के लिए सरकार विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की मदद से ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त करने की 14 हजार करोड़ रुपये की परियोजना चला रही है। इसके अलावा सरकार सड़कों के ऑडिट के जरिये दुर्घटनाओं का कारण पता कर दोषियों की जिम्मेदारी तय करेगी। हिमाचल प्रदेश में बस हादसों पर नियंत्रण के लिए नदियों के किनारे बैरियर लगाए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे एक्सिडेंट रिलीफ स्कीम के बारे में उन्होंने कहा कि यह योजना 2017 तक वैध थी और एनएचएआइ एंबुलेंस प्रदान करती थी। अब टोल प्लाजा पर एंबुलेंस उपलब्ध कराई जा रही है।

संसदीय समितियों से भी गायब होते हैं सांसद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : मंत्रालयों के कामकाज पर नजर रखने वाली संसदीय समितियों की बैठकों में सदस्यों की कम अनुपस्थिति पर गुरुवार को राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने बेहद नाखुशी जताई। उन्होंने कहा कि सदस्यों का इस तरह का रवैया ठीक नहीं है। सभापति इससे पहले भी सदन में सदस्यों की कम उपस्थिति और सवाल करने के बाद गायब होने को लेकर नाराजगी जता चुके हैं।

गुरुवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति ने इसका जिक्र छेड़ा। उन्होंने बताया कि उनकी गुरुवार को ही आठों संसदीय समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक हुई है। इसमें उन्हें बताया गया कि सभी समितियों की अब तक करीब 41 बैठकें हुई हैं, लेकिन इनमें से राज्यसभा से कुल 18 सदस्य ही ऐसे रहे हैं जो अपनी समिति की सभी बैठकों में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि यह स्थिति तब है जबकि संसदीय समितियों में राज्यसभा के कुल 80 सदस्य हैं। सभापति ने कहा कि लोकसभा सदस्यों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही रही है। उनके भी 18 सदस्य ही सभी बैठकों में मौजूद रहे हैं, जबकि सभी समितियों में लोकसभा के कुल 168 सदस्य हैं। नायडू ने कहा कि सदस्यों का यह रवैया इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि प्रत्येक सदस्य उस बैठक में 25 सदस्यों के प्रतिनिधि के तौर पर रखा जाता है। ऐसे में सदस्यों की अनुपस्थिति से उनकी आवाज कमजोर पड़ रही है। बता दें कि एक संसदीय समिति में अध्यक्ष सहित राज्यसभा के 10 सदस्य और लोकसभा के 21 सदस्य होते हैं।

मंत्री समूह ने की प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के उपायों की समीक्षा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ जमाखोरों पर सख्ती और प्याज के आयात सौदों पर विचार किया

प्याज की महंगाई को लेकर मची हायतौबा थमने का नाम नहीं ले रही है। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष सरकार पर हमलावर हो रहा है तो उपभोक्ताओं की मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। इसे लेकर सरकार भी चुप नहीं है। हर स्तर पर उपाय किए जा रहे हैं। घरेलू बाजार में जमाखोरों पर सख्ती के साथ विदेशों से प्याज आयात करने को प्राथमिकता दी जा रही है। प्याज की किल्लत कम करने और महंगाई रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली मंत्रियों के समूह की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की गई। इसमें मंत्रियों के साथ सरकारी एजेंसियों के आला अफसरों ने भी हिस्सा लिया। शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ कैबिनेट सचिव राजीव गाबा और पीएम के सलाहकार पीयूष सिन्हा ने हिस्सा लिया।

उधर, लंबे समय तक जेल में रहे कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और गौरव गोगोई के साथ कुछ अन्य सदस्यों ने संसद परिसर में प्याज के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने टोकरी में प्याज लेकर सरकार पर महंगाई बढ़ाने वाले कदम उठाने का आरोप लगाया। हाथों में सरकार विरोधी बैनर लेकर उन्होंने सरकार पर गरीब विरोधी होने के आरोप भी मढ़े। चिदंबरम ने एक संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री के बुधवार के प्याज पर दिए गए बयान की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि इससे सरकार की सोच को जाना जा सकता है जबकि राज्यसभा में एक चर्चा के जवाब में सीतारमण ने चिदंबरम पर पलटवार करते हुए कहा कि वह केवल पूरे बयान को समग्रता में लेने के बजाय एक टुकड़े पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो उचित नहीं है।

हालांकि सरकार की ओर से बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्याज के भंडारण के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने का आश्वासन दिया था। लोकसभा में एक चर्चा के दौरान उठे प्याज की महंगाई के मुद्दे पर भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष बिरेंद्र सिंह मस्त ने विपक्ष से कहा कि वह उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र बलिया में 25 रुपये किलो की दर से प्याज मुहैया करा सकते हैं। प्याज की कमी के चलते देश के कुछ हिस्सों में कीमतें 100 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों से स्थानीय स्तर पर प्याज की आपूर्ति बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके पहले कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने सभी राज्यों में स्थानीय बफर स्टॉक गठित करने को कहा है। आयातित प्याज की पहली खेप अगले सप्ताह तक भारतीय बंदरगाह पर पहुंच जाएगी।

कौशल विकास के तहत पीएसयू में अब ज्यादा युवाओं को मिलेगी अप्रेंटिसशिप

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण पाने वाले युवाओं को अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में अप्रेंटिसशिप का मौका पहले से ज्यादा मिल सकेगा। पीएसयू में कुल कामगारों के 15 फीसद तक अप्रेंटिसशिप उपलब्ध कराना अनिवार्य है। सरकार ने सभी पीएसयू को नियम का सख्ती से अनुपालन करने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि इससे देश में लगभग सात लाख प्रशिक्षित युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अवसर मिल सकेगा।

अप्रेंटिसशिप के मुद्दे पर गुरुवार को यहां आयोजित एक सेमिनार में इसके नियमों के अनुपालन और आ रही अड़चनों पर चर्चा की गई। इस दौरान कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने सभी पीएसयू से युवाओं की अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देकर उन्हें अपने कर्मचारियों के समकक्ष खड़े होने का अवसर प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अप्रेंटिसशिप के माध्यम से युवाओं को उद्योग जगत के अनुरूप तैयार करते हुए उनकी क्षमता का उपयोग करें। पांडेय ने कहा कि इससे उद्यम और अप्रेंटिसशिप पाने वाले युवाओं की सफलता सुनिश्चित की जा सकेगी।

▸ पीएसयू में कुल कामगार के 15 फीसद तक अप्रेंटिसशिप का है प्रावधान

▸ नियम का पालन होने पर सात लाख युवाओं को मिलेगा बेहतरीन अवसर

कौशल विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सेमिनार में ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, एनबीसीसी, पावर ग्रिड, बीएसईएल, एनटीपीसी, एयर इंडिया समेत देश के लगभग सभी सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधि मौजूद थे। पीएसयू के प्रतिनिधियों ने अपने प्रबंधकों से परामर्श कर 15 फीसद अप्रेंटिसशिप के प्रावधान को लागू करने का भरोसा दिया।

उल्लेखनीय है कि कौशल विकास मंत्रालय देश भर में युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर उन्हें कुशल कामगार बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी समस्या प्रशिक्षित युवाओं को ऑन-जॉब-ट्रेनिंग यानी नौकरी करते हुए प्रशिक्षण देने की आती है। इसे दूर करने के लिए कई स्तर पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ सेमिनार का उद्देश्य उनकी जरूरतों को समझने और प्रशिक्षित युवाओं के बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था।

आम आदमी की उम्मीदों के अनुरूप ढाले जाएंगे कानून

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ संसद में उठी थी ब्रिटिश कालीन कानूनों को बदलने की मांग

▸ गृह मंत्रालय ने कानूनों में बदलाव के लिए राज्यों से मांगे सुझाव

मौजूदा वक्त की जरूरतों के मुताबिक भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) और अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में संशोधन के लिए गृह मंत्रालय ने राज्यों से सुझाव मांगा है। इन कानूनों को आम आदमी की लोकतांत्रिक अपेक्षाओं के अनुरूप और महिलाओं, बच्चों व समाज के कमजोर तबकों को त्वरित न्याय मुहैया कराने के योग्य बनाने के लिए गृह मंत्रालय इस कवायद में जुटा है। इसके साथ ही जटिल कानूनी प्रावधानों को सरल बनाया जाएगा, ताकि आम आदमी को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े।

गौरतलब है कि संसद के मानसून सत्र के दौरान सत्ता और विपक्ष दोनों ओर के सांसदों ने ब्रिटिश काल के दौरान बने कानूनों को बदलने और उन्हें देश की मौजूदा जरूरतों के अनुरूप ढालने की मांग की थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो को सीआरपीसी, आइपीसी, भारतीय साक्ष्य कानून, मादक पदार्थों से जुड़े कानून में संशोधन का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसी क्रम में सभी राज्य सरकारों को सुधारों के लिए अपने-अपने विचार भेजने को कहा गया है। राज्यों की ओर से मिले सुझावों पर विचार और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो कानून में संशोधनों का प्रारूप तैयार करेगी। अधिकारी ने कहा कि अभी इन कानूनों में संशोधन की समय-सीमा तय करना मुश्किल होगा। यह राज्यों के सहयोग पर निर्भर करेगा। पूरी प्रक्रिया में लंबा वक्त भी लग सकता है।

बहुत जटिल हैं अभी कानून : ब्रिटिश काल में तैयार सीआरपीसी और आइपीसी के प्रावधानों को इस तरह जटिल बनाया गया था कि ब्रिटिश अधिकारियों व बड़े लोगों को सजा से बचाया जा सके। वहीं आम आदमी कानून की जटिलताओं में उलझकर न्याय की उम्मीद छोड़ देता था। यही नहीं, जटिलताओं के कारण न्याय पाने की पूरी प्रक्रिया अत्यंत लंबी, मुश्किल और खर्चीली भी हो गई। अधिकारी ने कहा कि पूरी न्याय प्रक्रिया को सरल और आम आदमी की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने की जरूरत है। इसके लिए मौजूदा कानूनों को बदलना जरूरी है।

सुस्ती का मर्ज नहीं पकड़ पा रही सरकार : चिदंबरम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ रिहाई के तत्काल बाद पूर्व मंत्री ने किया सरकार पर हमला

▸ कहा, नोटबंदी, त्रुटिपूर्ण जीएसटी जैसे कदमों ने अर्थव्यवस्था को तबाह किया

सरकार की आर्थिक नीतियों के मुखर आलोचक रहे पूर्व मंत्री पी चिदंबरम ने साढ़े तीन महीने की जेल से रिहाई के अगले ही दिन आर्थिक मंदी के मौजूदा हालात को लेकर केंद्र पर जमकर हमला बोला। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि लगातार घटती विकास दर से साफ है कि सरकार अर्थव्यवस्था की असल बीमारी को अभी तक समझ नहीं पाई है। हालात उस ओर बढ़ रहे हैं कि यह अर्थव्यवस्था के लिए घातक भी साबित हो सकता है। डांवाडोल अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाते हुए चिदंबरम ने कहा कि अपनी नासमझी से ध्यान बंटाने को सरकार ने अपने मंत्रियों को भटकाने और आंख में धूल झोंकने का जिम्मा सौंप रखा है।

रिहा होने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिदंबरम ने जीडीपी की गिरावट 4.5 फीसद तक आने को अर्थव्यवस्था के गंभीर रोग से ग्रस्त होने का प्रमाण बताया। मौजूदा आर्थिक सुस्ती को चक्रीय गिरावट बताने के सरकार के दावों को खारिज करते हुए इसे गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि हकीकत में नोटबंदी, त्रुटिपूर्ण जीएसटी, टैक्स आतंक, नियामक प्रक्रियाओं की अधिकता और निर्णय प्रकिया का पीएमओ में पूरी तरह केंद्रीकरण जैसे कदमों ने अर्थव्यवस्था को तबाही के मुहाने पर ला खड़ा किया है। पिछली छह तिमाही में जीडीपी के आठ फीसद से 4.5 फीसद आने तक के आंकड़ों के सहारे तंज कसते हुए चिदंबरम ने कहा कि ये सरकार के अच्छे दिन हैं। हम सौभाग्यशाली होंगे अगर वित्त वर्ष के अंत तक जीडीपी पांच फीसद को छू ले। सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम के बयान का हवाला देते हुए चिदंबरम ने कहा कि उन्होंने जीडीपी के पांच फीसद तक घटने की चेतावनी दी थी। मगर आशंका है कि इसमें और डेढ़ फीसद तक गिरावट संभव है। चिदंबरम ने भारत पेट्रोलियम समेत तमाम लाभकारी सरकारी कंपनियों को बेचने की तैयारी पर कहा कि यह एक बड़ा स्कैंडल है। सरकार अपना सकल घाटा कम करने के लिए यह हथकंडा अपना रही है। उनका यह भी कहना था कि संप्रग सरकार ने अपने 10 साल के शासन में जहां रिकार्ड 14 करोड़ लोगों को गरीबी के दायरे से बाहर निकाला वहीं राजग सरकार लाखों लोगों को फिर से गरीबी के दलदल में धकेल रही है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। संजय

चिदंबरम ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया : जावडेकर

नई दिल्ली, एएनआइ : भाजपा ने पूर्व मंत्री चिदंबरम पर जमानत शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आइएनएक्स मीडिया मामले में जमानत के लिए लगाई गई शर्तों का चिदंबरम ने पहले दिन ही उल्लंघन कर दिया। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि चिदंबरम केस के मामले में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। लेकिन, उन्होंने गुरुवार को कहा कि मंत्री के रूप में मेरा रिकॉर्ड बहुत साफ है। जावडेकर ने कहा कि यह एक ऐसा मुकदमा है, जिसमें मंत्री रहते हुए उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। लेकिन, वे खुद को निर्दोष बता रहे हैं। यह जमानत की शर्तों का उल्लंघन है।

जेल में रीढ़ और गर्दन ही नहीं दिमाग भी हुआ मजबूत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 106 दिन बाद जेल से रिहा होने पर जहां खुशी का इजहार किया, वहीं भाजपा सरकार से सीधे मुकाबला करने के लिए डटे रहने का संदेश भी दिया। अपने मुकदमे का जिक्र किए बिना उन्होंने कहा कि जेल में बिना तकिए के लकड़ी की बेंच पर सोने से न केवल उनकी रीढ़ और गर्दन बल्कि दिमाग भी मजबूत हुआ है। चिदंबरम ने कहा कि मंत्री के तौर पर उनका ईमान पूरी तरह साफ था और न्याय प्रक्रिया पर उन्हें पूरा भरोसा है। चिदंबरम ने कहा कि सरकार संसद में उनकी आवाज को दबा नहीं सकती। उन्होंने कहा कि बेशक 106 दिन बाद आजाद हवा में सांस लेकर वे खुश हैं मगर साथ ही कश्मीर घाटी के उन 75 लाख लोगों के लिए वे प्रार्थना कर रहे जिन्हें चार अगस्त से ही स्वतंत्रता के बुनियादी अधिकार से वंचित रखा गया है। भय के माहौल पर राहुल बजाज के रुख से जुड़े सवाल पर चिदंबरम ने कहा कि बजाज इतने सक्षम हैं कि सत्ता के सामने इस सच को कह सकते हैं। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य यह है कि मीडिया भी इस भय से अछूता नहीं है।

सेवानिवृत्ति की उम्र में बदलाव का प्रस्ताव नहीं : सरकार

संसद प्रश्नोत्तर

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र 60 रखने या इसके लिए 33 वर्षों की सेवा पूरी करने जैसा कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यसभा में गुरुवार को एक लिखित उत्तर में कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल से कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार से पूछा गया था कि क्या वह सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र या तो 60 साल या 33 वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद, दोनों में से जो भी पहले हो उसे निर्धारित करने पर विचार कर रही है।

लोक सेवा परीक्षा 2018 में हिंदी के साथ 485 प्रत्याशी हुए सफल : जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2018 की संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में करीब 485 ऐसे प्रत्याशी सफल हुए जिन्होंने मातृ भाषा के रूप में हिंदी का चयन किया था। 2018 की जांच के आधार पर कुल 812 प्रत्याशी चुने गए थे। अन्य प्रत्याशियों ने दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं का चयन किया था।

गोद लिए गए 2,279 बच्चों में से 1,342 लड़कियां : महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि 2019-20 के दौरान करीब 2,279 बच्चे गोद लिए गए। इनमें से 1,342 लड़कियां हैं। 2,004 बच्चे देश में गोद लिए गए और 275 को दूसरे देश के व्यक्तियों ने गोद लिए।

पांच अगस्त के बाद जम्मू-कश्मीर में 4000 पासपोर्ट सौंपे गए : संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा को बताया कि पांच अगस्त के बाद जम्मू एवं कश्मीर में लगभग 4000 पासपोर्ट बांटे गए। उन्होंने कहा कि राज्य में डाक सेवा निलंबित नहीं है।

छात्रावास का खर्च बढ़ने के कारण जेएनयू में शुल्क बढ़ा

एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि छात्रावासों के खर्च में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए जेएनयू में शुल्क बढ़ाया गया। करीब 40 साल बाद विवि ने छात्रावासों का किराया बढ़ाया है।

लोकसभा में अगले हफ्ते पेश हो सकता है नागरिकता संशोधन विधेयक

▸ कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने लिया विरोध का निर्णय

▸ सरकार को बीजद व टीआरएस जैसे दलों का भरोसा

नई दिल्ली, एजेंसियां : विपक्ष के विरोध के बावजूद नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) सोमवार को लोकसभा में पेश हो सकता है। मंगलवार को यह विधेयक बहस और अनुमति के लिए पटल पर रखा जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे बुधवार को ही हरी झंडी दे दी है।

इस विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भागकर आने वाले गैर मुसलमानों के लिए भारतीय नागरिकता को आसान बनाने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में तो विधेयक की राह आसान होगी, लेकिन राज्यसभा में अड़चनें आ सकती हैं। हालांकि, केंद्र सरकार को भरोसा है कि गठबंधन से इतर बीजू जनता दल (बीजद) और तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) जैसे दलों के समर्थन से यह राज्यसभा में भी आसानी से पास हो जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार ने कार्य मंत्रणा समिति में विभिन्न दलों को सूचित कर दिया है कि वह मंगलवार को लोकसभा में विधेयक को चर्चा के लिए रखेगी। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस विधेयक का विरोध करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए इसे संसदीय समिति के समक्ष रखने की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस भी इसी खेमे में खड़ी है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने लोकसभा में विधेयक के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है।

उधर, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने विधेयक का विरोध करने वाले नरमपंथियों पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया, 'विधेयक लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में नहीं पहुंच सका। उत्पीड़ित को आश्रय देने वाली भारतीय परंपरा का पालन करते हुए पुनरीक्षित विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।'

शिवसेना के रुख पर रहेगी सबकी नजर

कभी भाजपा की सहयोगी रही शिवसेना ने महाराष्ट्र में कांग्रेस व राकांपा के साथ सरकार बना ली है। इसके बाद हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर रही शिवसेना का नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर रुख स्पष्ट नहीं है। हालांकि, पहले वह विधेयक का समर्थन करती रही है। उधर, भाजपा ने इस मुद्दे पर शिवसेना से कोई बात नहीं करने का फैसला किया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, 'हमें शिवसेना से क्यों संपर्क करना चाहिए? अगर उन्हें समर्थन करना होगा तो वे करेंगे।' इस बीच कांग्रेस के सूत्र ने बताया कि पार्टी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से संपर्क करेगी और विधेयक का विरोध करने के लिए कहेगी। अब दोनों पार्टियां यह देखना चाहेंगी कि सदन में शिवसेना किस तरफ का रुख करती है। अगर शिवसेना ने भाजपा का साथ दिया तो महाराष्ट्र सरकार के भविष्य पर भी इसका असर पड़ सकता है।

सोशल मीडिया से हटानी ही होगी बाल यौन हिंसा संबंधी सामग्री

▸ नियम तैयार कर रही है सरकार, आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाली सामग्री हटाना भी अनिवार्य बनाया जाएगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने कहा है कि वह ऐसे नियम तैयार करने में जुटी है जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों के लिए बाल यौन हिंसा और आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाली सामग्री को हटाना अनिवार्य बनाया जाएगा। निजता को प्रभावित किए बगैर कंपनियां ऐसी सामग्री हटाएंगी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार ने मध्यवर्ती नियम 2011 में संशोधन के अपने मसौदे पर लोगों से राय मांगे हैं। इसपर सार्वजनिक इनपुट भी लिए हैं।

प्रसाद ने कहा, 'अन्य बातों के अलावा संशोधन में प्रस्ताव है कि मध्यवर्ती संस्थाएं सक्रियता से बाल यौन हिंसा सामग्री, दुष्कर्म-सामूहिक दुष्कर्म के काल्पनिक चित्र और आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाली सामग्री की पहचान करें और तकनीक आधारित टूल और तंत्र का इस्तेमाल करते हुए उसे हटाएं। इस काम में सटीकता या निजता के साथ समझौता नहीं करें। नियम को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है।' उन्होंने कहा कि सूचना तकनीक (आइटी) अधिनियम 2000 में आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री को हटाने के लिए पर्याप्त प्रावधान है। अधिनियम में सोशल मीडिया प्लेटफार्म को मध्यवर्ती के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रसाद ने कहा कि आइटी अधिनियम 2000 सरकार को किसी भी सूचना की उत्पत्ति, प्रसारण, प्राप्ति, संग्रह को रोकने का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार देश की संप्रभुता और एकता के हित में, देश की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, कानून व्यवस्था बनाए रखने या संज्ञेय अपराध होने से रोकने के लिए है।

इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी सामग्री मुद्दे का अध्ययन करेगी अनौपचारिक समिति : राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने घोषणा की कि 14 सदस्यीय अनौपचारिक समिति इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोर्नोग्राफी सामग्री संबंधी मुद्दे का अध्ययन करेगी। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश इस समूह के समन्वयक होंगे। एक महीने में समिति रिपोर्ट तैयार करेगी। पिछले सप्ताह शून्यकाल में कई सदस्यों के चिंता जताने के बाद नायडू ने समिति गठित की है। सदस्यों ने इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोर्नोग्राफी सामग्री से बच्चे किस तरह प्रभावित हो रहे हैं इसे लेकर चिंता जताई थी।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

हुई चर्चा

दिल्ली में कानून लागू नहीं होने से घटे चालान, लेकिन कोर्ट पर बढ़ा दबाव, जुर्माना बढ़ाने से पहले सरकार को अपना तंत्र दुरुस्त करने का सुझाव

सड़क सुरक्षा सम्मेलन में राज्यों की आलोचना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सड़क सुरक्षा पर कितने भी नियम-कानून बना दिए जाएं, जब तक इनके कार्यान्वयन को लेकर देश में राजनीतिक सहमति नहीं बनती, तब तक सड़क दुर्घटनाओं और मौतों में कमी होने वाली नहीं है। फिक्की द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा सम्मेलन में वक्ताओं की यही राय थी। सम्मेलन में ज्यादातर वक्ताओं ने संशोधित मोटर एक्ट के तहत बढ़े प्रावधानों को उचित ठहराया और इन्हें लागू करने में आनाकानी करने वाली राज्य सरकारों की आलोचना की।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं देश को बहुत महंगी पड़ रही हैं। लिहाजा हमें नियमों के अनुपालन के साथ अपने रवैये में बदलाव लाना होगा। सड़क सुरक्षा की आदत बचपन से ही डाले जाने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि दो जंबो जेट के टकराने से उतने लोग नहीं मरते, जितने एक दिन में सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। इसके बावजूद जेट टकराने पर ज्यादा शोर मचता है। परिचर्चा के दौरान वक्ताओं ने संशोधित मोटर एक्ट, 2019 की खूबियों और खामियों का जिक्र किया।

बैजयंत पांडा। फाइल

सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ कमल सोई ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्णयों को राज्य सरकारें पलीता लगा रही हैं। मसलन, केंद्र ने बिना हेलमेट दुपहिया चलाने वालों पर जुर्माना बढ़ा दिया। परंतु गुजरात सरकार हेलमेट को शहरों के लिए गैरजरूरी बता रही है। कई राज्यों ने एक्ट लागू करने की अधिसूचनाएं जारी नहीं की हैं। वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस व पैनिक बटन लगाने का निर्णय कई वर्ष पहले हुआ था। परंतु आज तक लागू नहीं हुआ है। उन्होंने ड्राइविंग टेस्ट प्रक्रिया को दोषपूर्ण बताते हुए इसे विदेश की तरह वास्तविक यातायात स्थितियों में किए जाने का सुझाव दिया।

दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त (यातायात) ताज हसन का कहना था कि दिल्ली सरकार के अधिसूचना जारी न करने से हमें कंपाउंडिंग अपराधों में भी चालान कोर्ट भेजने पड़ रहे हैं, जिससे कोर्ट का काम भी बढ़ गया है। पहले हम 20 हजार चालान करते थे, जिनमें केवल 1,200 कोर्ट जाते थे। अब केवल 5000 चालान हो रहे हैं, और सब कोर्ट जा रहे हैं। एक्ट की धारा 136ए में कैमरों के जरिये इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग का प्रावधान है। इसके लिए हमने 22 जंक्शन पर रेड लाइट वायलेशन और 100 जगहों पर ओवरस्पीडिंग कैमरे लगा रखे हैं। परंतु अधिसूचना नहीं जारी होने से इनका कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। एक्ट लागू होने के बाद से अब तक पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 105 हादसे कम हुए हैं।

सड़क सुरक्षा पर काम करने वाली रजनी गांधी ने कांफ्रेंस में मौजूद लोगों से पूछा कि कितने लोग संशोधित मोटर एक्ट को सही मानते हैं तो एक महिला को छोड़ सभी ने हाथ उठा दिए। महिला का कहना था कि सरकार को पहले सड़क सुरक्षा का अपना तंत्र मजबूत करना चाहिए तब जुर्माना बढ़ाना चाहिए। जब सड़कें टूटी हैं, रेड लाइटें काम नहीं करतीं, रोड साइन दोषपूर्ण हैं, तो कैसे केवल चालकों को दोषी ठहराया जा सकता है।

11 ट्रांसपोर्ट कंपनियां स्वीकार कर रही हैं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश की 11 ट्रांसपोर्ट एजेंसियां नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड स्वीकार कर रही हैं। लोकसभा में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक सवाल के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। इस कार्ड से देश भर में कहीं भी सरकारी परिवहन में भुगतान किया जा सकता है।

2014 में झारखंड विधानसभा चुनाव में विधायक पद के उम्मीदवारों को पहली बार नोटा का सामना करना पड़ा था। प्रदेश में कुल 1136 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 732 को नोटा से भी कम वोट मिले थे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 6 दिसंबर 2019

स्टार प्रचारक

जनता करेगी विकास गाड़ी और 'बेलगाड़ी' में चुनाव : संबित पात्रा

राज्य ब्यूरो, रांची : भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में यह जनता तय करेगी कि उसे विकास गाड़ी लानी है या 'बेलगाड़ी'। उन्होंने ये बातें गुरुवार को रांची में पत्रकार वार्ता के दौरान कहीं। कहा, महागठबंधन के बड़े-बड़े नेता 'बेलगाड़ी' पर सवार हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी तो बेल पर हैं ही, अब पी चिदंबरम भी उसी क्लब का हिस्सा हो गए हैं। हाल ही में दिए गए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के वक्तव्य का हवाला देते हुए कहा कि मनमोहन सिंह कहते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव जब गृह मंत्री थे, तब वे चाहते तो सिख दंगे रोक सकते थे। पहली बार कांग्रेस ने यह माना है कि उसी ने सिख दंगे करवाए। पात्रा ने गठबंधन के घटक दलों पर घुसपैठियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखने का भी आरोप लगाया। कहा, रघुवर दास सरकार ने राज्य में दो चरणों में 25 हजार और एक लाख नौकरी देकर लिम्का बुक में नाम दर्ज कराया तो हेमंत सोरेन ने एक दिन में 16 जमीन की रजिस्ट्री कराकर एक रिकार्ड बनाया।

नोटबंदी और जीएसटी लाकर सरकार ने गरीबों की तोड़ी कमर : शत्रुघ्न सिन्हा

जेएनएन, चतरा/हजारीबाग : नोटबंदी व जीएसटी ने गरीबों के साथ-साथ व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। भाजपा सरकार ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, लेकिन विकास कहीं दिख नहीं रहा है। विकास गरीबों का होना चाहिए था, लेकिन विकास भाजपा के नेताओं का हुआ है। यह बातें कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहीं। वह गुरुवार को चतरा के इटखोरी और हजारीबाग के चौपारण में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बीच-बीच में फिल्मी अंदाज में सरकार पर व्यंग्य करते हुए लोगों को हंसाया। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता महंगाई की मार से त्राहिमाम है। गरीबों की थाली से हरी सब्जियां और प्याज गायब है।

डबल इंजन की सरकार में भी झारखंड पिछड़ा और बदहाल : तेजस्वी यादव

जेएनएन, जमशेदपुर/कोडरमा : राजद नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को जमशेदपुर और कोडरमा में महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं कीं। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में भी झारखंड पिछड़ा व बदहाल है। कहा, भाजपा ने ऐसे कमल छाप साबुन का ईजाद किया है, जिससे नहाते ही सारे पाप धुल जाते हैं। जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा हिंदुस्तान-पाकिस्तान, हिंदू-मुस्लिम और इमरान खान की ओर लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। आज भाजपा के अच्छे दिन की हालत यह है कि प्याज 120 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। लोग प्याज खाकर नहीं, सूंघकर काम चला रहे हैं। अपने पिता लालू यादव का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के लोगों ने साजिश के तहत उन्हें जेल भिजवाया है।

विपक्ष के पास नहीं है कोई मुद्दा : आठवले

जागरण संवाददाता, बोकारो : केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास आठवले ने दावा किया कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से पांच पर आरपीआइ चुनाव लड़ रही है। चुनाव में पार्टी के जितने भी प्रत्याशी विजयी होंगे, एनडीए सरकार को अपना समर्थन देंगे। अठावले बोकारो में आरपीआइ प्रत्याशी नवल शर्मा के पक्ष में चुनावी सभा करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड हो या पूरा देश कांग्रेस व उनके सहयोगी दल एससी व आदिवासियों की बात तो करते रहे हैं, लेकिन उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम नहीं किया। पहली बार मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का बजट बढ़ाकर 81 हजार करोड़ कर दिया। इसका लाभ झारखंड के आदिवासी व दलितों को भी मिल रहा है।

दो टूक ▸ उप्र के मुख्यमंत्री ने झारखंड में चुनावी सभा को किया संबोधित

देश में एक प्रधान, एक निशान व एक ही विधान रहेगा : योगी

कहा, डबल इंजन की सरकार से झारखंड में तेजी से हो रहा विकास

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर

झारखंड के जमशेदपुर में गुरुवार को चुनावी सभा को संबोधित करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जागरण

भाजपा के स्टार प्रचारक व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में एक प्रधान, एक निशान और एक ही विधान रहेगा। भाजपा ने गरीबों का कल्याण किया है। 2024 तक घर-घर पानी का कनेक्शन पहुंच जाएगा। नक्सलवाद का सफाया किया जाएगा और हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा। योगी आदित्यनाथ गुरुवार को झारखंड के जमशेदपुर के बागबेड़ा में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे।

योगी ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। कहा, आतंकवाद को पैदा करने वाले कश्मीर के अनुच्छेद 370 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके में समाप्त कर दिया। अयोध्या के राम मंदिर मसले को विपक्षियों ने वर्षों से उलझा रखा था। मोदी सरकार ने मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आयुष्मान योजना, शौचालय, विद्युत कनेक्शन, घर-घर में गैस कनेक्शन वर्ष 2014 से पहले नहीं हुआ था, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश की जनता को मिला। डबल इंजन की सरकार होने के कारण झारखंड में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं।

विपक्ष को विकास से मतलब नहीं, बस सत्ता चाहिए : उप्र के सीएम ने कहा कि राजद, कांग्रेस, झामुमो ने झारखंड में समस्याओं को जन्म दिया है, लेकिन भाजपा ने उन समस्याओं का समाधान किया है और पूरे देश में शांति का माहौल कायम किया है। विपक्षियों को झारखंड के विकास से मतलब नहीं है, इनको बस सत्ता चाहिए। जो लोग देश के अंदर शांति व सौहार्द्र में विश्वास नहीं करते, वे लोग सदा मामले को लटकाते और भटकाते हैं। उन्होंने कहा कि एयर कनेक्टिविटी हाईवे व रेलवे को बेहतर किया जा रहा है। लोगों की आवश्यकता के अनुसार मेडिकल कॉलेज व अस्पताल, तकनीकी संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। इससे पूर्व योगी आदित्यनाथ के पहुंचते ही जय श्री राम के नारों से पूरा मैदान गूंजने लगा। योगी ने करीब 20 मिनट तक जनता को संबोधित किया।

मोदी हैं तो मुमकिन है

गोविंदपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा जो कहती है, वह करती है। जो 70 साल में नहीं हुआ उसे भाजपा ने कर दिखाया। इसीलिए कहा जाता है मोदी हैं तो मुमकिन है। योगी ने कहा कि झारखंड का विकास सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि झारखंड विकास की प्रगति पर मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में आगे बढ़ चुका है और अगर झारखंड का विकास करना है तो फिर से डबल इंजन की सरकार बनानी होगी।

नड्डा का कांग्रेस पर प्रहार, आधे जेल में हैं और आधे बेल पर बाहर

झारखंड के गिरिडीह में गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी रैली को संबोधित किया। जागरण

जागरण संवाददाता, गिरिडीह

महासमर झारखंड विधानसभा चुनाव 2019

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और झामुमो पर जमकर निशाना साधा। नड्डा गुरुवार को झारखंड के गिरिडीह में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। कहा कि जिन्होंने आपका हक छीना, आपकी तिजोरी लूटी वे लुभावने नारे दे रहे हैं। वे क्या करेंगे उस पर वोट न दें, भाजपा ने क्या किया है उस पर वोट दें। कांग्रेस पर हमला बोल कहा कि बड़े-बड़े नारे देने वाले आधे जेल में हैं और आधे बेल पर। पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने न धरती छोड़ी न पाताल, न ही आसमान छोड़ा। सब जगह घोटाला किया। समाज को बांटने वाली कांग्रेस और झामुमो अब लाचारी में विकास की बात कर रहे हैं। उन्हें पता चल गया कि मोदी के जमाने में विकास के सिवा कुछ नहीं चलेगा।

उन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, तीन तलाक बिल, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को मोदी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। साथ ही राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने की स्थिति को भी भाजपा सरकार की पहल की देन बताया। नड्डा ने मजबूत विदेश नीति व अर्थनीति को मोदी सरकार की कोशिशों का नतीजा करार दिया।

दंभ न भरे भाजपा, 25 पर सिमटेगी : आरपीएन सिंह

जागरण संवाददाता, हजारीबाग : घमंड से चूर सरकार यह भूल गई कि जनता के वोट से सब कुछ तय होता है। जनता की निराशा के बाद भी भाजपा झारखंड में 65 पार का खोखला नारा दे रही है। हकीकत यह है कि वह 25 भी पार नहीं करेगी। यह बातें झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी व पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री आरपीएन सिंह ने कही। वह गुरुवार को हजारीबाग में प्रेस से बात कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार महागठबंधन की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई है। महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और राज्य में सरकार बनाएगा। आरपीएन ने कहा कि सत्तालोलुप भाजपा जीत में सहयोग लेने के लिए अपने पुराने मित्र आजसू व झाविमो को अलग-अलग चुनाव लड़वा रही है, ताकि रघुवर सरकार से नाराज चल रहे लोगों का जो वोट आजसू और झाविमो के खाते में जाए उसका फायदा भी भाजपा को ही मिले। जनता उनके इरादों को समझ रही है। उन्होंने आगे कहा, सरकार पारा शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविकाओ, सहियाओं पर लाठी बरसा रही है, व्यापारी बेहाल हैं। लोग भूख से मर रहे हैं। वहीं, युवा पलायन को और किसान आत्महत्या को मजबूर हैं। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। राज्य में चार हजार स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इन सबके बावजूद भाजपा आत्ममुग्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जहां भी चुनावी सभा में जाते हैं, मूलभूत विषयों से इतर लोगों का ध्यान भटकाने का काम करते हैं।

जदयू ने जारी किया घोषणा पत्र, बिहार की तरह झारखंड में भी शराबबंदी का किया वादा

राज्य ब्यूरो, रांची

▸ नौकरी में आदिवासियों-मूलवासियों को प्राथमिकता देने की बात कही

जनता दल यूनाइटेड (जदयू) झारखंड में भी नीतीश कुमार के मॉडल को आगे बढ़ाएगी। जदयू ने चुनाव को लेकर अपने वादों और संकल्पों का पिटारा गुरुवार को खोल दिया। राजग में शामिल होते हुए भी झारखंड में भाजपा से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ रही जदयू ने पहले चरण की 13 सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद तथा दूसरे चरण की 20 सीटों पर चुनाव प्रचार लगभग खत्म होने के समय अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें जदयू की सरकार बनने पर बिहार की तरह झारखंड में भी शराबबंदी लागू करने तथा देशी शराब और हड़िया बेचने वालों को आर्थिक सहायता देकर दूसरे रोजगार से जोड़ने का वादा किया गया है।

बिहार के सूचना और जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार, प्रदेश सह झारखंड प्रभारी अरुण कुमार और प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने घोषणा पत्र जारी किया। कहा कि झारखंड की दशा-दिशा में बदलाव की जरूरत है। इसलिए पार्टी के घोषणा पत्र में बदलाव के दस सूत्रों पर फोकस किया गया है। नीरज कुमार ने बिहार में हुए विकास कार्यों की तुलना झारखंड की स्थिति से करते हुए कहा कि 'नीतीश मॉडल' ही झारखंड को विकास मार्ग प्रशस्त कर सकता है। पार्टी ने बदलाव के दस सूत्रों में शराबबंदी के अलावा घर-घर निर्बाध बिजली, हर गांव-घर को नल का जल, सबको पढ़ने का अवसर, युवाओं को बल सहित पर्यावरण संरक्षण के लिए बिहार की तरह जल-जंगल-हरियाली अभियान झारखंड में भी शुरू करने के वादे किए हैं। जहां सभी दलों ने पिछड़ों के आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर जोर दिया है, वहीं जदयू ने नौकरी में आदिवासियों और मूलवासियों को प्राथमिकता का भरोसा दिलाया है। साथ ही महिलाओं को नौकरी व पंचायत चुनाव में विशेष आरक्षण का वादा किया है। इसने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को भी निर्धारित आरक्षण देने की भी घोषणा की है।

'दैनिक जागरण' द्वारा उठाए गए मुद्दे भी शामिल

जदयू ने अपने घोषणा पत्र में ऐसे मुद्दों को भी शामिल किया है जिन्हें दैनिक जागरण ने 'इस बार वोट झारखंड के लिए' अभियान के तहत प्रमुख रूप से उठाया था। इनमें हर पंचायत में एक हाई स्कूल व प्रखंड में कॉलेज की स्थापना, सामूहिक अखड़ा व धुमकुड़िया भवन के निर्माण, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्रभावी बनाना, भाषा अकादमी की स्थापना आदि शामिल हैं।

रघुवंश-जगदानंद की अदावत लालू के लिए चुनौती

अरविंद शर्मा, पटना

▸ अनुशासन के मुद्दे पर सामने आया दोनों वरिष्ठ नेताओं का मतभेद

राजद और लालू परिवार के सामने नई परेशानी आ खड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे ने तेजप्रताप और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच वर्चस्व की लड़ाई पर पानी तो डाल दिया, किंतु अब पुराने और बुजुर्ग नेताओं में ठन गई है। संगठन के कामकाज में अनुशासन के मसले पर दो पुराने नेताओं में अनबन शुरू हो गई है। राजद के नए बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के तौर-तरीके पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह को रास नहीं आ रहे। बिना लाग-लपेट के रघुवंश ने कह दिया कि पार्टी ऐसे नहीं चलती है। कार्यकर्ताओं से कर्मचारियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता।

मौका भांपकर बिना भूमिका और संकोच के अपनी बात साफ-साफ रख देने के लिए मशहूर रघुवंश प्रसाद सिंह ने ऐसा क्यों बोला? महज दो दिन पहले राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नामांकन के दौरान जिस रघुवंश ने पार्टी में अनुशासन को अनिवार्य बताया था, अब उन्हें ही नागवार क्यों लगने लगा? दरअसल, रघुवंश को जगदानंद की कार्यशैली से कम, पार्टी में अपनी कम होती पूछ से ज्यादा परेशानी है। जगदानंद के हाथ में प्रदेश राजद की कमान आ जाने से रघुवंश असहज हो गए हैं। उधर राजद में आए अचानक अनुशासन से प्रभावित कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को रघुवंश में रहनुमाई नजर आने लगी है। लोग उन तक नए नेतृत्व की शिकायतें लेकर जाने लगे हैं। दुखड़ा सुनाकर राहत की उम्मीद भी करने लगे तो रघुवंश को इसमें मौका नजर आया और बोल दिया हमला। बकौल रघुवंश, उनके पास लोग फरियाद लेकर आ रहे हैं तो वह चुप कैसे रह सकते हैं।

नई नहीं है अदावत : रघुवंश और जगदानंद की सियासी अदावत नई नहीं है। दोनों पहले भी टकराते रहे हैं। हालांकि खुलकर कभी सामने नहीं आए। अंदरूनी अदावत से लालू भी वाकिफ हैं। फिर भी उनकी ओर से दोनों को एक करने की कभी कोशिश नहीं की गई। यह लालू की राजनीति की स्टाइल हो सकती है, किंतु ताजा विवाद से राजद के नुकसान की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लालू जेल में हैं और अभी पार्टी में एकता की अत्यंत जरूरत है।

दोनों में समानताएं भी काफी

रघुवंश और जगदानंद में विरोध के बावजूद कुछ समानताएं भी हैं। दोनों की बिरादरी एक है। दोनों का समाजवाद से गहरे ताल्लुकात हैं। दोनों खुद को लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के शिष्य बताते हैं। यह अलग बात है कि जबसे बिहार की सियासत में लालू प्रसाद का अभ्युदय हुआ है, तभी से दोनों राजद के रंग-ढंग में ही ढले नजर आते हैं। कोई किसी से कम नहीं। लालू परिवार के प्रति वफादारी साबित करने में दोनों एक-दूसरे से खुद को आगे दिखाते हैं। लालू ने भी दोनों की बराबर की। एक को केंद्र में मंत्री बनाया तो दूसरे को बिहार में अपनी सरकार में लगातार 15 साल मंत्री रखा।

कर्नाटक उप चुनाव में ग्रामीण मतदाताओं ने की सबसे ज्यादा वोटिंग

बेंगलुरु, आइएएनएस : कर्नाटक विधानसभा क 15 सीटों के लिए हुए उप चुनाव में गुरुवार शाम छह बजे तक लगभग 62.18 फीसद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन सीटों का परिणाम राज्य का राजनीतिक भविष्य तय करने वाला साबित होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं ने पूरे उत्साह से भाग लिया। आठ ग्रामीण क्षेत्रों में 75 फीसद से ज्यादा और बेंगलुरु के चार क्षेत्रों में 50 फीसद से कम मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान ग्रामीण क्षेत्र चिक्कबल्लापुर में हुआ, जहां 86.40 फीसद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बेंगलुरु के पूर्वी उपनगर केआर पुरा में सबसे कम 37.50 फीसद मतदान हुआ।

उत्तर कन्नड़ जिले के येल्लापुर में 77.52 फीसद मतदान होने की जानकारी मिली है। बेंगलुरु ग्रामीण जिले के होसकोट में 76.19 फीसद मतदान होने की जानकारी दी गई है। इसी सीट से भाजपा प्रत्याशी एमटीबी नागराज ने 1,223 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है। बेलगावी जिले में अथानी क्षेत्र में 75.23 फीसद मतदान होने की सूचना है।

उद्धव सरकार ने आरएसएस से जुड़े संस्थान की स्टांप शुल्क छूट रद की

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र में सात दिनों पहले राकांपा व कांग्रेस के सहयोग से बनी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के उस निर्णय को रद कर दिया है, जिसमें आरएसएस से जुड़े एक शोध संस्थान को स्टांप शुल्क में छूट प्रदान की गई थी। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में शिवसेना अहम साझीदार थी।

एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया, 'स्टांप शुल्क में मिली छूट को रद करने का निर्णय शिवसेना की नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने बुधवार को लिया।' उन्होंने बताया कि नागपुर के पुनरुत्थान शोध संस्थान ने करोल तहसील में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की शाखा भारतीय शिक्षण मंडल ने की थी। नौ सितंबर को देवेंद्र फड़नवीस की नेतृत्ववाली राज्य की तत्कालीन सरकार ने संस्थान को जमीन सौदे के लिए स्टांप और पंजीकरण शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की थी। अधिकारी ने कहा, '105 हेक्टेयर जमीन की खरीद के लिए 1.5 करोड़ रुपये के स्टांप शुल्क पर दी गई छूट को अब रद कर दिया गया है। संस्थान को अब स्टांप शुल्क का भुगतान करना होगा।' सूत्रों ने बताया था कि बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम दिनों में लिए गए 34 फैसलों पर चर्चा की गई थी। राज्य के मंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा था कि महाविकास अघाड़ी सरकार पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की समीक्षा करेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि ठाकरे सरकार पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी।

भाजपा नेताओं की सात चीनी मिलों की कर्ज गारंटी भी रद : उद्धव ठाकरे सरकार ने बुधवार को एक अन्य फैसले के तहत भाजपा नेताओं की सात चीनी मिलों को दी गई कर्ज गारंटी भी रद कर दी। महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे समेत अन्य नेताओं की सहकारी चीनी मीलों ने 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज ले रखा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) सहकारी समितियों को कर्ज उपलब्ध कराता है। राज्य सरकार कुछ नियम एवं शर्तों के तहत समितियों के कर्ज पर गारंटी देती है। एक अधिकारी ने बताया, 'इन सात सहकारी चीनी मिलों ने गारंटी की शर्तों को पूरा नहीं किया। ऐसे में राज्य मंत्रिमंडल ने गारंटी रद करने का फैसला किया है।' उन्होंने बताया कि भाजपा की सहयोगी जनसुराज्य शक्ति पार्टी के नेता विनय कोरे की सहकारी मिल को भी गारंटी दी गई थी।

उद्धव के फैसले से नाराज 400 शिवसैनिकों ने थामा भाजपा का दामन

मुंबई, एएनआइ : शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के राकांपा व कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाने संबंधी फैसले से नाराज 400 शिवसैनिकों ने धारावी में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा का दामन थाम लिया।

भाजपा में शामिल होने वाले शिवसैनिकों का नेतृत्व करने वाले रमेश नाडर ने कहा, 'हम शिवसेना के लिए 10 वर्षों से काम कर रहे थे। हम पार्टी की हिंदुत्व वाली विचारधारा का समर्थन करते थे। मुझे लोगों की सेवा का दायित्व दिया गया था, लेकिन शिवसेना ने राकांपा व कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। यह हमें मंजूर नहीं है, इसलिए हमने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है।'

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में भाजपा व शिवसेना ने गठबंधन के तहत हालिया विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव बाद दोनों दलों के बीच सरकार बनाने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद शिवसेना ने राकांपा व कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार का गठन कर लिया।

बंगाल विधानसभा के गेट पर खड़े रहे राज्यपाल

जागरण संवाददाता, कोलकाता

▸ बंगाल में ममता बनर्जी के साथ जगदीप धनखड़ का टकराव जारी

▸ विधानसभा पहुंचने पर नहीं खुला वीआइपी गेट, नहीं किया गया स्वागत

▸ राज्यपाल ने साधारण गेट से पैदल चल कर विधानसभा के अंदर प्रवेश किया

▸ इस प्रशासनिक गड़बड़ी के लिए ममता को जिम्मेदार ठहराया

बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ का टकराव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत राज्यपाल गुरुवार को विधानसभा गए, लेकिन उनके लिए विधानसभा का वीआइपी गेट नहीं खुला। विधानसभा का मुख्य गेट बंद देख राज्यपाल ने साधारण गेट से पैदल चल कर विधानसभा के अंदर प्रवेश किया। सरकार और सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के इस तरह के रवैए से राज्यपाल को एक बार फिर अपमानित होना पड़ा। उन्होंने अपना क्षोभ भी संवाददाताओं के समक्ष व्यक्त किया। राज्य में इस तरह प्रशासनिक गड़बड़ी के लिए उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। राज्यपाल ने कहा कि राजभवन की ओर से विधानसभा सचिवालय को उनके आने की सूचना दी गई थी। विधानसभा स्पीकर के सचिव ने राज्यपाल के विधानसभा पहुंचने पर खुशी भी जाहिर की थी। स्पीकर के हवाले से राजभवन को बताया गया कि राज्यपाल के सम्मान में विधानसभा में दोपहर के भोज का आयोजन है। उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि राजभवन को फिर दोबारा बताया गया कि स्पीकर विधानसभा में उपस्थित नहीं रहेंगे। उनके सचिव व अन्य कर्मचारी भी नहीं रहेंगे। राज्यपाल के सम्मान में विधानसभा में आयोजित भोज भी रद कर दिया गया।

मैं नहीं, लोकतंत्र अपमानित हुआ : राज्यपाल ने विधानसभा गेट पर ही संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि एक बार फिर उन्हें अपमानित होना पड़ा। लेकिन वह समझते हैं कि यह उनका अपमान नहीं है। लोकतंत्र का अपमान है। सरकार के इस तरह के काम काज से लोकतंत्र शर्मसार हुआ है।

पहली बार विस में पैदल गए राज्यपाल : उन्होंने कहा, बंगाल में पहली बार किसी राज्यपाल को विधानसभा के अंदर पैदल जाना पड़ा। मुख्यमंत्री अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में विफल हैं। कहा कि विधानसभा का सत्र नहीं चलने का मतलब यह नहीं है कि विधानसभा भी बंद रहेगी। सत्र नहीं चलने के बावजूद विधानसभा का सचिवालय काम करता है। राज्यपाल ने कहा कि वह विधानसभा की लाइब्रेरी का जायजा लेना चाहते थे, लेकिन सत्र नहीं चलने कारण लाइब्रेरी भी बंद थी। स्पीकर ने खुद विधानसभा में उनका स्वागत करने की बात कही थी। लेकिन वह उपस्थित नहीं रहे। लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता है। इससे पहले बुधवार को जब राज्यपाल कलकत्ता विश्वविद्यालय गए तो वहां भी न तो कुलपति थे और ना ही रजिस्ट्रार ही मौजूद थे। राज्यपाल को वीसी के दफ्तर के सामने कुछ देर खड़ा होना पड़ा।

यह है मामला

कुछ विधेयकों पर राज्यपाल के दस्तखत नहीं करने के कारण ममता सरकार के साथ राजभवन की खींचतान चल रही है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि राज्यपाल एक पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करते हुए विधेयकों पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं तो वहीं राजभवन की ओर से कहा गया है कि राज्यपाल रबर स्टांप नहीं हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल पर साधा निशाना

कोलकाता में गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में ममता ने राज्यपाल पर इशारों में हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में समानांतर सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने विधेयकों की मंजूरी में कथित देरी का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में समानांतर प्रशासन चलाया जा रहा है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई क्योंकि विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं किए गया था।

विधानसभा अध्यक्ष ने पहले ही बताया था वह उपस्थित नहीं रहेंगे। इसके बावजूद राज्यपाल विधानसभा गए। राज्यपाल को लोकतंत्र की चिंता होती तो वह विधेयक पर हस्ताक्षर करते। जरूरत पड़ने पर संबंधित मंत्री को बुलाकर पूछते। उन्हें राज्य के लोगों की इतनी चिंता है तो केंद्र पर बंगाल का बकाया फंड लाकर देना चाहिए।

–पार्थ चटर्जी, शिक्षा मंत्री, बंगाल

रणनीति

दिल्ली रैली के लिए उप्र से ताकत जुटाएंगी प्रियंका

14 दिसंबर को दिल्ली में होनी है भारत बचाओ रैली, तैयारियों का जायजा लेंगी कांग्रेस महासचिव, दो दिन में 13 घंटे करेंगी बैठकें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

सियासी रूप से कांग्रेस के लिए लगभग बंजर हो चुके उत्तर प्रदेश में पार्टी के सपनों की झंडाबरदार प्रियंका गांधी वाड्रा को न सिर्फ प्रतिद्वंद्वी दलों से जूझना है, बल्कि संगठन को भी खड़ा करने की चुनौती है। घर में बैठे कार्यकर्ताओं को निकालकर सड़कों पर उतारने के लिए फिलहाल 14 दिसंबर को दिल्ली में होने जा रही भारत बचाओ रैली बड़ा मौका है। इसकी तैयारियों की समीक्षा के साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए वह शुक्रवार को लखनऊ आ रही हैं। वह यहां दो दिन में 13 घंटे मैराथन बैठकें करेंगी।

कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा शुक्रवार को 11 बजे प्रदेश मुख्यालय पहुंच जाएंगी। इसके बाद 11.15 से दोपहर दो और फिर शाम चार से आठ बजे तक पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। शनिवार को भी सुबह 11 से दो और फिर शाम चार से सात बजे तक बैठकें होंगी। मुख्य मुद्दा है 14 दिसंबर को नई दिल्ली में होने जा रही भारत बचाओ रैली। हर जिले से अधिक से अधिक भीड़ कैसे जुटाई जाए, इस पर वह पदाधिकारियों के साथ बात करेंगी।

चूंकि शीर्ष नेतृत्व में शामिल किसी भी नेता की तुलना में सबसे बड़े राज्य की कमान बतौर प्रभारी प्रियंका के पास है, इसलिए दिल्ली की रैली में यूपी का दम भी उन्हें दिखाना है। प्रदेश के हर मुद्दे पर वह सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट कर रही हैं। सरकार को घेरने का प्रयास लगातार चल रहा है। अब दो दिन यहीं रुक कर सतत बैठकों का इशारा यही है कि अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए प्रियंका लखनऊ में सक्रियता बढ़ाने जा रही हैं।

2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए वह शुक्रवार को लखनऊ आ रही हैं कांग्रेस महासचिव

प्रियंका गांधी वाड्रा फाइल

शीला कौल के घर में हो सकता है प्रवास

प्रियंका के प्रस्तावित कार्यक्रम में उनके रात्रि प्रवास के स्थान का उल्लेख नहीं है। मगर, चर्चा है कि वह अपनी रिश्तेदार पूर्व मंत्री शीला कौल के गोखले मार्ग स्थित घर में ठहर सकती हैं। स्थानीय पुलिस ने भी देर शाम यहां सुरक्षा के लिहाज से जायजा लिया। वहीं बैठकों के बीच में ही प्रियंका मैनपुरी की मृत छात्रा के परिवार को मुख्यालय में बुलवाकर मुलाकात कर सकती हैं। कयास इसलिए है, क्योंकि उन्हीं के पत्र के बाद इस प्रकरण में कार्रवाई शुरू हुई।

मुकुल को सभा में जाने से पुलिस ने रोका

जागरण संवाददाता, कोलकाता : पूर्व घोषित आंदोलन के तहत विरोध सभा करने जा रहे मुकुल राय सहित अन्य भाजपा नेताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मुकुल राय ने अपने पार्टी नेताओं के साथ रास्ते में ही बैठकर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया। भाजपा प्रतिनिधिमंडल कोलकाता में गार्डेनरिच थानांतर्गत मटियाब्रुज स्थित केशोराम कॉटन मिल गेट पर आयोजित होने वाली सभा के लिए जा रहा था। आरोप है कि पुलिस ने इन भाजपा नेताओं को भू-कैलाश के समीप रोक दिया। ऐसी स्थिति में भाजपा नेता बीच रास्ते में ही विरोध-प्रदर्शन पर बैठ गए। उसी बीच स्थानीय तृणमूल कांग्रेस समर्थक वहां पार्टी का झंडे लिए पहुंच गए। ऐसी स्थिति में कुछ देर बाद ही भाजपा नेता वहां से लौट गए। इस बारे में भाजपा नेता मुकुल राय का आरोप है कि पुलिस और तृणमूल के गुंडों ने यह सब किया। तृणमूल आश्रित गुंडों ने उनपर ईंट-पत्थर से हमला किया। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा, यदि केंद्रीय बल के जवान उनके साथ नहीं होते उनका जिंदा लौटना मुश्किल था।

3169 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है पिछले चार सालों में। इसके साथ ही नक्सलियों की हिंसा की घटनाओं में भी 43 प्रतिशत की कमी आई है। यह जानकारी गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने दी।

...तो इसलिए रेपो रेट में आरबीआइ ने नहीं किया बदलाव

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक चिंता की बात विकास की रफ्तार का सुस्त पड़ना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी विकास दर का अनुमान 6.1 फीसद से घटाकर 5 फीसद कर दिया है। मौद्रिक नीति समिति का रेपो रेट में बदलाव नहीं करना अर्थ विशेषज्ञों के गले नहीं उतर रहा है। खुदरा क्षेत्र में छाई मंदी से निपटने और कीमतों को बनाए रखने के साथ अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आरबीआइ के तरकश में क्या है? पेश है एक नजर

क्यों नहीं बदली रेपो रेट

आरबीआइ की प्राथमिक कोशिश में महंगाई को रोकना है। दूसरी वजह आरबीआइ अभी तक रेपो रेट में 135 आधार अंकों की कमी कर चुका है। हालांकि उपभोक्ता के पास तक 44 आधार अंकों का ही लाभ मिल सका है। आरबीआइ गवर्नर **शशिकांत दास** का कहना है कि मार्केट में फिलहाल अतिरिक्त नकदी है। इसके अतिरिक्त आरबीआइ को उम्मीद है कि आने वाला केंद्रीय बजट विकास को रफ्तार देने के लिए वित्तीय प्रयास करेगा।

बदलाव पर लगा ब्रेक

लगातार पांच बार बदलाव के बाद आरबीआइ ने रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया है। आरबीआइ की मौद्रिक नीति समिति के सभी छह सदस्य सर्वसम्मति से रेपो रेट में कमी लाने के खिलाफ रहे। फिलहाल रेपो रेट 5.15 फीसद और रिवर्स रेपो रेट 4.90 है।

फैसले का प्रभाव

रेपो रेट में बदलाव नहीं होना सावधि जमा में निवेश करने वालों के लिए राहत की खबर है। इससे पहले रेपो रेट में बदलाव के कारण जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज में लगातार कमी देखी जा रही थी। वहीं नए ऋण लेने वाले लोगों को इससे निराशा हुई है। रेपो रेट घटती तो ऋण दरों में कमी हो सकती थी और घर, कार जैसी चीजें खरीदने का सपना साकार हो सकता था।

भविष्य की राह

भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी से गुजर रही है और उपभोक्ता मांग घट रही है। जब तक उपभोक्ता मांग नहीं बढ़ती तब तक अर्थव्यवस्था का इस भंवर से निकलना मुश्किल होगा। महंगाई चिंता की बात तो है लेकिन यह स्थायी नहीं है। आरबीआइ को रेपो रेट में जितनी कमी करनी थी वो कर चुकी है। अब वह उसके प्रभावों की प्रतीक्षा में है।

सकारात्मक पहलू

- मार्च 2019 के बाद विदेशी मुद्रा भंडार 38.8 अरब डॉलर बढ़कर अब 451.7 अरब डॉलर पहुंचा
- रबी की बुवाई पिछले साल के मुकाबले महज 0.5 फीसद कम
- पिछले साल के 61 फीसद के मुकाबले देश के प्रमुख जलाशय अब तक 86 फीसद लबालब
- शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में बढ़ोतरी

नकारात्मक पहलू

- जीडीपी विकास दर गिरकर 4.5 फीसद
- अक्टूबर में सेवा क्षेत्र में गिरावट
- निर्यात में गिरावट जारी
- जीएसटी संग्रह लक्ष्य से दूर

न्यूज गैलरी

रॉबर्ट वाड्रा मामले में सुनवाई 23 दिसंबर को

नई दिल्ली : विदेश में संदिग्ध संपत्ति के मामले में फंसे उद्यमी रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत को रद करने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई 23 दिसंबर तक के लिए टाल दी। ईडी ने वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत बताते हुए निचली अदालत से दी गई अग्रिम जमानत का विरोध किया है। ईडी ने वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा को दी गई अग्रिम जमानत को भी चुनौती दी है। लंदन में एक फ्लैट को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया था। ईडी का आरोप है कि यह फ्लैट मनोज अरोड़ा के बजाय वाड्रा का है और यह हथियार डीलर संजय भंडारी से 2010 में खरीदा गया था। (जासं)

रतुल पुरी की जमानत याचिका का ईडी ने किया विरोध

नई दिल्ली : बैंक लोन घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित कारोबारी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की जमानत याचिका का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विरोध किया है। जांच एजेंसी ने विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार को बताया कि मामले की जांच अभी शुरुआती दौर में है और अगर आरोपित को राहत दी गई तो वह सुबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। आरोपित के भागने की भी संभावना है। मामले पर अदालत में शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। (जासं)

कान्हा नेशनल पार्क में बाघ का कंकाल मिला

मंडला : मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क के बफर इलाके में एक बाघ का कंकाल मिला है, जो करीब एक सप्ताह पुराना है और सड़-गल चुका था। वन्यप्राणी चिकित्सक ने बाघ को करंट से मारे जाने का संदेह जताया है। आशंका है कि ऐसा शिकार के उद्देश्य से किया गया। (नईदुनिया)

मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडर पुनर्वास बोर्ड बनेगा

भोपाल : मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अनुपूरक बजट में कुछ नई घोषणाएं कर सकती है। इंदिरा गांधी समाजसेवा सम्मान की राशि एक लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जाएगी। किन्नरों के कल्याण के लिए ट्रांसजेंडर पुनर्वास बोर्ड भी बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के मुताबिक ट्रांसजेंडर समाज के पुनर्वास और कल्याण कार्यों के लिए बोर्ड गठित किया जाएगा। वही, इंदौर के समीप महू स्थित डॉ. आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय में ट्रांसजेंडर पर शोध किया जाएगा। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएसएसआर) ने इस दो वर्षीय शोध का चयन पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप के लिए किया है। (राब्यू)

जनमत
मुद्दा

क्या पोर्नोग्राफी की सहज-सर्व सुलभता बाधित होनी चाहिए, इसके लिए सख्त नियम कानून बनने चाहिए।

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हैं। **MUDDA** लिखें, स्पेस देकर **YES** या **NO** लिखकर 57272 पर भेजें।

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को जलाने की घटना पर राज्यसभा में हंगामा

बड़ा मामला ▶ कांग्रेस, सपा सहित विपक्षी दलों ने की चर्चा की मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता को जिंदा जलाने का मामला गुरुवार को राज्यसभा में उठा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दलों ने शून्यकाल में मामला उठाते हुए सभापति से चर्चा की मांग की, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मांग खारिज कर दी कि कार्यसूची में पहले से काफी मामले सूचीबद्ध हैं, ऐसे में अभी इस पर चर्चा नहीं हो सकती। इसके बाद सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। शोरगुल बढ़ते देख सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

राज्यसभा में जब यह हंगामा चल रहा था तभी तृणमूल कांग्रेस ने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत इस मामले को उठाने की मांग की। इसका समर्थन विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने भी किया। उन्होंने कहा कि तय हुआ था कि हफ्ते में कम से कम दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए समय दिया जाएगा, लेकिन वह भी नहीं हो रहा है। हालांकि शोर-शराबे के बीच सभापति ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इस मसले पर राज्यसभा में जिन सदस्यों ने चर्चा की मांग की उनमें कांग्रेस के आनंद शर्मा, सपा के प्रोफेसर रामगोपाल यादव, राकांपा की वंदना चौहान और तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ-ब्रायन शामिल थे। हालांकि जब सदन में बात रखने का मौका नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन से बाहर निकलकर पत्रकारों से चर्चा की। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। महिलाओं के साथ आए दिए दुष्कर्म की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। उन्होंने चित्रकूट की भी घटना का जिक्र किया। साथ ही कहा कि प्रदेश में जहां एक दुष्कर्म पीड़िता को जलाने की कोशिश की गई, वहीं दूसरी दुष्कर्म पीड़िता को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया है। सपा सांसद जया बच्चन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नियम-कानून का हर तरफ उल्लंघन किया जा रहा है।

गुरुवार को राज्यसभा में बोलते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा। एएनआइ

उत्तर प्रदेश में विपक्ष सरकार पर हमलावर, मांगा इस्तीफा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उप्र के उन्नाव जिले में दुष्कर्म पीड़िता को जलाने की घटना को लेकर विपक्ष ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और त्यागपत्र देने की मांग की। सपा, कांग्रेस और रालोद सभी ने कहा कि प्रदेश में अपराधी बेलगाम हो गए हैं।

सामूहिक इस्तीफा दे सरकार : अखिलेश : समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को ट्वीट किया, 'उन्नाव की दुष्कर्म पीड़िता को जिंदा जलाए जाने के दुस्साहस की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार का सामूहिक इस्तीफा होना चाहिए। माननीय न्यायालय से गुहार है कि इस घटना की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता के समुचित उपचार व सुरक्षा की तत्काल व्यवस्था का निर्देश दे।'

जिम्मेदारी सरकार की : प्रियंका

कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया, 'उन्नाव पीड़िता के स्वास्थ्य समाचार से मन आहत है। ईश्वर से प्रार्थना है, पीड़िता जल्द स्वस्थ हो। कल भाजपा सरकार का बयान था, यूपी में सब ठीक है। आज एक बयान और आया। लेकिन कानून व्यवस्था के बारे में झूठी बयानबाजी व झूठा प्रचार करने की जिम्मेदारी सीएम और उप्र सरकार की ही है।' इससे पूर्व सुबह एक अन्य ट्वीट में प्रियंका ने लिखा, 'कल देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ-साफ झूठ बोला कि यूपी की कानून व्यवस्था अच्छी हो चुकी है। हर रोज ऐसी घटनाओं को देख कर मन में रोष होता है। भाजपा नेताओं को भी अब फर्जी प्रचार से बाहर निकलना चाहिए।'

सीएम योगी ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उन्नाव में गुरुवार को दुष्कर्म पीड़िता युवती को जलाए जाने की जघन्य घटना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लेते हुए आरोपितों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने बुरी तरह जल चुकी पीड़िता को सरकारी खर्च पर हर संभव चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने का निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री ने उन्नाव के डीएम व एसपी को आरोपितों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त लखनऊ व आइजी लखनऊ रेंज को तत्काल उन्नाव जाकर पूरे प्रकरण की जांच कर आख्या मांगी। दूसरी ओर डीजीपी ओपी सिंह ने दुष्कर्म पीड़िताओं की सुरक्षा-व्यवस्था की समीक्षा नए सिरे से किए जाने का निर्देश दिया है।

घटनाक्रम

4:30 बजे	पीड़िता घर से निकली
05	अधजली हालत में गैस एजेंसी की गोदाम तक पहुंची
05:05	डायल-112 को सूचना
05:25	डायल-112 पहुंची
06	पीड़िता प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर
07	पीड़िता जिला अस्पताल पहुंची
08:30	प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर
10.30	पीड़िता को सिविल अस्पताल, लखनऊ की इमरजेंसी लाया गया
5.54	शाम को एएलएस एंबुलेंस से पीड़िता एयरपोर्ट रवाना
6.30	शाम को एयर एंबुलेंस ने किया टेकऑफ

देश के सभी थानों में खोली जाएंगी महिला हेल्प डेस्क

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : महिला सुरक्षा को लेकर देश भर में मचे कोहराम के बीच सरकार ने देश के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाने का फैसला किया है। इसके लिए राज्यों को निर्भया फंड से 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सरकार का मानना है कि महिला हेल्प डेस्क बनने के बाद थानों को महिलाओं के अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी। दिल्ली के निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए यह फंड बनाया गया था।

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को अपने सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाने को कहा गया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मंजूर कर दी गई है। उनके अनुसार, जिन थानों में पहले से महिला हेल्प डेस्क मौजूद है, उसे इस फंड की मदद से और मजबूत बनाया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि महिला हेल्प डेस्क महिलाओं के लिए पुलिस थानों में संपर्क प्रथम बनना चाहिए ताकि वे अपनी शिकायतें बेझिझक दर्ज करा सकें। जाहिर है इन महिला हेल्प डेस्क पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी।

वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि महिला हेल्प डेस्क में महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति के साथ ही वकीलों, मनोचिकित्सकों और एनजीओ की सूची भी होगी। ताकि महिला को किसी तरह की कानूनी व अन्य सहायता के लिए भटकना नहीं पड़े और उन्हें आसानी से वकील मिल सके। एनजीओ की मदद से पीड़ित महिला की दूसरी जरूरतों को पूरी करने में मदद मिलेगी।

बंगाल के मालदा में युवती से दुष्कर्म कर जिंदा जलाया

जागरण संवाददाता, मालदा

▶ युवती की पहचान नहीं हो पाई, पुलिस कर रही मामले की जांच

हैदराबाद की तरह बंगाल के मालदा में भी युवती से दुष्कर्म कर उसे जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। यह घटना गुरुवार सुबह की है। पुलिस को आशंका है कि दुष्कर्म के बाद युवती को जलाया गया है। घटनास्थल पर जिला पुलिस अधीक्षक अलोक राजोरिया, डीएसपी प्रशांत देवनाथ सहित जिला के दो पदाधिकारी पहुंचे कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। फिलहाल युवती की पहचान नहीं हो पायी है। अर्धनग्न हालत में उसकी जली हुई लाश मिली है।

जिला पुलिस अधीक्षक अलोक राजोरिया ने बताया कि शव के पास हमें नमूना मिला है, उसकी फोरेंसिक जांच की जाएगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डीएसपी प्रशांत देवनाथ ने बताया कि युवती के शव को देखकर उसकी उम्र 20 से 22 साल लगती है। वह 80 फीसदी जली अवस्था में मिली। उसके प्राइवेट पार्ट पर जख्म के निशान थे। शव के पास से एक जोड़ी जूता मिला है। यह जूता युवती का हो सकता है। साथ माचिस की तीली भी मिली है। उसका गला दबाकर मारा गया होगा, उसके गले पर निशान से ऐसा लगता है। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह खेत पर जाते समय हमने हमने युवती का शव देखकर सभी को सूचित किया। बाद में पुलिस को इसकी सूचना दी गई।

बक्सर व समस्तीपुर में पुलिस खाली हाथ

जागरण टीम, पटना : बिहार के बक्सर और समस्तीपुर में जिंदा जलाई गई दोनों युवतियों की शिनाख्त अब तक नहीं की जा सकी है। बक्सर मामले का राज्य महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। दोनों जिलों के मामले की अलग-अलग टीम बनाई गई है। पहचान के लिए शव की तस्वीर विभिन्न थाना क्षेत्रों में भेजी गई है।

पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित

मुंबई, एजेंसियां : पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के प्रमुख अभियुक्त हीरा कारोबारी नीरव मोदी को विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर गुरुवार को विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया। पिछले साल अगस्त में भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून बनाए जाने के बाद वह दूसरा कारोबारी है, जिसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। इससे पहले अदालत ने शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था।

विशेष पीएमएलए (मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम) अदालत के न्यायाधीश वीसी वर्डे ने नीरव और ईडी के वकीलों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।

लगभग 14,000 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल नीरव ने अदालत से इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की याचिका खारिज करने का अनुरोध किया था। उल्लेखनीय है कि नीरव और उसका मामा मेहुल चोकसी पीएनबी घोटाले के मुख्य अभियुक्त हैं। जनवरी 2018 में यह घोटाला सामने आने से पहले ही दोनों देश छोड़कर चले गए थे। नीरव मोदी को इस साल मार्च में लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया लंबित है। ईडी का कहना है कि नीरव और मेहुल ने पीएनबी अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी अंडरटेकिंग देकर बैंक को 14,000 करोड़ रुपये का चूना लगाया। कानून के मुताबिक, यदि 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक के घोटाले में शामिल अभियुक्त देश छोड़ चुका है और वारंट जारी होने के बाद भी नहीं लौटता है, तो उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा सकता है। इस मामले में अब नीरव की संपत्ति जब्त की जा सकती है। कोर्ट उसकी संपत्ति की जब्ती प्रक्रिया बाद में शुरू करेगा।

कार्रवाई

- ▶ विजय माल्या के बाद भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होने वाला दूसरा कारोबारी
- ▶ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

मासूम से दुष्कर्म के प्रयास पर आजीवन कारावास

नईदुनिया, अंबिकापुर : छत्तीसगढ़ में मासूम को घुमाने ले जाने का झांसा देकर दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को अपर सत्र न्यायाधीश ने मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि अंबिकापुर में 17 अक्टूबर 2018 की शाम मूलतः बिहार के औरंगाबाद जिले के रहने वाले रंजीत गिरी उर्फ मुखिया (48) ने घर के बाहर खेल रही मासूम के साथ घुमाने ले जाने का झांसा देकर दुष्कर्म का प्रयास किया। दूसरे दिन मासूम पीड़िता ने इस बारे में परिजनों को बताया। पुलिस ने आरोपित रंजीत गिरी उर्फ मुखिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने बताया कि प्रकरण के सारे तथ्यों की सुनवाई और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी, विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम सुनीता टोप्पो की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया। आरोपित को धारा 363 व 366क के सात-सात वर्ष का कारावास और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

आइटीआइ इंस्ट्रक्टर का पेपर कांग्रेस नेता की बिल्डिंग में लीक

कुलदीप शुक्ला, चंडीगढ़

यूटी पुलिस ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की आइटीआइ इंस्ट्रक्टर परीक्षा का पेपर लीक करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 स्थित कांग्रेस पार्षद देवेंदर बबला के प्लॉट नंबर 153 में चल रहे मैपल टेक कंम्प्यूटर लैब के मैनेजर नीतिश को गिरफ्तार कर लिया। वहा से भागे लैब संचालक राकेश उर्फ राका, उसके भाई मंजीत और असिस्टेंट (ड्राइवर) अमित सहित चारों के खिलाफ सेक्टर-31 थाना पुलिस ने धारा 420, 120बी, 511 के तहत केस दर्ज किया है। मौके पर मिले हरियाणा के अलग-अलग जिलों से महिला सहित 11 उम्मीदवारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

उम्मीदवारों ने बताया कि पेपर देने के लिए आरोपितों से किश्तों में 10 से 15 लाख का सौदा किया था। पुलिस मैनेजर नीतिश को शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल करेगी। बता दें कि 1 जून 2019 को प्लॉट मालिक बबला और सुनील राठी के बीच एग्रीमेंट हुआ है। इसमें यूटी कांस्टेबल अजय कुमार ने गारंटी ली है।

इस तरह हुआ भंडाफोड़ : एसएसपी निलांबरी जगदाले ने बताया कि वीरवार सुबह सेंट्रल डीएसपी कृष्ण कुमार को सूचना मिली कि 10.30 बजे होने वाली परीक्षा का पेपर पढ़ने कैंडिडेट्स आए हैं। इस पर सेक्टर-31 थाना प्रभारी राजदीप सिंह के साथ मिलकर फेज-2 स्थित मैपल टेक कंम्प्यूटर लैब में रेड कर मैनेजर नीतिश को गिरफ्तार कर लिया गया। सुबूत के तौर पर मैनेजर का मोबाइल, उसकी कैंडिडेट्स से बातचीत की रिकार्डिंग, वाट्सअप मैसेज, ऑडियो रिकार्डिंग जब्त की हैं। इसमें मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वेल्डिंग इंजीनियरिंग सहित अन्य पेपर भी शामिल थे।

सभी एक-दूसरे के रिश्तेदार : मैनेजर नीतिश ने बताया कि वे लोग परीक्षा के समय कैंडिडेट्स से संपर्क कर 10 से 15 लाख में पेपर पास करवाने का सौदा करते थे। बातचीत के बाद कैंडिडेट्स अपने रिश्तेदार कैंडिडेट्स को उनके साथ जोड़ लेते थे। इसके बाद कॉल, वाट्सअप और ऑडियो मैसेज से उन्हें परीक्षा के एक दिन पहले लैब में बुलाकर पेपर करवाते थे।

संजय सिंघल की जमानत याचिका खारिज, भेजे गए जेल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : धोखाधड़ी, बैंक लोन समेत कई अन्य मामलों के विभिन्न मनी लांड्रिंग में आरोपित भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड के पूर्व सीएमडी संजय सिंघल की जमानत याचिका को खारिज करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 19 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने जमानत याचिका तब खारिज की जब प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि पूर्व में भी संजय सिंघल सुबूतों से छेड़छाड़ कर चुके हैं और अगर जमानत दी गई तो वह दोबारा ऐसा कर सकते हैं। हालांकि, अदालत ने कहा कि वह जरूरत की दवाएं साथ ले जा सकते हैं और जरूरत हो तो राम मनोहर लोहिया या एम्स में स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जा सकता है। उधर, जमानत आवेदन में संजय सिंघल ने दावा किया था कि वह कई बीमारियों से जूझ रहे हैं और उन्हें स्वास्थ्य के संबंध में कई कदम उठाने हैं, ताकि कोई आपात स्थिति न उत्पन्न हो और हिरासत में उनकी जान का खतरा हो। सिंघल को ईडी ने कई करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के आरोप में 27 नवंबर को गिरफ्तार किया था।

टला विवाद

कहा, सौ बार दंडवत होकर भी मांग सकता हूं माफी, भू अधिग्रहण से जुड़े मामले में वकील गोपाल शंकरनारायण को दी थी धमकी

अवमानना की धमकी के लिए जस्टिस अरुण मिश्रा ने मांगी माफी

नई दिल्ली, प्रेट्र : भू-अधिग्रहण के एक मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन को अवमानना कार्यवाही की चेतावनी देने पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने गुरुवार को माफी मांग ली। उन्होंने कहा, 'अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मैं न सिर्फ माफी मांगता हूं बल्कि सौ बार दंडवत होकर भी माफी मांग लूंगा। अगर किसी को किसी भी समय कुछ महसूस हुआ हो तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं।'

जस्टिस अरुण मिश्रा ने उक्त टिप्पणी तब की जब कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनु सिंघवी, दुष्यंत दवे और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश खन्ना के नेतृत्व में वरिष्ठ वकीलों की टीम ने न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उनसे वकीलों के साथ संयमित व्यवहार करने का अनुरोध किया। दरअसल मंगलवार को भू अधिग्रहण के एक मामले की जस्टिस मिश्रा की अगुआई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ में सुनवाई चल रही थी। नारायणन दलीलें रख रहे थे। जस्टिस मिश्रा ने उन्हें दलीलों को नहीं दोहराने को कहा जिसके बाद दोनों में नोकझोंक हुई थी। इसी दौरान जस्टिस मिश्रा ने उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की चेतावनी दी, जिसके बाद नारायणन कोर्ट रूम से बाहर चले गए थे। गुरुवार को जैसे ही जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एमआर शाह की पीठ कोर्ट संख्या-3 में बैठी, वकीलों ने इस मामले को मेंशन कर दिया। वकीलों की ओर से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, युवा वकील इस कोर्ट में आने से डरते हैं। इससे बार के युवा सदस्यों पर असर पड़ता है। वहीं, कपिल सिब्बल और सिंघवी ने कहा कि यह बार और पीठ की जिम्मेदारी है कि हम कोर्ट का डेकोरम कायम रखें और एक-दूसरे को सम्मान दें।

करियर में किसी वकील पर नहीं चलाया अवमानना मामला : जस्टिस मिश्रा ने कहा, 'मैंने जज के तौर पर अपने करियर में किसी वकील पर अवमानना का मामला नहीं चलाया। मैं ज्यादा समय बार से जुड़ा रहा हूं। मैं मानता हूं कि बार पीठ की मां जैसी होती है। मैं बार की दिल से इज्जत करता हूं। कृपया इस बात की छाप अपने दिमाग पर न पड़ने दें। इस फोरम पर काम का जितना दबाव है और जितने मामलों को मैं निपटा रहा हूं, वे इतने ज्यादा हैं कि उनके दबाव में मैंने कुछ कह दिया, मैं तहे दिल से कहना चाहता हूं कि मेरा वो मतलब नहीं था।'

बार की संस्था को बर्बाद कर रहा अक्खड़पन : शंकरनारायणन के बारे में जस्टिस मिश्रा ने कहा, 'वह मुझसे आधी उम्र के हैं। वह बहुत ही प्रतिभावान वकील हैं, लेकिन उन्हें पांच सदस्यीय पीठ के समक्ष अक्खड़पन नहीं दिखाना चाहिए था। उन्हें बहस करने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने नहीं की। वह ऐसे दिखा रहे हैं कि उन्होंने बहस शुरू ही की थी और हमने उन्हें रोक दिया था। यह सही नहीं है।' उन्होंने आगे कहा, 'अक्खड़पन बार की संस्था को बर्बाद कर रहा है। मामलों पर बहस करते वक्त वकीलों को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। अगर आप सम्मान देंगे तो बदले में सम्मान पाएंगे।' उन्होंने कहा कि इन दिनों अदालतों के साथ सही तरीके व्यवहार नहीं होता और उस पर कई हमले किए गए हैं।

न्यायाधीश अरुण मिश्रा फाइल

जस्टिस शाह ने कहा, दोनों तरफ से हो सम्मान

जस्टिस शाह ने जस्टिस मिश्रा का बचाव करते हुए कहा कि सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। भू अधिग्रहण मामलों पर सुनवाई कर रही पीठ ने मंगलवार को जब शंकरनारायणन को बहस जारी रखने के लिए बुलाया तो उन्होंने आने से इन्कार कर दिया।

कवाल कांड में मारे गए सचिन के पिता 14 दिनों से लापता

जासं, मुजफ्फरनगर

वर्ष 2013 में बेटे सचिन की हत्या और उसके बाद चले हत्या के मुकदमे ने बिशन सिंह को शराब का आदी बना दिया था। 22 नवंबर की रात शराब के लिए पैसे मांगने पर घर में विवाद हुआ। इससे नाराज होकर वह घर से चले गए थे।

मुजफ्फरनगर के कवाल में 2013 में शाहनवाज के अलावा सचिन और गौरव की हत्या हुई थी, जिसके बाद मुजफ्फरनगर दंगा हो गया था। मलिकपुरा गांव निवासी बिशन सिंह की पत्नी मुनेश देवी ने बताया कि सचिन व गौरव की हत्या के बाद वह टूट गए थे। हत्या के बाद पुत्रवधू स्वाति भी पोते गगन को लेकर चली गई। पुत्र व पोते के खुद से दूर चले जाने के गम में वह शराब पीने लगे थे। बिशन सिंह कई बार घर से लड़कर चले जाते थे, लेकिन शाम तक लौट आते थे। 22 नवंबर को भी उन्होंने पांच सौ रुपये मांगे थे। रुपये नहीं मिले तो घर में काफी विवाद हुआ। अगले दिन नाराज होकर बिशन सिंह सुबह बाइक लेकर घर से निकल गए। करीब दस दिन तक परिजन उनकी तलाश में भटकते रहे। चार दिसंबर को बिशन सिंह के पुत्र राहुल ने गुमशुदगी दर्ज कराई।

हत्या के आरोप में जाना पड़ा था जेल

बिशन सिंह व उनके भाइयों पर कवाल निवासी शाहनवाज के पिता की ओर से हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। हालांकि, एसआइटी ने उस मुकदमे से सभी आरोपितों को क्लीन चिट दे दी थी। बाद में शाहनवाज के पिता सलीम की ओर से एक निजी परिवाद दायर किया गया, जिसमें सभी के वारंट जारी हुए थे। बिशन सिंह व उनके भाई चार जून को इसी मामले में जेल गए थे। 37 दिन बाद जेल में रहने के बाद उन्हें 11 जुलाई को जमानत मिली थी।

99.5 प्रतिशत 10वीं के छात्रों ने तो 99.7 प्रतिशत 12वीं के छात्रों ने कश्मीर में बोर्ड की परीक्षा में हिस्सा लिया। 10वीं में कुल 50,537 छात्र थे। यह जानकारी गृह मंत्रालय की ओर से बताई गई है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 6 दिसंबर 2019

न्यूज गैलरी

चीफ इंजीनियर करेंगे नए विस भवन में लगी आग की जांच

रांची : रांची में राज्य की नए विधानसभा भवन में आग लगने के मामले की प्रशासनिक जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया है। इसका नेतृत्व भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर करेंगे। जांच दल में विभाग के अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता भी शामिल हैं। जांच रिपोर्ट पुलिस की जांच से अलग होगी। बता दें कि रांची स्थित नए विधानसभा भवन के एक हिस्से में बुधवार को आग लग गई थी और उस हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है। आग लगने से हुए नुकसान का अभी पूरी तरह आकलन नहीं किया गया है, लेकिन सरकार की ओर से एक बात स्पष्ट है कि यह ठेकेदार की परेशानी है। जब तक भवन हैंडओवर नहीं लिया जाता, तब तक की समस्याओं से सरकार को कुछ लेना-देना नहीं है। (राब्यू)

ओडिशा में नष्ट किए गए 2.15 लाख गांजा के पौधे

भुवनेश्वर : ओडिशा के बौद्ध जिले में की गई गांजा की खेती को नष्ट कर दिया गया है। करीब 107 एकड़ जमीन में लगाए गए 2 लाख 15 हजार गांजा के पौधों को जला दिया गया है । एसपी के निर्देश पर मनमुंडा थाना पुलिस के साथ आबकारी, राजस्व विभाग एवं जंगल विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर गांजा के पौधों को आग लगाकर नष्ट किया। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट-1985 के अनुसार गांजा की खेती को गैरकानूनी घोषित किया गया है। (जासं)

अवैध रूप से सीमा पार कर रहे चार घुसपैठिए गिरफ्तार

कोलकाता : बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र से घुसपैठियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करते हुए चार और बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। बुधवार रात में चलाए गए अभियान के दौरान उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट थाना क्षेत्र से तीन बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करते हुए गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा मुर्शिदाबाद जिले के जालंगी थाना क्षेत्र से एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सभी घुसपैठियों ने बताया है कि वे दलालों की मदद से भारत में आए थे। (जासं)

अरुण सिंह राज्यसभा सदस्य निर्वाचित

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह को गुरुवार को निर्विरोध राज्यसभा सदस्य निर्वाचित घोषित कर दिया गया। सपा की तजीन फात्मा द्वारा त्यागपत्र देने के बाद रिक्त राज्यसभा की सीट के लिए दो दिसंबर को अरुण सिंह ने नामांकन पत्र जमा किया था। इस सीट पर एकमात्र नामांकन पत्र भरा होने व गुरुवार को नाम वापसी की समय अवधि खत्म होने के बाद अरुण सिंह निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए। (राब्यू)

पाकिस्तान ने हीरानगर सेक्टर में रातभर की गोलाबारी

हीरानगर : जम्मू के कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने बुधवार को रातभर गोलाबारी की। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने भी इसका कड़ा जवाब दिया। पाकिस्तान ने बुधवार रात करीब दस बजे हीरानगर के पानसर व रठुआ गांवों में मोर्टार दागने के साथ छोटे हथियारों से गोलीबारी की, जो तड़के साढ़े चार बजे तक रुक-रुक कर जारी रही। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। कई ग्रामीणों ने घर पर तो कुछ ने बंकरों में रात बिताई। (जासं)

सम्मानपूर्वक घर भेजे गए शहीद जवानों के पार्थिव शरीर

जम्मू : कश्मीर के टंगडार में हिमस्खलन की चपेट में आकर शहीद हुए सेना के तीन जवानों के पार्थिव शरीर गुरुवार को सम्मानपूर्वक श्रीनगर से विशेष विमान के जरिये दिल्ली भेजे गए। वहां से उनके पार्थिव शरीर संबंधित राज्यों में भेजे जाएंगे। इससे पहले चिनार कोर मुख्यालय बादामी बाग में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों, सुरक्षाबलों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। थलसेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के साथ उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह की ओर से भी शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए। (राब्यू)

उद्योगों के लिए लैंड बैंक बना रहा जम्मू-कश्मीर

तैयारी ▶ अभी तक करीब 18 हजार कनाल भूमि चिह्नित की

राज्य ब्यूरो, जम्मू

नया जम्मू-कश्मीर तेज आर्थिक विकास की जमीन तैयार करने में जुट गया है। उद्योगों को आकर्षित करने के लिए लैंड बैंक बनाया जा रहा है ताकि उन्हें उचित दर पर जमीन उपलब्ध करवाई जा सके। राज्य प्रशासन ने जमीन का डाटा बैंक बनाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में अब तक करीब 18 हजार कनाल भूमि को चिह्नित कर लिया गया है। सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर इस पर काम कर रहे हैं।

केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में अगले वर्ष निवेशक सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी कर रही है। इसमें एक लाख करोड़ का निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इस नए केंद्र शासित प्रदेश को हजारों करोड़ के प्रस्ताव पहुंच भी चुके हैं। ऐसे में चुनौती नए उद्योगों को जमीन उपलब्ध करवाने की है।

जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद कई बड़े समूहों ने जम्मू-कश्मीर में निवेश की घोषणा की थी। चार माह में 35-40 समूहों ने अपने प्रोजेक्ट प्रशासन को सौंपे हैं। इन निवेश में सबसे बड़ी चुनौती पर्याप्त जमीन उपलब्ध करवाने की है। प्रदेश सरकार के पास अपना लैंड बैंक न होने के कारण अभी यह सभी प्रोजेक्ट लंबित पड़े थे।

जम्मू और कश्मीर में भी देखी जगह

प्रशासन ने फिलहाल करीब 18 हजार कनाल भूमि को चिह्नित किया है। इसमें से 10 हजार कनाल भूमि जम्मू संभाग के जम्मू और सांबा जिलों में है। इसके अलावा गांदरबल और कुपवाड़ा में भी जगह चिह्नित की गई है। इस बात की पुष्टि करते स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक रवींद्र कुमार ने कहा कि प्रशासन पहले ही यह साफ कर चुका है कि उनके पास पर्याप्त जगह है।

इन क्षेत्रों में हैं संभावनाएं : जम्मू-कश्मीर में सेब उद्योग, सूखे मेवे, केसर, होटल और पर्यटन क्षेत्र में सबसे अधिक रुचि दिखाई जा रही है। लैमन ट्री समूह ने भी होटल बनाने में रूचि दिखाई थी। इसके अलावा अन्य कई समूह भी होटल बनाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

पहले नहीं खरीद सकते थे जमीन : जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन से पहले राज्य से बाहर का कोई भी व्यक्ति यहां पर जमीन नहीं खरीद सकता था। यहां पर सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट वाले लोग ही जमीन खरीद सकते थे।

कश्मीर की अर्थव्यवस्था को हुआ 15 हजार करोड़ का नुकसान

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद कश्मीर की अर्थव्यवस्था को अभी तक करीब पंद्रह हजार करोड़ रुपये का नुकसान पहुंच चुका है। यह दावा कश्मीर चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज ने किया है। चैंबर प्रधान शेख आशिक हुसैन ने कहा कि कश्मीर में हुए नुकसान का सही आकलन किया जा रहा है। एक सप्ताह तक वह नुकसान का सही आंकड़ा देंगे। शेख आशिक हुसैन ने कहा कि दुकानें व इंटरनेट बंद होने के कारण कइयों का रोजगार चला गया है। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक नुकसान हैंडीक्राफ्ट, पर्यटन और ई-कामर्स को पहुंचा है। हालांकि अभी अधिकांश क्षेत्रों में लगे प्रतिबंधों को हटा दिया गया है, लेकिन दुकानें, इंटरनेट, प्री पेड फोन अभी भी बंद पड़े हुए हैं। कश्मीर में इस समय सिर्फ लैंडलाइन और पोस्ट पेड मोबाइल ही चल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में ही कश्मीर में पचास हजार लोगों को रोजगार से वंचित होना पड़ा है। इंटरनेट न होने के कारण कोई भी काम नहीं मिल रहा है।

आइटीबीपी कैंप में रहा सन्नाटा जवानों ने 30 घंटे बाद खाया खाना

इमरान खान, बीजापुर

- आइटीबीपी जवानों को सदमे से उबारने पहुंचे अधिकारी
- फोरेंसिक की टीम ने ढाई घंटे तक घूम-घूमकर लिए कई सैंपल

छत्तीसगढ़ के बीजापुर स्थित कड़ेनार के आइटीबीपी कैंप में बुधवार की मातमी सुबह का खौफनाक सन्नाटा गुरुवार को भी पसरा रहा। इसी कैंप में बुधवार को एक जवान ने फायरिंग कर पांच साथियों की हत्या कर दी थी। घटनास्थल पर फायरिंग करने वाला जवान भी मृत मिला था। ऐसे में गुरुवार को यहां के जवानों के चेहरे की घोर उदासी और उन्नींदी आंखें बयां कर रहती रहीं कि हालात से उबरने में जवानों को अभी वक्त लगेगा। फायरिंग की घटना के बाद करीब 30 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन जवानों ने न तो नाश्ता किया है, न भोजन। हालात ऐसे कि जवानों को समझाने, हौसला देने के लिए आए आइटीबीपी के आला अधिकारियों को भी पसीने छूट गए। जवान किसी तरह माने और अधिकारियों के साथ खाना खाया।

गुरुवार को आइटीबीपी के शीर्ष अधिकारियों का दल हेलीकॉप्टर से कड़ेनार कैंप पहुंचा। कैंप प्रभारी से लेकर जवानों से वन टू वन बात भी की। इधर, फोरेंसिक के संयुक्त संचालक डॉ. बी सूरी बाबू के नेतृत्व में टीम ने ढाई घंटे तक निरीक्षण किया। वहां फैले खून के सैंपल लिए। मृत जवानों की पांच सर्विस रायफलें, पोस्टमार्टम के दौरान मृत जवानों के शरीर से मिली गोलियां, मौके पर मिले कारतूस और कारतूस के खोखे बरामद कर उन्हें सीलबंद कर जब्त किया। इसे बैलेस्टिक परीक्षण के लिए सेंट्रल लैब एफएसएल रायपुर भेजा जाएगा।

आइटीबीपी के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि किसी भी जवान को किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत हो तो अपने शीर्ष अधिकारियों से जरूर बात करें। उन्होंने कहा कि कोई भी साथी अगर तनाव से गुजर रहा है तो वह अपने साथी के मन के बोझ को हलका करें और कैंप प्रभारी को संबंधित जवान की गतिविधियों से वाकिफ कराए।

जवान ने क्यों चलाई गोली, इसकी होगी जांच

नारायणपुर में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) के कैंप में एक कांस्टेबल के अपने पांच साथियों को गोली मारने की घटना की जांच होगी। आइटीबीपी के आला अधिकारियों ने बताया कि डीआइजी स्तर के अधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा जाएगा। इस टीम में तीन सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इसमें बटालियन के प्रभारी अधिकारी और बैरक के प्रभारी अधिकारी को शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि टीम घटना के कारणों, गोलीबारी की परिस्थिति और उससे बचाव के उपाय के बारे में एक महीने में रिपोर्ट देगी।

नारद स्टिंग की जांच रिपोर्ट नहीं मिलने पर हाई कोर्ट ने जताई हैरानी

जागरण संवाददाता, कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने नारद स्टिंग मामले से संबंधित टेप की फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं मिलने पर हैरानी जताई है। गुरुवार को राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने कहा कि यह काफी हैरान करने वाली बात है कि नारद स्टिंग मामले में सबूत के तौर पर जुटाए गए टेप की जांच रिपोर्ट अब तक सीबीआइ को नहीं मिली है। उन्होंने सीबीआइ से पूछा कि इस टेप की जांच के लिए एक वर्ष पहले ही अमेरिका भेजा गया था लेकिन जांच के लिए पर्याप्त समय पूरा होने के बाद भी रिपोर्ट क्यों नहीं मिली।

इस पर सीबीआइ के अधिवक्ता अमजीत दे ने अदालत को बताया कि केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा वीडियो टेप में आवाज के नमूने की जांच रिपोर्ट निर्माता कंपनी को जांच के लिए भेजी गई है लेकिन वहां से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इसके बाद न्यायाधीश बागची ने उक्त याचिका को नारद स्टिंग मामले के साथ टैग करने का निर्देश देते हुए कहा कि क्रिसमस की छुट्टी के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि नारद न्यूज के सैमुअल मैथ्यू ने 2014 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिलते-जुलते कुछ लोग और आइपीएस अधिकारी कुछ लाभ के बदले में एक काल्पनिक कंपनी के प्रतिनिधियों से पैसा लेते नजर आए थे। यह वीडियो 2016 में बंगाल विधानसभा चुनावों से ठीक पहले सामने आया था।

संसदीय समिति के समक्ष पेश हुए फेसबुक वाट्सएप के अधिकारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के उत्पीड़न के मसले पर गुरुवार को फेसबुक, इंस्टाग्राम और वाट्सएप के अधिकारी संसदीय समिति के समक्ष पेश हुए। इन तीनों सोशल मीडिया कंपनियों के अधिकारियों ने महिला सशक्तीकरण पर संसद की स्थायी समिति के समक्ष प्रजेंटेशन दिया। यह समिति महिलाओं की साइबर सिक्योरिटी पर विमर्श कर रही है।

सूत्रों के मुताबिक, फेसबुक ने समिति को अपने उस मैकेनिज्म के बारे में जानकारी दी, जिसके जरिये महिलाएं इस प्लेटफॉर्म पर किसी तरह के उत्पीड़न की शिकायत कर सकती हैं। इंस्टाग्राम और वाट्सएप भी फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनियां हैं। संसदीय समिति के सदस्यों ने इन कंपनियों को सरकार का सहयोग करने और ऑनलाइन निगरानी को मजबूत करने की दिशा में मदद को कहा। पूर्ण महिला सदस्यों वाली समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद हीना गावित कर रही हैं। बुधवार को ट्विटर इंडिया के अधिकारियों ने समिति को अपने मैकेनिज्म के बारे में बताया था।

पंजाब में स्कूल में एयरगन का छर्रा लगने से छात्र की मौत

जागरण संवाददाता, बरनाला

मृतक जसवीर सिंह। फाइल

लाला लाजपत राय आर्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भदौड़ में पिकनिक के दौरान एयरगन से चला छर्रा दूसरी क्लास के सात वर्षीय छात्र जसवीर सिंह निवासी भदौड़ को लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना बुधवार दोपहर 12.30 बजे हुई, जिसके बाद देर रात दो बजे के करीब अस्पताल में बच्चे ने दम तोड़ दिया।

फिरोजपुर की हरीश अरोड़ा एंड कंपनी ने स्कूल में पिकनिक का आयोजन किया था। स्कूल की प्रिंसिपल सुरेश प्रभा ने बताया पिकनिक में दसवीं की छात्रा ने एयरगन चलाई तो बच्चा सामने आ गया और छर्रा उसके गले व गर्दन के बीच में लगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच कमेटी नियुक्त कर दी है। वहीं पुलिस अपने स्तर पर ही केस की जांच में जुट गई है। पुलिस ने वीरवार को स्कूल प्रिंसिपल, शिक्षकों व प्रबंधकों के बयान ले लिए हैं। हादसे के बाद इवेंट कंपनी के कारिंदे भाग गए।

सामने आई स्कूल की लापरवाही : पिकनिक के लिए स्कूल प्रिंसिपल ने शिक्षा विभाग से इजाजत नहीं ली थी। घटना के 24 घंटे बाद भी स्कूल प्रिंसिपल सुरेश प्रभा और मैनेजर भूषण कुमार ने इसकी जानकारी न तो पुलिस को दी और न ही जिला शिक्षा अधिकारी को।

रिपोर्ट के आधार स्कूल की मान्यता रद करने सिफारिश : डीसी तेजप्रताप सिंह फूलका ने कहा कि डीईओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल की मान्यता रद करने के लिए डीजीएसई और शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर सिफारिश करेंगे।

उप्र में पराली जलाने पर 53 लोगों पर मुकदमा

जेएनएन, लखनऊ : पराली जलने पर प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई करने का क्रम गुरुवार को भी जारी रहा। प्रदेश में 53 किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए जबकि चिह्नित लोगों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। लापरवाही पर कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जा रही है। बुधवार को 260 लोगों को पर मुकदमे दर्ज किए गए थे।

गोरखपुर, बस्ती मंडल में धान की पराली जलाने वाले 29 किसानों पर प्रशासन ने गुरुवार को मुकदमा दर्ज कराया है। जिन किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उनमें बस्ती जिले के 11, सिद्धार्थनगर के तीन और कुशीनगर के 15 किसान शामिल हैं। बस्ती के जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि पराली जलाने की सूचना देने में लापरवाही बरतने वाले चार लेखपालों को प्रतिकूल प्रविष्टि और तीन लेखपालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

जालौन के ग्राम कुदरा बुजुर्ग और खकल्ल का मौजा में बुधवार रात एक-दो नहीं, 500 बीघा में पराली जलाई गई। इससे आसमान धुएं से पट गया। रिपोर्ट में 13 किसानों को चिह्नित किया गया है। नायब तहसीलदार संजय कुमार ने बताया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

पंजाब में कैप्टन की कैबिनेट में 'काली दवाई' पर चर्चा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में काली दवाई (अफीम) पर हुई बातचीत का वीडियो वायरल होने से सरकार की काफी फजीहत हो रही है। वहीं, मीटिंग की फुटेज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देने पर लोक संपर्क विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी और वीडियोग्राफर को चार्जशीट कर दिया गया है। सवाल उठ रहा है कि जब राज्य गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा हो और आए दिन युवा नशे के कारण मारे जा रहे हों, वहां जनप्रतिनिधियों के लिए मुख्य एजेंडा क्या है?

हुआ यूं कि कैबिनेट की मीटिंग में तकनीकी शिक्षा मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी काफी बीमार दिख रहे थे। मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने उन्हें काली दवाई (अफीम) लेने की सलाह दी। तभी वीडियो में मंत्री रजिया सुल्ताना की आवाज सुनाई पड़ती है। वह कहती हैं- 'आपको काली दवाई लाकर दें क्या?' इतने में सभी हंसने लगते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन हंसी के शोर में ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा। मालवा के एक मंत्री कह रहे हैं, 'इसके लिए तो राजस्थान जाना पड़ेगा।' उसी समय स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा कहते सुनाई पड़ते हैं, 'ये कब राजस्थान जाएगा और वहां से काली दवाई लाएगा?'

लोक संपर्क विभाग ने इसके लिए एडिशनल डायरेक्टर रैंक के अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए चार्जशीट कर दिया। इस तरह का वीडियो शूट हर कैबिनेट मीटिंग से पहले कराया जाता है, ताकि उसे विभिन्न चैनलों को फुटेज के लिए दिया जा सके। इसे म्यूट करके शूट करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

सरकार की किरकिरी

नशे के मुद्दे पर पंजाब सरकार हमेशा से घिरी रही है। पूर्व अकाली-भाजपा सरकार तो नशे के मुद्दे पर ही चली गई थी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी चुनाव के दौरान यह मुद्दा उठाया था। आए दिन पंजाब में नशे के कारण मौतें हो रही हैं। कैप्टन ने सत्ता में आने पर श्री गुटका साहिब की शपथ खाकर नशा मिटाने की बात कही थी। ऐसी सरकार के मंत्रियों की अफीम लेने पर अनौपचारिक चर्चा उजागर होने से किरकिरी हो रही है।

बढ़े वायु प्रदूषण से बीमारियों में 43 फीसद इजाफा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- संसदीय समिति को एम्स सहित स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने दी जानकारी
- इस दौरान ज्यादा देखने को मिली हैं सांस से जुड़ी समस्याएं

दिल्ली-एनसीआर सहित देशभर में बढ़े वायु प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। गुरुवार को वायु प्रदूषण के मुद्दे पर बुलाई गई संसदीय समिति की बैठक में एम्स सहित स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने यह जानकारी साझा की। साथ ही बताया कि पिछले वर्षों में वायु प्रदूषण के चलते बीमारियों में करीब 43 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। इनमें सांस से जुड़ी बीमारियां सबसे ज्यादा बढ़ी हैं। कमेटी ने इसे लेकर तुरंत प्रभावी कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया।

बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर संसदीय समिति की गुरुवार को तीसरी बैठक थी। इसमें करीब 18 सदस्य शामिल हुए। इससे पहले दो बैठकें 15 और 20 नवंबर को भी हो चुकी हैं। हालांकि, इसकी पहली बैठक में गिनती के सिर्फ चार संसद सदस्य और कुछ अधिकारी ही पहुंचे थे। इसके बाद समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बैठक को रद कर दिया था। समिति की दूसरी बैठक में कुल 28 सदस्यों में से 23 पहुंचे थे। इसमें अधिकारियों से इस समस्या से निपटने का पूरा प्लान मांगा गया था। इस दौरान पर्यावरण मंत्रालय की ओर से एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया था। समिति की गुरुवार की बैठक इसलिए अहम थी, क्योंकि इनमें एम्स निदेशक सहित स्वास्थ्य मंत्रालय और वायु प्रदूषण के प्रभावों पर नजर रखने वाली एजेंसियों को भी बुलाया गया था। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मंत्रालय की ओर से वायु प्रदूषण से मरीजों की बढ़ रही संख्या की जानकारी दी गई है। इनमें सांस से जुड़ी समस्या ज्यादा देखने को मिली है।

फिर नहीं पहुंचे पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी

संसदीय समिति की इस बैठक में इस बार फिर से पर्यावरण मंत्रालय का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी नहीं पहुंचा। इसकी वजह अधिकारियों की व्यस्तताएं थी। सूत्रों की मानें तो इसकी सूचना पहले ही समिति को दे दी गई थी।

हनी ट्रैप में फंसे जीतू सोनी के साम्राज्य पर चला बुलडोजर

नईदुनिया, इंदौर

- इंदौर नगर निगम ने सोनी के दो होटल, रेस्त्रां और बंगला तोड़े
- 2100 वर्गफीट की अनुमति थी, 24000 वर्ग फीट में बनाया बंगला

मध्य प्रदेश के इंदौर में बहुचर्चित हनी ट्रैप से जुड़े मामले में आरोपित बने जितेंद्र (जीतू) सोनी के खिलाफ गुरुवार को बड़ी कार्रवाई हुई। नगर निगम के दस्ते ने सोनी के दो होटल, रेस्त्रां और बंगले को अवैध निर्माण के चलते खंडहर में तब्दील कर दिया। अलसुबह ही कार्रवाई शुरू हो गई। न्यू पलासिया स्थित ओ-2 रेस्त्रां दोपहर तक टूट चुका था। होटल बेस्ट वेस्टर्न को लेकर हाई कोर्ट का स्थगन सुबह 11.30 बजे तक आया, लेकिन तब तक उसका काफी हिस्सा ढहा दिया गया था। विवादित माय होम होटल का अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई देर शाम तक चलती रही।

निगम दस्ते ने आलोक नगर में सीलिंग की जमीन पर बना जीतू सोनी का बंगला भी ध्वस्त कर दिया गया। सोनी ने बंगले से लगी कनाडिया मुख्य मार्ग की सर्विस रोड को पाइप लगाकर बंद कर रखा था, ताकि लोग वाहन न निकाल सकें। बताया जाता है कि करीब 24000 वर्ग फीट में फैले बंगले में 2100 वर्गफीट के निर्माण की ही अनुमति थी। धीरे-धीरे आसपास की जमीन का अधिकांश हिस्सा कब्जे में ले लिया गया था। बंगले के बीच में मंदिर बना हुआ है। इसके ऊपर गुंबद और शिखर भी है। दस्ते को निर्देश दिए गए थे कि मंदिर को न तोड़ा जाए।

इंदौर में विवादित माय होम होटल की दीवारें तोड़ता निगम का अमला। नईदुनिया

माय होम में पार्किंग की जगह पर बना रखे थे डांस फ्लोर

गीता भवन चौराहे के पास स्थित होटल 'माय होम' पर 13 घंटे में कार्रवाई पूरी हुई। होटल की इमारत वैध थी, इसलिए अतिक्रमण वाले हिस्सों को लक्ष्य कर तोड़फोड़ की गई। होटल को ओपन बालकनी की अनुमति थी, लेकिन उसे कवर कर कमरे बनाए गए थे। इस वजह से बिल्डिंग के दोनों ओर की दीवारें तोड़ी गईं। ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग की जगह को कवर कर डांस फ्लोर व कमरे बना लिए गए थे। इससे निगम ने ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग के हिस्से की दीवारों को तोड़ा। तलघर भी अवैध रूप से बनाया गया था। उधर, एक अन्य होटल बेस्ट वेस्टर्न का भी बड़ा हिस्सा ढहा दिया गया। हालांकि सुबह 11.30 बजे हाई कोर्ट ने इस मामले में स्टे दे दिया।

कोर्ट ने निगम की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए होटल प्रबंधन को नोटिस का जवाब देने के लिए सात दिन का समय दे दिया। कोर्ट ने कहा कि इस अवधि के बाद निगम को लगता है कि कार्रवाई जरूरी है तो वह होटल प्रबंधन को तीन दिन का नोटिस देगा। इसके बाद ही तोड़फोड़ की कार्रवाई होगी।

यह है मामला

हनी ट्रैप मामले में ब्लैकमेलिंग करने, युवतियों को बंधक बनाने और मानव तस्करी करने के आरोपित जीतू सोनी को आरोपित बनाया गया है। वह अभी फरार है। इसी मामले में जीतू के बेटे अमित सोनी और अन्य पर भी केस दर्ज हैं। अमित सोनी को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने शनिवार देर रात कार्रवाई की थी।

सभ्य समाज

विवाद की स्मृति छोड़ सृजन की छाप छोड़ने की तैयारी, विवाद के पैरोकारों के रुख से भी बखूबी बयां हो रहा है शांति का पैगाम

जय-पराजय दरकिनार, विवाद से मुक्ति शिद्दत से स्वीकार

रमाशरण अवस्थी, अयोध्या

शरद शर्मा (विहिप प्रवक्ता) फाइल

इकबाल (मस्जिद के पक्षकार रहे) फाइल

अचार्य किशोर कुणाल जागरण

महंत रामदास। जागरण

सभ्य समाज बड़े से बड़े फैसले को किस तरह स्वीकार करता है, रामलला के हक में आया सुप्रीम फैसला इसका शानदार उदाहरण है। रामलला करोड़ों भक्तों की भावनाओं के केंद्र में रहे हैं। रामलला के पक्ष में आए फैसले का जश्न भी मना पर दूसरे पक्ष की भावनाएं आहत न होने पाएं, इस मर्यादा का भी पूरा पालन किया गया। दूसरे पक्ष ने भी फैसले को जय-पराजय के बोध से इतर विवाद से मुक्ति के रूप में स्वीकार किया। यह सच्चाई इस विवाद के पैरोकारों के रुख से भी बखूबी बयां हो रही है।

सबसे बड़ी मिसाल मो. इकबाल ही हैं। रामजन्मभूमि परिसर के सामने की सड़क पार करते ही उनका पीढ़ियों पुराना घर है, जहां से उनके पिता हाशिम अंसारी 1949 से रामजन्मभूमि को चुनौती देते रहे। विवादित स्थल को मस्जिद मानने और वहां से रामलला की मूर्ति हटाने की मांग को लेकर वर्षों अदालती लड़ाई लड़ने वाले हाशिम को 2016 में इंतकाल से पूर्व कुछ वर्षों के दौरान जैसे अंतिम सत्य का बोध हुआ और वह आपसी सहमति से मसले के हल का प्रयास करने लगे। इकबाल ने सहमति से समाधान की विरासत आगे बढ़ाने के साथ अदालत में पैरोकारी जारी रखी पर विगत नौ नवंबर को आया निर्णय उनके लिए किसी अंतिम सत्य से कम नहीं है। वह जहां यह कहते हैं कि फैसला आने के साथ विवाद खत्म, वहीं फैसला आने के बाद इस पर अमल होते देखना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि कोर्ट के आदेश के अनुरूप दी जाने वाली भूमि पर स्कूल और चिकित्सालय बने। इकबाल जहां विवाद को भुला देना चाहते हैं, वहीं खास दिन मनाए जाने के सवाल पर कहते हैं, अब लद गए खौफ के दिन। गुजरात के एडीजी रहते स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले पूर्व आइपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल उन चुनिंदा किरदारों में शुमार रहे हैं, जिन्होंने अदालत में मंदिर की दावेदारी को पूरी प्रामाणिकता से प्रस्तुत किया। आचार्य कुणाल कहते हैं, अब तो सृजन की अमिट छाप छोड़ी जानी है। पौराणिक महत्व की पीठ नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास को अपने गुरु भास्करदास से मंदिर की पैरोकारी विरासत में मिली। निर्णय के बाद स्मृति आयोजनों को भूल सृजन की भरी-पूरी संस्कृति साकार होते देखने की ख्वाहिश पाल बैठे हैं। विहिप प्रवक्ता शरद शर्मा को अब छह दिसंबर का शौर्य दिवस छोड़कर उस दिन का इंतजार है, जब रामलला के मंदिर का शिलान्यास हो।

शहर से लेकर गांव तक पुलिस ने किया रूटमार्च

जासं, अयोध्या : छह दिसंबर को लेकर शहर से लेकर गांव तक पुलिस ने आरएएफ और पीएसी के जवानों के साथ रूट मार्च कर शांति की अपील की। संवेदनशील क्षेत्रों में खासी सतर्कता बरती जा रही है। गलियों से चौराहों तक पुलिस की तैनाती कर दी गई है। खुफियाकर्मी रामनगरी से गांव तक हर गतिविधि पर नजर रखे हैं। जिला प्रशासन ने खुशी व गम का इजहार करने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। देर शाम जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और एसएसपी आशीष तिवारी ने फोर्स के साथ शहर में रूट मार्च किया। एडीएम प्रशासन एसके सिंह ने बताया कि धारा 144 का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। गुरुवार को अयोध्या में सीओ अयोध्या अमर सिंह व शहर में सीओ सिटी अरविंद चौरसिया की अगुवाई में रूट मार्च किया गया। अति संवेदनशील क्षेत्रों में आरएएफ, पीएसी और पुलिस के जवानों ने मार्च कर शांति बनाए रखने की अपील की। एडीएम प्रशासन व एसपी ग्रामीण की अगुवाई में ग्रामीण क्षेत्र कुमारगंज, इनायतनगर, बारुन, अमानीगंज में गोसाईंगंज में रूट मार्च किया गया। शुक्रवार की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी ने जोन व सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की है।

विवादों को पीछे छोड़ शांत व मुस्कुराती दिख रही अयोध्या

नवनीत श्रीवास्तव, अयोध्या

छह दिसंबर की पूर्व संध्या पर अयोध्या सौहार्द के आभूषणों से विभूषित और नौ नवंबर के फैसले की आभा में विवाद से मुक्ति की शांति बिखेरती, मुस्कुराती नजर आई।

कुछ वक्त अयोध्या में गुजारने पर एहसास होता है कि रामनगरी 27 साल पुराने दौर को भूल चुकी है। हां, सख्त सुरक्षा व्यवस्था अवश्य बताती है कि अगला दिन छह दिसंबर है पर आम लोगों की भाव-भंगिमा, दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं का उत्साह और अयोध्यावासियों की रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्तता सहज ही इशारा कर देती है कि 27 वर्ष पुराना छह दिसंबर कब का पीछे छूट चुका है।

छह दिसंबर की बेफिक्री में मंदिरों में होती आरती और मस्जिदों की अजान सौहार्द की लालिमा को सुर्ख कर देती है। चंद लोगों से बातचीत करने पर पुष्ट हो जाता है कि अयोध्या का सौहार्द केवल शहर तक नहीं, बल्कि देश के लिए संदेश है।

अयोध्या में ध्वंस की बरसी से जुड़ी तुर्शी से दूर छह दिसंबर की पूर्व बेला में यूं गुलजार दिखा पुण्य सलिला सरयू का घाट। जागरण

रामजन्मभूमि न्यास कार्यशाला में गुजरात के सूरत से आए संजय मिलते हैं। उत्साह में जय श्रीराम का उद्घोष के भाव से भरे संजय कहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि ईश्वर अयोध्या को दुनिया का श्रेष्ठतम शहर बनाएं।

14500 एनजीओ पर प्रतिबंध लगाया है केंद्र सरकार ने पिछले पांच साल में देशभर में। इस साल अभी तक 1808 एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद किया गया है। केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी दी।

खूंटी सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में फादर अल्फोंस सहित छह बरी

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड के खूंटी जिले के कोचांग में पांच महिलाओं के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के दूसरे मामले में आरोपित फादर अल्फोंस आईंद को बड़ी राहत मिली है। खूंटी की निचली अदालत ने साक्ष्य के अभाव में फादर अल्फोंस सहित छह आरोपितों को बरी कर दिया है। बरी होने वालों में फादर अल्फोंस आइंद, बाजी सामद उर्फ टकला, अजुब सांडीपूर्ति, जोनास मुंडा, जॉन जुनास तिड़ू, और बलराम सामद शामिल हैं। इस मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पहली दुष्कर्म पीड़िता की ओर से और दूसरी एनजीओ संचालक संजय शर्मा ने दर्ज कराई थी। पहले मामले में निचली अदालत ने 17 मई 2019 को फादर अल्फोंस सहित छह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लेकिन दूसरे मामले में अभियोजन मामला साबित करने में नाकाम रहा। इस कारण अदालत ने सभी आरोपितों को बरी कर दिया।

यह है मामला : खूंटी में पत्थलगड़ी के दौरान नुक्कड़ नाटक से लोगों को जागरूक करने पहुंची पांच महिलाओं के साथ जून 2018 में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इस मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की गई। इसमें फादर अल्फोंस आइंद सहित छह को आरोपित बनाया गया था।

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को अनुमति का फैसला 'अंतिम' नहीं

टिप्पणी ▶ शीर्ष अदालत ने कहा, बड़ी पीठ को भेजा गया है मामला

महिला श्रद्धालु की हमले की शिकायत पर सुनवाई अगले सप्ताह

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

▶ श्रद्धालु बिंदू अम्मिनी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह की दलीलों पर कोर्ट ने कहा

▶ वकील ने आरोप लगाया कि कोर्ट के 2018 के फैसले का उल्लंघन हो रहा है, मंदिर में प्रवेश पर हमला हुआ

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केरल के सबरीमाला अयप्पा मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने वाला उसका फैसला 'अंतिम' नहीं है। इसका कारण यह है कि इसे बड़ी पीठ को भेजा गया है। शीर्ष अदालत ने महिला श्रद्धालु बिंदू अम्मिनी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह की दलीलों पर यह टिप्पणी की। वकील ने आरोप लगाया कि कोर्ट के 2018 के फैसले का उल्लंघन हो रहा है और मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान उनकी मुवक्किल पर हमला किया गया। कोर्ट बिंदू की याचिका समेत इस तरह की अन्य याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई को तैयार हो गया है। एक अन्य महिला फातिमा भी इसी तरह की याचिका लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 2018 का फैसला अंतिम नहीं है, क्योंकि यह मुद्दा सात जजों की पीठ के पास विचार के लिए भेजा गया है।

पीठ ने कहा, 'मामले में फैसला के लिए इसे बड़ी पीठ को भेजने का आदेश है। अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।'

उल्लेखनीय है कि 14 नवंबर को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से शीर्ष कोर्ट के 2018 के ऐतिहासिक फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं को सात न्यायाधीशों की पीठ को भेजने का आदेश दिया था। नई पीठ मुस्लिम और पारसी महिलाओं के साथ कथित भेदभाव पर भी विचार करेगी। गौरतलब है कि सितंबर, 2018 में पांच जजों की एक संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत वाले फैसले में अयप्पा मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की यह कहते हुए इजाजत दी थी कि शारीरिक स्थिति के आधार पर भेदभाव संविधान प्रदत्त समानता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

जयसिंह ने कहा कि उनकी मुवक्किल पर पुलिस आयुक्त के कार्यालय के ठीक बाहर हमला किया गया। शीर्ष अदालत ने 14 नवंबर के आदेश में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की इजाजत देने वाले अपने पूर्व फैसले पर रोक नहीं लगाई थी। उन्होंने कहा, 'बिंदू पर कुछ रासायनिक पदार्थों से हमला किया गया था।'

इसके बाद पीठ ने महिला श्रद्धालु की याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई की सहमति दे दी। पीठ ने कहा कि यह याचिका पूर्व की दूसरी याचिकाओं के साथ अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी।

लखनऊ-आगरा और यमुना एक्सप्रेस वे पर दौड़ेंगे फास्टैग लगे वाहन

जागरण संवाददाता, लखनऊ : नेशनल हाईवे के बाद उप्र सरकार के एक्सप्रेस वे पर भी फास्टैग अनिवार्य किया जा रहा है। इस संबंध में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआइ) और यूपी एक्सप्रेस वे डेवलमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) के बीच अनुबंध हुआ है। फिलहाल लखनऊ-आगरा और यमुना एक्सप्रेस वे पर इसे लागू किया जा रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी फास्टैग लगे वाहन ही फर्राटा भर पाएंगे।

देशभर के हाईवे पर टोल टैक्स वसूली के लिए फास्टैग सिस्टम 15 दिसंबर से लागू होने जा रहा है। केवल एक लेन छोड़ कर बाकी सभी लेन पर टोल भुगतान कैशलेस हो जाएगा। इससे वाहन बिना रुके टोल प्लाजा से निकल जाएंगे। फिलहाल इस व्यवस्था को एक्सप्रेस वे का संचालन करने वाली एजेंसी यूपीडा नहीं अपना रही थी।

एनएचएआइ के रीजनल आफिसर अब्दुल बासित ने बताया कि यूपीडा ने एनएचएआइ के साथ एमओयू किया है, जिसमें एक्सप्रेस वे भी फास्टैग से लैस होंगे। वे भी एनएचएआइ की तर्ज पर पूरी व्यवस्था को लागू करेंगे।

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे: आठ लेन में 302 किमी लंबा लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे लखनऊ से आगरा के बीच नौ जिलों को जोड़ता है। यमुना एक्सप्रेस वे छह लेन में 165 किमी लंबे मार्ग आगरा को नोएडा से जोड़ता है।

छग फर्जी मुठभेड़ पर गर्माया माहौल, आदिवासी लामबंद

नईदुनिया, जगदलपुर

▶ मानवाधिकार कार्यकर्ता पहुंचे सारकेगुड़ा, आज कराएंगे एफआइआर

▶ अगर पुलिस ने आनाकानी की तो थाने के सामने ही सत्याग्रह किया जाएगा

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला स्थित सारकेगुड़ा में नक्सलियों के नाम पर हुए नरसंहार पर आदिवासी और सामाजिक संगठन लामबंद होने लगे हैं। बड़े आंदोलन की तैयारी के बीच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों की टीम सारकेगुड़ा पहुंच गई है। गुरुवार देर शाम वकीलों ने सारकेगुड़ा के पीड़ितों से चर्चा की और उन्हें थाने में एफआइआर कराने के लिए तैयार किया। शुक्रवार सुबह बासागुड़ा थाने में एफआइआर कराने के लिए आवेदन दिया जाएगा।

दिल्ली से पहुंचे मानवाधिकार कार्यकर्ता हिमांशु कुमार ने दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नईदुनिया से कहा कि इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, आइजी इंटेलिजेंस मुकेश गुप्ता, सीआरपीएफ व पुलिस के अफसरों समेत वारदात में शामिल जवानों के खिलाफ हत्या, साक्ष्य मिटाने और फर्जी आरोप गढ़ने की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया जाएगा।

अगर पुलिस ने एफआइआर करने में आनाकानी की तो थाने के सामने ही सत्याग्रह किया जाएगा। हाई कोर्ट बिलासपुर से पहुंचे वकील किशोर नारायण ने सारकेगुड़ा के ग्रामीणों का बयान लिया और उसके आधार पर एफआइआर की कॉपी तैयार की। इस मामले की लड़ाई लड़ने वाली कमला काका रिपोर्ट दर्ज कराएंगी जबकि अन्य पीड़ित गवाह बनेंगे।

मौके पर आदिवासी नेत्री सोनी सोरी, मानवाधिकार संगठन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) के प्रदेशाध्यक्ष डिग्री प्रसाद चौहान तथा कमल बघेल भी मौजूद हैं। यह टीम सारकेगुड़ा में ही रात गुजारेगी और सुबह थाना कूच करेगी। सारकेगुड़ा मामले में जस्टिस अग्रवाल आयोग की रिपोर्ट को सामाजिक संगठन बड़ी जीत मान रहे हैं।

यह है मामला

28 जून 2012 को बीजापुर व बासागुड़ा से निकले कोबरा बटालियन व सीआरपीएफ जवानों ने सारकेगुड़ा गांव में ग्रामीणों पर गोलियां चलाई जिसमें 17 ग्रामीण मारे गए। मृतकों में आठ स्कूली बच्चे भी शामिल थे। ग्रामीण फर्जी मुठभेड़ की जांच की मांग लेकर मानवाधिकार आयोग तक पहुंचे। तब विपक्ष में रही कांग्रेस ने मुद्दे को आगे बढ़ाया। भाजपा सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया। आयोग की रिपोर्ट में मुठभेड़ को फर्जी बताया गया है। मीडिया में रिपोर्ट लीक होने के बाद बवाल मचा हुआ है। रिपोर्ट विधानसभा में भी पेश की जा चुकी है।

मप्र के रीवा में ट्रक से भिड़ी बस, नौ की मौत

नईदुनिया, रीवा: मध्य प्रदेश के रीवा जिला मुख्यालय से करीब 32 किमी दूर राष्ट्रीय राजमार्ग-39 पर भीषण सड़क हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई और 23 लोग घायल हो गए। हादसा गुरुवार सुबह करीब सवा छह बजे जबलपुर से सिंगरौली जा रही यात्री बस के खड़े ट्रक से टकराने से हुआ। घायलों के मुताबिक, दुर्घटना का कारण चालक को झपकी आना था।

मृतक सीधी और रीवा जिले के हैं। इनमें तीन लोग एक ही परिवार के हैं। हादसे पर मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। रीवा के कमिश्नर डॉ. अशोक भार्गव ने बताया कि चालक का लाइसेंस, बस का परमिट और फिटनेस निरस्त कर दिया गया है। मृतकों के स्वजन को दो-दो लाख, गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार और सामान्य घायलों को 25-25 हजार रुपये की मदद की घोषणा की है।

हिसार में ट्रैक्टर-ट्राली से टकराई कार, चार युवकों की मौत: वहीं, हरियाणा के हिसार में दिल्ली बाईपास रोड पर बहुतकनीकी संस्थान के पास पलटी ट्रैक्टर ट्राली से बुधवार देर रात कार टकरा गई। इससे कार में सवार छह में चार युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। सभी मृतक चरखी दादरी जिले के रहने वाले थे।

छात्र आंदोलन स्थल से हार्दिक पटेल को धक्के मारकर निकाला

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद

▶ गैर सचिवालय कर्मचारी भर्ती परीक्षा रद करने की मांग को लेकर छात्रों के आंदोलन में पहुंचे थे कांग्रेस नेता

गैर सचिवालय कर्मचारी भर्ती परीक्षा रद करने की मांग को लेकर गांधीनगर में आंदोलन कर रहे हजारों छात्रों व सरकार के बीच गतिरोध जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री ने एसआइटी जांच की बात कही है, लेकिन छात्रों ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को नकार दिया है। उधर धरना स्थल पर आंदोलन का समर्थन करने पहुंचे कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को धक्के मारकर छात्रों ने बाहर निकाल दिया।

आंदोलन कर रहे हजारों छात्र बीते दो दिनों से गांधीनगर में जमे हैं। सरकार भर्ती परीक्षा में अनियमितता की एसआइटी जांच कराने को तैयार है, लेकिन छात्रों की मांग है कि परीक्षा रद की जाए और पुनः परीक्षा आयोजित की जाए। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधान सचिव के कैलासनाथन व गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा के साथ चर्चा करने के बाद कहा कि सरकार इस मामले की पारदर्शी तरीके से जांच को तैयार है। सरकार ने एसआइटी के गठन के भी संकेत दिए। इसके बाद हालांकि, छात्र नेता युवराज सिंह ने आंदोलन समेटने के संकेत दिए, लेकिन दूसरे छात्र परीक्षा रद होने तक यहां डटे रहने पर अड़े हुए हैं। गुरुवार दोपहर कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल भी आंदोलन के समर्थन में पहुंचे, लेकिन छात्रों ने उन्हें धक्के मारकर धरना स्थल से बाहर निकाल दिया। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा, वरिष्ठ नेता शंकरसिंह वाघेला व करणी सेना के अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने भी आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की। धरने पर बैठे छात्रों का कहना है कि आंदोलन के नाम पर हम किसी दूसरे को राजनीति नहीं करने देना चाहते हैं। करीब दो सप्ताह से इस मामले को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन तब कोई नेता मदद को नहीं आया। बता दें कि गुजरात सेवा भर्ती मंडल की ओर से गैर सचिवालय कर्मचारियों के तीन हजार पदों के लिए 19 नवंबर को परीक्षा का आयोजन किया गया था। गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा का कहना है कि साबरकांठा, मेहसाणा, गीर सोमनाथ, पालनपुर समेत पांच जिलों में पेपरलीक होने व नकल की शिकायतें मिली हैं।

2014 से रक्षा मंत्रालय ने स्थानीय उद्योगों के साथ 180 करार किए

नई दिल्ली, आइएएनएस : रक्षा मंत्रालय ने 2014 से अब तक लगभग दो लाख करोड़ रुपये के 180 से ज्यादा रक्षा सौदे करार किए हैं। कुछ करार विचाराधीन हैं जिनपर निकट भविष्य में हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह जानकारी गुरुवार को मंत्रालय ने दी।

फरवरी 2015 में मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के साथ प्रोजेक्ट 17ए के तहत युद्ध पोत बनाने का करार हुआ था। यह करार 45 हजार करोड़ रुपये का था। अक्टूबर 2018 में हुए करार के तहत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को प्रोजेक्ट पी1135.6 के तहत दो युद्ध पोत बनाने का करार हुआ था। यह करार लगभग 14 हजार करोड़ रुपये का था।

रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ वायुसेना के लिए 41 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और नौसेना के लिए 32 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बनाने का करार हुआ है। 2017 में हुआ करार लगभग 14 हजार करोड़ रुपये का है। इसके अलावा एचएएल के साथ फरवरी 2015 में हुए करार के तहत 1100 करोड़ रुपये के 14 डोर्नियर 228 विमान खरीदे गए हैं।

अनुशासनहीन छात्रों को मिले सुधरने का मौका : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

अनुशासनहीन छात्रों को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए सुधार व पुनर्वास स्कीम लागू करने की जरूरत है। यह कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। कोर्ट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को आदेश दिया है कि वह अनुशासनहीनता के आरोपित छात्रों के विकास, सुधार व पुनर्वास की स्कीम लागू करें। जिससे छात्रों पर अनुशासनिक कार्रवाई करने से पहले उन्हें सुधरने का अवसर मिल सके।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने छात्र अनंत नारायण मिश्र की याचिका पर दिया है। याचिका में कुलसचिव बीएचयू वाराणसी के 30 मार्च 2019 के आदेश को चुनौती दी गई है। इसके तहत आरोपित छात्रों के विशेषाधिकार व परिसर के भीतर के क्रियाकलापों पर रोक लगा दी गई है। आदेश में कहा गया है कि मामले में लंका थाना में दर्ज शिकायत पर इनके दोषमुक्त होने तक ये निलंबित रखे जाएंगे। गौरतलब है कि 28 जनवरी 2019 को बीएचयू के एक प्रोफेसर कक्षा में जा रहे थे, तभी उन पर हमला कर जातिसूचक टिप्पणी की गयी। इसको लेकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आरोपित छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कोर्ट ने सुनवाई के साथ आरोपित छात्रों को कोर्स पूरा करने की अनुमति देने का निर्देश दिया है।

विभिन्न पहलुओं पर किया विचार

हाई कोर्ट ने इस मामले में विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त मूल अधिकारों, मानवाधिकारों, छात्रों व समाजहित को दृष्टिगत रखकर कहा कि विश्वविद्यालय ऐसी कार्ययोजना तैयार करे, जिससे छात्रों को सुधरने मौका मिले।

छह माह में लागू हो स्कीम

हाई कोर्ट ने सुधार व पुनर्वास स्कीम को छह माह व अधिकतम एक साल में लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस कार्य में जरूरी सुविधाएं देने का निर्देश दिया है।

500 ग्राम दूध 63 बच्चों को पिलाने के मामले में प्रधानाध्यापक निलंबित

जागरण संवाददाता, जौनपुर : उप्र के मछलीशहर ब्लाक के अइलहा प्राथमिक विद्यालय में पाउडर वाला 500 सौ ग्राम दूध 63 बच्चों को पिलाने के मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापक बांकेलाल पांडेय को निलंबित कर दिया और खंड शिक्षा अधिकारी शैलपति यादव को प्रतिकूल प्रविष्टि दी। बुधवार को जागरण पड़ताल में मामला उजागर होने पर गुरुवार सुबह निरीक्षण करने पहुंचे बीएसए राजेंद्र प्रसाद ने यह कार्रवाई की। उन्होंने एबीएसए को निर्देशित किया कि वह विद्यालयों में जाकर एमडीएम की गुणवत्ता जरूर परखें। इस दौरान प्रधानाध्यापक दूसरे दिन भी विद्यालय से गैरहाजिर मिले। एबीएसए भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए। बीएसए ने प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया। खंड शिक्षा अधिकारी शैलपति यादव को प्रतिकूल प्रविष्टि दी।

गाजीपुर में एमडीएम दूध पीकर पांच बच्चे बीमार: उप्र स्थित गाजीपुर के प्राथमिक विद्यालय प्रथम में बुधवार को मिड-डे-मील में खिचड़ी व दूध पीने वाले कक्षा एक के पांच बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। एक-एक कर अभिभावक बच्चों को लेकर निजी चिकित्सकों के यहां पहुंचे तो मिड-डे-मील में गड़बड़ी का पता चला।

विधेयक का विरोध

नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में गुरुवार को असम के गुवाहाटी में कृषक मुक्ति संग्राम समिति के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को ही मंजूरी दी थी। प्रेट्र

अब किसी भी जहाज की तलाशी व जब्ती कर सकेगा तटरक्षक बल

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय तटरक्षक बल अब और ताकतवर हो गया है। तटरक्षक कानून के तहत अब वह देश के समुद्री क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध जहाज की तलाशी व जब्ती तथा आरोपित की गिरफ्तारी कर सकेगा। समुद्री सुरक्षा एजेंसी को पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से गुजरने वाले किसी भी जहाज पर सवार होने की भी अनुमति नहीं थी। रक्षा सचिव अजय कुमार ने गुरुवार को ट्वीट किया, 'भारतीय तटरक्षक को सशक्त बनाते हुए तटीय सुरक्षा बढ़ाई गई है।' रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, तटरक्षक कानून-1978 के तहत केंद्र सरकार तटरक्षक बल के हर सदस्य को किसी भी संदिग्ध जहाज पर जाने, उस पर सवार होने, उसकी तलाशी लेने और उसे जब्त करने या किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। तटरक्षक बल के जवान ऐसे किसी भी कृत्रिम द्वीप या तैरती वस्तु या जल के नीचे किसी भी चीज को जब्त कर सकेंगे, जिनके किसी अपराध में शामिल होने का संदेह हो। इससे पहले तटरक्षक बल ईईजेड में जहाजों पर सवार होने या उन्हें जब्त करने के लिए सीमा शुल्क कानून, एनडीपीएस कानून और अन्य कानूनों का इस्तेमाल करता था। अधिकारियों ने बताया कि इसे जरूरी कानूनी समर्थन नहीं प्राप्त था और कई मामले कोर्ट में ही गिर जाते थे। जहाज कंपनियों के पास कानून से बचने के कई रास्ते थे। वे बिना किसी अधिकार के जहाज को रोकने पर तटरक्षक बल के खिलाफ मामला दर्ज करा सकती थीं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि समुद्री सुरक्षा बल वर्ष 2009 से ही क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय शेल्फ (तटों के निकट अपेक्षाकृत संकरी व उथली सागरीय पेटी), विशेष आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम-1976 के तहत ज्यादा अधिकार दिए जाने की मांग कर रहा था।

उप्र के प्रयागराज में अखाड़ा परिषद ने किया कच्चे-पक्के मकानों पर सेना की कार्रवाई का विरोध

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

संगम से लगे परेड मैदान में सेना की ओर से चलाई जा रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने नाराजगी जताई है। परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने कहा है कि इस मामले में रक्षामंत्री से मुलाकात की जाएगी। इससे पहले 10 दिसंबर को हरिद्वार में होने वाली बैठक में इस मसले पर चर्चा होगी। जरूरत पर संत महात्मा संगम पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पिछले कुछ समय से संगम से लगे परेड मैदान में विभिन्न कच्चे-पक्के निर्माण ध्वस्त किए जा रहे हैं। संत समाज इस कार्रवाई का विरोध कर रहा है। अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी इसमें आगे आया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि का सवाल है कि यदि संगम क्षेत्र में तीर्थ पुरोहित, साधु संन्यासी नहीं रहेंगे, प्राचीन मठ मंदिर नहीं रहेंगे तो वहां तीर्थ यात्रियों की सेवा कैसे हो सकेगी। उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर को हरिद्वार में होने वाली बैठक में इस कार्रवाई के विरोध में प्रस्ताव पारित कर संत महात्मा, रक्षामंत्री से मिलेंगे। फिर भी यदि सेना की कार्रवाई बंद नहीं हुई तो संत महात्मा संगम पर विरोध जताएंगे।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!
शाखा: जी.टी. रोड, निकट घंटा घर, गाजियाबाद
कब्जा सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 की नियम 8 (1) के साथ पठित प्रतिभूतिकरण एक्ट, 2002 की धारा 13 (4) के अंतर्गत (अचल संपत्ति हेतु)
पंजाब नेशनल बैंक, शाखा: जी.टी. रोड, निकट घंटा घर, गाजियाबाद के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'उक्त एक्ट' के रूप में ज्ञात) के अंतर्गत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (इसके बाद उक्त नियमावली के रूप में ज्ञात) की नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल में कर्जदार/गारंटर (1) श्री अनिल कुमार सोलंकी पुत्र श्री विशन सिंह सोलंकी, (2) श्रीमती संध्या सोलंकी पत्नी श्री अनिल कुमार सोलंकी, पता: ए-002, ऋषभ प्लेटिनम, माल रोड, अहिंसा खंड-2, इंदिरापुरम, गाजियाबाद (उ.प्र.), मार्फत इर्नी एग्रो फूड्स, प्लाट नं. 4, आनंद इंडस्ट्रियल एरिया, मोहन नगर, गाजियाबाद, उ.प्र. ऋण खाता सं. 522100NC00014099 को दिनांक 18.01.2019 को मांग सूचना जारी किया जिसमें कहा गया कि भावी ब्याज, उस पर लागत एवं खर्चे के साथ दिनांक 30.09.2019 को बकाया राशि सूचना में वर्णित रु. 61,10,316/- (रुपये एकसठ लाख दस हजार तीन सौ सोलह मात्र) का भुगतान करें।
कर्जदार/गारंटर/जमानतदाता उक्त सूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर राशि का भुगतान करने में विफल रहे एवं एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटर/जमानतदाता एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 02.12.2019 को उक्त नियमावली की नियम 9 के साथ पठित उपरोक्त एक्ट की धारा 13(4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल में नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।
जनसाधारण को एवं विशेषकर कर्जदार/गारंटर/जमानतदाता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि इस प्रापर्टी की कोई डीलिंग (लेनदेन) नहीं करें एवं 30.09.2019 को बकाया ऋण राशि रु. 61,10,316/- (रुपये एकसठ लाख दस हजार तीन सौ सोलह मात्र) एवं उस पर ब्याज, लागत एवं खर्चे के साथ राशि की डीलिंग पंजाब नेशनल बैंक, शाखा: जी.टी. रोड, निकट घंटा घर, गाजियाबाद के प्रभार में होगी।
अचल संपत्ति का विवरण
आवासीय फ्लैट नं. ए-002 की ईएम, ऋषभ प्लेटिनम, माल रोड, अहिंसा खंड-2, इंदिरापुरम, गाजियाबाद (उ.प्र.)
दिनांक: 02.12.2019, स्थान: गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!
शाखा: जी.टी. रोड, निकट घंटा घर, गाजियाबाद
कब्जा सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 की नियम 8 (1) के साथ पठित प्रतिभूतिकरण एक्ट, 2002 की धारा 13 (4) के अंतर्गत (अचल संपत्ति हेतु)
पंजाब नेशनल बैंक, शाखा: जी.टी. रोड, निकट घंटा घर, गाजियाबाद के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'उक्त एक्ट' के रूप में ज्ञात) के अंतर्गत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (इसके बाद उक्त नियमावली के रूप में ज्ञात) की नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल में कर्जदार/गारंटर (1) श्री मुकेश यादव, (2) श्री नरेश यादव पुत्र श्री त्रिलोक यादव, (3) गनेश कुमार यादव, (4) श्री मंगल यादव, पता: म.सं. 135 ब्लॉक जी, सेक्टर-20, नोएडा, जी.बी. नगर 201301 उ.प्र. ऋण खाता सं. 522100NC00011579 को दिनांक 22.11.2018 को मांग सूचना जारी किया जिसमें कहा गया कि भावी ब्याज, उस पर लागत एवं खर्चे के साथ दिनांक 22.11.2019 को बकाया राशि सूचना में वर्णित रु. 24,61,000/- (रुपये चौबीस लाख एकसठ हजार मात्र) का भुगतान करें।
कर्जदार/गारंटर/जमानतदाता उक्त सूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर राशि का भुगतान करने में विफल रहे एवं एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटर/जमानतदाता एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 02.12.2019 को उक्त नियमावली की नियम 9 के साथ पठित उपरोक्त एक्ट की धारा 13(4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल में नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।
जनसाधारण को एवं विशेषकर कर्जदार/गारंटर/जमानतदाता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि इस प्रापर्टी की कोई डीलिंग (लेनदेन) नहीं करें एवं 22.11.2019 को बकाया ऋण राशि रु. 24,61,000/- (रुपये चौबीस लाख एकसठ हजार मात्र) एवं उस पर ब्याज, लागत एवं खर्चे के साथ राशि की डीलिंग पंजाब नेशनल बैंक, शाखा: जी.टी. रोड, निकट घंटा घर, गाजियाबाद के प्रभार में होगी।
अचल संपत्ति का विवरण
ईडब्ल्यूएस हाउस नं. 135, ब्लॉक जी, सेक्टर-20, नोएडा, जी.बी. नगर
दिनांक: 02.12.2019, स्थान: गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

बढ़ा विवाद

कहा था, गुजराल की सलाह मानते नरसिम्हा राव तो नहीं होते दंगे, शिअद, भाजपा और राव के पौत्र ने राजीव गांधी पर उठाई अंगुली

सिख विरोधी दंगे पर बयान देकर घिरे मनमोहन

नई दिल्ली, एएनआइ : 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए तत्कालीन गृह मंत्री नरसिम्हा राव को जिम्मेदार ठहराकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह चौतरफा घिर गए हैं। शिरोमणी अकाली दल (शिअद) और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने दंगों के लिए सीधे-सीधे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दोषी ठहराया। वहीं, राव के पौत्र और भाजपा नेता एनवी सुभाष ने सवाल किया कि क्या कोई गृह मंत्री कैबिनेट मंजूरी के बिना फैसला ले सकता है।

पूर्व प्रधानमंत्री गुजराल की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मनमोहन सिंह ने कहा था, 'जब 1984 की दुखद घटना (तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या) हुई थी तो उसी शाम गुजराल जी तत्कालीन गृह मंत्री नरसिम्हा राव के पास गए और उनसे कहा कि हालात इस कदर खराब हैं कि सरकार को जल्द से जल्द सेना बुलाना जरूरी है। अगर उस सलाह पर ध्यान दिया गया होता तो 1984 में जो कत्लेआम हुआ उसे रोका जा सकता था।' शिरोमणि अकाली दल (शिअद) विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने मनमोहन के बयान को सनसनीखेज बताते हुए कहा, वे (शिअद) पिछले 35 साल से यही कह रहे हैं कि यह कत्लेआम किसी और द्वारा नहीं, बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा प्रायोजित था। उन्होंने कहा, 'मनमोहन सिंह के बयान से बिल्कुल साफ है कि

मनमोहन सिंह। फाइल

तत्कालीन प्रधानमंत्री ने नरसिम्हाराव को सेना नहीं बुलाने के निर्देश दिए थे और तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा नीचे तक संदेश दिया गया था कि कत्लेआम के हमलावरों और गुंडों को संरक्षण दिया जाए।' उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से पूरे मामले की जांच कराने का अनुरोध किया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा, 'मनमोहन सिंह जी, किसी समस्या से निपटने के लिए सेना को आदेश देना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। सच यह है कि राजीव गांधी ने खुलेआम कत्लेआम का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती में कंपन्न होता ही है। उनके ये शब्द समर्थन करने वाले ही थे।' नरसिम्हा राव के पौत्र और भाजपा नेता एनवी सुभाष ने सवाल किया कि क्या कोई गृह मंत्री कैबिनेट की मंजूरी के बिना स्वतंत्र रूप से फैसला ले सकता है। उन्होंने कहा कि अगर सेना बुला ली गई होती तो अनर्थ हो जाता।

दंगे के दोषी कांग्रेस और गांधी परिवार, माफी मांगें : हरसिमरत

नईदुनिया, देवास : 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के बयान पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल भड़क उठीं। उन्होंने कहा कि इस कत्लेआम के लिए कांग्रेस और गांधी परिवार ही दोषी हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हरसिमरत कौर गुरुवार को मप्र के देवास जिले के बिंजाना में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन करने आई थीं। उन्होंने कहा कि 1984 का कत्लेआम कांग्रेस पर काला दाग है, जो कभी नहीं धुलेगा। लगातार तीन दिन तक पास ही मौजूद आर्मी की मदद नहीं ली गई। सिखों को मरने दिया गया। आज भी दोषी लोगों को बचाकर मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया है। बादल ने कहा कि गांधी परिवार और कांग्रेस को इस पर माफी मांगना चाहिए।

दैनिक जागरण

प्रार्थना ईश्वर से जोड़ने वाली कड़ी है

आर्थिक सुस्ती का उपचार

रिजर्व बैंक ने ब्याज दर घटाने के सिलसिले पर विराम लगाते हुए जिस तरह चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान घटाया उससे यही संकेत मिल रहा है कि आर्थिक सुस्ती दूर करने में कठिनाई आ रही है। शायद यही कारण है कि अर्थव्यवस्था की सेहत को लेकर संसद के भीतर और बाहर चिंता जताने का सिलसिला तेज हो रहा है। इसे देखते हुए सरकार को ऐसे और कदम उठाने के लिए आगे आना चाहिए जिससे आर्थिक सुस्ती टूटे। ऐसा करते हुए उसे यह भी देखना होगा कि उसकी ओर से आर्थिक सुस्ती को दूर करने के लिए अभी तक जो कदम उठाए गए हैं वे जमीन पर प्रभावी साबित हो रहे हैं या नहीं? इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बीते दो माह में सरकार की ओर से छोटे-बड़े करीब दो दर्जन कदम उठाए जा चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा कदम कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का था। यह सही है कि इन कदमों का असर दिखने में समय लगेगा, लेकिन इसका आकलन तो किया ही जाना चाहिए कि हालात बदल रहे हैं या नहीं? ऐसा आकलन इसलिए किया जाना चाहिए, क्योंकि उद्योग-व्यापार जगत के लोग अभी भी उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। वे तरह-तरह की शिकायतों से लैस दिखते हैं। जब किसी भी क्षेत्र के लोगों के शिकायती स्वर बढ़ जाते हैं तब यही माहौल बनता है कि कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा है। कई बार यह माहौल यथार्थ से भिन्न होता है, लेकिन वह उसे ढकने का काम करता है।

बेहतर हो कि सरकार उद्योग-व्यापार जगत को भरोसे में लेने के कदम उठाते समय यह ध्यान रखे कि भरोसे की बहाली तभी होगी जब कारोबारियों की चिंताओं और आशंकाओं को सचमुच दूर किया जाएगा। इससे इन्कार नहीं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार यह भरोसा दिला रही हैं कि आर्थिक सुस्ती दूर करने के लिए जो कुछ भी संभव है वह सब किया जाएगा, लेकिन तथ्य यही है कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बाद से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है जिसे क्रांतिकारी या फिर तात्कालिक असर वाला कहा जा सके। उचित यह होगा कि सरकार दीर्घकालिक असर वाले कदमों के साथ तात्कालिक प्रभाव वाले कदम भी उठाए। इसी क्रम में सरकार को यह भी देखना होगा कि उद्योग-व्यापार जगत की जीएसटी संबंधी परेशानियां अनिवार्य रूप से दूर हों। इसका कोई औचित्य नहीं कि इस टैक्स व्यवस्था की जटिलताएं अभी भी उद्योग-व्यापार जगत को परेशान करें। निःसंदेह यह भी समय की मांग है कि सरकार श्रम कानूनों में बदलाव की दिशा में आगे बढ़े। इसी के साथ उद्योग जगत को भी यह समझना होगा कि उसे प्रतिस्पर्द्धी बनने की जरूरत है।

नए नशे का जाल

पिछले कुछ वर्षों से बंगाल में अचानक नए-नए मादक पदार्थों की बरामदगी और इस कारोबार से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी यह बताने को काफी है कि इस नए नशे का जाल काफी फैल हो चुका है। इस समय लगभग हर सप्ताह ही याबा नामक मादक पदार्थ जब्त हो रहा है। आखिर याबा है क्या? यह देखने में गुलाबी रंग की गोली है। जिसका असली नाम मेथेम्फेटामाइन-कैफीन है। याबा गोली का धंधा बंगाल में इतना फलफूल रहा है कि पिछले एक वर्ष में कई करोड़ याबा गोलियां पकड़ी जा चुकी हैं। अभी कोलकाता के हेस्टिंग्स थाना क्षेत्र के बेकरी रोड से पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने एक लाख से अधिक याबा टैबलेट के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया था। जिनके नाम टिंकू शेख और शेख जमाल हुसैन हैं। दोनों ही मुर्शिदाबाद के रहनेवाले हैं। इसके कुछ दिनों पहले ही लाखों याबा टैबलेट के साथ एसटीएफ अधिकारियों ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया था। असल में याबा को थाई भाषा में पागलपन की दवा कहा जाता है। कहा जा रहा है कि याबा टैबलेट म्यांमार, चीन से बांग्लादेश के रास्ते भारत और खासकर पश्चिम बंगाल में पहुंच रहा है। याबा टैबलेट अक्सर ही गुलाबी या फिर मैरून रंग का होता है तथा इसके कवर पर डब्ल्यूवाई अक्षर लिखे होते हैं। याबा थाईलैंड में सबसे खराब श्रेणी का मादक पदार्थ है। जो लोग इसका इस्तेमाल से लेकर धंधा करते हैं वहां इस जुर्म के लिए उम्रकैद से लेकर मौत तक की सजा दी जाती है। कहा जा रहा है कि असल में इस नशे की गोली को घोड़ों को पहाड़ी क्षेत्रों की चढ़ाई अथवा भारी कामों के दौरान दिया जाता था, परंतु अब इसे इंसान भी इस्तेमाल करने लगे हैं। इसका सेवन कई तरीकों से किया जा रहा है। एक है याबा टैबलेट को एल्युमीनियम पेपर (सिगरेट वाले रैपर) पर रखकर इसे नीचे से गर्म कर उसके भाप को सुंघा जाता है। या फिर गोलियों को निगला जाता है। इस गोली का इस्तेमाल स्कूल, कॉलेजों के छात्र से लेकर रेब पार्टी में हो रहा है। यह बहुत ही खतरनाक नशा है। इस नए नशे के जाल को पूरी तरह से खत्म करना होगा नहीं तो हमारे देश का भविष्य बर्बाद कर सकता है।

अभी कोलकाता के हेस्टिंग्स थाना क्षेत्र के बेकरी रोड से पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने एक लाख से अधिक याबा टैबलेट के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया था

कांग्रेस को दिशा देने वाला फैसला

रशीद किदवई

अगर सोनिया की जगह राहुल गांधी होते तो शिवसेना के साथ गठबंधन का निर्णय नहीं हो पाता और महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक इधर-उधर भाग जाते

कांग्रेस के इतिहास में 28 नवंबर, 2019 का दिन बहुत अहम बन गया है। इस दिन कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा बन गई। हालांकि मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया एवं राहुल गांधी शामिल नहीं हुए, लेकिन अहमद पटेल, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, कमलनाथ जैसे प्रमुख नेता अगली पंक्ति में बैठे नजर आए। कांग्रेस द्वारा शिवसेना को समर्थन देने का निर्णय आसान नहीं था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एके एंटनी, मनमोहन सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित ज्यादातर नेता स्वाभाविक ही शिवसेना से किसी भी तरह के गठबंधन के खिलाफ थे, लेकिन कमलनाथ ने याद दिलाया कि 1979-80 में जब कांग्रेस सत्ता से वंचित हो चुकी थी तब पार्टी ने एक व्यावहारिक निर्णय करते हुए अपने धुर विरोधी बालासाहब ठाकरे की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। बालासाहब ने न सिर्फ आपातकाल का समर्थन किया, बल्कि 'नसबंदी' को लेकर संजय गांधी के जुनून की प्रशंसा भी की थी। कांग्रेस में इस पर भी मंथन हुआ कि शिवसेना शुरू से ही उग्र राष्ट्रवाद की झंडाबरदार रही है, लेकिन वह जनसंघ, बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद की तरह आरएसएस का आनुषंगिक संगठन नहीं है।

कमलनाथ के प्रयासों को तब बल मिला जब महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेता जैसे पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण और बालासाहब थोराट ने कांग्रेस के कई जमीनी मुस्लिम कार्यकर्ताओं की सोनिया से बातचीत कराई। वे सब शिवसेना के साथ गठबंधन के पक्ष में थे। यह देख शिवसेना से गठबंधन का विरोध कर रहे भूपेश बघेल, जयराम रमेश और अहमद पटेल के सुर नरम पड़े और यह तय हुआ कि शिवसेना के साथ कांग्रेस का गठबंधन केवल न्यूनतम साझा कार्यक्रम की हद तक सीमित रहेगा और उद्धव ठाकरे सरकार इस पर अडिग रहेगी। इसके साथ ही तय हुआ कि सरकार में शामिल कांग्रेस, शिवसेना एवं शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा अपनी राजनीतिक विचारधारा पर कायम रहकर स्वतंत्र रूप से कार्य करती रहेंगी। राजनीतिक रूप से देखें तो सोनिया ने इस तरह एक तीर से कई निशाने साध लिए। भाजपा वैचारिक रूप से कांग्रेस की दुविधा और पवार की बार-बार रंग बदलने वाली प्रकृति पर तीखे हमले करती रही, लेकिन इसके बावजूद सोनिया गांधी ने लक्ष्य पर नजरें जमाए रखीं और हर पक्ष से चर्चा की। उदार वामपंथी इसके विरुद्ध दबाव बनाते रहे, जबकि गठबंधन समर्थक इस बाबत शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता बताते रहे। आखिरकार सोनिया की चिर परिचित ज्यादा-से-ज्यादा विचार-विमर्श की शैली काम आई और सारे लोग एक छत के नीचे जमा हो गए। सोनिया की यह कार्यशैली निश्चित ही राहुल गांधी के लिए महत्वपूर्ण सबक है।

अवधेश राजपूत

कांग्रेस के भीतर इस पर सभी एकमत हैं कि अगर सोनिया की जगह राहुल होते तो शिवसेना के साथ गठबंधन का यह निर्णय नहीं हो पाता और महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक इधर-उधर भाग जाते। आम धारणा के विपरीत कांग्रेस खुद को एक हिंदू समर्थक पार्टी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करती रही है। 1980 में इंदिरा गांधी को जब दोबारा सत्ता हासिल हुई तो उन्होंने विश्व हिंदू परिषद की 'एकात्मता यात्रा' का निमंत्रण स्वीकार कर बहुसंख्यक समुदाय में पैर जमाने के जतन किए। नौकरशाह एसएस गिल ने महसूस किया कि 1980 के बाद इंदिरा ने मुसलमानों की अनदेखी शुरू कर दी थी। अपनी किताब 'द डायनास्टी-अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ द प्रीमियर रूलिंग फैमिली ऑफ मॉडर्न इंडिया' में वह लिखते हैं कि कैसे इंदिरा के विश्वासपात्र सीएम स्टीफन ने 1983 में यह घोषणा की कि 'हिंदू संस्कृति एवं कांग्रेस संस्कृति की धारा एक ही है।' अपनी हत्या से कोई छह माह पहले इंदिरा गांधी ने बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को विश्वास दिलाने के लिए कहा था कि 'अगर उनके साथ कोई अन्याय होता है या उन्हें अपने अधिकार नहीं मिलते हैं तो यह देश की अखंडता के लिए घातक होगा।' तब कांग्रेस के विचारक वीएन गाडगिल कहते थे कि 'मुसलमानों के वोट महज 18 प्रतिशत हैं। अगर वे सभी मिलकर कांग्रेस को वोट दे दें तो भी पार्टी सत्ता हासिल नहीं कर सकती। इसीलिए हम बाकी 82 प्रतिशत लोगों की भावनाओं को अनदेखा नहीं कर सकते।'

16 जनवरी, 1999 को सोनिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकारिणी ने धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा संबंधी जो प्रस्ताव पारित किया उसके मुताबिक 'भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि यहां के हिंदू धर्मनिरपेक्ष हैं।' 1989 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने अयोध्या जाकर सरयू के तट से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए रामराज्य लाने का वादा किया था। वैचारिक एवं ऐतिहासिक रूप से इस पुरानी पार्टी ने राष्ट्र के नेतृत्व को अपना 'कर्तव्य' मान रखा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के मात्र एक साल बाद 1948 में हुए कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में ही पट्टाभि सीतारमैया ने अपने कार्यकर्ताओं को यह 'कर्तव्य' समझाया था। इसमें उन्होंने कांग्रेस एवं उसकी विचारधारा को पूरे देश की विचारधारा बताते हुए आग्रह किया था कि इस बाबत आमजन का समर्थन जुटाना चाहिए, जिससे कांग्रेस और सरकार अच्छे से काम कर सके, लेकिन राष्ट्र नेतृत्व के इस 'कर्तव्य' निर्वहन का चित्र 1998 में तब बदलने लगा जब सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने राजनीतिक साझेदारी के लिए औपचारिक रूप से सहमति प्रदान कर दी। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्तावों में इसे नकारा जाता रहा कि एक पार्टी की सत्ता के दिन लद गए।

पचमढ़ी चिंतन शिविर में कांग्रेस का आग्रह था कि वैचारिक, नीतिगत और राष्ट्र निर्माण के मामलों में पार्टी को क्षेत्रीय पार्टियों पर वरीयता प्राप्त है, जो स्थानीय जाति एवं भाषा आधारित मुद्दों से आगे नहीं निकल पातीं, लेकिन जुलाई 2003 में कांग्रेस के शिमला अधिवेशन में सोनिया ने पार्टी को राजद जैसी अपेक्षाकृत छोटी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे के लिए तैयार किया। 14 सूत्रीय 'शिमला संकल्प' में कहा गया कि भाजपा के नेतृत्व वाले राजग का सामना करने के लिए धर्मनिरपेक्ष ताकतों को भी आपस में गठबंधन कर लेना चाहिए। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली मिली-जुली सरकार के लिए जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय किया गया है उसके लिखित अंग्रेजी प्रारूप में 'सेक्युलर' शब्द कई जगह मिलता है, लेकिन हिंदी एवं मराठी प्रारूप में कहीं भी धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं की गई है। ऐसे में महा विकास अघाड़ी की यह सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम से चिपकी भी रही तब भी आगे कई ऐसे मुद्दे आने वाले हैं जिन पर वैचारिक रूप से मतभेद हो सकते हैं। जैसे एनआरसी या राम मंदिर निर्माण का मसला। अघाड़ी के ये तीनों दल इनसे कैसे निपटते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में विजिटिंग फैलो हैं)

response@jagran.com

नाकाम नीतियों का नतीजा महंगा प्याज

चौधरी पुष्पेंद्र सिंह

आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमने जिस प्याज का निर्यात किया उसी को अब महंगे दामों पर आयात करने के लिए मजबूर हैं?

कई शहरों में प्याज की खुदरा कीमतें अब सौ रुपये प्रति किलो के पार चली गई हैं। सरकार ने प्याज की जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों पर छापेमारी के अलावा, प्याज के थोक व्यापारियों की भंडारण सीमा 500 से घटाकर 250 क्विंटल और खुदरा विक्रेताओं की सीमा 100 से घटाकर 50 क्विंटल कर दी है। केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों को काबू करने के लिए 1.2 लाख टन प्याज दूसरे देशों से आयात करने का निर्णय लिया है। इसमें से मिस्र, तुर्की आदि देशों से कुल 21,000 टन प्याज आयात के सौदे किए जा चुके हैं, पर देश की लगभग 60,000 टन प्रतिदिन की मांग के सापेक्ष यह बहुत कम है और फिर इस प्याज के देश में पहुंचने में भी करीब एक माह का समय लगेगा। प्याज की कम अवाक और विलंबित आयात के कारण ही प्याज के दाम फिर बढ़ने शुरू हुए हैं।

सरकार ने कीमतें काबू करने के लिए सबसे पहले जून में प्याज निर्यातकों को दी जा रही 10 प्रतिशत सब्सिडी खत्म की। फिर सितंबर में प्याज के निर्यात पर 850 डॉलर प्रति टन (लगभग 60 रुपये प्रति किलो) का न्यूनतम निर्यात मूल्य लगा दिया। इसके बाद भी जब कीमतें काबू में नहीं आईं तो प्याज के थोक व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक लिमिट तय कर दी गई। प्याज के निर्यात को भी पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया। इन कदमों से कीमतों में कुछ कमी तो आई पर असमय अत्यधिक बारिश के कारण महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में प्याज और अन्य सब्जियों की फसल को काफी नुकसान हुआ जिसके चलते अक्टूबर-नवंबर में खरीफ की प्याज, टमाटर और अन्य सब्जियों की आवक आशा के अनुरूप नहीं हुई। इससे कीमतें फिर आसमान छूने लगीं। प्याज उत्पादक राज्यों में पहले तो देरी से आए मानसून और फिर अत्यधिक बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। वहीं प्याज का रकबा भी पिछले साल के लगभग तीन लाख हेक्टेयर के मुकाबले इस साल लगभग 2.60 लाख हेक्टेयर रह गया। खरीफ के प्याज का उत्पादन भी पिछले साल के 70 लाख टन के मुकाबले 52 लाख टन रहने का अनुमान है। देश में सबसे ज्यादा, लगभग एक-तिहाई प्याज उत्पादन करने वाले महाराष्ट्र में नवंबर में प्याज की आवक पिछले साल के 41 लाख टन के मुकाबले घटकर 24 लाख टन रह गई। इस कारण अब प्याज की कीमतें जनवरी में ही कुछ कम हो पाएंगी।

आखिर तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार प्याज, टमाटर, आलू और अन्य सब्जियों की कीमतों को नियंत्रित रखने, उपभोक्ताओं और किसानों के हितों की रक्षा करने में बार-बार नाकाम क्यों होती है? 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के मोदी सरकार के लक्ष्य में बागवानी फसलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट में कई योजनाएं शुरू की हैं। सब्जियों में मात्रा के लिहाज से आधा उत्पादन आलू, प्याज और टमाटर का ही होता है।

एक तथ्य यह भी है कि आलू, प्याज और टमाटर, इन तीनों फसलों का देश की घरेलू मांग से ज्यादा उत्पादन हो रहा है और हम इन फसलों के निर्यात की स्थिति में हैं। गत वर्ष प्याज का 22 लाख टन निर्यात कर हम विश्व के सबसे बड़े प्याज निर्यातक थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब उसी प्याज को देश महंगे दामों पर आयात करने के लिए मजबूर हैं। आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में स्थायित्व हेतु सरकार ने पिछले साल 500 करोड़ रुपये की ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप (टोमैटो, अनियन, पोटैटो) योजना शुरू की थी। इसका मूल उद्देश्य एक तरफ उपभोक्ताओं को इन सब्जियों की उचित मूल्य पर साल भर आपूर्ति सुनिश्चित करना और दूसरी तरफ किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना था, लेकिन सरकार को कुछ और कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तो इन फसलों की उचित मात्रा में खरीद, भंडारण एवं वितरण हेतु शीतगृहों और अन्य आधारभूत संरचना का इंतजाम करना होगा। हमारे देश में लगभग 8000 शीतगृह हैं, पर इनमें से 90 प्रतिशत में आलू का ही भंडारण किया जाता है। यही कारण है कि आलू की कीमतों में कभी भी अप्रत्याशित उछाल नहीं आती। प्याज के भंडारण को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि किसानों और उपभोक्ताओं, दोनों के हितों को संरक्षित किया जा सके। केंद्र सरकार ने इस साल प्याज का 57,000 टन का बफर स्टॉक बनाया था, पर यह देश की केवल एक दिन की मांग के बराबर ही था। हमें प्याज का कम से कम 10 लाख टन का बफर बनाना होगा। इन तीनों सब्जियों का बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण करने हेतु उद्योग लगाने होंगे। अभी आलू की फसल का केवल 7 प्रतिशत, प्याज का 3 प्रतिशत और टमाटर का मात्र 1 प्रतिशत प्रसंस्करण हो पा रहा है। इनके मूल्यों को स्थिर रखने, ऑफ-सीजन में उपलब्धता सुनिश्चित करने और निर्यात बढ़ाने के लिए इन फसलों का कम से कम 20 प्रतिशत प्रसंस्करण का लक्ष्य होना चाहिए। इसे प्रोत्साहित करने के लिए जीएसटी भी कम करना चाहिए। साथ ही घरेलू मांग से ज्यादा उत्पादन की सूरत में हमें निर्यातक देश के रूप में भी स्थापित होना होगा। अभी इन फसलों का लगभग 5500 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात हो पा रहा है, जिसे तीन-चार गुना बढ़ाने की दरकार है। इसके लिए भंडारण और प्रसंस्करण नीति दुरुस्त करनी होगी।

बार-बार न्यूनतम निर्यात मूल्य या स्टॉक लिमिट लगाने से व्यापारी भंडारण, प्रसंस्करण और निर्यात की व्यवस्था में निवेश करने से पीछे हट जाते हैं। स्पष्ट है कि स्थिर सरकारी नीतियां बनाने और आवश्यक वस्तु अधिनियम में सुधार की जरूरत है। नाबार्ड के एक अध्ययन के अनुसार आलू, प्याज, टमाटर के उपभोक्ता द्वारा चुकाए मूल्य का 25-30 प्रतिशत ही किसानों तक पहुंच पाता है। हमें इन फसलों में अमूल मॉडल को लागू करना होगा। इसमें दूध के उपभोक्ता-मूल्य का 75-80 प्रतिशत किसानों को मिलता है। सरकार को कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम में सुधार कर बिचौलियों की भूमिका सीमित करनी होगी। इन तीनों फसलों को एमएसपी के तहत लाकर इनकी उचित खरीद, भंडारण और प्रसंस्करण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि किसान को फसल फेंकने की नौबत न आए और लोगों की जेब भी न कटे।

(लेखक किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

ईश्वर का विधान

हम सभी परमपिता परमात्मा के पुत्र हैं। वे हम सभी पुत्रों को समान रूप से चाहते हैं, पर वह जिन्हें योग्य, विश्वसनीय और ईमानदार समझते हैं, उन्हें अपनी राजशक्ति का कुछ अंश इसलिए सौंप देते हैं कि वे उसके ईश्वरीय उद्देश्यों की पूर्ति में हाथ बटाएं। धन, बुद्धि, स्वास्थ्य, शिल्प, चतुरता, मनोबल, नेतृत्व आदि शक्तियां जिन्हें अधिक मात्रा में दी गई हैं वे अधिकार नगराधिकारी को देकर राजा कोई पक्षपात नहीं करता, बल्कि अधिकार योग्य व्यक्ति से अधिक काम लेने की नीति बरतता है। परमात्मा भी कुछ थोड़े से लोगों को अधिक संपन्न बनाकर अपने अन्य लोगों के साथ अन्याय नहीं करता। उसने सभी को समान रूप से विकसित होने के अवसर दिए हैं। वह पक्षपात करे तो फिर समदर्शी और दयालु कैसे कहा जा सकता है।

भोजन, वस्त्र, आवास तथा जीवनयापन की उचित आवश्यकता पूरी करने वाली वस्तुएं प्रभु प्रदत्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए वेतन के समान हैं। आलसी, अकर्मण्य, उल्टे-सीधे काम करने वाले लोगों का वेतन कट जाता है और उन्हें किन्हीं अंशों में अभावग्रस्त रहने को विवश होना पड़ता है। जो परिश्रमी, पुरुषार्थी, सीधे मार्ग पर चलने वाले हैं, वे अपना उचित वेतन यथासमय पाते रहते हैं। इस वेतन के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की शक्तियां लोगों को जन्मजात मिली होती हैं। ये शक्तियां केवल इस उद्देश्य के लिए होती हैं कि इनसे संपन्न कोई व्यक्ति अपने से कमजोर लोगों को ऊपर उठाने में लगाए। अर्थात प्रत्येक समृद्ध मनुष्य को प्रभु ने यह कर्तव्य सौंपा है कि अपने से जो कमजोर हैं, उनकी मदद करने में इन शक्तियों को व्यय किया जाए। जैसे कि यदि कोई सुशिक्षित है तो उसका फर्ज है कि अशिक्षितों में शिक्षा का प्रसार करे। कोई शक्तिशाली है तो उसका कर्तव्य है कि निर्बलों को सताने वालों को रोके। धनवान के निकट धन इसलिए अमानत के रूप में रखा गया है कि वह उसके उपयोग से विद्या, बुद्धि, व्यवसाय, संगठन, सद्ज्ञान आदि का इस प्रकार आयोजन करे कि उससे जरूरतमंद लोग अपनी चतुर्मुखी उन्नति कर सकें।

श्रीमती रमन त्रिपाठी

आक्रामक क्यों हो रहे हैं बंदर

डॉ. महेश परिमल

हमें इस भ्रम को दूर करना होगा कि पृथ्वी पर रहने का अधिकार केवल मानव को ही है। यहां सभी जीवों को रहने का समान अधिकारहै

बीते दिनों संसद में बंदरों के 'आतंक' के बारे में चर्चा हुई, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान देने की आवश्यकता ही महसूस नहीं कि आखिर वे क्यों शहरी इलाकों में घुस रहे हैं? उनके आक्रामक होने के पीछे का कारण क्या है? आज मानव जाति जानवरों की दुश्मन बन गई है। बंदरों के रहने की जगह पर मानव बसाहट शुरू हो गई है। सुदूर जंगल तक मानव ने अपने घर बना लिए हैं, ऐसे में आखिर ये बंदर जाएं तो कहां जाएं? एक बार स्वयं को बंदरों के स्थान पर रखकर देख लें तो समझ में आ जाएगा कि आखिर बंदरों का आतंक बढ़ क्यों रहा है? इंसान इस मुगालते में न रहे कि पृथ्वी पर केवल उसका ही अधिकार है। चर्चा के दौरान एक सांसद ने कहा कि बंदरों के लिए विशेष रूप से पार्क होने चाहिए, पर प्रकृति ने उनके लिए जो स्थान दिया है, उस पर तो इसी मानव ने अपना कब्जा कर लिया है। विशेष पार्क बनाकर क्या होगा? धार्मिक स्थलों पर बंदर मानव जाति पर टूट पड़ते हैं। दरअसल वे उसके पास की खाद्य सामग्री पर हमला बोलते हैं। आखिर वे खाद्य सामग्री पर ही हमला क्यों बोलते हैं? जाहिर है, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस स्थिति में इंसान या तो चोरी करता है या लूट। बंदर खाने की चीजों पर झपटते हैं। इस चक्कर में उन्हें कई बार लाठियां भी खानी पड़ती हैं। भूखे बंदरों से कोई भी किस तरह से अच्छे व्यवहार की आशा कर सकता है? यह भूख उन्हें हमने ही दी है, उनके रहने की जगह पर अपना कब्जा जमाकर।

कभी-कभी जंगली जानवर किसी एक विशेष वाहन पर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि वे आखिर ऐसा क्यों करते हैं? मथुरा में कुछ ट्रक चालक एक लाल मुंह की बंदरिया से उसका बच्चा छीनकर ले गए। इससे बंदरिया क्रोधित हो गई। अब वह वहां से गुजरने वाले सभी ट्रकों पर हमला करती। उसकी नजर में हर ट्रक वाला उसका मुजरिम है जिसने उसका बच्चा छीन लिया। उसके आक्रामक होने का कारण भी यही है। उसकी इस लड़ाई में उसके साथी भी उसका साथ देते हैं। जिसे हम सामूहिक विरोध के रूप में देखते हैं। यह ध्यान रखें कि एक जानवर खुद भी इंसान से डरा हुआ होता है। वह पहले आक्रमण नहीं करता। आक्रमण करने के लिए हम ही उसे विवश करते हैं।

संसद में बंदरों के आतंक के बजाय उनके रहने के लिए वनों को तैयार करने पर बात होती तो वह एक सार्थक पहल होती, पर ऐसा नहीं हो पाया। बंदरों को लाठी से फटकारने या पटाखे चलाकर उन्हें भयभीत करने वालों को चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को याद रखना होगा। बंदर यदि आज हमारे बीच हैं तो अपने संघर्ष के कारण ही हैं। वे हमारे हमसफर हैं। उनकी सुरक्षा के लिए हमें ही प्रयास करने होंगे। हमारे देश में बंदरों की पूजा की जाती है। पृथ्वी पर रहने का अधिकार केवल मानव को ही है, इस भ्रम को हमें दूर करना होगा। जब तक जानवर हैं, तब तक हम हैं। इनका विनाश हमारा विनाश है। बंदरों के माध्यम से हमें यह चेतावनी मिल रही है कि जब वे नहीं रहेंगे तो फिर हम भी नहीं रह पाएंगे।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

पश्चिम और इस्लामी अपरिवर्तनशीलता

तसलीमा नसरीन का लेख 'इस्लामी दुनिया और पश्चिमी जगत' पढ़ा। मैं उनकी इस बात से असहमत हूं कि पश्चिम इस्लाम की वास्तविकताओं से अपरिचित है। 16वीं सदी में ईसाई प्रोटेस्टेंट आंदोलन शुरू करने वाले जर्मनी के मार्टिन लूथर तथा 18वीं सदी के फ्रेंच दार्शनिक वॉल्टेयर ने इस्लाम की जड़ता के विषय में काफी कुछ लिखा है। 19वीं सदी में इटली के लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि इस्लाम में सुधार का अर्थ इस्लाम की समाप्ति है। कुरान हाथ में लेकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन ने हाउस ऑफ कॉमंस में कहा था कि इस पुस्तक के रहते विश्व-शांति संभव नहीं। इसका प्रमाण 1980 में दुनिया ने देखा। जब मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात ने इजरायल के साथ 1979 में शांति संधि करने के बाद काहिरा-स्थित मिस्र के सबसे बड़े इस्लामी विश्वविद्यालय अल अजहर में कुरान की उन 200 से ऊपर आयतों को पढ़ाना बंद करवाया जो गैर-मुस्लिमों पर जिहादी हमले के लिए उकसाती हैं, तो सादात को इस्लामी उग्रवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। उनके उत्तराधिकारी हुस्नी मुबारक ने भी बिना खौफ सादात की नीति जारी रखी। आज मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे खौफनाक संगठन की मौजूदगी के बावजूद कुरान का संशोधित संस्करण ही वहां पढ़ाया जाता है। इस्लाम में सुधार या संशोधन का यह आज तक का एकमात्र प्रयोग है। किंतु 40 वर्षों में इसका कोई विस्तार मिस्र के बाहर अन्यत्र कहीं नहीं हुआ, यह निराशाजनक है। तसलीमा का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि इस्लाम का कट्टर समर्थक भी वहां नहीं रहना चाहेगा, जहां शरिया का शासन हो, लेकिन गैर-मुस्लिमों के प्रति शरिया के अनुसार व्यवहार अब भी इस्लामी जगत को प्रिय है, यह कहा जा सकता है। वैसे समय के साथ-साथ मुस्लिमों को भी उसी प्रकार परिपक्व तथा मानवतावादी होते चले जाना चाहिए था, जिस प्रकार पहले यहूदी और फिर ईसाई हो गए। प्रारंभ में ये दोनों मजहब भी कट्टरपंथी स्वभाव वाले थे। अब उनमें परिवर्तन हो चुका है। लंबी आयु के लिए व्यक्ति और विचार, दोनों में सामंजस्यवादिता का होना जरूरी है।

अजय मित्तल, मेरठ

अपराध और शिक्षा

दिल्ली के वसंत विहार में एक युवती की हत्या के विरोध में करीब सात साल पहले जैसा माहौल यहां था, अब एक बार फिर वैसा ही हैदाराबाद की घटना के बाद देखने को मिल रहा है। लोगों की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? 2012 की उस लड़ाई में देश का हर एक इंसान यह मांग कर रहा था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। उसके बाद महिलाओं के लिए कानून बने भी। उनके लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए, लेकिन सोचने की बात यह है कि जो भी काम किए गए, उसका कितने प्रतिशत प्रभाव देखने को मिला है? यह समस्या कानून की नहीं, सभ्यता की है। सभ्यता अच्छी शिक्षा से आती है। शिक्षा से व्यक्ति शिष्टाचारी बनता है और सही और गलत में फर्क करना सीखता है। शिक्षित व्यक्ति अपराध करने से पहले एक बार जरूर सोचेगा। शिक्षा के स्तर पर अभी भी हमारा देश बहुत पीछे है जिसके कारण ऐसे जघन्य अपराध सामने आते हैं। हमें जरूरत है कि देश में शिक्षा का स्तर और भी अच्छा हो। अपराधियों के पीछे उनकी बिगड़ी मानसिकता ही अपराध का सबसे बड़ा कारण होती है और इसे शिक्षा से ही बदला जा सकता है।

palshivani542@gmail.com

मार्शल आर्ट जरूरी

राज्यों ने उन्हें जारी निर्भया फंड का प्रयोग ही नहीं किया है। वास्तव में इस फंड के जरिये हर स्कूल, कॉलेज में अनिवार्य रूप से एक मार्शल आर्ट शिक्षक की नियुक्ति के साथ जूडो कराटे को सिलेबस में शामिल कर हर शहर में एक मार्शल आर्ट केंद्र तो खोला ही जा सकता है। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ने के साथ उन्हें हर समय किसी रक्षक की जरूरत नहीं होगी। हर स्कूल, कॉलेज, चौराहे और सड़क पर महिला थाने तथा महिला हेल्पलाइन के नंबर लिखे हों। इनके अलावा सभी लोगों को बेटों के चाल चलन पर भी नजर रख उन्हें घर की महिलाओं के साथ बाहर की महिलाओं का सम्मान करना भी सिखाना होगा। इन सबकी शुरुआत समाज को खुद से करनी होगी, क्योंकि दुष्कर्म और छेड़छाड़ करने वाले लोग कहीं बाहर से नहीं आते, इसी समाज में ही पनपते हैं।

pradeepwbsr@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

97 प्रतिशत मात्रात्मक दृष्टिकोण से और करीब 75 फीसदी मूल्यात्मक दृष्टिकोण से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर के जरिये होता है भारत का।

आजकल

भारत जापान टू प्लस टू वार्ता के मायने

बीते सप्ताह भारत और जापान के बीच नई दिल्ली में पहली 'टू प्लस टू' वार्ता संपन्न हुई। यह इस बात का प्रमाण है कि प्रतिरक्षा व सामरिक महत्व के मामलों में दोनों देश आपसी सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। दोनों देशों की सामरिक साझेदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित इस वार्ता में जापानी विदेश मंत्री तोशी मित्सू और रक्षा मंत्री तारो कोनो तथा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई महत्वपूर्ण मामलों पर संवाद किया। इसलिए इसे 'टू प्लस टू' संवाद भी कहते हैं

विवेक ओझा
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार

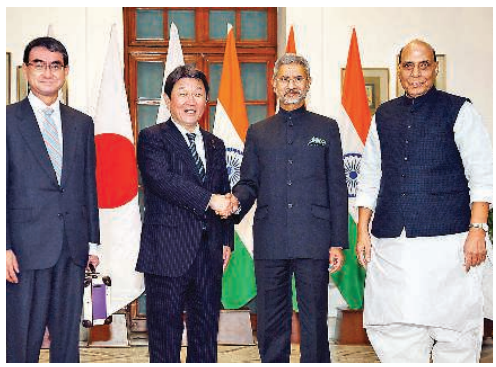

भारत और जापान के बीच हालिया आयोजित 'टू प्लस टू' वार्ता के दौरान हिंद महासागर और प्रशांत महासागर सहित विश्व के अन्य सागरों, महासागरों की स्वतंत्रता, नौगमन की स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल देते हुए समुद्री क्षेत्र में सहयोग को सुनिश्चित करने की बात की गई। भारत और जापान दोनों एशियाई शक्ति के रूप में हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रभुत्व की राजनीति, क्षेत्रीय विवादों, प्राकृतिक और अन्य संसाधनों पर स्वामित्व के अनैतिक प्रयासों जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाना चाहते हैं, क्योंकि इन सागरीय क्षेत्रों में स्थिरता, व्यापारिक मार्गों की स्वतंत्रता इन दोनों देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है।

यदि हम हिंद महासागर के महत्व को भारत और जापान के साझे लाभों के मद्देनजर समझें तो यह और स्पष्ट होता है। हिंद महासागर में स्थित दक्षिण एशियाई देश मालदीव की सामरिक स्थिति भारत और जापान सहित चीन के ऊर्जा हितों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर में मालदीव के क्षेत्र में स्थित अंतरराष्ट्रीय समुद्री जहाजी मार्ग भारत, जापान और चीन की ऊर्जा आपूर्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। मात्रात्मक दृष्टि से भारत का 97 प्रतिशत से अधिक और मूल्यात्मक दृष्टि से 75 प्रतिशत से अधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर में स्थित मालदीव के अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शिपिंग लेन्स के जरिये होता है। इस दृष्टि से भारत और जापान के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता का प्रश्न अहम है। इसी वर्ष भारत, जापान और श्रीलंका ने हिंद महासागर में चीनी प्रभाव वाले हंबनटोटा बंदरगाह के निकट कंटेनर टर्मिनल खोलने का निर्णय किया है। इसी प्रकार यदि हिंद प्रशांत के लिहाज से बात करें तो प्रशांत महासागर के एक भाग पूर्वी चीन सागर में जापान के सेनकाकू द्वीप को चीन दियायू द्वीप नाम देते हुए उस पर कब्जा करने का प्रयास करता आया है। इसलिए इन मामलों में साझे विचार के साथ भारत और जापान ने टू प्लस टू वार्ता के तहत जापान के स्वतंत्र और मुक्त इंडो पैसिफिक विजन और भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी को नई ऊर्जा के साथ बढ़ावा देने की बात की है।

दोनों देशों ने पुष्टि की है कि यह संवाद आपसी सुरक्षा और रक्षा सहयोग की सामरिक गहराई को और ज्यादा व्यापक बनाएगा। उभरती सुरक्षा चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मंत्रियों ने सुरक्षा सहयोग पर आधारित 2008 के संयुक्त घोषणा पत्र और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने से संबंधित 2009 की कार्य योजना के आधार पर द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस बात को स्मरण करते हुए कि दोनों देश मुक्त, खुले, समावेशी और नियमों पर आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति समान दृष्टि रखते हैं, जिसके अंतर्गत सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत सुनिश्चित किए गए हैं और सभी देशों को नौवहन और उस क्षेत्र से उड़ान भरने की स्वतंत्रता है, मंत्रियों ने इस बात पर बल दिया कि द्विपक्षीय सहयोग को ज्यादा मजबूती प्रदान करना दोनों देशों के परस्पर हित में है तथा इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। जापानी पक्ष ने हाल ही में संपन्न 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षित, संरक्षित, स्थिर, समृद्ध और टिकाऊ सामुद्रिक क्षेत्र का सृजन करने के लिए भारत द्वारा की गई 'हिंद-प्रशांत महासागर पहल' की सराहना की और इस के आधार पर ठोस सहयोग के बारे में विचार-विमर्श करने की इच्छा व्यक्त की। भारतीय पक्ष ने जापान और आसियान के बीच रक्षा सहयोग के लिए एक नई पहल के रूप में नवंबर में जापान के 'वियनतेन विजन 2.0' का स्वागत किया। चारों मंत्रियों ने दिसंबर 2018 में भारत द्वारा सूचना समेकन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (आइएफसी-आइओआर) की स्थापना का स्वागत किया। भारत ने आइएफसी-आइओआर में जापान द्वारा एक संपर्क अधिकारी भेजने की मंशा भी व्यक्त की।

इस वार्ता के दौरान दोनों देशों के रक्षा बलों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नियमित रूप से आयोजित करने और उन्हें व्यापक बनाने के निरंतर प्रयास जारी रखने पर समान रूप से बल दिया गया। इस संदर्भ में मंत्रियों ने हाल ही में संपन्न द्वितीय 'धर्म गार्जियन-2019' और द्वितीय 'शिन्यू मैत्री-2019' का स्वागत किया। मंत्रियों ने जापान में प्रथम भारत-जापान संयुक्त लड़ाकू विमान अभ्यास के लिए समन्वयन की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति प्रकट की। वर्ष 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती देने के लिए अभ्यास में भारतीय सेना जापान के सैनिकों को आतंकवाद निरोधक अभियानों का प्रशिक्षण दिया है। टोक्यो ओलंपिक को संभावित आतंकी हमले से बचाने के लिए भारत द्वारा दिया गया प्रशिक्षण दोनों देशों के मध्य सुरक्षा और सैन्य गठजोड़ों को एक नई दिशा दे रहा है।

भारत और जापान के बीच हाल के समय में अमेरिका और भारत के बीच हुए कॉमकेसा समझौते की तर्ज पर एक अति महत्वपूर्ण सैन्य समझौता एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट (एसीएसए) को मूर्तमान स्वरूप देने का निर्णय 2018 में हुआ। यह सैन्य व अन्य सामग्री को आपस में साझा करने का समझौता है। अमेरिकी नौसेना के साथ दोनों देश हिंद तथा प्रशांत महासागर में जिस तरह से अभ्यास करते हैं, उस दृष्टि से सैन्य उपकरणों का एक दूसरे को साझा करने का निर्णय काफी तार्किक है। मंत्रियों ने अक्तूबर 2018 में एसीएसए प्रारंभ किए जाने की घोषणा के बाद से इससे संबंधित बातचीत में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का स्वागत किया।

इस वार्ता के दौरान अंतरराष्ट्रीय मामलों पर भी ध्यान दिया गया। इसमें उत्तर कोरिया द्वारा व्यापक संहार की क्षमता वाले सभी हथियारों और समस्त रेंज वाली बेलिस्टिक मिसाइलों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इससे संबंधित प्रस्तावों (यूएनएससीआर) के अनुरूप प्रमाणन योग्य एवं अपरिवर्तनीय ढंग से नष्ट करने के महत्व की पुष्टि की गई और यूएनएससीआर के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। यूएनएससीआर का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए उत्तर कोरिया द्वारा हाल ही में बेलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए जाने की निंदा दोनों देशों ने की। इसके साथ ही दक्षिण चीन सागर में हाल की घटनाओं के संदर्भ में मंत्रियों ने नौवहन और क्षेत्र से उड़ान भरने की स्वतंत्रता, अबाधित वैध व्यापार तथा संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि (यूएनसीएलओएस) सहित कानूनी और सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय कानूनों के सिद्धांतों के अनुरूप कानूनी एवं राजनयिक प्रक्रियाओं का सम्मान करते हुए विवादों के समाधान के महत्व की पुष्टि की।

पाकिस्तान से निपटने के इंतजाम : वार्ता के दौरान दोनों देशों के चारों मंत्रियों ने पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से चलने वाले आतंकी नेटवर्क द्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा के समक्ष पैदा किए गए खतरों की निंदा की और पाकिस्तान को इसे खत्म करने की आवाज उठाई। साथ ही भारत व जापान ने पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्राविधानों के अनुपालन की भी आवाज उठाई। इस दौरान भारत के गृह मंत्री ने कहा कि भारत का जापान के साथ संबंध एशिया में स्थिरता का एक प्रमुख कारक बन चुका है। वर्ष 2018 में 13वें भारत जापान वार्षिक समिट में प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो अबे ने एशिया में सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए द्विपक्षीय प्रतिरक्षा संबंधों को मजबूती देने के लिए टू प्लस टू वार्ता के आयोजन का निर्णय किया था, उसे विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अधिक ऊर्जावान बनाने का कदम बताया।

भारत और जापान टू प्लस टू वार्ता के दौरान दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। फाइल फोटो

दोनों देशों में वैश्विक और सामरिक साझेदारी

वर्ष 2000 में भारत और जापान के बीच वैश्विक साझेदारी कायम की गई। वैश्विक मसलों पर सहयोग के साथ कार्य करने की इस कार्य संस्कृति की शुरुआत भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री योशिरो मोरी ने की थी। वर्ष 2006 में दोनों देशों के संबंधों को एक कदम आगे ले जाते हुए 'वैश्विक और सामरिक साझेदारी' में बदल दिया गया। वर्ष 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि उनके बीच 'विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी' केंद्रित संबंध रहे। वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना था। इस पॉलिसी के एक अपरिहार्य हिस्से के रूप में भारत ने जापान की पहचान की और यही कारण है कि 2015 में दोनों देशों ने 'जापान भारत विजन 2025 विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी' की घोषणा की जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र और विश्व में शांति और समृद्धि के लिए काम करना है। वर्ष 2016 में जापानी प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत जापान संबंध का नया युग शुरू हो चुका है। आपसी संबंधों को मजबूती देने के इन क्रमिक प्रयासों के पीछे दोनों देशों के साझे और व्यक्तिगत हित दोनों ही छिपे हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण एशिया को एक ध्रुवीय अर्थव्यवस्था की चाह रखने वाले चीन को प्रतिसंतुलित करने की जरूरत है। भारत की मजबूत नौसैनिक शक्ति को देखते हुए जापान का भारत की तरफ रुझान होना स्वाभाविक भी है। आज भारत दुनिया भर के देशों के साथ संयुक्त नौसैनिक, सैन्य और वायु सेना अभ्यास के जरिये महाशक्तियों को भरोसा दिलाने में सफल हुआ है कि समुद्री सुरक्षा, समुद्री व्यापार में भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाल के समय में रूस द्वारा भारत के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में एक वैकल्पिक समुद्री व्यापारिक मार्ग खोलना इसका प्रमाण है। अमेरिका की विश्व राजनीति में चौतरफा चुनौतियों के झेलने और उससे उत्पन्न शक्ति शून्यता को भारत कुछ हद तक भरने की क्षमता रखता है। जापान को ऐसा लगता है और यह महत्वपूर्ण बात है कि जापान अभी तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश पर ही रणनीतिक महत्व के मामलों पर विश्वास कर पाया है। भारत भी उसके लिए विश्वसनीय मित्र है। जापान को इस बात का भी भरोसा है कि भारत दक्षिण पूर्वी एशिया में सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभा सकता है और वास्तव में भारत ने फिलीपींस और चीन के विवाद में फिलीपींस का साथ देकर, वियतनाम के अधिकारों की बात कर, म्यांमार में विकासात्मक गतिविधियों पर बल देकर इस बात को सिद्ध भी किया है। वर्ष 2012 में जापान ने पहली बार इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम में भाग लिया और हिंद महासागर की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील हुआ। जापान एक मात्र विदेशी शक्ति है जिसे भारत के संवेदनशील उत्तर पूर्वी क्षेत्र में संरचनात्मक विकास की परियोजनाओं को चलाने की मंजूरी मिली है। इसके लिए 2017 में भारत और जापान ने मिलकर एक्ट ईस्ट फोरम का गठन किया है जिसका मुख्य उद्देश्य जापान द्वारा उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों में संरचनात्मक विकास के लिए निवेश को बढ़ावा देना है। भारत और जापान ने चीन के 'मोतियों की लड़ी की नीति' के जवाब में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की शुरुआत का फैसला 2019 में किया था जो भारत और जापान की एक महत्वाकांक्षी सामुद्रिक अंतरसंपर्क पहल है।

खरी-खरी

ठंडा बाजार, गरम इलाज

जवाहर चौधरी

इधर दिन भर फोन आ रहे हैं, कार ले लो साब। कीमत में छूट देंगे, सोने का सिक्का भी देंगे, नगद नहीं हो तो उधार देंगे, लोन फटाफट देंगे आदि। सरकार ने करोड़ों खर्च कर सड़कें बनवाई हैं तो उससे चिपक के चलो। और क्या चइए? सोचो मत, हमने सोच लिया है। आप तो आधार आइडी लाओ और हाथोंहाथ कार ले जाओ। आज की डेट में किराने वाला उधार नहीं दे रहा, आपके लिए कार उधार है। कहने को मंदी है, समझो तो उपहार है।

चारों तरफ चर्चा है कि बाजार ठंडा है। ठंडा बाजार होता है, लेकिन गरमी अंदर बढ़ जाती है। वो पसीना-पसीना हो रहे थे। पूछा तो लाचारी से कहने लगे, क्या करें! पूरा बाजार ही ठंडा है। कायदे से बाजार अगर ठंडा है तो स्वेटर पहनो। लेकिन नहीं, बाजार की ठंड स्वेटर से नहीं भागती। और न ही एसी की ठंडक से दुकानदारों का पसीना सूखता है। उस पर टीवी का हंगामा कि पड़ोसियों को नानी याद दिला देंगे। मंदी के जलों पर पाकिस्तानी सेंधा नमक! कोई हाय-हाय करना चाहे तो देशद्रोही कहा जाए।

इधर, बाजार की कोई सुन ही नहीं रहा। देशभक्ति वगैरह के चलते बाजार की क्या औकात! भैया, दादा, बाउजी बोलते-चिल्लाते गला सूख जाता है। कल ही बाजार ने केके महाकाले से पूछा कि इस बार तो दीवारों पर रंग करवाओगे ना? उन्होंने साफ मना कर दिया- कोई गुंजाइश नहीं है भाई। हाथ तंग है, उम्मीद भंग है, जिम्मेदारियों का लश्कर संग है, चितकबरे के साथ दीवारें अभी मस्त हैं, बैंक अकाउंट पस्त है।

लोग नरपति के पास पहुंचे तो वे भी गरम हो गए। बाजार कमबख्त बाजार है वरना एकाध मॉब-लिंचिंग करवा देते तो सहम जाता। नरपति गरम हो तो पूरे दरबार को गरम होना जरूरी है। पर दरबार की गरमी से भी बाजार की ठंड दूर नहीं हुई।

लोग अब हवाई सफर करने लगे हैं, डेढ़ जीबी डाटा माह भर खर्च करने वालों को अब दो जीबी रोजाना भी कम पड़ने लगा है, हर हफ्ते दो नई फिल्में लग रही हैं और हाउसफुल जा रही हैं। तो कहां है ठंडापन? इसी बाजार में कुछ लोगों का तो बढ़िया चल रहा है। जिनके भाग्य खोटे हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है?

सर, जनता कष्ट में है। कुछ कीजिए। कष्ट का ग्राफ बढ़ रहा है।

तो इसमें बुरी बात क्या है, बढ़ने दो। हम दुख का नाम बदलकर सुख कर देते हैं। सुख का ग्राफ बढ़ेगा तो किसी को दिक्कत होगी क्या?

ट्वीट-ट्वीट

प्याज के बढ़ते दामों पर सवाल के जवाब में वित्त मंत्री का कहना है कि वह ऐसे परिवार से आती हैं जहां प्याज-लहसुन नहीं खाया जाता। इस पर यही कहूंगा, मैं ऐसे परिवार से आता हूं जहां पेट्रोल नहीं पिया जाता, पेट्रोल के दाम बढ़ने से मुझे कोई परेशानी नहीं।
कुमार विश्वास@DrKumarVishwas

एक सांसद महोदय चिल्लाकर पूछते हैं कि 'आप प्याज खाती हैं?' जिस पर वित्तमंत्री जवाब देती हैं कि 'नहीं, मैं इतना लहसुन-प्याज नहीं खाती हूं जी।' जो सवाल था उसका जवाब दिया गया बस और उसको यूं दिखा दिया गया मानो वित्तमंत्री लोगों के जले पर नमक छिड़क रही हों। गजबे है।
सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

सिखों के नरसंहार पर मनमोहन सिंह जो स्वीकारोक्ति कर रहे हैं, वही बात मैं बीते 35 वर्षों से कहता आया हूं। मैंने तमाम साक्ष्य भी दिए हैं कि यदि एक नवंबर, 1984 को सेना बुला ली जाती तब उस नरसंहार को रोका जा सकता था, पर राजीव गांधी ने इसकी इजाजत नहीं दी।
एचएस फूल्का@hsphoolka

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या कानून को कठोर बना देने से देश में दुष्कर्म के मामले रुक जाएंगे?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या नागरिकता संशोधन बिल पर कुछ दलों की आपत्ति उचित है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y-हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

रोटी-दाल तिहाड़ की है कितनी दमदार,
हम सकते हैं जान यह सुनकर जोर दहाड़।
सुनकर जोर दहाड़ भूल करके स्व-अवस्था,
चिदंबरम जी याद कर रहे अर्थव्यवस्था!
जाकर जेल तिहाड़ गली जब अपनी बोटी,
आई उनको याद गरीबों की तब रोटी।
– ओमप्रकाश तिवारी

झारखंड डायरी

उन्नीस का जवान झारखंड और जिम्मेदारी

प्रदीप शुक्ला
स्थानीय संपादक, झारखंड

झारखंड उन्नीस वर्ष का हो गया है। उम्र की यह दहलीज हर मायने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैली में राज्य के लिए इसके मायने समझा गए हैं। एक नए राज्य के लिए हर साल इस तरह बीतता है कि उसके साथ अपेक्षाएं और सपने बढ़ जाते हैं। झारखंड चुनाव के इस माहौल में थोड़ा चिंतित भी है- खासकर समाज के लिए। इस चुनाव में विकास, नक्सलवाद, पिछड़ापन, असमानता, जाति जैसे मुद्दे लोगों के बीच है, लेकिन इसी दौरान रांची की एक झकझोर देने वाली घटना ने हमारे समाज और सियासत के सामने एक सवाल खड़ा किया है।

दरअसल रांची में कानून की एक छात्रा के साथ बारह दरिंदों ने दरिंदगी की है। पीड़ित बिटिया को न्याय दिलाने के लिए रांची की सड़कों पर भी गुस्सा फूट रहा है, लेकिन हैरत इस बात पर हो रही है राजनीतिक मंचों से कहीं कोई आवाज मुखर नहीं हो रही है। बड़े-बड़े दावे हो रहे हैं, पर इस भटकाव पर कोई बात नहीं हो रही है। हर घटना के बाद कुछ दिन तक शहर-देश उद्वेलित रहता है, कड़े कानून की पैरोकारी होती है और फिर सब कुछ पुराने ढर्रे पर आ जाता है।

मजबूत लोकतंत्र जितना जरूरी है उतनी ही जरूरत एक मजबूत सभ्य समाज की है। आखिर यह विकृति पैदा कहां से हो रही है? घर से लेकर स्कूल तक क्या संस्कार दिए जा रहे हैं? रांची के ही एक स्कूल के कुछ बच्चों के बीच आपसी बातचीत आपको चिंतित ही नहीं भयभीत भी कर देगी। महज ग्यारह-बारह वर्ष का एक बच्चा अपने सहपाठियों से अक्सर 'दुष्कर्म' के संबंध में जिस तरह की बातें कहता रहता है, उसे यहां लिखना उचित नहीं होगा। लेकिन वह जो बात बोलता है, वह बहुत भयावह है। इसे कैसे समझा जाए? कह सकते हैं कि शायद वह इस शब्द से ठीक से वाकिफ न हो, लेकिन चिंता की बात तो है ही? वह घर से लेकर स्कूल तक सीख क्या रहा है? अभिभावक से लेकर शिक्षक तक उससे क्या बात कर रहे हैं? क्या उसकी इस मनोदशा को किसी भी स्तर पर समझने-जानने की कोशिश हो रही है? यही बच्चा तो आठ-दस वर्ष बाद युवा बनेगा? ऐसा युवा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होकर अपने माननीय चुनेगा।

लोकतंत्र के इस उत्सव में बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं, यह हर चुनाव में होता है। समाज है तो मुद्दे भी रहेंगे ही। राज्य में नक्सलवाद पर लगभग काबू पा लिया गया है। गरीबी, कुपोषण, मानव तस्करी, रोजगार के लिए पलायन, जल, जंगल और जमीन के लिए जूझते आदिवासी। यह मुद्दे भी हैं और सभी दल इनके समाधान का वादा भी कर रहे हैं, लेकिन 'घातक प्रवृत्ति' वाले जवान हो चुके अथवा जवानी की दहलीज की तरफ कदम बढ़ा रहे युवाओं को कैसे सही रास्ते पर लाया जाए, इसका न तो किसी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में जिक्र है और ना ही किसी मंच पर। हर तरफ खामोशी है। यह इतना आसान नहीं है, फिर भी मंथन तो होना ही चाहिए। हमें दलों से पूछना चाहिए, समाज को संस्कारों की ओर ले जाने के लिए उनके पास क्या एजेंडा है। वे ऐसी घटनाओं पर केवल दिखावटी प्रदर्शन क्यों करते हैं। राजनीतिक दलों के बीच भी ऐसे मामले आते रहते हैं, जब उनके अपने नेता इस तरह के मामलों में घिरे होते हैं, लेकिन उनकी पहली कोशिश मामले पर पर्दा डालने की या फिर अपने नेता को बचाने की होती है। कथित कड़ी कार्रवाई तभी होती है जब मामला बहुत अधिक बढ़ जाता है। जाहिर है, मतदाताओं को अपना माननीय चुनने से पहले सभी दलों के प्रत्याशियों को भी ठीक से परखना चाहिए। क्योंकि, तमाम ऐसे दागी भी विभिन्न दलों से मैदान में डटे हुए हैं, जिनका खुद का चरित्र ही संदेहास्पद रहा है। राज्य जवान हो चुका है और उसे सही हाथों में ही जाना चाहिए, ताकि उसका बेहतर विकास हो सके।

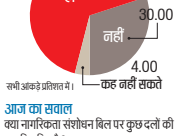

देश भर में दुष्कर्म के विरुद्ध आवाज उठाती महिलाएं (प्रतीकात्मक) फाइल फोटो

महापरिनिर्वाण दिवस

युग परिवर्तक थे डॉ. आंबेडकर

देश का एक आम नागरिक डॉ. भीमराव आंबेडकर को देश के संविधान के शिल्पी के तौर पर जानता है, लेकिन वह सामाजिक बदलाव के एक बड़े पैरोकार के रूप में भी जाने जाते हैं

रामदास आठवले
केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार

बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भारतीय समाज के दलितों, वंचितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए मसीहा की भूमिका का निर्वाह किया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए भी महान कार्य किया। बाबा साहब को युग प्रवर्तक या युग परिवर्तनकारी व्यक्ति कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी।

बाबा साहब का पूरा नाम डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर था। उनका जन्म 14 अप्रैल, 1891 को हुआ था और वह छह दिसंबर, 1956 को स्वर्गवासी हुए। बाबा साहब जानेमाने विधिवेत्ता थे। वह भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे और इसीलिए उन्हें संविधान का शिल्पी और जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा, बाबा साहब भारतीय गणराज्य के संस्थापक पुरोधाओं में से एक थे। बाबा साहब की यह ख्याति केवल भारत और आसपास के देशों में ही नहीं है, बल्कि पश्चिम के भी तमाम देश उनकी प्रतिभा और कृतित्व का लोहा मानते हैं। वे जानेमाने अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक के रूप में भी प्रख्यात हैं। उनके जन्म के समय से ही समाज में पिछड़ों, दलितों और वंचितों के विरुद्ध जो भेदभाव था, उसका सामना उनके परिवार को भी करना पड़ा। वे स्वयं इस भेदभाव से पीड़ित थे, लेकिन इसके बावजूद उनके नैतिक बल पर इन विपरीत परिस्थितियों का नकारात्मक प्रभाव कम ही पड़ा।

विशेष बात तो यह है कि बाबा साहब ने इस सामाजिक कुरीति को झेलते हुए इसके खिलाफ न सिर्फ आवाज उठाई, बल्कि लोगों को संगठित कर एक आंदोलन खड़ा करने का काम भी किया। हालांकि बाबा साहब आंबेडकर को अपने समय में जब यह महसूस हुआ कि वह समाज के परिवर्तन के कार्य में वांछित सफलता नहीं पा सके हैं तो उन्होंने यह घोषणा तक कर दी कि वह भले ही एक हिंदू के रूप में जन्मे हैं, किंतु उनकी मृत्यु एक हिंदू के रूप में नहीं होगी।

इसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के आखिरी समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया। यह बात अलग है कि आज भले ही बाबा साहब का सपना पूरी तरह से पूरा नहीं हो सका है, लेकिन फिर भी पिछड़ों और दलितों की स्थिति में बीते सात दशकों में जो सुधार हुआ है, उसका बहुत बड़ा श्रेय डॉ. भीमराव आंबेडकर को ही जाता है।

यहां यह कहना प्रासंगिक होगा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को दस वर्ष बढ़ाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है। उल्लेखनीय है कि यह आरक्षण वर्ष 2020 के जनवरी महीने की 20 तारीख को खत्म होने जा रहा है। अब दस वर्ष की अवधि बढ़ाने के बाद आरक्षण वर्ष 2030 तक जारी रहेगा। जाहिर है कि बाबा साहब के सपने और गैर बराबरी को खत्म करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने यह कदम उठाया है।

मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजे गए बाबा साहब को स्कूल में अन्य छात्रों के साथ इसलिए बैठने को नहीं मिलता था, क्योंकि वह दलित थे, लेकिन उन्होंने इस उपेक्षा को अपनी ऊर्जा में बदलने का काम किया। कमोबेश इन्हीं स्थितियों का सामना उनको देश में उच्चस्तर तक की पढ़ाई के दौरान भी करना पड़ा। यहां तक कि जब उन्होंने शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया तो उनके साथ के शिक्षकों ने उन बर्तनों से पानी पीना स्वीकार नहीं किया, जिसका इस्तेमाल बाबा साहब करते थे।

बाबा साहब का कहना था कि छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। यह समझा जा सकता है कि उस समय देश तो गुलामी की जंजीरों से जकड़ा ही हुआ था, लेकिन समाज भेदभाव की उससे भी बुरी और जटिल बेड़ियों में फंसा हुआ था। बाबा साहब ने चूंकि उच्च शिक्षा बड़ौदा की रियासत के संरक्षण में पाई थी और उनकी सेवा करने के लिए वे एक समझौते के तहत बाध्य थे, लेकिन उन्हें महाराजा गायकवाड़ के सैन्य सचिव का पद भी जातिगत भेदभाव के कारण रास नहीं आया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद वह लेखाकार और निजी शिक्षक के रूप में काम करने लगे। फिर निवेश परामर्श के कार्य में लगे, लेकिन यहां भी छुआछूत का जो बोलबाला था, उसके कारण उनके क्लाइंट उनसे दूर हो गए।

भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने संविधान को शक्ल देने में दिन-रात एक कर दिया। उन्होंने दुनिया भर के लोकतंत्रवादी अनेक संविधानों का अध्ययन किया और उनकी अच्छी-अच्छी बातों को भारत के संविधान में समायोजित किया। भारत की जनसंख्या जिस तरह से बहुलतावादी है, इसका ध्यान रखते हुए उन्होंने अल्पसंख्यकों और कम आबादी वाले धर्मों तथा गरीबों और वंचितों के हितों के संरक्षण का विशेष ध्यान रखा।

26 नवबर, 1949 को जब उन्होंने संविधान की प्रति संविधानसभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद को सौंपी तो डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने उनकी मेधा, परिश्रम और दूरदर्शिता की व्यापक प्रशंसा की। समता, स्वतंत्रता और भाईचारा उनके जीवन का मिशन रहा, जिसे उन्होंने भारतीय संविधान में भी शामिल किया है। संविधान के अनुच्छेद 14ए, 15ए, 16 और 17 दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए अहम हैं।

आज देश बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। विकास की इस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों का शामिल होना जरूरी है। लेकिन आज भी जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, नक्सलवाद और आतंकवाद भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। इन चुनौतियों से निपटने की शक्ति बाबा साहब द्वारा दिए गए भारत के संविधान में निहित है। इन समस्याओं से निपटने और बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार निरंतर प्रयत्न कर रही है। हम यह उम्मीद करते हैं कि भारतीय समाज से गैर बराबरी की विसंगतियां आने वाले समय में जल्द ही खत्म होंगी और पूरा समाज एकसाथ तरक्की करेगा।

डॉ. भीमराव आंबेडकर। फाइल फोटो

37 लाख करोड़ रुपये की लागत से सऊदी अरब दुनिया की पहली स्पोर्ट्स सिटी बनाने जा रहा है। यह सऊदी क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान के विजन-2030 का हिस्सा है। इसके जरिये सऊदी अरब को स्पोर्ट्स इवेंट का वैश्विक केंद्र बनाया जाना है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 6 दिसंबर 2019

प्रियम का खेल अक्स पिता का परिश्रम आईना

प्रियम के पिता नरेश कुमार गर्ग। जागरण

- पिता संसाधनहीन हो, गरीब हो या सिंगल पेरेंट की भूमिका में हो, मायने नहीं रखता, यदि जज्बा इस पिता के जैसा हो
- भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के नवनियुक्त कप्तान प्रियम गर्ग के पिता नरेश कुमार के हौसले की कहानी

भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के नवनियुक्त कप्तान प्रियम गर्ग। फाइल फोटो

जागरण विशेष

अमित तिवारी, मेरठ

यह कहानी है भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के नवनियुक्त कप्तान प्रियम गर्ग की सफलता में निहित उनके पिता के घोर संघर्ष की। पिता के साथ मां का भी किरदार निभाते हुए उन्होंने न केवल प्रियम वरन सभी बेटे-बेटियों का भविष्य संवारा।

होनहार क्रिकेटर प्रियम अब अपने करियर की शुरुआती चढ़ान पर हैं, आखिर अंडर-19 विश्वकप में भारतीय टीम का नेतृत्व करना कोई छोटी-मोटी बात तो नहीं। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने के पहले प्रियम व उनके परिवार की मेहनत अपने में एक लंबी दास्तां छुपाए है। उनके खेल में प्रियम की मेहनत के साथ ही पिता नरेश कुमार गर्ग के कठिन परिश्रम का भी अक्स झलकता है। प्रियम में क्रिकेट के प्रति दिखी ललक ने उनका हौसला बढ़ाया तो पिता के किरदार में वह भी प्रियम के खेल से जुड़ गए। हर सुबह प्रियम को मेरठ, उप्र के निकट पैतृक गांव किला परीक्षितगढ़ से शहर स्थित भामाशाह पार्क पहुंचाना और शाम को घर ले जाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। यहां तक कि बिटिया की शादी में भी सुबह उसे विदा करने से पहले वह प्रियम को मैच खेलने के लिए दिल्ली छोड़कर आए थे। नरेश कुमार गर्ग के अनुसार बेहद खराब आर्थिक दौर से गुजरने के दौरान ही 11 मार्च 2012 को प्रियम की माता कुसुम देवी का करीब छह महीने के इलाज के बाद निधन हो गया। उनके लिवर में पीलिया के बाद इंफेक्शन हो गया था। इसके बाद प्रियम की ट्रेनिंग बंद हो गई। घर में छोटे बच्चों का खाना बनाने से लेकर उन्हें पढ़ाने तक की जिम्मेदारी के बीच प्रियम को रोज शहर लाने का क्रम टूट गया। उस दौरान प्रियम यूपीसीए अंडर-14 के प्रबल दावेदार बन चुके थे। कोच संजय रस्तोगी और एमडीसीए पदाधिकारियों के प्रोत्साहन पर नरेश ने फिर हिम्मत बांधी और पिता के साथ मां का भी किरदार निभाते हुए प्रियम को नियमित ट्रेनिंग में पहुंचाने लगे। पूर्व क्रिकेटर और कोच राहुल द्रविड़ ने भी एक मुलाकात में प्रियम के खेल को देख भरोसा दिलाया था कि अगर मेहनत चलती रही तो प्रियम को मुकाम जरूर मिलेगा। मेहनत रंग रंग लाई, प्रियम का बल्ला बोलने लगा। नरेश का फोकस केवल प्रियम तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने बाकी बच्चों को भी उसी लाड़-प्यार से पाला। उनकी कुशल परवरिश का ही नतीजा है कि प्रियम के बड़े भाई शिवम गर्ग, बड़ी बहन पूजा और च्योति चिकित्सा क्षेत्र में सेवारत हैं। तीसरी बहन रेशु ने भी फार्मेसी की पढ़ाई पूरी कर ली है। अब वह सिविल सेवा की तैयारी कर रही हैं। वर्ष 2009 में नरेश कुमार प्रियम को भामाशाह पार्क में संचालित मेरठ कॉलेज क्रिकेट एकेडमी में कोच संजय रस्तोगी के पास लेकर पहुंचे थे। क्रिकेट का ककहरा सीखने के क्रम में ही प्रियम अपने हुनर का परिचय देने लगे थे। टैक्सी चालक नरेश कुमार हर दिन सुबह प्रियम को भामाशाह पार्क पहुंचाते और शाम को साथ लेकर घर जाते। प्रियम भी सुबह से शाम तक क्रिकेट की ट्रेनिंग करने के साथ ही क्रिकेट को जीने लगे। प्रियम की दुनिया घर और क्रिकेट के मैदान तक सिमटी रही, वहीं पिता नरेश भी हमेशा बेटे के साथ खड़े रहे। प्रियम की सफलता, संघर्ष की कथा-कहानी के बीच लंबी सांस लेते हुए नरेश ने बताया कि मैंने टैक्सी चलाने के अलावा पैसे जोड़ने को और भी छोटे-मोटे काम किए। जीने की जद्दोजहद के बीच मैं अपने सभी बच्चों को बताता रहा कि किसी का अपमान और पैसे पर गुमान कभी मत करना। आशीर्वाद सबका लेते रहें पर दोस्ती-यारी सिर्फ पढ़ाई, ट्रेनिंग और अपने काम से ही करें। इसी मार्गदर्शन ने बच्चों को तंगी के समय भी भटकने नहीं दिया। बताते हैं, अपने साथियों के साथ किला परीक्षितगढ़ में ही स्थानीय संगम क्लब के लिए क्रिकेट खेला करते थे। खेलता देख प्रियम भी घर आने पर प्लास्टिक की छोटी गेंद से क्रिकेट खेलता, और आज वह भारतीय टीम का कप्तान है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

महज 30 सेकंड में जख्म से रक्तस्राव रोक देगा स्वदेशी पाउडर

हृदयानंद गिरि, दुर्गापुर

जी हां, इस तरह के पाउडर विदेश में चलन में आ चुके हैं, लेकिन भारतीय युवा वैज्ञानिक ने सस्ता और कारगर स्वदेशी पाउडर विकसित कर दिखाया है। जख्म वाले स्थान पर डालते ही 30 सेकंड के अंदर यह खून का बहना रोक देगा। एनआइटी (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान) राउरकेला में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से एमटेक साबिर हुसैन की इस युक्ति रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने मान्यता दी है।

स्वस्थ समाज

बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले के खंडघोष के रहने वाले मुबारक हुसैन के पुत्र साबिर के इस शोध को हालही डीआरडीओ के डेयर टु ड्रीम इनोवेशन कॉन्टेस्ट में प्रथम पुरस्कार मिला। साबिर कहते हैं, दुर्घटना में अकसर लोगों की अधिक खून निकलने से मौत होने की बात बचपन से ही सुनता था। तभी प्रण किया कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर कुछ बड़ा काम करूंगा, ताकि लोगों की जान बच सके। यह स्टॉप ब्लीड पाउडर मौत से जंग कर रहे जख्मी लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगा। साबिर का स्टार्टअप अब इसका पेटेंट कराने की तैयारी कर रहा है।

> जल्द ही इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर देंगे। कीमत 250 रुपये तक और इससे भी कम लाने की है। यह भी कोशिश होगी कि इसे घर-घर तक पहुंचाया जाए। वाहन चालक भी अपात स्थिति के लिए इसे साथ लेकर चलें।
> **-साबिर हुसैन, शोधार्थी व मिराकल्स मेड सॉल्यूशन स्टार्टअप के संस्थापक**

> साबिर ने स्टॉप ब्लीड पाउडर बनाने में पूरी लगन से प्रयास किया। इस कारण उन्हें सफलता मिली। डीआरडीओ की प्रतियोगिता में शोध ने पहला स्थान पाया। इतनी खुशी है कि शब्दों में बयां नहीं कर सकता।
> **-डॉ. देवेंद्र वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, एनआइटी राउरकेला**

साबिर ने पढ़ाई के दौरान इस पर शोध शुरू कर दिया था। 2017 में उन्होंने एमटेक किया। उसके बाद एक अच्छी कंपनी में सहायक इंजीनियर की नौकरी मिली, लेकिन च्वाइन नहीं किया। 2018 में साबिर ने दवा बनाने व शोध के लिए स्टार्टअप मिराकल्स मेड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड शुरू किया। इसमें 20 लाख की लागत से लैब बनाई। पढ़ाई के दौरान रक्तस्राव रोकने के लिए जिस दवा की खोज शुरू की, वह यहां पूरी हो गई। तीन वर्ष के प्रयास में पाउडर का एकदम नया फॉर्मूला ईजाद कर लिया। साबिर का कहना है कि पाउडर पर तीन वर्ष तक गहन शोध किया। घाव पर रक्त का थक्का कैसे बनता है, किस रसायन की क्या भूमिका है, इसमें फाइब्रिनोजन, थ्राम्बोप्लास्टिन और ब्लड प्लेटलेट्स कैसे काम करते हैं। इन बिंदुओं पर अध्ययन कर इसका निर्माण किया। जानवरों पर किया गया प्रयोग बेहद उत्साहवर्धक रहा। यह पाउडर रक्त का थक्का जमाने वाले अवयवों को अत्यधिक तेजी से सक्रिय करता है। प्रो. डॉ. देवेंद्र वर्मा के मार्गदर्शन में अंततः सफलता मिल गई। अब कुछ और तकनीकी बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। यह पाउडर बाजार में उपलब्ध रक्त का थक्का बनाने वाली दवाओं से पांच गुना कम कीमत का होगा। डीआरडीओ की ओर से भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की याद में किए जाने वाले डेयर टु ड्रीम इनोवेशन कॉन्टेस्ट में साबिर के इस शोध ने प्रथम पुरस्कार जीता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ चेयरमैन डॉ. जीएस रेड्डी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मौजूदगी में साबिर को 15 अक्टूबर को पुरस्कार दिया। डोभाल ने भी इसकी सराहना की। साबिर ने जो पाउडर तैयार किया, उसके तीन ग्राम की कीमत 250-300 रुपये के बीच आएगी। बकौल साबिर वह जल्द ही इसका व्यवसायिक उत्पादन शुरू कर देंगे। अपने प्रयोग के सफल होने और उसे मान्यता मिलने से साबिर बहुत खुश और उत्साहित हैं।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

बायोमेडिकल इंजीनियर साबिर हुसैन को डेयर टू ड्रीम इनोवेशन प्रतियोगिता का पुरस्कार प्रदान करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। फाइल फोटो (सौजन्य : साबिर)

इंडो-नेपाल नो मेंस लैंड पर बसीं बस्तियां, पिलर गायब

ग्राउंड रिपोर्ट ▶ बहराइच, श्रावस्ती व बलरामपुर सीमा पर ज्यादा कब्जे

गायब और क्षतिग्रस्त पिलर की रिपोर्ट गृह विभाग को भेजी गई

विजय द्विवेदी, बहराइच

इंडो-नेपाल सीमा पर भविष्य के खतरे आकार ले रहे हैं। नो मेंस लैंड पर सीमा निर्धारण के लिए लगे पिलर गायब हो रहे हैं। यहां नेपालियों ने कब्जा कर मकान बना लिए हैं। सबसे ज्यादा कब्जा बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों की सीमा पर है। अधिकारी भी बस्तियां बसने और सीमा स्तंभ गायब होने की खबर से इन्कार नहीं कर रहे। गायब व क्षतिग्रस्त पिलर की रिपोर्ट गृह विभाग को भेजी गई है। इसके लिए दिसंबर में दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक भी बुलाई गई है।

भारत-नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के दोस्ताना रिश्तों की गवाह है, लेकिन बढ़ते कब्जों ने नए खतरे को जन्म दिया है। बड़े पैमाने पर नो मेंस लैंड पर नेपाल के लोगों ने मकान बना लिया है। नवाबगंज ब्लॉक के होलिया गांव के पास नो मेंस लैंड पर नेपाल के बांके जिला स्थित ग्राम विकास समिति होलिया के वार्ड नंबर एक के कुछ लोगों ने पक्का घर खड़ा कर लिया है। यहां पिलर संख्या 18 का अस्तित्व ही मिट चुका है। यहां बसने वाले अर्जुन वर्मा, मनीराम, बराती आर्य या कुबेर, सभी परिवारों के साथ नो मेंस लैंड पर आबाद हैं। कहा जाता है कि ये लोग भारत के नागरिक भी बन गए हैं। इसी प्रकार पचपकरा के पास भी नो मेंस लैंड पर अवैध कब्जा है। नेपाल के जमुनी, शांती नगर, शिवपुरी, सैनिक गांव, बहादुरपुर आदि में नो मेंस लैंड गायब है।

> भारत-नेपाल सीमा पर लगे क्षतिग्रस्त, गायब व जलमग्न सीमा स्तंभों की रिपोर्ट 17 सितंबर, 2018 को केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है। दिसंबर में ही इस पर दोनों देशों की बैठक भी बुलाई गई है। इनमें सीमा स्तंभों के साथ सुरक्षा पर भी चर्चा की जाएगी।
> **-जयचंद्र पांडेय, एडीएम बहराइच**

> गायब व क्षतिग्रस्त सीमा स्तंभों के साथ अतिक्रमण की रिपोर्ट तैयार कराकर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। दोनों देशों की बैठक में भी यह मुद्दा उठता है।
> **-अभिषेक पाठक, डीआइजी एसएसबी-लखीमपुर रेंज**

56 पिलर गायब, 17 जलमग्न

इंडो-नेपाल सीमा पर बहराइच, श्रावस्ती व बलरामपुर की लगभग 250 किमी सीमा जुड़ी है। अकेले बहराइच सीमा पर ही कुल मुख्य स्तंभ 81 व उप स्तंभों की संख्या 236 है। इनमें से 44 पिलर क्षतिग्रस्त हैं। 56 गायब हैं, जबकि 17 पिलर जलमग्न हैं।

नदियों ने बिगाड़ा भूगोल : नेपाल से निकली मांद नदी डेढ़ दशक पहले स्तंभ संख्या 40 को बहा ले गई। जांच के बाद भी यह स्तंभ दोबारा नहीं लगा। नवाबगंज में समतलिया चौकी के आगे बढ़ने पर श्रावस्ती जिले की सीमा शुरू हो जाती है। यहां भी राप्ती नदी कई स्तंभों को बहा ले गई है।

शिमला का लाल गुब्बारा देगा आइस स्केटिंग की खबर

रामेश्वरी ठाकुर, शिमला

- अंग्रेजों के समय से ऐतिहासिक टाउनहाल भवन की छत पर सर्दियां शुरू होते ही इसे लगाया जाता रहा है
- 2014 में मरम्मत का काम शुरू होने पर हटा दिया गया था

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के मालरोड पर स्थित ऐतिहासिक टाउनहाल भवन की छत पर अब फिर से लाल गुब्बारा टंगा हुआ दिखेगा। भवन की छत पर गुब्बारा लगाने के लिए आइस स्केटिंग रिंक क्लब ने उपायुक्त अमित कश्यप से अनुमति मांगी है।

अंग्रेजों के समय से सर्दियां शुरू होते ही टाउनहाल की छत पर लाल रंग का गुब्बारा दिख जाता था। सुबह और शाम के समय ये गुब्बारा टाउनहाल ही छत पर टंगा दिखता था। 2014 में जब टाउनहाल की मरम्मत का काम शुरू हुआ तो चार साल से ये गुब्बारा दिखना भी बंद हो गया। यह गुब्बारा 1920 से टाउनहाल की छत पर लगता आया है।

गुब्बारा बताता था कि आइस स्केटिंग रिंक में स्केटिंग शुरू हो चुकी है। ये गुब्बारा उतनी देर ही टंगा रहता था, जितनी देर स्केटिंग होती थी। सुबह और शाम के सेशन के वक्त ये गुब्बारा टाउनहाल पर टंगा होता था। जिस दिन टाउनहाल पर ये गुब्बारा नहीं दिखता था तो उसका मतलब था कि मौसम की वजह से स्केटिंग नहीं हो रही है। मरम्मत पूरी होने के बाद इस साल गुब्बारा लगाने की तैयारी की जा रही है। क्लब के कोषाध्यक्ष पंकज प्रभाकर ने बताया कि 2020 में आइस स्केटिंग रिंक के 100 साल पूरे हो रहे हैं। कोशिश रहेगी कि टाउनहाल के भवन की छत पर नए सेशन से गुब्बारा लग जाए।

अंग्रेजों ने सहूलियत के लिए लगाया था ये गुब्बारा : अंग्रेजों के जमाने में टाउनहाल के दूसरी तरफ रिवॉली सिनेमा के ऊपर के हिस्से में घना जंगल था। पेड़ों की वजह से रिंक नजर नहीं आता था। तभी अंग्रेजों ने स्केटिंग के शौकीनों की सुविधा के लिए ये गुब्बारा लगाना शुरू किया, ताकि माल रोड पर टहलते हुए स्केटिंग के शौकीनों को पता चल जाए कि रिंक में स्केटिंग हो रही है या नहीं। गुब्बारा लटकता देख शिमला घूमने आए पर्यटक और स्थानीय लोग भी स्केटिंग का लुत्फ उठाने के लिए स्केटिंग रिंक में पहुंच जाते थे। सैलानियों की सुविधा के लिए टाउनहाल पर करीब 94 साल तक गुब्बारा लगाया जाता था।

गोल्डन जुबली के लिए तैयारियां : आइस स्केटिंग रिंक एशिया का एकमात्र ऐसा रिंक है, जहां हर साल जिमखाना और कार्निवल की प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। इस बार भी मौसम अनुकूल होने की वजह से इसी माह के अंतिम दिनों में प्रतियोगिताएं करवाने की तैयारी है। ऐसे में इन प्रतियोगिताओं में नए कार्यक्रम आयोजित करने की भी योजना है।

दैनिक जागरण के सहयोगी मीडिया प्लेटफॉर्म विश्वास.न्यूज की पड़ताल में सामने आया सच

घरेलू नुस्खे से कैंसर ठीक होने का दावा फर्जी

विश्वास.News
क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है
www.vishvasnews.com

विश्वास न्यूज, जेएनएन: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि अखरोट, अंकुरित अनाज, शहद, लहसुन और नींबू से घर में तैयार किए गए मिश्रण का सेवन कर अंतिम स्टेज का कैंसर भी 72 घंटे में ठीक किया जा सकता है। वीडियो के मुताबिक, इस मिश्रण को फ्रिज में रखना है और दिन में कई बार सेवन करना है। विश्वास न्यूज की टीम की पड़ताल में यह दावा फर्जी साबित होता है।

पड़ताल: विश्वास न्यूज की टीम ने सबसे पहले इस वीडियो पर आए कमेंट्स को देखा तो पाया कि कई पाठकों ने यह कमेंट किया है कि वीडियो फर्जी है। फिर टीम ने वीडियो के कैप्शन को ध्यान से पढ़ा तो कैंसर की स्पेलिंग गलत मिली। टीम ने आगे पड़ताल करते हुए देखा कि क्या वीडियो दिए गए आहार का कैंसर की रोकथाम और इलाज से कोई लेना-देना है या नहीं। टीम को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च की वेबसाइट पर एक रिपोर्ट मिली। इसके मुताबिक, 'कोई भी खाद्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ के घटक आपको कैंसर से नहीं बचा सकते। हालांकि, शोधों से ये बात पता चली है कि कई तरह की सब्जियां, फल, साबूत अनाज, बींस और दूसरे पौधों से जुड़े खाद्य पदार्थों को खुराक में शामिल करने से कई तरह के कैंसर का खतरा कम हो सकता है।'

टीम ने इस संबंध में आयुर्वेद डॉक्टर विमल एन से बात की। उन्होंने बताया, 'यह मिश्रण कैंसर इलाज में काम नहीं करता है। यह पूरी तरह से फर्जी खबर है।'

क्या है वायरल पोस्ट में?

वायरल किए जा रहे वीडियो के कैप्शन में लिखा है, '3 दाने खाने से 72 घंटे में हो जाता है लास्ट स्टेज कैंसर भी जड़ से खत्म।' यूट्यूब पर इस वीडियो को अबतक 107,733 लोग देख चुके हैं।

झूठी खबर और अफवाहों की हकीकत जानने के लिए वाट्सएप करें:
9205 270 923

देशभर में गायब होने वाले कुल बच्चों में 15 फीसद बंगाल से : रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, कोलकाता : इंटरनेशनल जस्टिस मिशन की ओर से मानव तस्करी मामलों में 50 दोषियों के जीवन पर आधारित पुस्तक 'उम्मीद' का बंगाल की महिला एवं बाल विकास व कल्याण मंत्री शशि पांजा ने विमोचन किया। इस मौके पर आयोजित विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एनजीओ के संचालन निदेशक साजी फिलिप ने बताया कि 2017 में देशभर में लापता हुए बच्चों में से 14.7 फीसद यानी 3,055 बच्चे बंगाल के थे। 2017 की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्य से बच्चों और महिलाओं की तस्करी की घटना पर फिलिप ने कहा कि देश भर में गायब होने वाले 1.19 लाख बच्चों में से 19,671 बंगाल से थे।

बंगाल पड़ोसी बांग्लादेश व नेपाल से होने वाली मानव तस्करी का गंतव्य बन गया है और तस्करी के जरिये यहां आने वाले महिलाओं व बच्चों को शोषण के लिए बेच दिया जाता है, लेकिन इन सब के इतर राज्य पुलिस व गैर सरकारी संगठन पीड़ितों को बचाने की दिशा में तालमेल के साथ काम में लगे हुए हैं।

जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2007 से 2016 के बीच बंगाल में मानव तस्करी के मामलों में 50 दोषियों को पकड़ा गया, जबकि इस समयावधि के दौरान बचाए गए व्यक्तियों में से एक तिहाई विदेशी नागरिक थे और इसमें से भी 42 फीसद नाबालिग थे।

हरिद्वार में देश के पहले हाइब्रिड इम्यूनिटी एसटीपी का किया गया लोकार्पण

जागरण संवाददाता, हरिद्वार

केंद्र की महत्वाकांक्षी परियोजना नमामि गंगे के तहत उत्तराखंड के हरिद्वार में 41.40 करोड़ रुपये की लागत से बने 14 एमएलडी क्षमता वाले हाइब्रिड इम्यूनिटी एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) ने काम करना शुरू कर दिया है। गुरुवार को देश के अपनी तरह के इस पहले एसटीपी का स्वीडन के 16वें राजा कार्ल गुस्ताफ व रानी सिल्विया की मौजूदगी में लोकार्पण किया गया। इस मौके पर कार्ल गुस्ताफ ने गंगा की निर्मलता को हो रहे प्रयासों की सराहना करते हुए पर्यावरण रक्षा के लिए स्वीडन की ओर से निरंतर सहयोग की बात कही।

इस अवसर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गंगा को भारत की आत्मा बताते हुए उसकी निर्मलता का संकल्प दोहराया। उन्होंने शाही परिवार समेत सभी अतिथियों को रुद्राक्ष का पौधा भी भेंट किया। इस दौरान अतिथियों ने एसटीपी और नमामि गंगे-पर्यटन विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया।

हाइब्रिड इम्यूनिटी एसटीपी का शुभारंभ स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताफ व रानी सिल्विया, केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संयुक्त रूप से किया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि गंगा के किनारे ही भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का उदय हुआ है। यही वजह है कि भारतीयों के लिए गंगा सिर्फ एक नदी न होकर देश की आत्मा, विश्वास और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। इसकी निर्मलता, अविरलता और शुद्धता हमारा संकल्प है और इसके लिए हम पूरी दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 14 एमएलडी का यह एसटीपी प्लांट हरिद्वार की अगले 15 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जरूरत पड़ने पर इसका विस्तार भी किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे परियोजना सरकार और जनता के संकल्प एवं समर्पण को परिलक्षित करती है। उन्होंने गंगा जल के प्रदूषित होने की मुख्य वजह खेती-किसानी में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे रसायन और रसायनिक उर्वरकों को बताया। साथ ही सभी का नदी पर्यावरण और आम जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्लास्टिक-पॉलीथिन का इस्तेमाल त्यागने का आह्वान किया।

उत्तराखंड में ऋषिकेश के गंगा माता मंदिर घाट पर गुरुवार को स्वीडन के शाही दंपती राजा कार्ल गुस्ताफ और रानी सिल्विया ने गंगा पूजन किया। शाही दंपती हरिद्वार में हाइब्रिड इम्यूनिटी एसटीपी के लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल हुआ। जागरण

एक लाख घरों का सीवर बनी गंगा, कहां हैं शौचालय

14 दिसंबर को कानपुर में सरकार के गंगा सम्मेलन और नमामि गंगे की समीक्षा से पहले खुल रही सभी की पोल

राहुल शुक्ल, कानपुर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दस केंद्रीय मंत्रियों और गंगा से संबंधित सभी पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित 14 दिसंबर को कानपुर, उप्र में नमामि गंगे परियोजना के कामों की समीक्षा करेंगे। लेकिन संशय यह कि क्या वह वाकई ईमानदार समीक्षा कर सकेंगे। क्योंकि राज्य सरकार उन्हें सच दिखाने की हिम्मत शायद ही जुटा सके।

कानपुर में गंदे नालों को मोड़ा जा रहा है, गंगा किनारे की बस्तियों-गांवों में आनन-फानन शौचालय बन रहे हैं और जलस्तर बढ़ाकर गंगा में बहते पाप को छिपाने का प्रयास जारी है। समीक्षा बैठक से पहले कानपुर में चल रहे इस खेल से अपने पाठकों को हम बुधवार के अंक में अवगत करा चुके हैं। कानपुर ही नहीं, दैनिक जागरण अपनी इस पड़ताल में उप्र के दो अन्य बड़े केंद्रों प्रयागराज और वाराणसी के अलावा बिहार और बंगाल में भी नमामि गंगे की 'समीक्षा' करने में जुट गया है, ताकि देश और प्रधानमंत्री को सच से अवगत कराया जा सके।

नमामि गंगे समीक्षा की... जागरण पड़ताल

पानी से पाप बहाने की कोशिश में नरोरा बांध से बुधवार को 5728 क्यूसिक जल की तुलना में गुरुवार को 8862 क्यूसिक जल छोड़ा गया। तेजी से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा किनारे की गंदगी भी साफ होने लगी है। 14 तक प्रधानमंत्री को गंगा एकदम स्वच्छ दिखेगी। हालांकि यदि वह आचमन करेंगे, जैसा कि कहा जा रहा है, तो गंगाजल में बदबू महसूस कर सकते हैं। फिलहाल कानपुर की बात करते हैं, जहां समीक्षा की तैयारी से पहले ही गंगा सफाई में हुए कामों की पोल एक-एक कर खुल रही है। शहर के एक तिहाई से अधिक हिस्से में सीवर लाइन नहीं है। गंगा किनारे की बस्तियों समेत शहर के करीब एक लाख, जी हां, एक लाख घरों का सीवर गंगा के सीने पर लोट रहा है। सीवेज सिस्टम न होने से पांच लाख से अधिक आबादी क्षेत्र का सीवर नालों में ही जा रहा है। यह हालात तब हैं, जब वर्ष 1989 से अभी तक गंगा की सफाई के नाम पर 1500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो चुके हैं। सीवेज निस्तारण का प्लान भी नहीं बना। शहर का 40 फीसद हिस्सा बिना सीवर लाइन के है।

कानपुर के रानीघाट के पास बस्ती से निकल रहा सीवेज सीधे गंगा में गिर रहा है। धीरज गुप्ता

> यह सही है कि कुछ स्थानों पर सीवर लाइन नहीं है, लेकिन मुझसे पहले के अधिकारियों ने क्या किया, मुझे नहीं पता। पहली प्राथमिकता गंगा में गिर रहे छोटे नालों को गंगा में गिरने से रोकने के लिए अस्थायी रूप से मोड़ना है, हम यही कर रहे हैं।
> **-एचसी कंसल, महाप्रबंधक जल निगम, कानपुर, उप्र**

देखती रही उप्र सरकार : यहां 14 को प्रधानमंत्री स्टीमर (स्वचालित नौका) से गंगा का निरीक्षण करेंगे, इसलिए पहले चरण में गंगा किनारे की बस्तियों में सीवेज सिस्टम का सर्वे हो रहा है, ताकि पर्दा डालने का काम किया जा सके। अभी तक हुए महज 3500 घरों के सर्वे में ही 500 से अधिक घर शौचालय विहीन और 1000 से अधिक सेप्टिक टैंक विहीन मिले हैं। जी हां, बावजूद इसके कि गत दो अक्टूबर को देश 'शौचालययुक्त' घोषित हो चुका है। यानी लोग खुले में शौच जा रहे हैं और घरों का सीवर बरसाती नालियों से जोड़कर गंगा में गिराया जा रहा है।

...और अब भी देख रही : जल निगम और नगर निगम एड़ी चोटी का जोर लगाकर समीक्षा से पहले गंगा को अविरल-निर्मल दिखाने की कोशिश में लगे हैं। इसीलिए बस्तियों में शौचालय बनाने, गंगा की तरफ दिख रहे घरों के सीवर पाइप काटने, उनका मुंह बंद करने का अभियान तेजी से चल रहा है। सीसामऊ नाला बंद कर अपनी पीठ थपथपाने वाले जल निगम और नगर निगम बस्तियों से आ रहे इस जहर को नहीं रोक पाए और यह गंगा के लिए नासूर बन गया।

खर्च हुए 1500 करोड़, 40 फीसद कानपुर सीवरविहीन

गंगा एक्शन प्लान : 166 करोड़ रुपये

जेएनएनयूआरएम : 745 करोड़ रुपये

अमृत योजना : 195 करोड़ रुपये

नमामि गंगे : 433 करोड़ रुपये

> अभी तक हुए 3500 घरों के सर्वे में 500 घर शौचालय विहीन मिले हैं। 50 लोगों ने शौचालय के लिए फार्म भरा है। उनके यहां शौचालय बनवाए जा रहे हैं।
> **-अक्षय त्रिपाठी, नगर आयुक्त एवं नोडल अफसर, नमामि गंगे, कानपुर**

पोल-खोल : पार्ट-2

- स्वच्छ भारत मिशन और आवास योजना का सच भी आ रहा सामने, क्या कर रही थी राज्य सरकार
- **कानपुर का हाल** : एक तिहाई शहर में सीवर लाइन नहीं, अनेक घरों मे शौचालय नहीं, गंगा में बहा रहे गंदगी

शौचालयमुक्त 'स्वच्छ भारत' का सच

- 3500 घरों के सर्वे में ही 500 शौचालय विहीन मिले हैं, 1000 में सेप्टिक टैंक नहीं, सर्वे जारी है
- आधा दर्जन से अधिक नाले घरों का सीवर लेकर गंगा में गिर रहे, नहीं हुए टैप

कह रहे कानपुर के लोग : शौचालय गंदे हैं, कहां जाएं...

रानी घाट निवासी रानी, सीता और रमेश ने बताया कि सेप्टिक टैंक भर गया है। बदबू के नाते खड़े तक नहीं हो सकते। सामुदायिक शौचालय बंद और गंदे हैं। आप ही बताइये हम क्या करें...।

दैनिक जागरण
सबरंग
प्लान वीकेंड के
नई दिल्ली, शुक्रवार, 6 दिसंबर, 2019
सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें :sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

आइफैक्स में आयोजित राबता पेंटिंग प्रदर्शनी का अवलोकन करते पेंटिंग प्रेमी। सभी फोटो -संजय

कलाकार राजेश राठौर ने इस पेंटिंग के जरिए कम उम्र में काम करने वाली बच्चियों के जीवन को दर्शाया है जिन्हें नन्ही सी उम्र में बुरी नजर का सामना करना पड़ता है।

इस बार यहां चलें

थ्रू द लिव्स टू द लाइट

डिंपी मेनन की कलाकृतियां अनूठी हैं। ये कलाकृतियां प्रकृति की आंखों से प्रकाश की खोज करती हैं। इनकी कलाकृतियों में प्रकृति इस कदर जीवंत हो उठती है मानों कैनवस के जरिए दर्शकों से संवाद कर रही हो। आसमान में तारों का चमकना, पक्षियों का चहचहाना, नदियों का इठलाना कलाकृतियां दिल को छू जाती हैं। • **कहां** : गैलरी आर्ट पॉजीटिव, लाडो सराय, दक्षिणी दिल्ली। • **कब** : 11 दिसंबर से 5 फरवरी तक। सुबह दस से शाम छह बजे तक। • **प्रवेश** : निश्शुल्क।

मर्जिंग बॉर्डर

कनाडा और भारत के कलाकारों की यह प्रस्तुति बेहद शानदार है। लता पाडा, डॉ आइ बयान डिबिया, शीला मेहता, हेमा राजगोपालन जैसे कलाकार महफिल में चार चांद लगाएंगे, वहीं महाभारत पर आधारित नृत्य प्रस्तुति भी दर्शकों का दिल जीत लेगी। जिसका केंद्र है पासा का खेल।
• **कहां** : कमानी ऑडिटोरियम, मंडी हाउस, नई दिल्ली।
• **कब** : 12 दिसंबर शाम चार बजे, 13 दिसंबर शाम सात बजे।
• **प्रवेश** : आमंत्रण द्वारा।

स्प्लेंडर इन द ग्रास

विलियम इंगेज की इस खूबसूरत प्रेम कहानी को किरनदीप शर्मा ने हिंदी में रुपांतरित किया है। रोमांटिक और मार्मिक स्पलेंडर इन द ग्रास की कहानी सनी और विशु के इर्द गिर्द घूमती है। 16 साल के दो युवकों के जरिए समाज की सच्चाई को दमदार तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा।
• **कहां** : श्रीराम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट, मंडी हाउस, नई दिल्ली। • **कब** : 6 दिसंबर शाम सात बजे, 7 दिसंबर दोपहर साढ़े तीन बजे। • **प्रवेश** : ऑनलाइन बुकिंग द्वारा। टिकट 200–1000 रुपये।

बेफिक्र बचपन

अल्हड़, बेलौस और बेफिक्र बचपन। उन दिनों की बातें और कारनामे जवानी में भी चेहरे पर मुस्कान ला देती हैं। तो इस वीकेंड ऐसे ही एक इवेंट में चलते हैं, जो चेहरे पर मुस्कान ला देगा। कार्यक्रम में रजत चौहान ऐसे किस्से सुनाएंगे जो बचपन में आपने भी जरूर किए होंगे।
• **कहां** : अक्षरा थियेटर, बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली। • **कब** : सात दिसंबर, रात 8 से 11 बजे तक। • **प्रवेश** : ऑनलाइन बुकिंग द्वारा। टिकट 399 से शुरू।

अब नहीं मानूंगी...चुप नहीं बैठूंगी। कब तक खामोश रहकर भय के लिबास में जियूं...बहुत हुआ अत्याचार अब उठानी है बुलंद आवाज...। क्यों खौफजदा रहूं मैं...यही है आधी आबादी की पूरी आवाज। रंग जब कूची से लिपटे थे तो समझ गए कि अब आंसू बहाने से नहीं,कुछ कर जाने से बदलाव होगा। इसलिए रंगों ने कैनवस पर कूची के साथ कुछ ऐसी ही सशक्तता दिखाई। सबरंग के इस अंक में आपको ऐसी प्रदर्शनी से रूबरू करा रहे हैं

संजीव कुमार मिश्र :

रंगों में संबल

कूची के इशारों पर रंगों ने दिखाया सशक्त रूप

आंखों से आंसू बहाना बंद करो। आवाज को भरभराना बस करो। माथे पर चिंता की लकीरें जंचती नहीं, अब जुल्मों सितम क्यों सहो। ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसायटी में 'राबता' प्रदर्शनी में दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर के कलाकारों ने आधी आबादी के इसी दर्द को कैनवस पर उकेरा। रंग बयां कर रहे थे कि यह मुहिम यह पहल ये आवाज अब नहीं रुकने वाली है। वहीं दिल्ली के कलाकारों ने आधी आबादी के दर्द को दुनिया के सामने रंगों को कैनवस पर उनमुक्त हो दर्शाने के लिए एक आयोजन तय किया है। नौ दिसंबर को आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में कलाकार लगातार हो रही दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ उपजे जनाक्रोश समेत महिलाओं की व्यथा बताएंगे।

राबता की क्यूरेटर इरम खान कहती हैं कि आधी आबादी यहां रंगों में बसी पूरी दुनिया है। उसका हर रूप हर व्यथा, हर आक्रोश यहां आपको दिख जाएगा। यही वह आबादी है जो सदियों से सांस्कृतिक सरोकारों को सहेजती आई है। पीढ़ियों को संस्कार सिखाती आई है। बड़ी शीतलता से वो अपने भीतर दर्द सह लेती है और परिवार के साथ सुख दुख में खड़ी होती है। कहने को तो यह आधी आबादी है लेकिन दुनिया में अब भी वो हाशिए पर है। राबता में करीब 35 कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित रहीं। प्रदर्शनी मे कलाकारों द्वारा पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, फोटोग्राफी और मूर्ति कला आदि को प्रदर्शित किया गया। लेकिन चर्चा का केंद्र आधी आबादी की जिंदगी ही रही। बकौल इरम खान इसका शीर्षक राबता था। यहां हरजीत ढिल्लो, सूरज शुक्ला, दीपा सिंह,ज्योति सिंह, स्वाति सनिल,नेहा मंत्री, गुरबाज कौर, काजल कौर श्रीनिवास, रीना डी सबलोक, पूर्णिमा गुप्ता, लिप्पी परिदा, अनिष्का, साइमा कामरान, राहुल बत्रा, रितिका शर्मा, राजेश राठौर, संध्या रोहतगी, राजकुमार टंडन, अभिनव मुखर्जी, करुणा शर्मा, मंडावी पाठक, कमलेश कुमार, सुधा आदर्श इत्यादि की कलाकृतियां प्रदर्शित थीं।

आयोजन : न्याय
कहां : भारत फाइन आर्ट्स अकादमी, ईस्ट विनोद नगर।
कब : 9 दिसंबर सुबह 11 से शाम पांच बजे तक।
प्रवेश : निश्शुल्क

सोच का आइना ठीक करो

कमलेश कुमार के रंग समाज को आइना दिखाते हैं। इन्होंने बड़ी संजीदगी से महिलाओं के प्रति गलत सोच को कैनवस पर उकेरा है।

संवेदनशील हो व्यवहार

इस कैनवस पर हेमाली गजेंद्र सिंह आधी आबादी के प्रति व्यवहार दिखाते हैं। महिला का आधा चेहरा सफेद जबकि आधा पीला और लाल रंग मिश्रित है। बकौल गजेंद्र महिलाओं के प्रति व्यवहार संवेदनशील होना चाहिए। हेमाली के रंग बेटी पढ़ाओ–बेटी बचाओ का नारा देते हैं। समाज में महिलाएं ऐसा ही तो चाहती हैं। वो कर भी रही हैं लेकिन जब पढ़ी लिख कर बड़ा करने के बाद भी उन्हें जलाकर मार दिया जाता है तो मां की ममता सहम जाती है। हेमाली के रंग कहते हैं...आधी आबादी हर दिन संघर्ष करती है। वो घर से लेकर बाहर तक अपने आप को साबित करना चाहती है लेकिन हर बार उसे एहसास दिलाया जाता है कि वो निर्बल है।

हेमाली गजेंद्र सिंह परमार की पेंटिंग

प्रकृति और मां का अपमान

काजल श्रीनिवास ने स्त्री को प्रकृति की भी मां बताया है। उनकी कला बयां करती है कि समाज प्रकृति और मां दोनों का अपमान कर रहा है। प्रकृति के प्रति भी लोग संवेदी नहीं है जबकि महिलाओं के खिलाफ तो लगातार अत्याचार हो ही रहे हैं। वहीं एक और पेंटिंग है जो एक लड़की के आजाद होने की लालसा को दर्शाती है। वो अपने पंख फैलाना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती।

काजल श्रीवास्तव की पेंटिंग

काली धुंध में उलझा हर कोई

सूरज शुक्ल समकालीन विषयों पर चोट करते हुए फैल रही धुंध, और खतरे में स्त्रियों का अस्तित्व को बखूबी दर्शाते हैं। अपने मुंह पर उस धुंध से बचती हुई जिंदगी की जद्दोजहद करती हुई महिला...। हर दर्शक को आकर्षित करती है।

सूरज शुक्ला की पेंटिंग

न्याय की आवाज

इरम खान कहती हैं कि 9 दिसंबर को एक पोस्टर–पेंटिंग प्रतियोगिता न्याय का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें दिल्ली–एनसीआर के कलाकार महिला आक्रोश को कैनवस पर उकेरेंगे। दरअसल, वसंत विहार हो या फिर हैदराबाद में हाल ही में सामूहिक दुष्कर्म के बाद युवती को जलाकर मार देने की घटना, ये दरिंदगी की हद है। आधी आबादी सुरक्षित नहीं है, वो हर जगह असुरक्षित है। वो डरी सहमी रह रही है। महिलाओं के इसी दर्द और गुस्से को कलाकारों के नजरिए से दर्शक देखेंगे। वहीं एक पेंटिंग में बोलते रंग बानगी करते हैं स्त्री के समाज में प्रमुख अंग होने की। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार मां का है। जो आजीवन अपने बच्चों के लिए बलिदान देती है। मां अपने बच्चों को इस तरह की परवरिश दे कि वो समाज में स्त्री के महत्व को समझे। वो चाहे बेटी, बहन, प्रेमिका, पत्नी, बहू या कोई और हो।

मुगल रसोई से निकली नूर महल बिरयानी

अपनी स्पेशल डिश बनाते हुए शेफ एमपी भंडारी। फोटो- सौजन्य शेफ

बिरयानी : सौजन्य : इंडियन ग्रिल रूम

जायका

आपने तंदूरी जायके, कांटिनेंटल, और थाई तो बहुत जगह खाए होंगे, लेकिन क्या मुगल खानसामों की चुनिंदा रेसिपी से तैयार नूर महल बिरयानी, नवाब वाजिद अली शाह के लिए खास तौर पर ईजाद किए गए गालावटी कबाब (गलौटी कबाब), अवधी दही कबाब जैसे मुगलई जायकों का आनंद लिया है। नहीं न, तो गुरुग्राम के इंडियन ग्रिल रूम में बतौर हेड शेफ कार्यरत एमपी भंडारी इतिहास के पन्नों से इन जायकों को ढूंढ कर आपकी थाली में परोस रहे हैं।

हर तरह के भोजन में महारथ : शेफ भंडारी इंडियन करी, तंदूरी जायके, चाइनीज रेसिपी, कांटिनेंटल, मेक्सिकन और थाई भोजन में खासा अनुभव रखते हैं। शेफ एमपी भंडारी खासतौर पर चिकन डिशेज को इतिहास के पन्नों से तलाश कर लाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मुगल शासक जहांगीर से लेकर वाजिद अली शाह तक के मुगल रसोई से निकली डिशेज को कई रेस्त्रां की मेन्यू में जगह दिलवाई है। उनकी विशेषताओं में अमृतसरी फिश, काजू करी, चिली वाटर चेस्टनट्स, कॉर्न चीज रोल और वेजीटेबल क्रकेट्स जैसी डिशेज शामिल हैं।

चिकन चेटिनाड का बेमिसाल स्वाद : सूखी लाल मिर्च को भून कर कल्पासी, नारियल, राई दाना, साबुत धनिया, जीरा, सौंफ, काली मिर्च, मूंगफली, प्याज, गार्लिक इन जिंजरली ऑयल के साथ मिलाकर अच्छी तरह पीस कर पेस्ट बना लिया जाता है। इस डिश के लिए चिकन को दही, हल्दी पाउडर व मसाले के मिक्सचर में मैरिनेट किया जाता है। इसे हरी धनिया पत्ती के साथ गार्निश कर परोसा जाता है।

इतिहास की गलियों से निकली नूर महल बिरयानी : बिरयानी वेज हो या नॉनवेज उसकी खुशबू ही मुंह में पानी लाने को काफी है। उस पर बिरयानी अगर शाही हो तो कहने ही क्या। अगर आप भी बिरयानी के शौकीन हैं तो शेफ बता रहे हैं कि किस तरह से बिरयानी को और बेहतर और खुशबूदार बनाया जा सकता है। शेफ भंडारी के मुताबिक बिरयानी बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बासमती चावल और केसर मुख्यतौर पर सामग्री में शामिल हो। इसे लंबे समय तक उबालने और भाप देकर छोड़ने से खुशबूदार और स्पंजी बिरयानी बनती है। बिरयानी जितनी धीमी आंच पर और जितने लंबे समय के लिए पकती है उसमें उतना ही स्वाद आता है। इस बिरयानी का नाम नूरजहां दिया गया है। क्योंकि मुगल रसोई में बिरयानी को इसी तरह लंबे समय तक कम आंच पर पकाया जाता था।

मटन गलौटी कबाब का नवाबी स्वाद : नवाब वाजिद अली शाह के शासन में उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए गालावटी कबाब (अब गलौटी कबाब) बनाया गया था। उनके दांत गिर गए थे, लेकिन गोश्त के प्रति वे अपना प्रेम नहीं छोड़ पाए थे। ऐसे में खानसामों ने ऐसी डिश का इजाद किया जो मुंह में रखते ही गल जाए। गालावटी का मतलब था कि मुंह में रखते ही गल जाए। समय के साथ इसका नाम गलौटी कबाब हो गया।

– प्रियंका दुबे मेहता

जहां लोग प्रबंधन से लेकर बैंकिंग व सिविल सर्विसेज को करियर बनाने के सपने देखते हैं वहीं इंडियन ग्रिल रूम के हेड शेफ एमपी भंडारी शुरुआत से ही जायकेदार डिशेज की कल्पना में डूबे रहते थे। डिशेज का फ्यूजन, उनका स्वाद, उनकी खुशबू उनके जेहन में तैरती रहती थी। हमेशा डिशेज की मिक्सिंग, उनकी सजावट के सपने देखते थे। अपने शौक को पूरा करने के लिए बारहवीं कक्षा के बाद उन्होंने इसी क्षेत्र में डिग्री ली और फिर ताज होटल में नियुक्त हुए। विभिन्न होटलों में शेफ का तजुर्बा लेने के बाद वे रेस्त्रां में अच्छे पदों पर पहुंचे और अब वे गुरुग्राम के इंडियन ग्रिल रूम में बतौर हेड शेफ कार्यरत हैं।

साज और संगीत सी है गुरु शिष्य परंपरा

नृत्य संगीत उत्सव

हम अक्सर गुरु-शिष्य परंपरा की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में यह परंपरा क्या है। कैसी होती है गुरु और शिष्य के बीच विश्वास की भावना। भारत में हजारों वर्ष पहले पनपी और वर्तमान में भी फल-फूल रही इस संस्कृति में सूक्ष्म और स्थूल ज्ञान को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता है। इस रागात्मक संबंध और इसकी आभा को देखने और महसूस करने का बेहतरीन जरिया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र परिसर में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय दीक्षा गुरु-शिष्य परंपरा आयोजन।

नाद गुंजन में साज और संगीत की दोस्ती : इस श्रृंखला की चौथी कड़ी में कथक के सरताज पद्मविभूषण पं. बिरजू महाराज एवं उनके शिष्यों समेत पोतियों की प्रस्तुति होगी। तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में नाद गुंजन, ठुमरी मलिका एवं घुंघरू संगीत की प्रस्तुति होगी। पंडित बिरजू महाराज कहते हैं कि नाद गुंजन की सालों बाद प्रस्तुति होगी। यह साज पर आधारित संगीत है। किस तरह साज आपस में बातें करते हैं, समूह बनाते हैं और एकता का भाव दर्शाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शक देख और जान पाएंगे।

गुरु के मन में भेदभाव नहीं होता : पोतियों एवं अन्य शिष्यों को दीक्षा देने में कोई अंतर या फिर किसी तरह की नरमी के सवाल पर बिरजू महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। उस समय मैं सिर्फ गुरु होता हूं। पोतियों ने बचपन से घर में घुंघरुओं की खनक देखी है। अपने पिता को नृत्य करते देखा है, दादा की प्रस्तुति पर तालियां बजते देखा है। इसलिए बचपन से ही ये सीख रही है। कार्यक्रम में पंडित बिरजू महाराज की भी प्रस्तुति होगी।

इन कलाकारों की होगी प्रस्तुति : कार्यक्रम के दूसरे दिन की पहली प्रस्तुति दीपक महाराज, रानी खानम, वास्वती मिश्रा की होगी। जबकि परंपरा सीरीज के आखिरी दिन की पहली प्रस्तुति बिरजू महाराज की घुंघरू संगीत से होगी। इसके बाद मालती श्याम ठुमरी प्रस्तुत करेंगी। ममता महाराज, पंडित जयकिशन महाराज की प्रस्तुति भी होगी। कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति ग्रैंड फिनाले के रूप में पंडित बिरजू महाराज की होगी।

दीक्षा : गुरु-शिष्य परंपरा। सौजन्य : आयोजक

• **आयोजन** : दीक्षा : गुरु–शिष्य परंपरा।
• **कहां** : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र।
• **कब** : 6–8 दिसंबर तक, शाम छह बजे से।
• **प्रवेश** : निश्शुल्क।
• **नजदीकी मेट्रो स्टेशन** : केंद्रीय सचिवालय।

गुरु शिष्य परंपरा का महत्व : दीक्षा के सदस्य सचिव डॉ सच्चिदानंद जोशी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत महत्व है। खास कर रचनात्मक एवं कलात्मक कामों में तो इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। इन्ही बातों को केंद्र में रख कर हमने इस नई श्रृंखला की शुरुआत की है। दीक्षा के माध्यम से सिद्धहस्त गुरु अपने शिष्यों के साथ दर्शकों के सम्मुख अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं।

–संजीव कुमार मिश्र

नेचर ऑफ द सिटी

अलका झांब की कलाकृतियां बसते, बनते शहर की कहानी सुनाती है। शहर और इसकी वास्तुकला ऊर्जा से प्रेरित है और अफसरों के वादों के भीतर है। इसमें वह ऐसे तत्वों का उपयोग करती हैं, जो एक साथ मिलकर गतिशील गुणवत्ता बनाते हैं, जिससे शहर लोगों का पसंदीदा शहर बनता है।
• **कहां** : त्रिवेणी कला संगम, मंडी हाउस, नई दिल्ली। • **कब** : 4–12 दिसंबर, सुबह 11 से रात आठ बजे तक।
• **प्रवेश** : निश्शुल्क।

पैराफिट

इस सप्ताहांत परिवार और दोस्तों के साथ नॉर्थ इंडियन जायके का आनंद लेना चाहते हैं तो पैराफिट जा सकते हैं। यहां नॉनवेज, वेज मेन्यू की विविधता एनसीआर से भी लोगों को यहां खींच लाती है। बटर चिकन, पाश्ता, राजमा, चिकन हांडी सरीखे जायके लाजवाब हैं।
• **कहां** : मिनी डीडीए मार्केट, ई ब्लॉक, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली। • **कब** : सुबह साढ़े नौ से रात 11 बजे तक।
• **शुल्क** : 700 रुपये प्रति दो व्यक्ति।

टेस्टबाज का स्ट्रीट फूड

नॉर्थ इंडियन खाने के साथ अगर स्ट्रटी फूड का भी स्वाद लेना चाहते हैं तो टेस्टबाज बेस्ट है। यहां मोमोज से लेकर बटर चिकन तक लाजवाब है। यहां की दाल मखनी भी उतनी ही प्रसिद्ध है जितना की पनीर टिक्का, बटर चिकन या ड्रम ऑफ हेवेन। तो देर किस बात की इस वीकेंड प्लान कर लें।
• **कहां** : नीयर कैंब्रिज स्कूल, राजौरी गार्डन, पश्चिमी दिल्ली।
• **कब** : सुबह साढ़े ग्यारह से रात 12 बजे तक। • **शुल्क** : 500 रुपये प्रति दो व्यक्ति।

मूडीज ने यस बैंक की रेटिंग घटाई

मुंबई, प्रेट्र : ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने यस बैंक का आउटलुक घटाकर 'नकारात्मक' कर दिया है। एजेंसी ने बैंक की संपत्ति की गुणवत्ता और उसके घटते नकदी भंडार पर चिंता जताई है। बैंक के लिए मूडीज का यह कदम चिंता का विषय है, क्योंकि 10 दिसंबर को बैंक का निदेशक बोर्ड पूंजी जुटाने की योजनाओं पर विचार के लिए बैठक करने वाला है। एजेंसी ने यह भी कहा है कि 200 करोड़ डॉलर जुटाने की बैंक की योजना में टाइमिंग, प्राइसिंग और नियामकीय संबंधी कई जोखिम हैं।

जीईएम के माध्यम से पांच लाख करोड़ रुपये का कारोबार हासिल करना अगले 10 साल से कम की अवधि में संभव होगा।

— पीयूष गोयल
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

सेंसेक्स	40,779.59	▼ 70.70
निफ्टी	12,018.40	▼ 24.80
सोना (प्रति दस ग्राम)	₹ 38,985	▼ ₹74
चांदी (प्रति किलोग्राम)	₹45,539	▼ ₹771
डॉलर	₹71.29	▼ ₹0.24
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 63.21	

कारपोरेट हलचल

एआइएमए का मैनेजमेंट ओलंपियाड

पोसोको को अखिल भारतीय प्रबंध एसोसिएशन (एआइएमए) की तरफ से आयोजित सामान्य ज्ञान (क्विज) ओलंपियाड में अलग-अलग श्रेणियों में तीन कांस्य पदक हासिल हुए हैं। क्विज टीम में सदर्न रीजनल लोड सेंटर के सुदीप एम. और हीरक रॉय शामिल थे। पोसोको के सीएमडी केवीएस बाबा ने विजेता टीम को बधाई दी।

कृभको को एफएआइ से चार पुरस्कार

कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको) की 'बूंद बूंद से खुशहाली' शीर्षक से बनी फिल्म को एफएआइ सम्मेलन में बेस्ट वीडियो का प्रथम पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार माननीय रसायन व उर्वरक राज्यमंत्री मनसुख मंडाविया ने कृभको के विपणन निदेशक वीएस सिरोही को प्रदान किया। उर्वरक सचिव छबीलेंद्र राउल भी इस अवसर पर उपस्थिति थे। कृभको को तीन पुरस्कार और मिले हैं।

मनोज कुमार बने ईडीसीआइएल के सीएमडी

मनोज कुमार ने ईडीसीआइएल (इंडिया) लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पद का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पूर्व मनोज कंपनी में ही एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (प्रोजेक्ट्स) के पद पर कार्यरत थे। वह यूपीएससी की इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के 1994 बैच के अधिकारी हैं।

डीके सिंह ने पावरग्रिड में संभाला कार्यभार

पावरग्रिड में एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीके सिंह ने उत्तरी क्षेत्र-1 के प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पूर्व वह पावरग्रिड पश्चिमी क्षेत्र-2 के प्रमुख के तौर पर अपनी सेवा दे रहे थे। सिंह को विद्युत के क्षेत्र में काम करने का लगभग 30 वर्ष का अनुभव है।

किसी भी बड़ी एनबीएफसी को हम टूटने नहीं देंगे : दास

मुंबई, प्रेट्र : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि किसी भी बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को टूटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरबीआइ एनबीएफसी सेक्टर की स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है और बैंक भी अब इस सेक्टर की बेहतर प्रबंधन वाली कंपनियों को कर्ज देना शुरू कर चुके हैं।

दास का कहना था कि इस सेक्टर में देश की शीर्ष 50 एनबीएफसी की करीब 70 प्रतिशत हिस्सेदारी है। आरबीआइ इन सभी पर पैनी नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी बैंक को जरूरी लगेगा, वह बड़ी एनबीएफसी को विफल होने से रोकने के लिए सभी उपयुक्त कदम उठाएगा। गौरतलब है कि पिछले वर्ष इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आइएलएंडएफएस) की दुर्गति शुरू होने के बाद से ही यह सेक्टर गंभीर वित्तीय कमी से जूझ रहा है। सेक्टर की अन्य बड़ी कंपनियों में एक दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) की दिवालिया प्रक्रिया शुरू हो गई है। आरबीआइ भी सेक्टर की प्रमुख कंपनियों के साथ नियमित अंतराल पर बैठकें कर रहा है। आरबीआइ का कहना था कि एनबीएफसी को तरलता उपलब्ध कराई जा रही है और अच्छी व खराब एनबीएफसी की बाजार भी पहचान कर रहा है।

निजी डिजिटल करेंसी को किसी कीमत पर मंजूरी नहीं : दास ने देश में निजी तौर पर जारी की जाने वाली किसी भी डिजिटल करेंसी को मंजूरी देने की सभी संभावनाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया है। गुरुवार को मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने कहा कि बैंक

शक्तिकांत दास। फाइल

- **आरबीआइ ने दिया भरोसा, कहा - सेक्टर पर केंद्रीय बैंक की पैनी नजर**
- **सेक्टर की तरलता स्थिति सुधारने के उपाय करने की भी बात कही**

ऐसी किसी भी करेंसी को इजाजत देने के पक्ष में कतई नहीं है। हालांकि, आरबीआइ खुद की डिजिटल करेंसी जारी करने के पर गौर कर रहा है।

दास ने कहा कि टेक्नोलॉजी से संबंधित दिक्कतों के चलते आधिकारिक डिजिटल करेंसी पेश करने के बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उनका कहना था कि दुनियाभर में सरकारें और केंद्रीय बैंक निजी डिजिटल करेंसी के खिलाफ हैं, क्योंकि करेंसी जारी करने का अधिकार सरकारी निकायों के पास है और इसे स्वायत्त एजेंसी की तरफ से ही जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्य देशों की सरकारों और केंद्रीय बैंकों के साथ सरकारी डिजिटल करेंसी के बारे में काफी चर्चा हुई है, लेकिन अभी इस बारे में कुछ कह पाना जल्दीबाजी होगी।

सही समय पर होगा फैसला

दास ने कहा कि जब पर्याप्त सुरक्षा के साथ टेक्नोलॉजी और विकसित हो जाएगी, मुझे लगता है कि यह ऐसा क्षेत्र है, जिसके ऊपर सही समय आने पर रिजर्व बैंक निश्चित रूप से गौर करेगा। गौरतलब है कि करीब एक वर्ष पहले सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी और बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी को अवैध करार दिया था। आरबीआइ ने ऐसी किसी भी करेंसी में लेनदेन पर रोक लगा दी थी। हालांकि, इसी वर्ष सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक ने लिब्रा नाम से डिजिटल करेंसी जारी करने की घोषणा कर दी है।

इन पर भी बोले दास

विदेशी मुद्रा भंडार : दास ने कहा कि तीन दिसंबर को देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 45,170 करोड़ रुपये (करीब 31.62 लाख करोड़ रुपये) पर जा पहुंचा है, जो अब तक का उच्च स्तर है। चालू वित्त वर्ष की शुरुआत से अब तक विदेशी मुद्रा भंडार में 3,880 करोड़ डॉलर (करीब 2.52 लाख करोड़ रुपये) की बढ़ोतरी हो चुकी है।

ग्राहकों को मिलने वाला फायदा : गुरुवार से पहले इस वर्ष आरबीआइ पांच बार रेपो रेट में कटौती कर चुका था। हालांकि जानकारों का मानना था कि बैंकों ने ग्राहकों तक इसका समुचित फायदा नहीं पहुंचाया। इस पर दास ने कहा कि अब तक बैंकों ने रेपो रेट में कटौती का जितना फायदा ग्राहकों तक पहुंचाया है, उससे केंद्रीय बैंक संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि सभी बैंकों से अपनी ब्याज दरों को किसी बाहरी बेंचमार्क से जोड़ना था और ज्यादातर बैंक ऐसा कर चुके हैं। इसके बाद ग्राहकों को मिलने वाले फायदे में सुधार की पूरी उम्मीद है।

पीएमसी बैंक पर : दास ने कहा कि पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट इस महीने के अंत तक मिल जाने की उम्मीद है। आरबीआइ इस कोशिश में है कि बैंक की ऐसी भरोसेमंद संपत्तियों की पहचान की जाए, जिनकी बिक्री संभव हो सके। उन्होंने कहा कि को-ऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के प्रभावी नियमन के लिए नियमों में सुधार संबंधी सलाह भी केंद्रीय बैंक ने दिया है। गौरतलब है कि पीएमसी बैंक में करीब 6,500 करोड़ रुपये तक घोटाले और उसमें से 4,300 करोड़ रुपये से ज्यादा के एनपीए बन जाने के बाद 23 सितंबर को आरबीआइ ने उस पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे।

जारी होगा नया प्रीपेड भुगतान कार्ड

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : लेस-कैश इकोनॉमी को बढ़ावा देने की अपनी नीति को आगे बढ़ाते हुए आरबीआइ ने 10 हजार रुपये तक के भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए एक और कार्ड जारी करने का फैसला किया है। यह प्रीपेड भुगतान (पीपीआइ) व्यवस्था के तहत होगा। जिसका इस्तेमाल 10 हजार रुपये तक की वस्तुओं या सेवाओं के भुगतान के लिए किया जा सकेगा। इसकी घोषणा मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए आरबीआइ गवर्नर डॉ. शक्तिकांत दास ने की। यह पीपीआइ बैंक खाते से जुड़ा होगा। लेकिन इसे जारी करने के लिए ज्यादा कड़े कायदे कानून नहीं होंगे बल्कि ग्राहकों की बहुत ही आधारभूत सूचना के आधार पर ही जारी कर दिया जाएगा। यह बैंक खाते से जुड़ा होगा लेकिन इसमें क्रेडिट कार्ड से भी राशि डाली जा सकेगी। इसके साथ ही आरबीआइ ने शहरी सहकारी बैंकों पर नियमन को और कसने की व्यवस्था की है। 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की पूंजी वाले देश के सभी शहरी सहकारी बैंकों को क्रिलिक (सेंटर रिपॉजिटरी आफ इन्फॉरमेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स) के तहत लाया जाएगा। क्रिलिक में देश के लगभग सभी वाणिज्यिक बैंक शामिल होते हैं। इसके अलावा वित्तीय संस्थानों को भी इसमें शामिल किया जाता है। इन बैंकों व संस्थानों को अपने बड़े ग्राहकों व कर्ज लेने वाले संस्थानों की सूचना साझा करनी होती है। इससे एक ग्राहक अगर कोई गड़बड़ी करता है या उसके खाते में कोई समस्या आती है तो उसकी जानकारी सभी को हो जाती है। इस व्यवस्था को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश बाद में जारी किया जाएगा। इसकी घोषणा भी मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए की गई है। सहकारी बैंकों के लिए आरबीआइ ने यह भी कहा है कि उनके नियमन से जुड़े दूसरे दिशानिर्देशों को भी आगे संशोधन किया जाएगा। इन कदमों का उद्देश्य यही है कि पंजाब व महाराष्ट्र सहकारी बैंक जैसी समस्या फिर किसी शहरी सहकारी बैंक में पैदा ना हो।

आरएसएफ लागू नहीं होने से गन्ना किसानों को हुआ बड़ा नुकसान

सीएसीपी चेयरमैन बोले ▶ 'रेवन्यू शेयरिंग फार्मूला' से किसानों को मिलते और 9,000 करोड़

गन्ना किसानों के लिए लागत को बताया बड़ी चुनौती, कहा, सेक्टर को मशीनीकरण की सख्त जरूरत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

गन्ना मूल्य निर्धारण को लेकर किसान संगठनों और चीनी उद्योग के बीच होने वाली रस्साकशी के लिए सीएसीपी चेयरमैन प्रो. विजयपाल शर्मा ने गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अगर 'रेवन्यू शेयरिंग फॉर्मूला' अपनाया गया होता तो पिछले 10 सालों में गन्ना किसानों को आठ से नौ हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होती।' यह वही फॉर्मूला है, जिसका जिक्र रंगराजन समिति की सिफारिशों में किया गया था। लेकिन गन्ना किसान संगठनों के विरोध के चलते किसी राज्य में इसे लागू नहीं किया जा सका।

प्रतीकात्मक

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) की 85वीं वार्षिक आमसभा में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) चेयरमैन शर्मा ने कहा, 'खेतिहर मजदूरों की मजदूरी बढ़ने से गन्ना खेती की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है। इसलिए आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली मेकनाइजेशन की सख्त जरूरत है। चीनी उद्योग को आगे बढ़कर इसमें सहयोग करना चाहिए।' उन्होंने कहा कि गन्ने से चीनी के अलावा अन्य उत्पाद बनाने की जरूरत है। पिछले कई सालों से देश में गन्ना और चीनी दोनों का अत्यधिक उत्पादन हुआ, जिसके लिए किसान और उद्योग बधाई के पात्र हैं। लेकिन दोनों क्षेत्रों के लिए यह गंभीर चुनौती बन गईं।

इसके पूर्व इस्मा के चेयरमैन रोहित पवार ने चीनी उद्योग की चुनौतियों का ब्यौरा पेश किया। इसमें उन्होंने गन्ने के उचित व लाभकारी मूल्य (एफआरपी) और कुछ राज्यों में लागू होने वाली राज्य समर्थित मूल्य (एसएपी) के नकारात्मक प्रभावों का विशेष रूप से उल्लेख किया।

दरअसल, चीनी की उत्पादन लागत अधिक होने की वजह से घरेलू बाजार की महंगी चीनी की वैश्विक बाजार में कोई पूछ नहीं हुई। लिहाजा, चीनी उद्योग के समक्ष वित्तीय संकट पैदा हो गया, जिससे भुगतान न होने से किसानों का एरियर बढ़ गया। शर्मा ने कहा कि एक ओर किसान अपने गन्ने का अधिक मूल्य चाहता है तो चीनी मिलें सस्ता कच्चा (गन्ना) चाहती हैं, जो परस्पर विरोधी बातें हैं। इसके लिए दोनों पक्षों के बीच समन्वय बनाने की सख्त आवश्यकता है। ऐसा न होने से भरोसे का संकट पैदा होता है। गन्ने की खेती की लागत कैसे कम हो, इस पर फोकस होना चाहिए। गन्ना खेती में पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिसकी भारी किल्लत होती जा रही है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में पानी की बड़ी किल्लत है। इसके लिए सिंचाई की आधुनिक तकनीक पर जोर देने की जरूरत है।

सीएसीपी चेयरमैन ने कहा कि एक ओर चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू खपत स्थिर है। इसलिए ऊर्जा क्षेत्र अहम हो गया है, जिसमें अपार संभावनाएं है। चीनी उद्योग को सिर्फ चार महीने चलता है, इससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा नहीं की जा सकती है। घरेलू चीनी उद्योग को इस दिशा में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। चीनी मूल्य को बढ़ाना ही समस्या का समाधान नहीं है, क्यों कि इसमें उपभोक्ता भी एक पक्ष है, जिसका ध्यान रखना जरूरी है। इस समय उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

आइजीएसटी के फंसे सेटलमेंट का निदान ढूंढेगा मंत्रिसमूह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्र और राज्यों के बीच आइजीएसटी के बकाया के सेटलमेंट का निदान निकालने के लिए एक मंत्रिसमूह का गठन किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी संयोजक होंगी, जबकि छह राज्यों वित्त मंत्री इसमें सदस्य के तौर पर शामिल किए गए हैं। ये सभी जीएसटी काउंसिल के भी सदस्य हैं।

बुधवार को जारी काउंसिल के सर्कुलर के मुताबिक मंत्रियों का यह समूह 31 मार्च, 2018 तक के आइजीएसटी सेटलमेंट का अध्ययन करेगा। समूह इस पर विस्तार से विचार कर तय करेगा कि आगे क्या कदम उठाया जाना है। समूह में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी, बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, छत्तीसगढ़ के कमर्शियल टैक्स मंत्री टीएस सिंहदेव, ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और तमिलनाडु के मत्स्य और कार्मिक व प्रशासनिक सुधार मंत्री डी. जयकुमार सदस्य बनाये गए हैं। मंत्रिसमूह की सिफारिशों को जीएसटी काउंसिल को सौंपा जाएगा।

आइजीएसटी का मामला लंबे समय से फंसा हुआ है। 31 मार्च 2018 तक आइजीएसटी के 1,76,688 करोड़ रुपये की राशि का सेटलमेंट नहीं हो पाया था। राज्यों की मांग इस राशि के निपटारे की है। सरकार ने इस राशि को राज्यों को देने के बजाय केंद्र के कंसोलिडेटेड फंड में डाल दिया था। इस मुद्दे को सीएजी ने भी 2017-18 की अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। गौरतलब है कि बुधवार को कुछ राज्यों के वित्त मंत्रियों ने सीतारमण के साथ मुलाकात कर कंपेंसेशन के भुगतान में हो रहे विलंब की शिकायत की थी। राज्यों का कहना है कि यदि जल्द ही इस राशि का भुगतान नहीं हुआ तो राज्यों की वित्तीय हालत और खराब हो जाएगी।

भारत में फ्यूलसेल कार लांच करेगी ह्युंडई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी ह्युंडई मोटर इंडिया ने प्रदूषण के खिलाफ एक बड़े अभियान की शुरुआत की है। कंपनी ने भारतीय बाजार में फ्यूलसेल कारें उतारने के लिए अध्ययन शुरू किया है। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि वह भारत सरकार की जीरो इमीशन मोबिलिटी यानी प्रदूषण-मुक्त परिवहन की अवधारणा का सम्मान करती है और उसी को आगे बढ़ाने के लिए फ्यूलसेल इलेक्ट्रिक कारों को लांच करने को लेकर गंभीर है। ये कारें बिजली से ही चलती हैं। लेकिन इनमें बैट्री की जगह फ्यूलसेल लगी होती हैं। इससे बैट्री से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकता है। कुछ समय पहले प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में इस तकनीक को अपनाने पर बात हुई थी।

हाल ही में मुंबई में वाहन बनाने वाली कंपनियों के अंतरराष्ट्रीय संगठन का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। इसमें फ्यूलसेल तकनीक पर काम करने वाली कोरियाई कंपनियों ने कोरिया मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में अपनी भावी योजनाओं के बारे में बताया था। ह्युंडई इस तकनीक पर आधारित कार 'नेक्सो' लांच कर चुकी है और उसे काफी पसंद किया जा रहा है। माना जा रहा है कि कंपनी भारत में भी अगले वर्ष नेक्सो को उतार

प्रतीकात्मक

- **इसके लिए कंपनी ने भारतीय बाजार का अध्ययन शुरू किया**
- **इस तरीके से प्रदूषण की संभावना होती है पूरी तरह खत्म**

सकती है। कुछ महीने पहले ही कंपनी ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार कोना लांच की है। कंपनी का दावा है कि इसके फ्यूलसेल कार सही मायने में जीरो इमीशन पर खरे उतरते हैं, क्योंकि इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला सेल पर्यावरण को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसा इसलिए होता है कि फ्यूलसेल हाइड्रोजन से बिजली पैदा करने की तकनीक पर काम करता है।

हाल ही में इस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए अध्ययन से यह बात सामने आई है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए यह तकनीक महंगी होने के बावजूद सामान्य इलेक्ट्रिक कारों के मुकाबले कई गुना बेहतर है।

संजीव जुनेजा को अवार्ड

चंडीगढ़, (वि) : एसबीएस बायोटेक के सीएमडी डॉ. संजीव जुनेजा को मुंबई में 'मोस्ट एडमायर्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2018-19' अवार्ड से सम्मानित किया गया। एबीपी न्यूज नेटवर्क एंड वर्ल्ड मार्केटिंग कांग्रेस के तत्वाधान में 'ब्रांड एक्सीलेंस अवार्ड्स - 2019' का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण भारत के 20 प्रमुख व्यवसायों को सम्मानित करने हेतु यह अवार्ड्स दिए गए। एबीपी न्यूज नेटवर्क द्वारा ब्रांड के वित्तीय मूल्यांकन, उपभोक्ता वरीयता, आम लोगों की संतुष्टि जैसे पैमानों को आधार मान एक स्वतंत्र ज्यूरी से विजेताओं को शॉर्टलिस्ट किया। डॉ. संजीव जुनेजा विश्व-प्रसिद्ध बिजनेस टाइकून और भारत की प्रसिद्ध आयुर्वेदिक कंपनी 'एसबीएस बायोटेक यूनिट 2' और 'दिविसा हर्बल केयर' के संस्थापक हैं।

सेटअप और बाजार, फिर भी बीएसपी लाचार

भिलाई, नईदुनिया

भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) घरेलू बाजार पर पकड़ नहीं बना पा रहा है। सेटअप और बाजार भी उसके साथ है, लेकिन उत्पादन की रफ्तार हद से ज्यादा कम होने की वजह से वह पिछड़ा हुआ है। बाजार की मांग के अनुरूप इस्पात की सप्लाई ही नहीं कर पा रहा है। करीब 1,200 करोड़ रुपये की लागत से तैयार बार एंड रॉड मिल (बीआरएम) में आए दिन तकनीकी खामियों से उत्पादन को रोकना पड़ता है। पूर्व में एक शिफ्ट में 250 से 300 बिलेट की रोलिंग होती थी, जिससे सरिया बनता है। मौजूदा समय में करीब 150 बिलेट की ही रोलिंग हो पा रही है। भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारी बताते हैं कि

- **बीआरएम की उत्पादन क्षमता सालाना नौ लाख टन, नवंबर में 25,693 टन रोलिंग हुई**

एक्सपांशन प्रोजेक्ट की लेटलतीफी की वजह से इसके कई पार्ट्स खराब हो चुके हैं। साथ ही स्पेयर पार्ट्स का भी अभाव है। विदेशी तकनीक से तैयार बीआरएम के पास पार्ट्स न होने से आये दिन काम रोकना पड़ता है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी और स्वदेशी पार्ट्स से किसी तरह उत्पादन को जारी किया जाता है। तकनीकी दिक्कत की वजह से उत्पादन की रफ्तार भी कम हो जाती है। बीआरएम की क्षमता नौ लाख टन है। इसने नवंबर में 25,693 टन रोलिंग किया। सबसे खास यह है कि बीएसपी ने जिस देश के सरकारी प्रोजेक्ट के लिए सरिया भेजा है, वहां मांग बढ़ती जा रही है। विश्वास बढ़ रहा है। बीएसपी के स्टील की क्वालिटी की वजह से बार-बार मांग की जा रही है, लेकिन उत्पादन कम होने से सप्लाई नहीं हो रही। इस वजह से घरेलू बाजार का लाभ भी सेल नहीं उठा पा रहा है।

बीएसपी का फोकस रेल पटरी उत्पादन पर : रेलवे से करीब 13 लाख टन रेल पटरी का ऑर्डर बीएसपी को मिला है। इसे पूरा करने के लिए रेल पटरी उत्पादन पर प्रबंधन द्वारा जोर दिया जा रहा है। यूनिवर्सल रेल मिल ने नवंबर में 52,756 टन फिनिश्ड रेल्स का सर्वाधिक उत्पादन किया, जिसमें 47,087 टन प्राइम यूटीएस-90 रेल्स का उत्पादन किया। मार्च 2019 के 44,047 टन रेल्स के उत्पादन और अक्टूबर में 44,711 टन प्राइम रेल्स के उत्पादन रिकॉर्ड को तोड़ते हुए यूआरएम ने एक नया मासिक उत्पादन का कीर्तिमान स्थापित किया है। यूआरएम ने एक दिसंबर को 'ए' शिफ्ट में 132 ब्लूम्स की रोलिंग कर नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पूर्व 27 नवंबर को 'बी' शिफ्ट में 131 ब्लूम्स की रोलिंग कर रिकॉर्ड स्थापित किया गया था। ऐसा इसलिए संभव हो सका कि बीएसपी ने ब्लूम्स उत्पादन पर जोर दिया, जिससे रेल पटरी बनती है। सरिया आदि के लिए बिलेट का उत्पादन किया जाता है, उसे फिलहाल दूसरे पायदान पर रखा गया है। बावजूद, बीआरएम ने नवंबर में 25,693 टन रोलिंग कर अब तक का सर्वश्रेष्ठ मासिक उत्पादन का कीर्तिमान स्थापित किया, लेकिन क्षमता के हिसाब से उत्पादन अब भी पीछे है।

हालात

सेंसेक्स में 70.70, निफ्टी में 24.80 अंकों की गिरावट, ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील स्टॉक्स दिखे सुस्त

रेट कट नहीं होने से बाजार मायूस

मुंबई, प्रेट्र : इस सप्ताह नीतिगत ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे शेयर बाजारों को मायूसी हाथ लगी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) द्वारा रेपो रेट में कटौती नहीं किए जाने के चलते प्रमुख सूचकांक फिसलकर बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 70.70 अंक यानी 0.17 प्रतिशत गिरकर 40,779.59 अंक पर स्थिर हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी भी 24.80 अंकों यानी 0.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 12,018.40 अंक पर बंद हुआ।

जानकारों का कहना था कि निवेशक ब्याज दरों में कटौती नहीं होने के मुकाबले जीडीपी विकास दर अनुमान घटाने के चलते ज्यादा चिंतित हुए। आरबीआइ का कहना था कि उसे महंगाई दर थामने की ज्यादा चिंता है। गुरुवार को सेंसेक्स पैक में भारती एयरटेल, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प और टाटा मोटर्स के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। ब्याज दर के प्रति संवेदनशील स्टॉक्स भी सपाट या नकारात्मक स्तर पर बंद हुए। हालांकि टीसीएस, आइटीसी, एलएंडटी, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और एचडीएफसी के शेयरों की मजबूती ने

प्रतीकात्मक

सेंसेक्स को बड़ी गिरावट से बचा लिया।

दिन के कारोबार के बारे में जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की अर्थशास्त्री दीप्ति मैरी मैथ्यू ने कहा कि आरबीआइ का रेपो रेट अपरिवर्तित रखना चौंकाने वाला फैसला था। बाजार कम से कम 25 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद कर रहा था। हालांकि बैंक ने कहा है कि भविष्य में रेपो रेट में कटौती की पूरी गुंजाइश बची हुई है।

सेक्टोरल इंडेक्स के मामले में बीएसई मेटल में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। बेसिक मेटल और एनर्जी सेक्टोरल इंडेक्स भी फिसले। दूसरी तरफ कैपिटल गुड्स, आइटी व टेक सेक्टोरल इंडेक्स में मजबूती देखी गई। बीएसई मिडकैप व लार्जकैप का प्रदर्शन सेंसेक्स से बेहतर रहा। वहीं, स्मॉलकैप लगभग सपाट स्तर पर बंद हुआ।

इनमें रही गहमागहमी

रेट-सेंसिटिव स्टॉक्स : ब्याज दरों के मामले में संवेदनशील स्टॉक्स में गुरुवार को खासा गहमागहमी देखी गई। बीएसई में इंडसइंड बैंक (2.21 प्रतिशत), आरबीएल बैंक (1.95 प्रतिशत), एसबीआइ (1.65 प्रतिशत), यस बैंक (1.51 प्रतिशत), एक्सिस बैंक (1.39 प्रतिशत), फेडरल बैंक (1.25 प्रतिशत), एचडीएफसी बैंक (0.50 प्रतिशत), कोटक महिंद्रा बैंक (0.46 प्रतिशत) और आइसीआइसीआइ बैंक (0.27 प्रतिशत) पर खासा दबाव देखा गया। बीएसई का बैंक इंडेक्स 0.76 प्रतिशत टूटकर बंद हुआ।

वोडाफोन आइडिया : रेटिंग डाउनग्रेड होने के चलते गुरुवार को बीएसई में वोडाफोन आइडिया के शेयर 5.56 प्रतिशत गिरकर 7.31 रुपये के स्तर पर बंद हुए। एनएसई में कंपनी के शेयर 5.81 प्रतिशत टूटकर 7.30 रुपये पर स्थिर हुए।

चीन की पांच कंपनियां ग्रेनो में करेंगी आठ सौ करोड़ का निवेश

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

- **इकाई लगाने के लिए प्राधिकरण से मांगी सौ एकड़ जमीन**
- **चीन के साथ-साथ ताइवान, कोरिया आदि की कंपनियां भी दिखा रही हैं रुचि**

चीन की पांच कंपनियां ग्रेटर नोएडा में आठ सौ करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। यह कंपनियां चीन की हॉलीटेक इंडिया प्रा. लिमिटेड की सहयोगी कंपनियां हैं। कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण से मिलकर उन्हें पत्र सौंपा। कंपनियों ने इकाई लगाने के लिए सौ एकड़ जमीन मांगी है।

हॉलीटेक इंडिया की ग्रेटर नोएडा में चार इकाइयां हैं। इसमें करीब चार सौ करोड़ का पूंजी निवेश है। कंपनी ग्रेटर नोएडा स्थित इकाईयों में मोबाइल स्क्रीन, कैमरा, फिंगर प्रिंट, एफपीसी का निर्माण करती है। कंपनी ने प्राधिकरण अधिकारियों से 1300 करोड़ के और पूंजी निवेश का वादा किया है। इसके साथ ही सहयोगी कंपनियों के लिए सौ एकड़ जमीन मांगी है। इनमें आठ सौ करोड़ का निवेश होगा।

भूषण ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिया कि प्राधिकरण उन्हें सरकार की नीति के अनुरूप सभी सहयोग देगा। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को प्रदेश सरकार की नीति एवं मिलने वाली छूट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध कराने के लिए किसानों से भूमि क्रय की जा रही है। नरेंद्र भूषण ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में निवेश के लिए चीन के साथ-साथ ताइवान, कोरिया आदि की कंपनियों की रुचि बढ़ी है। अगले तीन साल में विश्व में बनने वाले स्मार्ट फोन में एक तिहाई ग्रेटर नोएडा में बनने लगेंगे। उल्लेखनीय है कि भूषण के नेतृत्व में प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दिनों चीन का दौरा कर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए न्योता दिया था।

15वें वित्त आयोग ने सौंपी पहली रिपोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दी है। आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों की जानकारी भी दी।

सरकार आयोग की सिफारिशों को सार्वजनिक करने का फैसला बाद में लेगी। सूत्र बताते हैं कि पहले इसे संसद में पेश किया जाएगा। सरकार ने 27 नवंबर, 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन किया था। उस वक्त इसे 2020 से 2025 के लिए अपनी सिफारिशें देनी थी। लेकिन इसी वर्ष 27 नवंबर को सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके 30 नवंबर 2019 तक पहली रिपोर्ट 2020-21 के वित्त वर्ष के लिए देना तय किया था। इसके बाद आयोग 2021 से 2026 तक की अवधि के लिए अपनी दूसरी रिपोर्ट में सिफारिशें देगी। इस तरह आयोग कुल छह वर्ष के लिए सरकार को सिफारिश देगा। अभी तक वित्त आयोग पांच वर्ष की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार करता आया है। इसी प्रक्रिया में सरकार ने आयोग का कार्यकाल भी 30 अक्टूबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया था।

2011 से सीरिया में चल रहे गृह युद्ध के दौरान विरोध प्रदर्शनों के दमन के लिए सरकार की कार्रवाई में अब तक लगभग तीन लाख 70 हजार लोगों की जान जा चुकी है।

कंगाली से उबरने को इमरान सरकार बेचेगी संपत्तियां

इस्लामाबाद, प्रेट्र : प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार ने मुल्क को आर्थिक तंगी से उबारने के लिए अप्रयुक्त सरकारी संपत्तियों को बेचने का फैसला किया है। पिछले साल सत्ता में आने के बाद इमरान ने प्रधानमंत्री आवास के कई वाहनों, हेलीकॉप्टरों और भैंसों तक को बेच दिया था। लेकिन इससे उन्हें उम्मीद से कम आय हुई थी। आर्थिक मदद पाने की आस में इमरान चीन और सऊदी अरब समेत कई देशों का दौरा कर चुके हैं।

पाकिस्तानी मीडिया में गुरुवार को आई खबर के अनुसार, इमरान सरकार को उम्मीद है कि कीमती सरकारी संपत्तियों की बिक्री से विदेशी और पाकिस्तानी निवेशक आकर्षित होंगे और मुल्क की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। इमरान ने कहा है कि अप्रयुक्त सरकारी संपत्तियों की बिक्री से मिलने वाली रकम का उपयोग जन कल्याणकारी परियोजनाओं पर किया जाएगा।

डॉन अखबार के अनुसार, सरकारी संपत्तियों की बिक्री दुबई एक्सपो में होगी। निजीकरण मामलों के सचिव रिजवान मलिक ने कहा, 'दुबई एक्सपो में अप्रयुक्त सरकारी संपत्तियों को बेचने से विदेशी और पाकिस्तानी निवेशक आकर्षित होंगे।'

▸ दुबई एक्सपो में होगी अप्रयुक्त सरकारी संपत्तियों की बिक्री

इमरान खान। फाइल

जबकि न्यूज इंटरनेशनल अखबार में इमरान के हवाले से कहा गया है, 'दुर्भाग्य की बात यह है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इन बहुमूल्य संपत्तियों की अनदेखी की। हर साल अरबों रुपये के नुकसान के बावजूद उन्होंने इन संपत्तियों का कोई उपयोग नहीं किया।'

अधिकारियों को दी चेतावनी : इमरान ने अधिकारियों को यह चेतावनी भी दी है कि अप्रयुक्त सरकारी संपत्तियों की पहचान में रोड़ा खड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लक्जरी कारों और भैंसों की हुई थी नीलामी : इमरान सरकार ने पिछले साल सितंबर में आलीशान प्रधानमंत्री आवास के कई बुलेटप्रूफ वाहनों समेत 70 लक्जरी कारें नीलाम की थीं। इसके अलावा चार सरकारी हेलीकॉप्टर और नवाज शरीफ के कार्यकाल में पीएम हाउस में पाली गई आठ भैंसें भी बेची गई थीं।

पाकिस्तान में महंगाई नौ साल के उच्च स्तर पर

इस्लामाबाद, एएनआइ : कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान के नागरिकों पर आसमान छूती महंगाई की मार पड़ी है। पाकिस्तान में महंगाई दर नौ साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण महंगाई दर बढ़कर 12.7 फीसद हो गई है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने हालांकि दावा किया कि अगले माह से महंगाई में कमी आ जाएगी। लेकिन आर्थिक विशेषज्ञ अशफाक हसन खान का अनुमान है कि दिसंबर में महंगाई दर 13 फीसद के पार जा सकती है। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री इमरान खान की आर्थिक मामलों की सलाहकार समिति ने भारत के साथ कारोबार बंद होने को पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई का कारण बताया था।

400 रुपये किलो बिक रहा टमाटर

पाकिस्तान में टमाटर के दाम 400 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। प्याज और अन्य सब्जियां भी काफी महंगी हो गई हैं। शिमला मिर्च 200 रुपये प्रतिकिलो बिक रहा है।

इनसे मिली आर्थिक मदद

खस्ताहाल पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने इस साल जुलाई में छह अरब डॉलर (करीब 42 हजार करोड़ रुपये) का कर्ज मंजूर किया था। इसके अलावा पाकिस्तान को चीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से भी अरबों रुपये का आर्थिक पैकेज मिल चुका है।

इमरान के कार्यकाल में पाक ने लिया 10.40 अरब डॉलर का कर्ज

इस्लामाबाद, प्रेट्र : इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान ने चीन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अपने मित्र देशों से 10.40 अरब डॉलर (करीब 74 हजार करोड़ रुपये) का कर्ज लिया। यह कर्ज विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करने और पुराने लोन के भुगतान की खातिर लिया गया।

गत वर्ष अगस्त में प्रधानमंत्री बनने वाले इमरान खान ने मुल्क की बदहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास में ना सिर्फ अपने मित्र देशों के दौरे किए, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद की गुहार भी लगाई। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से दाखिल रिपोर्ट के अनुसार, इमरान सरकार ने चीन, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोपीय बैंकों से व्यावसायिक कर्ज लिया। इस तरह के कुल 4.80 अरब डॉलर (करीब 34 हजार करोड़ रुपये) के कर्ज लिए गए हैं। इसके अलावा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कर्ज भी लिए गए। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने इस साल मई में सीनेट को बताया था कि मुल्क पर विदेशी कर्ज बढ़कर 88.20 अरब डॉलर (करीब छह लाख 28 हजार करोड़ रुपये) हो गया है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने को मंजूरी

वाशिंगटन, एपी : अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर संसद की कानूनी मामलों की समिति विचार कर रही है लेकिन उससे पहले ही प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नेंसी पेलोसी ने सदन में चर्चा को हरी झंडी दे दी है। अगर सब कुछ तय कार्यक्रम पर हुआ तो विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाले इस निचले सदन में डोनाल्ड ट्रंप पर लगे आरोपों पर क्रिसमस (25 दिसंबर) के आसपास मतदान हो सकता है।

गुरुवार को पेलोसी ने कहा, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के मामले में प्रतिनिधि सभा आगे बढ़ेगी। ऐसा हम दुखी मन से करेंगे लेकिन यह कार्य हमें पूरे विश्वास के साथ पूरा करना होगा। हमारे राष्ट्रपति ने संविधान का गंभीर उल्लंघन किया है। मामला ट्रंप के पूर्व उप राष्ट्रपति जो बिडेन के खिलाफ यूक्रेन में जांच शुरू कराने की कोशिश का है। ट्रंप ने इसके लिए अपने यूक्रेनी समकक्ष वोलोदिमीर जेलेंस्की पर दबाव डाला था।

▸ आखिरी हफ्ते हो सकती है वोटिंग, स्पीकर पेलोसी ने कहा, राष्ट्रपति ने संविधान का गंभीर उल्लंघन किया

कहा जाता है कि बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से 2020 के चुनाव में ट्रंप के खिलाफ उम्मीदवार हो सकते हैं, इसलिए ट्रंप ने उनका रास्ता रोकने के लिए उन्हें जांच में फंसाने की कोशिश की। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को कई अधिकारियों ने सुना। उनमें से एक अधिकारी ने व्हिसल ब्लोअर के रूप में डेमोक्रेटिक नेताओं से पूरी बताई और उसी के बाद ट्रंप पर महाभियोग चलाने की रूपरेखा तैयार हुई। अगर दो तिहाई बहुमत से संसद ने प्रस्ताव पारित कर दिया तो ट्रंप को राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि उच्च सदन सीनेट में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है, जहां महाभियोग प्रस्ताव के गिर जाने के आसार हैं।

ट्रंप के खिलाफ सुनवाई में बेटे बैरन का नाम लेने पर बवाल

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चल रही महाभियोग प्रक्रिया में गुरुवार को बड़ा मोड़ तब आया जब स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर ने गवाही के दौरान ट्रंप के नाबालिग बेटे बैरन का नाम लिया। ट्रंप की पत्नी और बैरन की मां मेलानिया ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए नाराजगी जाहिर की है। बाद में प्रोफेसर ने अपनी गलती मानते हुए खेद जताया।

संसद की कानूनी मामलों की समिति के समक्ष पेश हुईं प्रोफेसर पामेला एस कार्लन ने संविधान के तहत राष्ट्रपति को मिले अधिकारों की चर्चा करते हुए एक स्थान पर ट्रंप के बेटे बैरन का नाम लिया। बैरन की चर्चा डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद शैला जैक्सन ली के सवाल के जवाब से शुरू हुई। सुनवाई में बताया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने अधिकार किसी अन्य को नहीं दे सकते। यह बात राष्ट्रपति और बादशाह के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है। यहां तक कि ट्रंप अपने 13 साल के बेटे बैरन को भी राष्ट्रपति से जुड़ा किसी तरह का संवैधानिक अधिकार नहीं दे सकते। प्रोफेसर कार्लन के इस उदाहरण से सुनवाई कक्ष में बैठे लोग हंस पड़े। इस पर फ्लोरिडा से राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की सांसद मैट गेट्ज ने आपत्ति भी जताई। मैट ने कहा कि इस तरह के कार्लन ने एक परिवार पर हमला किया है। राष्ट्रपति के नाबालिग बेटे को भी नहीं छोड़ा है।

▸ मेलानिया के भड़कने पर प्रोफेसर ने गलती मान खेद जताया

मेलानिया ट्रंप। एपी

अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने भी कार्लन की टिप्पणी पर उनकी निंदा की है। कार्लन को संबोधित अपने ट्वीट में मेलानिया ने कहा है कि एक नाबालिग बच्चे को निजता दी जानी चाहिए, न कि उसे राजनीति में घसीटा जाए। कार्लन आपको अपनी हरकत पर शर्म आनी चाहिए जिसमें आपने भेदभावपूर्ण तरीके से संसदीय समिति के समक्ष अपनी बात रखी और एक बच्चे का इस्तेमाल किया। मेलानिया के समर्थन में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव स्टेफनी ग्रीशम ने भी ट्वीट किया है। कहा, डेमोक्रेटिक गवाह के रूप में सुनवाई में पेश हुई प्रो. कार्लन ने सुर्खियां बटोरने के लिए जिस तरह से एक बालक का इस्तेमाल किया, वह घटिया हरकत है।

मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह मामले में फैसला 17 को

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह मामले में विशेष अदालत 17 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी। दोषी पाए जाने पर 76 वर्षीय मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई जा सकती है। नवंबर, 2007 में पाकिस्तान पर आपातकाल थोपने के आरोप में 2013 में तत्कालीन नवाज शरीफ सरकार ने मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में खुद को घिरते देख मुशर्रफ इलाज के बहाने 18 मार्च, 2016 को दुबई चले गए थे। तब से वह अपने मुल्क नहीं लौटे।

परवेज मुशर्रफ। फाइल

विशेष अदालत के जज वकार अहमद सेठ के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई 17 दिसंबर तक स्थगित करते हुए कहा कि उसी दिन फैसला भी सुनाया जाएगा। इससे पहले विशेष अदालत ने गत 19 नवंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने तब 28 नवंबर को फैसला सुनाने का एलान किया था। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार और मुशर्रफ के वकील फैसला सुनाने पर रोक लगाने की मांग को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए थे।

पर्ल हार्बर सैन्य ठिकाने पर गोलीबारी

बड़ा मामला ▸ दो लोगों की मौत, हमला करने के बाद अमेरिकी नौसैनिक ने खुद को भी मारी गोली

हमलावर यूएसएस कोलंबिया एसएसएन 771 पनडुब्बी में था तैनात

लॉस एंजिलिस, रायटर : अमेरिका का ऐतिहासिक सैन्य बेस पर्ल हार्बर बुधवार को गोलीबारी से दहल उठा। एक अमेरिकी नौसैनिक ने गोलियां बरसाकर दो नागरिकों की जान ले ली और एक को घायल कर दिया। हमलावर नौसैनिक ने बाद में खुद को भी गोली मार ली। यह घटना ऐसे समय पर हुई जब पर्ल हार्बर पर द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान हुए हमले की शनिवार को बरसी मनाने की तैयारी चल रही थी। सैन्य अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि हमलावर यूएसएस कोलंबिया एसएसएन 771 पनडुब्बी में तैनात था। हमले का शिकार हुए सभी नागरिक अमेरिक रक्षा विभाग में काम करते थे। राष्ट्रपति भवन ह्वाइट हाउस के प्रवक्ता के अनुसार, 'राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गोलीबारी के बारे में जानकारी दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।'

दो घंटे तक बंद रहा बेस : स्थानीय मीडिया ने एक चश्मदीद के हवाले से बताया कि स्थानीय समयानुसार बुधवार दोपहर करीब ढाई बजे गोलीबारी की घटना हुई। हमलावर ने तीन लोगों को गोली मारने के बाद अपने सिर में गोली मार ली थी। हमलावर अमेरिकी नौसेना की वर्दी में था। इस घटना के चलते बेस करीब दो घंटे तक बंद रहा।

अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर गोलीबारी की घटना के बारे में जानकारी देते नौसेना के रियर एडमिरल रॉब चाडविक। एपी

अमेरिका का संयुक्त सैन्य अड्डा : पर्ल हार्बर बेस प्रशांत महासागर में अमेरिका के इकलौते राज्य हवाई की राजधानी होनोलुलु से 13 किलोमीटर दूर है। यह अमेरिकी वायुसेना और नौसेना का संयुक्त अड्डा है। यहां दस विध्वंसक पोत और 15 पनडुब्बियां तैनात रहती हैं। इस बेस में अमेरिका के प्रशांत बेड़े के युद्धपोत और पनडुब्बियों की मरम्मत, रखरखाव और आधुनिकीकरण भी किया जाता है। प्रशांत बेड़े का मुख्यालय भी यहीं पर है।

भारतीय वायुसेना प्रमुख राकेश भदौरिया सुरक्षित

नई दिल्ली, प्रेट्र : पर्ल हार्बर में जिस समय गोलीबारी की घटना हुई, भारतीय वायुसेना प्रमुख राकेश भदौरिया भी वहीं मौजूद थे। वह पूरी तरह सुरक्षित हैं। भदौरिया अमेरिका के इस सैन्य अड्डे में दुनिया के प्रमुख देशों की वायु सेनाओं के प्रमुखों के सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। भारतीय वायुसेना के प्रवक्ता ने यहां कहा, 'वायुसेना प्रमुख और उनकी टीम पूरी तरह सुरक्षित है।' एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पर्ल हार्बर पर वायुसेना प्रमुख अमेरिकी एयरफोर्स के बेस में ठहरे हैं, जबकि गोलीबारी की घटना नौसैनिक अड्डे में हुई। दोनों स्थान एक-दूसरे के समीप नहीं हैं।

जापान के हमले में 2300 अमेरिकियों की गई थी जान : जापान ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान सात दिसंबर, 1941 को पर्ल हार्बर पर हमला किया था। इस हमले में अमेरिका का युद्धपोत यूएसएस एरिजोना 1177 सैनिकों के साथ समुद्र में डूब गया था। जापान के इस हमले में 2300 से ज्यादा अमेरिकी मारे गए थे।

भारतीय दूतावास ने जारी की सूडान फैक्ट्री हादसे में हताहतों की सूची

खारतूम, प्रेट्र : सूडान की एक फैक्ट्री के एलपीजी टैंकर में विस्फोट के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए या लापता भारतीय श्रमिकों में ज्यादातर तमिलनाडु और बिहार के हैं। चीनी मिट्टी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में मंगलवार को हुए धमाके में 18 भारतीयों समेत 23 लोगों की मौत हो गई थी। करीब 130 लोग घायल हुए थे, जिन्हें राजधानी खारतूम के अल-अमल और इब्राहिम मलिक अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

भारतीय दूतावास ने खारतूम के बाहरी इलाके में स्थित सीला सेरेमिक फैक्ट्री में विस्फोट का शिकार हुए भारतीय नागरिकों की सूची जारी की है। इसमें अस्पताल में भर्ती और लापता भारतीयों की भी जानकारी दी गई है। अस्पताल में भर्ती सात भारतीयों में से चार की हालत गंभीर बनी हुई है। 16 भारतीय लापता बताए गए हैं। इनमें छह तमिलनाडु, पांच बिहार, चार राजस्थान, चार उत्तर प्रदेश और दो हरियाणा के रहने वाले हैं। दिल्ली और गुजरात के भी एक-एक नागरिक लापता हैं। भारतीय दूतावास के अनुसार, 'कुछ लापता मृतकों की सूची में हो सकते हैं। अभी तक कई शवों की पहचान नहीं हो पाई है।'

▸ ज्यादातर घायल भारतीय श्रमिक तमिलनाडु और बिहार के

▸ एलपीजी टैंकर में धमाके से हो गई थी 18 भारतीयों की मौत

सूडान की फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने का प्रयास करते सिविल डिफेंस के सदस्य। फाइल/एएफपी

अस्पताल में ये हैं भर्ती: जय कुमार (तमिलनाडु), बोबलन (तमिलनाडु), मुहम्मद सलीम (तमिलनाडु), रविंद्र सिंह (राजस्थान), सुरेंद्र कुमार (राजस्थान), नीरज कुमार (बिहार) और सोनू प्रसाद (उत्तर प्रदेश)।

ये भारतीय हैं लापता : रमा कृष्णा (तमिलनाडु), राज शेखर (तमिलनाडु) और वेंकट चेलम (तमिलनाडु), राम कुमार, (बिहार), अमित तिवारी (बिहार), हरि नाथ (बिहार), नितिश कुमार मिश्रा (बिहार), जीशान खान (उत्तर प्रदेश), मोहित (उत्तर प्रदेश), प्रदीप वर्मा (उत्तर प्रदेश), भजन लाल (राजस्थान), जयदीप (राजस्थान), पवन (हरियाणा), प्रदीप (हरियाणा), इंतजार खान (दिल्ली) और बहादुर (गुजरात)।

फैक्ट्री में थे 60 भारतीय श्रमिक : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए बताया कि फैक्ट्री में 60 भारतीय काम करते थे। अनुमान है कि हादसे के समय 53 भारतीय घटनास्थल पर मौजूद थे।

प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ का डैनी काये मानवतावादी पुरस्कार

न्यूयॉर्क, प्रेट्र : अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ का डैनी काये मानवतावादी पुरस्कार से नवाजा गया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने वर्ष 2019 के पुरस्कार के लिए प्रियंका को जून में ही विजेता घोषित किया था। उन्हें यह पुरस्कार मंगलवार को यहां स्नोफ्लैक बाल में प्रदान किया गया।

प्रियंका चोपड़ा। फाइल

पुरस्कार ग्रहण करने के बाद प्रियंका ने कहा, 'समाज सेवा अब कोई विकल्प नहीं रह गया है, बल्कि अब यह जीने का तरीका बन गया है।' प्रियंका को यह पुरस्कार दिग्गज फैशन डिजाइनर डायने वॉन फुरस्टनबर्ग ने दिया। यह पुरस्कार अमेरिकी अभिनेता और समाजसेवी डैनी काये के नाम पर दिया जाता है। वह यूनिसेफ के पहले सद्भावना दूत थे।

एक दशक से अधिक समय से यूनिसेफ की सद्भावना दूत प्रियंका ने संगठन के साथ अपनी यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'यूनिसेफ के साथ जुड़कर मुझे लगा कि समाजसेवा के लिए एक मंच मिल गया है। मैंने उन अभियानों के साथ जुड़ना शुरू कर दिया, जिन्हें मैं महत्वपूर्ण मानती थी।'

हड़ताल से फ्रांस में जनजीवन प्रभावित

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के पेंशन सुधारों के विरोध में देश के ट्रांसपोर्ट कर्मचारी, शिक्षक, पुलिस विभाग और दूसरी महत्वपूर्ण सेवाओं से जुड़े लाखों लोग हड़ताल पर चले गए हैं। हाल के सालों में यह सबसे बड़ी हड़ताल है, जिस कारण पूरा देश ठप सा हो गया है। राजधानी पेरिस में गुरुवार को ट्रांसपोर्ट हड़ताल की वजह से लोगों को पैदल ही आवागमन करना पड़ा है। रायटर

कोड़े खाकर बेहोश हुआ युवक

इंडोनेशिया के अशेह प्रांत में अवैध शारीरिक संबंध स्थापित करने पर सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाने की दिए जाने से युवक बेहोश हो गया। इस्लामिक कानून के मुताबिक इस प्रांत में विवाह पूर्व संबंध बनाना गैरकानूनी है। रूढ़िवादी इस प्रांत के अशेह तैमूर में एक युवती और दो युवकों को दोषी पाए जाने पर सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाने की सजा दी गई थी। यह युवक पिटाई सहन नही कर सका और बेहोश होकर गिर पड़ा। एएफपी

प्रधानमंत्री मोदी का संदेश पढ़ भावुक हुआ इजरायली किशोर मोशे होल्ट्जबर्ग

येरुशलम, प्रेट्र : वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमले में जीवत बचा मोशे होल्ट्जबर्ग भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़कर भावुक हो गया। पीएम मोदी ने इस किशोर की कहानी को ऐसा चमत्कार बताया, जो सभी के लिए प्रेरक है।

पीएम मोदी ने यह पत्र मोशे के 'बार मित्जवाह' समारोह पर भेजा, जो रविवार को आयोजित हुआ था। उन्होंने पत्र में लिखा, 'यह एक महत्वपूर्ण बदलाव का क्षण और आपकी जीवन यात्रा में एक अहम पड़ाव है। सैंड्रा का साहस और भारत के लोगों की दुआएं आपको लंबी उम्र, स्वस्थ एवं सफल जीवन का आशीर्वाद देती रहेंगी। आपकी कहानी हर किसी को प्रेरित करती रहेगी। यह एक चमत्कार है और उम्मीद करता हूं कि इस त्रासदी से हुई अपूर्णीय क्षति से आप उबरेंगे।'

यहूदी बच्चों के 13 साल के होने पर 'बार मित्जवाह' आयोजित किया जाता है। कुछ यहूदी विद्वान इसकी तुलना हिंदुओं के 'उपनयन' (यज्ञोपवीत संस्कार) से करते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मोशे 28 नवंबर को 13 साल का हो गया। उसके दादा रब्बी शिमॉन रोजेनबर्ग ने खास बातचीत में कहा, 'पीएम मोदी के पत्र ने मोशे के दिल को छू लिया। भारत जैसे बड़े देश के नेता द्वारा भेजा गया इस तरह का भावपूर्ण पत्र मोशे को बहुत मजबूती देगा। कार्यक्रम में भारतीय राजदूत को अपनी पूरी टीम के साथ देख वह बहुत खुश हुआ।'

▸ वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमले में मारे गए थे माता-पिता, आया ने बचाई थी दो वर्षीय मासूम की जान

इजरायली किशोर मोशे होल्ट्जबर्ग को दुलारते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह तस्वीर पांच जुलाई, 2017 की है, जब वह इजरायल के दौरे पर थे और उन्होंने यरुशलम में मोशे से विशेष तौर पर मुलाकात की थी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (दाएं) भी इस मौके पर मौजूद रहे थे। फाइल/प्रेट्र

26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले में 166 लोग मारे और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान से आए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने नरीमन हाउस (चाबाड हाउस) को भी निशाना बनाया था, जहां मोशे के माता-पिता रब्बी गैब्रिएल और रिवका होल्ट्जबर्ग समेत छह यहूदी मारे गए थे। माता-पिता के शव के पास खड़े होकर बिलखते मोशे को उसकी नैनी (आया) सैंड्रा सैमुएल्स ने बचाया था।

अमेरिका में दो रूसी नागरिक घोटाला करने पर गिरफ्तार

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिका में दो रूसी नागरिकों पर कंप्यूटर हैक कर अन्य लोगों की अचल संपत्ति और नकद धनराशि के घपले का आरोप लगा है। दोनों रूसियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के अपराध से संबंधित आरोप पत्र गुरुवार को सार्वजनिक हुआ।

बताया गया है कि मैक्सिम याकूबेट्स कंप्यूटर हैकिंग कर कई तरह के आर्थिक अपराधों को अंजाम देने वाला शातिर है। उसका साथी इगोर तुराशेव इसी तरह के अपराधों में मैक्सिम का साथ देता है। अमेरिका में साजिश की शुरुआत नवंबर 2011 में हुई। तब पिट्सबर्ग की अदालत में कई पीड़ितों ने अपनी शिकायतें दाखिल कीं। मामले में ब्रिटिश नागरिकों के साथ भी धोखाधड़ी होने की जानकारी मिली है। कई ब्रिटिश नागरिकों के बैंक अकाउंट में सेंध लगने की शिकायत भी मिली है।

इसी के आधार पर अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकारियों ने मिलकर जांच की। जांच में पता चला है कि दोनों रूसी नागरिकों ने बीते आठ साल में कम से कम दो बार कंप्यूटर हैक कर बैंक घोटाला किया।

▸ कंप्यूटर हैक कर बैंक अकाउंट से धन हड़प लेते थे

बल्गारियाई राजनयिक को रूस ने निकाला

रूस ने गुरुवार को जासूसी के शक में बल्गारिया के राजनयिक को देश छोड़कर जाने के लिए कह दिया। रूसी विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बल्गारिया के मॉस्को में नियुक्त राजदूत अटनास क्रैस्टीन को एक दूतावास कर्मी के जासूसी में लिप्त होने का शक जताते हुए उसे वापस भेजने के लिए कहा गया है। इसे बल्गारिया की चंद रोज पहले की कार्रवाई का जवाब माना जा रहा है। बल्गारिया ने जासूसी के शक में रूसी राजनयिक को देश छोड़कर जाने के लिए कहा था।

ये भी जानिए

भारतीय टीम पिछले पांच टी-20 मुकाबलों में से तीन मैच जीती है, जबकि दो हारी है। वहीं, वेस्टइंडीज की टीम को सिर्फ एक ही जीत नसीब हुई है, जबकि चार में उसे हार मिली है।

मिशन 2020 को लक्ष्य बनाकर उतरेगी कोहली एंड कंपनी

धवन से आगे सोचने का समय, राहुल पर करें भरोसा

के श्रीकांत
कलम से

टी-20 विश्व कप शुरू होने में अभी 10 महीने का समय बचा है। ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज भारतीय टीम के लिए खुद को कसौटी पर कसने का अच्छा मौका है। उम्मीद है कि टीम अपनी कमियों को सुधारने पर काम करेगी। बांग्लादेश के हाथों टी-20 मैच में मिली हार आंखें खोलने वाली है। इस प्रारूप में किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कोई भी मैच जीतने के लिए कोई एक व्यक्तिगत प्रदर्शन ही काफी रहता है। विराट कोहली और भुवनेश्वर कुमार की वापसी के बाद भारत अपनी मजबूत टीम के साथ उतरेगा। जब जसप्रीत बुमराह टीम में लौटेंगे तो उसके बाद विश्व कप के लिए सही टीम का आकलन किया जा सकेगा।

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस प्रारूप में वेस्टइंडीज की टीम बेहद शानदार है। ऐसे में मेहमान टीम भारत के सामने कड़ी चुनौती पेश कर सकती है। इस सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम में कई रोमांचक नाम हैं। साथ ही कई बड़े नाम इस दौरे का हिस्सा नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि कीरोन पोलार्ड की अगुआई में विंडीज टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही वेस्टइंडीज ने भारतीय जमीन पर अफगानिस्तान के खिलाफ हाल ही में सीरीज खेली है, जिसका उसे फायदा होगा। वहीं, भारतीय टीम को बतौर ओपनर केएल राहुल पर भरोसा बरकरार रखना चाहिए। अब शिखर धवन से आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है। ताबड़तोड़ शुरुआत होना समय की मांग है और इस क्षेत्र में भारत हाल ही में असफल साबित हुआ है। बेशक पारी संभालने के लिए विराट कोहली समेत अन्य बल्लेबाज मौजूद हैं, लेकिन बड़े मौकों पर ये काफी साबित नहीं हुआ है, जैसा कि हम पिछले कुछ साल में आइसीसी टूर्नामेंट में देख भी चुके हैं।

भारत का गेंदबाजी विभाग बेहतरीन है और रवींद्र जडेजा की वापसी के बाद स्पिनरों के बीच प्रतिद्वंद्विता भी बढ़ गई है, जो अच्छा है। फील्डिंग ऐसा क्षेत्र है, जिसमें इस टीम ने जबरदस्त सुधार किया है। हैदराबाद में पिच हमेशा ही बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। यहां की आउटफील्ड भी काफी तेज है, जिससे बल्लेबाजों को अतिरिक्त मदद मिलती है। गेंदबाजों के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ये बेहद ही रोमांचक सीरीज होगी, लेकिन अगर भारतीय टीम अपनी क्षमता से खेली तो फिर उसकी नैया किनारे लग ही जाएगी। (टीसीएम)

आज के मैच में ACC KAMAAL KA MOMENT कौन जीतेगा?
वोट करने के लिए, लॉग ऑन करें facebook.com/accind
ACC OFFICIAL PARTNER

भारत-वेस्टइंडीज के बीच पहला टी-20 आज विश्व कप से पहले सही सामंजस्य बिठाना चाहेगी टीम इंडिया

हैदराबाद, प्रेट्र: भारतीय क्रिकेट टीम मिशन टी-20 विश्व कप (2020) की तैयारियों को लेकर अपनी रणनीतियां तैयार करने में जुटी है। इस कड़ी में शुकवार से टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन टी-20 मैचों की सीरीज का आगाज करेगी तो उसका लक्ष्य अगले साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले विश्व कप की तैयारियों पर ही होगा। विश्व कप मिशन में कूदने से पहले टीम इंडिया के पास 11 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच ही बचे हैं। ऐसे में कुछ सवाल हैं, जिनका हल टीम इंडिया को इन बचे हुए 11 मैचों में ढूंढना है।

बड़े लक्ष्य देने होंगे: टी-20 क्रिकेट में टीम इंडिया लक्ष्य का पीछा करना ज्यादा पसंद करती है। 2017 की शुरुआत में जब महेंद्र सिंह धौनी ने कप्तानी छोड़ी थी, तब से लेकर अब तक भारतीय टीम ने इस सबसे छोटे प्रारूप में 45 मैच खेले हैं। इनमें टीम इंडिया को 30 में जीत मिली, जबकि 14 में हार का सामना करना पड़ा है। इन 14 हार में से 10 हार तब मिली हैं, जब टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विरोधी टीम के लिए लक्ष्य सेट किया। ऐसे में टीम को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

राहुल के पास मौका: इस बात में कोई शक नहीं कि वनडे क्रिकेट में शिखर धवन बतौर ओपनर एक मैच विजेता खिलाड़ी हैं, लेकिन टी-20 के लिहाज से उनकी धीमी बल्लेबाजी ने समस्या जरूर खड़ी की है। वह शुरुआत में अधिक खाली गेंद निकाल रहे हैं और बाद में भी इसकी भरपाई भी नहीं कर पा रहे हैं। उनका खेल रोहित शर्मा जैसा नहीं है और ना ही वह विराट कोहली की तरह तेजी से एक-दो रन दौड़ते हैं। शिखर इस सीरीज में चोट के कारण उपलब्ध भी नहीं हैं और ऐसे में केएल राहुल के पास इस जगह पर कब्जा जमाने का शानदार मौका है। कर्नाटक के इस खिलाड़ी ने हाल ही में संपन्न हुई सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी में खूब रन ठोके हैं।

वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज से पहले हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में गुरुवार को अभ्यास सत्र के दौरान भारतीय कप्तान विराट कोहली ● एएफपी

कलाई के स्पिनर होंगे अहम: ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से देखें, जहां विकेट की सतह ठोस रहती है, वहां अंगुली के स्पिनर के साथ खेलना एक चुनौती हो सकता है। इसी कारण से विराट ने नेतृत्व वाली टीम इंडिया सफेद गेंद वाले प्रारूप में रवींद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के स्थान पर चाइनामैन कुलदीप यादव और लेग स्पिनर युजवेंद्रा सिंह चहल को तरजीह दे रही है। गेंदबाजी में तो यह बदलाव कारगर साबित हुआ है, लेकिन इससे टीम का बल्लेबाजी संतुलन भी प्रभावित हुआ है। कोहली टी-20 प्रारूप में टीम की बल्लेबाजी में ज्यादा गहराई में विश्वास जता रहे हैं। इसी मकसद से टीम इंडिया ने क्रुणाल पांड्या और वाशिंगटन सुंदर को आजमाया है। सुंदर पावरप्ले के दौरान भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और क्रुणाल लंबे-लंबे हिट लगा सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर एक मैच में पांच विकेट लेने का कारनामा कर सकते हैं।

चाहर का इस्तेमाल: आइपीएल में दीपक धौनी चाहर के चार ओवरों को पावरप्ले में ही इस्तेमाल करते रहे हैं। चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के लिए आइपीएल खेलने वाले इस खिलाड़ी ने बांग्लादेश के खिलाफ काफी प्रभावित किया। तब कप्तान रोहित शर्मा ने चाहर का उपयोग फिनिशर के तौर पर भी किया। बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच में सात रन देकर छह विकेट का प्रदर्शन करने के बाद इस युवा तेज गेंदबाज ने कहा था कि बुमराह की ही तरह मेरा इस्तेमाल होगा। क्या वह विंडीज के खिलाड़ियों के सामने भी ऐसा प्रदर्शन कर सकते हैं? टीम इंडिया के पास वैसे तो विश्व कप मिशन के लिए मुहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह मौजूद हैं, लेकिन बुमराह फिलहाल चोट से जूझ रहे हैं और उन्हें अभी अपनी फिटनेस हासिल करनी है। खलील को महंगा साबित होना भी टीम के लिए चुनौती है और ऐसे में बुमराह के विकल्प के तौर पर टीम चाहर को तैयार करना चाहेगी।

भारत: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, केएल राहुल, शिखर धवन, रिषभ पंत, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्रा सिंह चहल, कुलदीप यादव, दीपक चाहर, भुवनेश्वर कुमार और मुहम्मद शमी।
वेस्टइंडीज: कीरोन पोलार्ड (कप्तान), पूरन, फेबियान एलेन, ब्रेंडन किंग, रामदीन, शेल्डन कॉटरेल, इविन लुइस, शेरफेन रदरफॉर्ड, शिमरोन हेटमायर, खारे पियरे, लेंडल सिंमस, जेसन होल्डर, हेडन वाल्श जूनियर, कीमो पॉल, केसरिक विलियम्स।

मध्य क्रम भी समस्या

भारतीय टीम जब 2019 विश्व कप की तैयारियां कर रही थी तब से ही वह नंबर चार पर किसी बल्लेबाज को स्थापित नहीं कर पाई। वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में टीम के लिए यह घातक भी साबित हुआ और न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम को हारकर टूर्नमेंट से बाहर होना पड़ा। विराट नंबर तीन पर ही बल्लेबाजी करेंगे यह तय है और नंबर चार के लिए भारतीय टीम के पास मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर और रिषभ पंत के रूप में विकल्प मौजूद हैं और इस स्थान के लिए इतने सारे विकल्प भारतीय टीम प्रबंधन की दुविधा बढ़ाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ अय्यर ने शानदार खेल दिखाया और पांडे भी बड़े-बड़े स्ट्रोक्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। यहां पंत पर अपनी जगह को लेकर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि अगर वह यहां फ्लॉप हुए तो फिर उनके विकल्प के तौर पर संजू सैमसन भी बैठे हैं।

भारत के खिलाफ सीरीज में वेस्टइंडीज प्रबल दावेदार

मोहिंदर अमरनाथ
रिवर्स स्वीप

जैसे-जैसे यह साल खत्म होने के नजदीक है, ऐसे में भारतीय क्रिकेटर और प्रशंसक अपनी राष्ट्रीय टीम के प्रदर्शन से संतुष्ट होंगे जिस तरह से टीम ने पूरे साल और दुनिया में प्रदर्शन किया है। टीम ने सभी विभागों में अच्छी प्रतिभा के साथ खुद को स्थापित किया है। बेंच स्ट्रेंथ जबरदस्त है और घरेलू क्रिकेट में भी कई होनहार खिलाड़ी हैं। इन हालात में किसी को भी घरेलू क्रिकेट खेले बिना राष्ट्रीय टीम में अपने चयन के बारे में नहीं होना चाहिए। विश्व में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो टीम को बताने में सक्षम हो कि वह अपने मैचों को चुनना चाहता है। खासकर भारत में सैकड़ों क्रिकेटर हैं जो घरेलू क्रिकेट में मेहनत कर रहे हैं। भारतीय अनुभव विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा, युवा रिषभ पंत और संजू सैमसन सभी बहुत सक्षम हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए जोर लगाना चाहिए।

वेस्टइंडीज के खिलाफ शुक्रवार से भारत तीन मैचों की टी-20 सीरीज का आगाज करेगा। इस प्रारूप में वेस्टइंडीज मजबूत टीम है, लेकिन वह अभी आंद्रे रसेल जैसे विस्फोटक खिलाड़ियों के बिना खेल रही है। रसेल आइपीएल में भी खेलते हैं और अगर वह इस सीरीज में खेलते तो इसका कैरेबियाई टीम को फायदा मिलता। इस प्रारूप में मैच का नतीजा चौंकाने वाला होता है और एक खिलाड़ी ही अपने प्रदर्शन से मैच का नतीजा बदल सकता है, इसलिए सीरीज में वेस्टइंडीज बहुत अधिक दावेदार है। मेरी एकमात्र चिंता चोटिल जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या के लिए है। कमर की चोट के बाद वापसी करना एक गेंदबाज के लिए मुश्किल होता है। यह चोट अतिरिक्त गति प्राप्त करने के चक्कर में लग जाती है। वह दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अपनी बात खत्म करने से पहले मैं बॉब विलिस के बारे में कहना चाहूंगा। वह सज्जन इंसान थे। वह मैदान के बाहर भी मिलनसार व्यक्ति थे। मैं उनके खिलाफ मैच में खेला था। उनके तेज गेंदबाजी रन-अप को उनके प्रशंसक हमेशा याद रखेंगे। आपकी आत्मा को शांति मिले, मेरे दोस्त।

#WhatDrivesYou
EXIDE

05 टी-20 मुकाबले रिषभ पंत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले हैं और इसमें उन्होंने तीन खिलाड़ियों को आउट करने में योगदान दिया। धौनी ने इतने ही मैचों में पांच खिलाड़ियों को पवेलियन भेजने में मदद की। ऐसे में बतौर विकेटकीपर वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को पवेलियन भेजने के रिकॉर्ड को अपने पास करने का पंत के पास मौका है

2018 जनवरी से हैदराबाद में टी-20 में पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर का औसत 162.60 रहा है

2018 आइपीएल से भुवनेश्वर ने हैदराबाद में 47.75 के औसत से प्रति विकेट लिया है। आइपीएल में यह भुवी का घरेलू मैदान है

2015 से पहली बार ऐसा हुआ है जब एक कैलेंडर वर्ष में भारत ने वेस्टइंडीज से ज्यादा छक्के लगाए हैं। 2019 में टी-20 में भारत ने हर मैच में औसतन 6.46 छक्के लगाए हैं

नो बॉल पर तीसरा अंपायर लेगा फैसला

भारत-वेस्टइंडीज के बीच सीरीज से शुरू होगी यह नई प्रक्रिया

दुबई, प्रेट्र: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय और वनडे मुकाबलों में नो बॉल का फैसला तीसरा अंपायर करेगा, ना कि मैदान पर मौजूद अंपायर। गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) की ओर से यह घोषणा की गई।

वेस्टइंडीज के भारत दौरे पर तीन टी-20 और इतने ही वनडे मुकाबले खेले जाएंगे। शुक्रवार को हैदराबाद में शुरू हो रही इस सीरीज में तकनीक द्वारा नो बॉल पर फैसला लेने का परीक्षण किया जाएगा। आइसीसी ने कहा कि इस पूरे ट्रायल के दौरान तीसरा अंपायर ही हर नो बॉल पर फैसला करेगा। वही यह जांच करेगा कि क्या गेंदबाज ने अगली क्रीज का उल्लंघन किया है। इसमें आगे कहा गया है कि अगर गेंदबाज क्रीज का उल्लंघन करता है तो तीसरा अंपायर मैदानी अंपायर से बात करेगा। यानी मैदान पर मौजूद अंपायर तीसरे अंपायर की सहमति के बिना नो बॉल का फैसला नहीं देगा। आइसीसी ने कहा कि शक का फायदा गेंदबाज को मिलेगा। आइसीसी ने आगे कहा कि अगर फैसला देने में देरी होती है, तब मैदान पर मौजूद अंपायर आउट का फैसला बदलेगा (अगर बल्लेबाज आउट हुआ है तो)। बाकी सभी फैसलों के लिए पहले की तरह मैदानी अंपायर ही जिम्मेदार होगा। इसमें आगे कहा गया है कि इस ट्रायल को नो बॉल की सटीकता को जांचने के पैमाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि क्या इससे खेल की रफ्तार पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता है।

नो बॉल जांचने का काम तीसरे अंपायर को सौंपने का फैसला इस साल अगस्त में किया गया था। इस सिस्टम को पहली बार 2016 में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हुई वनडे सीरीज में प्रयोग किया गया था। इससे पहले आइसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में भी खिलाड़ियों की नंबर वाली जर्सी को शामिल किया था।

भारतीय कप्तान ने तेज गेंदबाज भुवनेश्वर और बुमराह के चुने जाने के दिए संकेत

टी-20 विश्व कप टीम में एक स्थान की जगह : कोहली

हैदराबाद, प्रेट्र: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले पहले टी-20 मुकाबले से पहले कहा कि अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण में सिर्फ एक स्थान भरा जाना बाकी है। कोहली ने इस तरह संकेत दिया कि तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मुहम्मद शमी का टीम में जगह बनाना लगभग तय है। कोहली ने कहा कि बेशक मुकाबला एक स्थान के लिए है और मुझे लगता है कि तीन खिलाड़ियों ने अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है और यह देखना रोमांचक होगा कि निष्कर्ष क्या निकलता है।

तेज गेंदबाजी विभाग में कई विकल्पों की मौजूदगी पर कोहली ने कहा कि एक कप्तान के रूप में यह उनके लिए अच्छा है। कोहली ने कहा कि ऐसा नहीं है कि यह हमारे लिए कोई समस्या है। मुझे लगता है कि भुवी और बुमराह अनुभवी खिलाड़ी हैं। टी-20 क्रिकेट में उनके प्रदर्शन में काफी निरंतरता रही है। दीपक चाहर ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की है। शमी वापसी कर रहे हैं और काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर वह लय में आ जाएं और टी-20 क्रिकेट के लिए जरूरी चीजों पर काम करें तो ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पर वह बेहद उपयोगी होंगे, विशेषकर नई गेंद से विकेट हासिल करने की क्षमता के कारण।

लक्ष्य बचाने पर टीम का ध्यान: टी-20 प्रारूप में बीते दो वर्षों में टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर मैच जीतने में इतनी सहज नहीं दिखती, जितना वह लक्ष्य का पीछा करते हुए दिखती है। कप्तान कोहली इस बात पर फोकस हैं और उन्होंने बताया कि अब टीम इसी कमजोरी को दूर करने पर काम करेगी जिसका नतीजा आने वाले समय में दिखाई देगा। विराट अब टीम के इसी पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं और उन्होंने मैच से पहले यह साफ कर दिया है कि विश्व कप से पहले टीम लक्ष्य बचाने पर फोकस करेगी।

छह गेंदबाज इस प्रारूप की जरूरत: विराट ने कहा कि टी-20 प्रारूप में छह गेंदबाज जरूरत हैं। हमें ऑलरांडर, स्पिनर और तेज गेंदबाजी का ऐसा मिश्रण तैयार करना होता है, जो मौका पड़ने पर टीम के काम आ सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टी-20 में मेरे वापस लौटने से टीम के संतुलन को सही दिशा मिलेगी। इस प्रारूप में बल्लेबाजी के लिए नंबर पांच या नंबर छह के स्थान की बात करना बेमानी है। इस प्रारूप में जरूरी यही है कि कोई एक खिलाड़ी टिककर लंबा खेले और दूसरे छोर से बल्लेबाज 170-180 के स्ट्राइक रेट स्कोर बनाए। विराट ने बताया कि टीम के जेहन में अब टी-20 विश्व कप है और अब हम टीम में उन खिलाड़ियों के साथ ही खेलते दिखेंगे, जो टीम विश्व कप में कूच करेगी।

अभ्यास सत्र के दौरान रिषभ पंत ● प्रेट्र

हमें पंत की काबिलियत पर पूरा भरोसा : कोहली

हैदराबाद: टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हो रही टी-20 सीरीज से पहले टीम की योजनाओं के बारे में बात की। इस मौके पर विराट ने मीडिया की ओर से उठाई गई तमाम चिंताओं के जवाब दिए और साथ इन दिनों आलोचकों के निशाने पर जमे युवा विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि पंत की काबिलियत पर हमें पूरा भरोसा है और यह टीम की जिम्मेदारी है कि वह अच्छा खेल सकें। इसके लिए हम सभी उनका समर्थन करें। पंत पर पूछे गए सवाल पर कप्तान कोहली ने कहा कि हमें उनकी योग्यता पर पूरा भरोसा है। कोई खिलाड़ी टीम के लिए अच्छा खेले यह हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। हमें हर खिलाड़ी को भरपूर मौका और समय देना चाहिए, ताकि वह अपनी जगह टीम में साबित कर सके। गलतियां होने पर खिलाड़ियों पर चिल्लाना सही नहीं है। पंत के संदर्भ में जो बात कुछ दिन पहले रोहित शर्मा ने कही थी मैं भी उसी के साथ हूं कि पंत पर ज्यादा हल्ला मचाने के बजाये उन्हें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दें।

युवा प्रतिभा को विश्व क्रिकेट के गिद्धों से बचाना जरूरी : पोलार्ड

वेस्टइंडीज के कप्तान ने कहा, युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए पर्याप्त मौके मिलने चाहिए

हैदराबाद, प्रेट्र: वेस्टइंडीज की टी-20 टीम के कप्तान कीरोन पोलार्ड ने गुरुवार को कहा कि उनके देश के युवा क्रिकेटरों को 'खेल के गिद्धों' से बचाने की जरूरत है। वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम में कुछ युवा खिलाड़ियों को रखा है और पोलार्ड का मानना है कि उन्हें अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए पर्याप्त मौके मिलने चाहिए।

पोलार्ड ने कहा कि वे (ब्रेंडन किंग और केसरिक विलियम्स) काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। यह अच्छा है कि सीपीएल (कैरेबियाई प्रीमियर लीग) से हमें युवा खिलाड़ी मिल रहे हैं। वे वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व करने को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम एक व्यक्ति के तौर पर लोगों के बारे में बहुत जल्दी राय बना लेते हैं। हमें संयम बरतने की जरूरत है। आखिर में हमें परिणाम चाहिए, लेकिन कई बार आपको खुद के साथ ईमानदार होना पड़ता है। हम दुनिया को इस प्रतिभा का परिचय कराने के लिए तैयार हैं कि वे क्या कर सकते हैं। कई बार आपको इन्हें सुरक्षा देने की और गिद्धों से बचाने की जरूरत पड़ती है। पोलार्ड ने कहा कि उन्हें (युवा खिलाड़ियों) अनुभव हासिल करने की जरूरत है और हमें उनका समर्थन करना होगा और देखते हैं कि वे कितने आगे जा सकते हैं क्योंकि हमने उनकी प्रतिभा और नजरिया देखा है।

आगामी सीरीज के बारे में पोलार्ड ने कहा कि उनकी टीम भारत में खेलने के अनुभव का उपयोग करके मेजबान को चुनौती देने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि हमने भारत में काफी क्रिकेट खेला है। यह केवल अपने अनुभव का इस्तेमाल करने से जुड़ा है और उम्मीद है कि यह अनुभव हमारे काम आएगा। हम आखिरकार अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए यहां आए हैं। हमने अच्छी तैयारी की है। पोलार्ड ने कहा कि भारत को कड़ी चुनौती देने के लिए उनकी टीम को अपने संपूर्ण खेल में सुधार करना होगा। हमें एक टीम के रूप में खेलना होगा। उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला एक मजबूत टीम से है। वह नंबर एक टीम (टेस्ट में) है और मुझे लगता है कि यह हमारे लिए अच्छा है कि हमें नंबर एक टीम से खेलने का मौका मिल रहा है। हमें अपनी सामने खड़ी चुनौती का डटकर सामना करके उससे निपटना होगा।

टीम इंडिया में विदेशी धरती पर निरंतर जीतने की क्षमता : गांगुली

खेल संवाददाता, कोलकाता: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने पर टीम इंडिया की तारीफ करते हुए कहा कि विराट कोहली की अगुआई वाली टीम के पास विदेशी धरती पर निरंतर जीतने की क्षमता है। एक कार्यक्रम में 'दादा' ने कहा, 'हमने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन किया। हमारे पास न्यूजीलैंड दौरे में अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम है। विश्व की सर्वोत्तम टेस्ट टीम बनना ही हमारा लक्ष्य है।'

शोले है सौरव की पसंदीदा फिल्म: कार्यक्रम के दौरान सौरव गांगुली से जब उनकी सर्वकालिक पसंदीदा फिल्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने 'शोले' का नाम लिया। उनसे जब यह सवाल किया गया कि मौका मिलने पर वह इस फिल्म का कौन सा किरदार निभाना चाहेंगे तो उन्होंने कहा 'यह बहुत कठिन सवाल है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अभिनय कर सकता हूं। शोले में मेरे सबसे पसंदीदा किरदार जय (अमिताभ बच्चन) और गब्बर सिंह (अमजद खान) हैं। गब्बर सिंह का किरदार थोड़ा ज्यादा लोकप्रिय है क्योंकि उसी की वजह से वह फिल्म बनी। सत्यजीत रे की विभिन्न फिल्मों में सौमित्र चटर्जी के निभाए किरदार भी मुझे बहुत पसंद हैं।'

पुरुष वनडे मैचों में पहली महिला रेफरी बनेंगी लक्ष्मी

दुबई, प्रेट्र: पूर्व भारतीय क्रिकेटर जीएस लक्ष्मी रविवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में विश्व कप लीग दो की तीसरी सीरीज के शुरुआती मैच के साथ पुरुष वनडे में मैच रेफरी की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बन जाएंगी।

लक्ष्मी यूएई और अमेरिका के बीच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैच में रेफरी की भूमिका निभाएंगी। इस टूर्नामेंट का लक्ष्य अधिकारियों के लिए विकास के मौके प्रदान करना है। 51 साल की लक्ष्मी की यह इस साल की दूसरी बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले वह मई में मैच रैफरियों के आइसीसी अंतरराष्ट्रीय पैनल में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी थीं। उस समय उन्होंने कहा था, 'आइसीसी द्वारा अंतरराष्ट्रीय पैनल में चुना जाना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है क्योंकि यह मेरे लिए नए रास्ते खोलेगा। भारत में एक क्रिकेटर और मैच रेफरी के रूप में मेरा लंबा करियर रहा है। मैं अपने अनुभव को एक खिलाड़ी और मैच अधिकारी के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छी तरह से उपयोग करने की आशा करती हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करूंगी और अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी।'

लक्ष्मी ने 2008-09 में घरेलू महिला क्रिकेट मैच में पहली बार मैच रेफरी की भूमिका अदा की थी। वह अब तक तीन महिला वनडे मैचों, 16 पुरुष टी-20 अंतरराष्ट्रीय और सात महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में रेफरी की भूमिका निभा चुकी हैं। आइसीसी के सीनियर मैनेजर (अंपायर एंव रेफरी) एड्रियन ग्रिफिथ ने लक्ष्मी को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी।

उपलब्धि

- यूएई और अमेरिका के बीच मैच में निभाएंगी जिम्मेदारी
- शारजाह स्टेडियम में रविवार को खेला जाएगा यह मैच

श्रद्धांजलि | आइसीसी ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और तेज गेंदबाज विलिस के निधन पर जताया शोक

सबसे बड़े क्रिकेट हीरो में से एक थे बॉब विलिस

दुबई, प्रेट्र: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ने गुरुवार को इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बॉब विलिस के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें खेल के सबसे बड़े हीरो में से एक करार दिया। लंबे समय से बीमारी से जूझने के बाद विलिस का इंग्लैंड में 70 साल की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया।

आइसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी ने वैश्विक संस्था की ओर से शोक जताया। साहनी ने कहा, 'बॉब के निधन की खबर सुनकर हम काफी दुखी हैं और आइसीसी की ओर से मैं उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। बॉब अपने समय के सबसे बड़े क्रिकेट हीरो में से एक थे, एक ऐसे तेज गेंदबाज जिन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला। उन्होंने आक्रामकता के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई की और पिछली सदी के आठवें और नौवें दशक में क्रिकेट देखने वाले लोगों के दिमाग में उनके गेंदबाजी के लिए दौड़ते हुए आने (रन अप) की छवि छपी हुई है।' विलिस ने 1971 से 1984 के दौरान 90 मैचों के अपने टेस्ट करियर में 325 विकेट चटकाए। साहनी ने कहा, 'ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1981 में हेडिंग्ले टेस्ट में उनकी भूमिका क्रिकेट में सबसे शानदार प्रदर्शन में से एक है। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद प्रसारणकर्ता के रूप में भी उन्हें सराहा गया और खेल के प्रति उनके योगदान को लंबे समय तक याद किया जाएगा।'

विलिस ने 18 टेस्ट और 29 वनडे अंतरराष्ट्रीय मैचों में इंग्लैंड की कप्तानी की। विलिस ने 1981 में एशेज सीरीज के हेडिंग्ले टेस्ट में विनाशकारी गेंदबाजी करते हुए करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 43 रन देकर आठ विकेट झटके थे, जिसकी मदद से इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया पर यादगार जीत दर्ज की थी। इंग्लैंड ने यह सीरीज 3-1 से जीती थी और विलिस ने छह टेस्ट मैचों में 22.96 की औसत से 29 विकेट झटके थे।

सदरलैंड में जन्मे इस गेंदबाज ने घरेलू क्रिकेट में सरे की ओर से अपना करियर शुरू किया। इसके बाद वह 12 साल तक वारविकशायर के लिए खेले। उन्होंने 308 प्रथम श्रेणी मैचों में 24.99 की औसत से 899 विकेट झटके।

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान व तेज गेंदबाज बॉब विलिस ● फाइल फोटो, एएफपी

मेरिलबॉन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) के मानद सदस्य बॉब विलिस के निधन के बारे में सुनकर हम बहुत दुखी हैं। लॉर्ड्स के दिग्गज और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान, जिनका नाम तीन बार सम्मान बोर्ड पर अंकित है, हमारे विचार उनके दोस्तों और परिवार के साथ हैं। **लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड**

क्रिकेट ने एक अच्छा मित्र खो दिया। **इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड**

बॉब विलिस के बारे में दुखद समाचार। उनकी आत्मा को शांति मिले। उनके पूरे परिवार को प्यार। भारत एक अपने समर्थक की कमी महसूस करेगा। **सौरव गांगुली**, बीसीसीआइ अध्यक्ष

दुनियाभर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए दुख का समय। ईश्वर बॉब की आत्मा को शांति प्रदान करे। **विवियन रिचर्ड्स**, पूर्व दिग्गज बल्लेबाज, वेस्टइंडीज

मैं उन्हें गेंदबाजी करते हुए नहीं देख सका। इसका अफसोस रहेगा। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा था। बॉब विलिस के परिवार और दोस्तों के लिए संवेदनाएं। बॉब ईश्वर आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे। **रविचंद्रन अश्विन**, भारतीय गेंदबाज

बॉब विलिस के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। मजाकिया होने के साथ-साथ एक प्यारे व्यक्ति, जिन पर इंग्लैंड क्रिकेट को गर्व है। **स्टुअर्ट ब्रॉड**, तेज गेंदबाज, इंग्लैंड

कपिल बोले, विलिस का सामना करना खतरनाक होता था: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने गुरुवार को कहा कि इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज बॉब विलिस का सामना करना खतरनाक होता था। कपिल ने कहा कि विलिस एक मात्र ऐसे गेंदबाज थे जिनकी गेंद उन्हें लगी थी। इंग्लैंड के इस पूर्व कप्तान का 70 साल की उम्र में निधन हो गया।

भारत को विश्व कप जिताने वाले कप्तान कपिल ने कहा, 'वो बहुत तेज गेंद थी, मेरी उम्मीद से ज्यादा तेज। वो गेंद मेरे कान पर लगी थी। वो पहली बार था जब मुझे गेंद लगी थी। विलिस बेहतरीन गेंदबाज थे, उनका रन-अप अलग था। बहुत धाराप्रवाह रनअप नहीं था, लेकिन एक बार गेंद जब उनके हाथ से निकलती तो यह बल्लेबाजों के लिए खतरनाक होती थी। मैंने विलिस को कभी बल्लेबाज पर चिल्लाते नहीं देखा था, ना ही उन्हें कभी अंपायर से झगड़ा करते देखा। वह चाहते थे कि उनकी गेंद बात करे।' वहीं भारत के एक और पूर्व क्रिकेटर संदीप पाटिल ने कहा कि वह कभी भी विलिस का सामना करने में सहज नहीं रहे। उन्होंने कहा, 'मैं विलिस का सामना करने में कभी भी सहज नहीं रहा। वह बल्लेबाज के दिमाग में अपनी तेजी खौफ पैदा करते थे।'

मेरी कॉम ने पंजाब को दिलाई जीत

ग्रेटर नोएडा, आइएएनएस : मेरी कॉम ने बिग बाउट मुक्केबाजी लीग में अपनी टीम पंजाब पैंथर्स को यहां गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी इंडोर स्टेडियम में खेले गए मैच में बांबे बुलेट्स के खिलाफ 5-2 से जीत दिलाई। मेरी कॉम ने रियो ओलंपिक 2016 कांस्य पदक विजेता इंग्रीड लोरेना को 5-0 से मात दे अपनी टीम की जीत की राह पक्की कर ली। मनोज कुमार की हार ने पंजाब को धक्का पहुंचा दिया था, लेकिन मेरी कॉम ने टीम को संभाल लिया। पुरुषों के 69 किलोग्राम भारवर्ग के मुकाबले में बांबे के नवीन बोरा ने 4-1 हरा दिया।

पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से बड़े खिलाड़ी नहीं हैं भारतीय कप्तान विराट कोहली।
– अब्दुर रज्जाक, पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी

रशफोर्ड के दम पर मैनचेस्टर युनाइटेड जीता

फुटबॉल डायरी ▸ मार्कस ने दागे दो गोल, टॉटनहम को 2-1 से हराया, लीसेस्टर ने वाटफोर्ड को 2-0 से हराया

ईपीएल की अंक तालिका में शीर्ष पर मौजूद लिवरपूल ने एवर्टन को दी मात

लंदन, एएफपी : मार्कस रशफोर्ड के दो गोल की बदौलत मैनचेस्टर युनाइटेड ने इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) में टॉटनहम को 2-1 से हराया, जबकि लिवरपूल ने एवर्टन को 5-2 से हराकर अंक तालिका के शीर्ष पर अपनी आठ अंक की बढ़त बरकरार रखी। लिवरपूल की टीम 15 मैचों में 43 अंक के साथ शीर्ष पर है, जबकि दूसरे स्थान पर मौजूदा लीसेस्टर के इतने ही मैचों में 35 अंक हैं। चेल्सी 15 मैचों में 29 अंक के साथ चौथे, जबकि मैनचेस्टर युनाइटेड इतने ही मैचों में 21 अंक के साथ छठे स्थान पर है। टॉटनहम की टीम 20 अंक के साथ आठवें पायदान पर चल रही है।

हालांकि, टॉटनहम के नए मैनेजर जोस मौरिन्हो की युनाइटेड के ओल्ड ट्रैफर्ड में वापसी को खराब कर दिया। मौरिन्हो इससे पहले मैनचेस्टर युनाइटेड के मैनेजर थे और युनाइटेड का साथ छोड़ने के बाद उन्होंने टॉटनहम का दामन थामा था। मौरिन्हो के मार्गदर्शन में टॉटनहम की यह पहली हार है। मैच के छठे मिनट में ही रशफोर्ड ने गोल करके युनाइटेड को मैच में जल्दी बढ़त दिला दी। हालांकि, इस गोल में टॉटनहम के गोलकीपर पाउलो गाजानिगा की गलती के कारण मेजबान टीम को फायदा पहुंचा। रशफोर्ड ने बॉक्स के बायें ओर से गेंद को गोल पोस्ट की ओर भेजा जिसे पाउलो ठीक से रोक नहीं पाए, जबकि वह गेंद रोकी जा सकती थी।

हालांकि टॉटनहम ने मैच में वापसी करने में ज्यादा देर नहीं लगाई। 33वें मिनट में डेले अली ने गोलकीपर के बॉक्स के अंदर से गोल किया और स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। पहला हाफ 1-1 से बराबर रहा। दूसरे हाफ की शुरुआत के चौथे मिनट में ही रशफोर्ड ने एक और गोल दाग दिया। इस बार युनाइटेड की टीम को पेनाल्टी मिली और रशफोर्ड ने इसे गोल में बदलने में कोई गलती नहीं की। आखिरी समय तक युनाइटेड की टीम ने कोई गोल नहीं खाया और मैच 2-1 से अपने नाम किया। मैच के बाद मौरिन्हो ने कहा, 'हम मैच जरूर हार गए, लेकिन मेरी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। अब हमारी कोशिश तालिका में शीर्ष-छह में आने की है। हमने कुछ गलतियां की, लेकिन उनसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।'

सलाह नहीं खेलें : वहीं, लिवरपूल के स्टार मुहम्मद सलाह इस मैच में नहीं खेलें और उनके जगह मैनेजर जुर्जेन क्लोप ने हर्देन शकीरी को मैदान पर उतरा। इसके अलावा रोबर्टो फिरमिनो के स्थान पर डिवोक ओरीगी को खेलने का मौका मिला। लिवरपूल के खिलाड़ियों ने शुरुआत से गोल करने का सिलसिला शुरू कर दिया और शुरुआती 17 मिनट में टीम ने दो गोल कर दिए। ओरीगी ने छठ मिनट और शकीरी ने 17वें मिनट में गोल करके लिवरपूल की बढ़त को 2-0 कर दिया। इसके चार मिनट बाद ही माइकल कीन ने एवर्टन का मैच में खाता खोला। तो वहीं, ओरीगी यहीं नहीं रुके और 31वें मिनट में एक और गोल करके स्कोर 3-1 किया। हालांकि पहले हाफ के अंतिम समय में दोनों टीमें एक-एक गोल करने में सफल हुई। सादियो माने ने 45वें मिनट गोल कर लिवरपूल की बढ़त 4-1 की तो वहीं, एवर्टन के रिचार्लिसन ने पहले हाफ के इंजुरी समय (45+3वां मिनट) में गोल कर हार के अंतर को कुछ कम करने की कोशिश की। इस बीच, जॉर्जीनियो वायनालडम ने 90वें मिनट में शानदार गोल करके लिवरपूल को 5-2 से जीत दिलाई।

अन्य मैचों में दूसरे स्थान पर चल रहे लीसेस्टर ने ईपीएल में लगातार आठवां मैच जीता और अंतिम स्थान पर चल रहे वाटफोर्ड को 2-0 से हराया। लगातार दो हार के बाद वापसी करते हुए चेल्सी ने एस्टन विला को 2-1 से शिकस्त दी, वहीं साउथैंप्टन ने इसी अंतर से नॉरविक को हराया।

ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में मैच के दौरान गेंद पर किक लगाते मैनचेस्टर युनाइटेड के मार्कस रशफोर्ड। एपी

नेमार और एमबापे के गोल से पीएसजी ने नांतेस को हराया

पेरिस, एएफपी : नेमार और कायलियन एमबापे के गोल से पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) ने नांतेस को 2-0 से हराकर लीग-1 फुटबॉल लीग के शीर्ष पर अपनी बढ़त को फिर पांच अंक तक पहुंचा दिया। एमबापे ने दूसरे हाफ (52वें मिनट) की शुरुआत में गोल दागकर पीएसजी को बढ़त दिलाई, जबकि नेमार ने 85वें मिनट में पेनाल्टी पर गोल दागकर टीम की 2-0 से जीत सुनिश्चित की। वहीं, मार्सेले ने मंगलवार को एंजर्स को 2-0 से हराकर पीएसजी की बढ़त को दो अंक का कर दिया था। पिछले सप्ताह पीएसजी का मोनाको के खिलाफ मैच खराब मौसम के कारण स्थगित करना पड़ा था। पीएसजी की टीम 15 मैचों में 36 अंक के साथ शीर्ष पर है जबकि दूसरे स्थान पर मौजूद मार्सेले के 16 मैचों में 31 अंक हैं।

कतर ओपन में खेलना हैं : बोपन्ना

नजरिया

- भारतीय अनुभवी डबल्स टेनिस खिलाड़ी कंधे की चोट से हैं परेशान
- चोट के कारण पाक के खिलाफ डेविस कप मुकाबले नहीं खेल पाए थे रोहन

मुंबई, प्रेट्र : कंधे की चोट के कारण भारत के हाल के डेविस कप टेनिस मुकाबले से हटने के लिए बाध्य होने वाले डबल्स टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने गुरुवार को कहा कि उनकी चोट से उबरने की प्रक्रिया सही दिशा में आगे बढ़ रही है और उनकी योजना जनवरी में कतर ओपन में भाग लेने की है।

बोपन्ना ने कहा, 'यह (कंधा) बेहतर हो रहा है और मैंने दो दिन पहले ट्रेनिंग शुरू कर दी है, इसलिए सत्र शुरू होने से पहले मेरे पास पूरा एक महीने का समय है। इसलिए जब पहला टूर्नामेंट शुरू होगा, तब तक यह सही हो जाएगा।' कतर एक्सोनमोबिल ओपन दोहा में छह से 12 जनवरी तक खेला जाएगा। बोपन्ना को कंधे की चोट के कारण पाकिस्तान के खिलाफ भारत के डेविस कप मुकाबले से हटना पड़ा था। उन्होंने कहा, 'एमआरआइ के बाद पता चला इसमें थोड़ी परेशानी थी। शुरुआत में डॉक्टरों ने कहा कि यह 15 दिन के आराम के बाद सही हो जाएगा और जब मैं अभ्यास के लिए गया तो इसमें तब भी काफी दर्द था।' भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 4-0 से मात देकर डेविस कप का 2020 क्वालीफायर स्थान हासिल कर लिया है। बोपन्ना ने कहा, 'हम हमेशा ही पाक के खिलाफ दावेदार थे।

चौथे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने जीते 50 पदक

दक्षिण एशियाई खेल

- तैराकी, वुशू, भारोत्तोलन व एथलेटिक्स में जीते ज्यादातर पदक
- भारत के कुल पदकों की संख्या अब 118 पर पहुंची

काठमांडू, प्रेट्र : वुशू खिलाड़ियों और तैराकों के दमदार प्रदर्शन से भारत ने दक्षिण एशियाई खेलों (सैग) के चौथे दिन गुरुवार को 50 पदक जीते, जिससे उसके कुल पदकों की संख्या 100 को पार कर गई और उसने शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। भारत ने खेलों के किसी एक दिन अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उसके नाम पर अब 58 स्वर्ण, 41 रजत और 19 कांस्य पदक सहित कुल 118 पदक हो गए हैं। वह दूसरे नंबर पर काबिज मेजबान नेपाल से काफी आगे निकल गया है। नेपाल ने 36 स्वर्ण, 26 रजत और 34 कांस्य पदक जीते हैं और वह 96 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। श्रीलंका (16 स्वर्ण, 31 रजत और 52 कांस्य) तीसरे स्थान पर है।

भारत ने गुरुवार को 26 स्वर्ण, 18 रजत और छह कांस्य पदक जीते। भारत ने अधिकतर पदक तैराकी, वुशू, भारोत्तोलन और एथलेटिक्स में जीते। वुशू में भारत ने सात स्वर्ण पदक हासिल किए। सूरज सिंह ने पुरुष गुंशू ऑलराउंड स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद वाई सनथोई देवी (महिला संसू 52 किग्रा), पूनम (महिला 75 किग्रा), दीपिका (महिला 70 किग्रा), सुशीला (महिला 65 किग्रा), रोशिबिना देवी (महिला 60 किग्रा) और सुनील सिंह (पुरुष 52 किग्रा) ने अपनी-अपनी स्पर्धाओं में सोने के तमगे जीते। विद्यापति चानू ने महिला 56 किग्रा में कांस्य हासिल किया। तैराकी में भारत ने चार स्वर्ण, छह रजत और एक कांस्य सहित 11 पदक जीते। लिखित सेल्वराज प्रेमा ने पुरुषों के 200 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक (शार्ट कोर्स) में दो मिनट 14.67 सेकेंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि दानुश सुरेश ने रजत पदक हासिल किया। अपेक्षा देयला फर्नांडीज ने महिलाओं के 200 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में स्वर्ण जीता। दिव्या सतिजा ने महिलाओं की 100 मीटर बटरफ्लाई और महिला 400 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम ने भी अपनी स्पर्धाओं में पहला स्थान हासिल किया।

अफ्रीका, इंग्लैंड में नहीं जीतने का पछतावा : प्रसाद

नई दिल्ली, आइएएनएस : बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली ने 88वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में कहा था कि एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली सीनियर चयन समिति का कार्यकाल खत्म हो गया है और भविष्य के लिए नई चयन समिति चुनी जाएगी। प्रसाद ने अब इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि समिति का चेयरमैन रहते भारतीय टीम का दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाना उनके लिए हमेशा पछतावा का विषय रहेगा।

प्रसाद ने कहा कि मुझे लगता है कि तीन साल से भारतीय टीम का टेस्ट क्रिकेट में नंबर एक बने रहना मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि देता है। हमने न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीती। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतना निश्चित रूप से सबसे अच्छी बात थी। विदेशों में मिली हार का मुझे बहुत अफसोस होगा। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में जो कुछ हुआ, मैं उसके उल्टा देखना पसंद करता। हमारी टीम में सब कुछ था। जिस तरह से टीम लड़ी, उसे देखते हुए हमारी टीम विदेशों में जीत की हकदार थी। मुझे कभी दबाव महसूस नहीं हुआ। अगर आपकी सोच स्पष्ट नहीं है तो फिर आप केवल असहज महसूस करेंगे। हम बहुत स्पष्ट थे, खासकर खिलाड़ियों का चयन करते समय।

अश्विन ने नहीं छोड़ी टी-20 विश्व कप की उम्मीद : नई दिल्ली, आइएएनएस : ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन बेशक सीमित ओवरों में भारतीय टीम की रणनीति का हिस्सा ना हों, लेकिन उन्होंने अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में शामिल होने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। अश्विन ने कहा कि युवराज सिंह ने उन्हें प्रेरित किया है और अगर वह 2014 टी-20 विश्व कप तथा चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में वापसी कर सकते हैं तो वह भी ऐसा कर सकते हैं।

अश्विन ने कहा कि मैं हर दिन खेलना पसंद करता हूं, लेकिन अपने करियर में मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे खेलने में आनंद नहीं आ रहा है और इसका कारण सीमित ओवरों की टीम से बाहर होना और चोटें थीं।

उन्होंने कहा कि यह ऐसी चीज है जिसका मैं लुत्फ नहीं उठाता। मैं हालांकि इस भावना से बाहर निकला। इसमें लोगों ने मेरी मदद की और मैं इससे बाहर निकल सका। टी-20 विश्व कप टीम में शामिल होना हर किसी का सपना है। इस टूर्नामेंट में कौन भारत का प्रतिनिधित्व करना नहीं चाहता। युवराज ने टी-20 विश्व कप-2014 और चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में वापसी की थी, मैं अभी सिर्फ 33 साल का हूं।

अश्विन इस बार इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते दिखेंगे। पिछले दो सत्र वह किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेल रहे थे। अश्विन ने इस पर कहा कि इस ट्रेड के लिए उन्होंने नहीं कहा था। अश्विन ने कहा कि पंजाब के साथ मेरा कार्यकाल शानदार रहा था। वहां से मिले अनुभव ने मुझे हर तरीके से फायदा पहुंचाया। मुझे कप्तानी दी गई थी, और यह नई चीज थी जिसे मैंने काफी कुछ सीखा। मुझे लगा था कि अगर मैंने बहुत अच्छा नहीं तो अच्छा काम तो किया है। अश्विन ने इस पर आगे कहा कि अन्य चीजें भी थीं। फ्रेंचाइजियों के मालिक को लगा कि मैंने अच्छा काम नहीं किया जो सही था क्योंकि मैं दोनों सत्रों में टीम को प्लेऑफ में नहीं ले जा सका। आप बहाने बना सकते हो, लेकिन मैं ऐसा इंसान हूं जो जिम्मेदारी लेता हूं और मैंने माना कि मैं अच्छा नहीं कर सका। उम्मीद है दिल्ली के साथ सत्र अच्छा जाएगा।

आइसीसी ने मोबाइल कंपनी ओप्पो के साथ अपनी साझेदारी 2023 तक बढ़ाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ने स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ओप्पो के साथ अपनी साझेदारी को सितंबर 2023 तक बढ़ाने की गुरुवार को घोषणा की। इस साझेदारी के तहत ओप्पो अब आइसीसी और इससे जुड़े सभी आइसीसी टूर्नामेंटों का आधिकारिक मोबाइल हैंडसेट और हेंडसेट साझीदार बना रहेगा। इन टूर्नामेंटों में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले आइसीसी अंडर-19 विश्व कप 2020 और ऑस्ट्रेलिया में अगले साल होने वाले पुरुष और महिला टी-20 विश्व कप भी शामिल हैं। इस करार की घोषणा के बाद आइसीसी के मुख्य कार्यकारी मनु साहनी ने कहा कि हम ओप्पो को बोर्ड में आइसीसी और इसकी टूर्नामेंटो के वैश्विक साझेदार के तौर पर कुछ साल और आने से काफी खुश हैं। एक खेल के रूप मे हमें अपने डिजीटल अप्रोच पर गर्व है और यह ओप्पो को इस तरह की टेक्नॉलोजी के लिए एक नई सोच प्रदान करता है।

विविध

माता-पिता जेल में, बच्ची देख रही सपने

नईदुनिया, भोपाल : आठ साल की बच्ची की पढ़ाई की ललक देख हर कोई सुखद आश्चर्य में है। माता-पिता से दूर दादी के पास रहकर गांव के सरकारी स्कूल से उसने पहली कक्षा की पढ़ाई की, लेकिन आगे अच्छे स्कूल में जाना चाहती थी। आखिर उसकी इच्छा पूरी हो गई। अब वह मध्य प्रदेश के भोपाल में आश्रय गृह में रहकर पढ़ाई करेगी। इसके लिए आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे उसके माता-पिता को भी रीवा केंद्रीय जेल से भोपाल जेल लाया जाएगा। ताकि समय-समय पर बच्ची उनसे मिल सके।

बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने इस संबंध में रीवा केंद्रीय जेल को पत्र लिखा है। हत्या के एक मामले में माता-पिता को सजा हुई, तब बच्ची तीन साल की थी। कुछ समय वह मां के साथ जेल में रही, लेकिन छह साल की उम्र के बाद उसे जेल में नहीं रखा जा सकता। लिहाजा उसे गांव में रह रही बुजुर्ग दादी के सुपुर्द किया गया।

गांव में पढ़ाई से नहीं थी संतुष्ट : जेल में रहने के दौरान बच्ची की पढ़ाई के प्रति उत्सुकता को देखते हुए रीवा जेल के सीनियर वेलफेयर अधिकारी ने उसकी नर्सरी की पढ़ाई निजी पब्लिक स्कूल से कराई। जेल से बाहर आने के बाद दादी ने उसका दाखिला बहुत ही पिछड़े गांव बिछी के सरकारी स्कूल में करा दिया। बच्ची ने गांव के स्कूल से पहली कक्षा पास की, लेकिन उसे उस स्कूल में पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा था। लगभग 20 दिन पहले वह दादी के साथ रीवा जेल पहुंची। उसने गांव के स्कूल से पढ़ाई न हो पाने की बात बताई। जेल के वेलफेयर अधिकारी और सिंगरौली सीडब्ल्यूसी ने मिलकर भोपाल सीडब्ल्यूसी से संपर्क किया और बच्ची को भोपाल के एक आश्रय गृह में रहने और पढ़ने का मौका मिल गया।

बच्ची होनहार है। काउंसिलिंग कर उसे आश्रय गृह भेज दिया गया है और स्कूल में दाखिला कराया जा रहा है। रीवा केंद्रीय जेल को सूचना दे दी गई है, ताकि उसके अभिभावकों को भी भोपाल जेल में स्थानांतरित किया जा सके। ऐसा होने से बच्ची माता-पिता से मिल सकेगी।
–डॉ. कृपाशंकर चौबे, सदस्य, सीडब्ल्यूसी भोपाल

आइआइटी के सुझावों पर हुआ पंद्रह फीसद काम

यमुना एक्सप्रेस-वे

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

- जून 2021 तक पूरा कार्य करने का किया जेपी इंफ्राटेक ने वादा
- सुप्रीम कोर्ट की समिति के सामने आज रखी जाएगी रिपोर्ट

यमुना एक्सप्रेस वे को लेकर दिए गए आइआइटी के सुझावों पर मात्र पंद्रह फीसद कार्य हुआ है। यमुना प्राधिकरण शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा निगरानी समिति की बैठक में एक्सप्रेस-वे पर हुए कार्यों का ब्योरा देगा। जेपी इंफ्राटेक ने आइआइटी के सुझावों को पूरी तरह से लागू करने के लिए जून 2021 तक का समय मांगा है। आइआइटी के 16 सुझावों पर जेपी इंफ्राटेक को अमल करने के निर्देश हैं।

यमुना एक्सप्रेस वे पर होने वाले हादसों की रोकथाम के लिए सड़क सुरक्षा निगरानी समिति ने आइआइटी से सुरक्षा ऑडिट कराने का आदेश दिए था। आइआइटी दिल्ली की टीम एक्सप्रेस वे का सुरक्षा ऑडिट कर यमुना प्राधिकरण को कई माह पहले अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। लेकिन एक्सप्रेस वे पर आइआइटी के सुझावों को लागू कराने की रफ्तार काफी धीमी है, जबकि एक्सप्रेस वे पर हादसों का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है।

यमुना प्राधिकरण ने बुधवार को जेपी इंफ्राटेक के साथ बैठक कर आइआइटी के सुझावों के क्रियान्वयन की रिपोर्ट ली थी। इसमें सामने आया है कि जेपी इंफ्राटेक अभी मात्र पंद्रह फीसद कार्य ही कर पाई है।

एक्सप्रेस वे पर पिछले चार साल के दौरान हुए हादसे

वर्ष	हादसे	मृतकों की संख्या
2016	1219	113
2017	763	146
2018	659	111
2019	511	182

मेडियन पर एक जगह पर लगा क्रैश बीम बैरियर

आइआइटी ने अपने अहम सुझाव में मेडियन (एक्सप्रेस वे के दोनों मार्गों के बीच का स्थान) पर क्रैश बीम बैरियर लगाने का सुझाव दिया था ताकि एक ओर के वाहन हादसे के बाद दूसरे ओर के मार्ग पर न जा सकें। यह क्रैश बीम बैरियर 330 किमी लगाया जाना है।

यमुना एक्सप्रेस वे पर आइआइटी द्वारा दिए गए सुझावों को लागू कराया जा रहा है। करीब पंद्रह फीसद कार्य हो चुका है। शेष कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश एक्सप्रेस वे संचालन कर्ता कंपनी को दिए गए हैं।
डा. अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण

हुए व शेष बचे कार्य : एक्सप्रेस वे के निकासी, प्रवेश, टोल प्लाजा, मुख्य मार्ग पर तीन लाख वर्गमीटर थर्मोप्लास्टिक मार्किंग होनी है। इसमें से एक लाख दो हजार वर्गमीटर मार्किंग का कार्य पूरा हो चुका है। एक्सप्रेस वे पर लगे साइनेज को हटाकर किनारों पर लगे क्रैश बीम बैरियर रेल गार्ड से बाहर कर दिया गया है। 304 साइनेज एक्सप्रेस वे से हटाए गए हैं। प्रवेश व निकासी के स्थान पर रफ्तार को नियंत्रण में करने के लिए लगने वाली 160 रंबल स्ट्रिप में सौ को लगाने का काम पूरा हो गया है। एक्सप्रेस वे पर पुलों पर चिह्नित किए गए 330 स्थानों में 110 पर रेल गार्ड बैरियर लगाने का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा एक्सप्रेस वे पर दूरी दर्शाने के लिए लगे पत्थरों को हटा दिया गया है। इनकी जगह क्रैश बीम बैरियर के बाहर बोर्ड लगाए गए हैं।

दो टोल के बीच तय दूरी के हिसाब से वाहन की रफ्तार सीमा की जांच करने व निर्धारित रफ्तार से अधिक होने पर चालान काटने का आइआइटी ने सुझाव दिया था। यह व्यवस्था निकासी बिंदु-आगरा टोल प्लाजा के बीच शुरू हो चुकी है।

टेलीविस्टा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक की हत्या में डॉक्टर सहित पांच दबोचे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- गुरुग्राम के विबन इस्टेट स्थित तीन करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए की गई हत्या
- 15 नवंबर को घर से मेट्रो स्टेशन जाने के दौरान उन्हें अगवा कर लिया गया था

टेलीविस्टा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक 64 वर्षीय अरुण शर्मा की हत्या में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने डॉक्टर सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। 15 नवंबर को घर से मेट्रो स्टेशन जाने के दौरान उन्हें अगवा कर लिया गया था। बाद में बदमाशों ने कार में गला दबाकर उनकी हत्या कर शव को झांसी, उत्तर प्रदेश स्थित एक नहर में फेंका दिया था। उनकी हत्या गुरुग्राम के विबन इस्टेट स्थित तीन करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए कराई गई। हत्या के लिए डॉक्टर ने 25 लाख रुपये की सुपारी दी थी।

अपराध शाखा के एडिशनल पुलिस कमिश्नर बीके सिंह ने बताया कि टेलीविस्टा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक अरुण शर्मा ग्रेटर कैलाश में रहते थे। गुरुग्राम के विबन इस्टेट स्थित तीन करोड़ की उनकी प्रोपर्टी का विवाद कोर्ट में चल रहा है। 15 नवंबर को गुरुग्राम कोर्ट में प्रॉपर्टी के संबंध में सुनवाई होनी थी। अरुण शर्मा 15 नवंबर की सुबह घर से निकले। उन्हें वकील से मिलना था और बाद में वह वकील की कार से गुरुग्राम कोर्ट जाते। इसी बीच वह लापता हो गए। रात में जब परिजनों ने उन्हें फोन किया तो उनका मोबाइल फोन बंद आ रहा था। बाद में उन्होंने वकील से बात की तो पता चला कि अरुण उनसे मिले ही नहीं।

इसके बाद अरुण की बहन शशि किरन शर्मा ने भाई के लापता होने की शिकायत ग्रेटर कैलाश थाने में की। मुकदमा दर्ज कर स्थानीय पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। लेकिन कारोबारी का कोई पता नहीं चल सका। लिहाजा 27 नवंबर को मामला क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया। क्राइम ब्रांच ने घटना वाले दिन मृतक के घर पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो उसमें वहां आए दो संदिग्ध युवक और एक स्कार्पियो कार दिखाई दी। जांच में कार का नंबर फर्जी निकला। इसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने डॉ. ऋषिराज से पूछताछ की तो उसने गुनाह कुबूल कर लिया। उसने बताया कि अरुण कुमार की हत्या के लिए उसने ही 25 लाख रुपये की सुपारी दी है। वारदात में उसका बेटा हितेश और उसके दोस्त का बेटा अमेत, अमेत का मौसेरा भाई प्रियंक और अमेत का एक कर्मचारी साहिल शामिल है। इसके बाद पुलिस ने चार दिसंबर को सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि 15 नवंबर को जब अरुण शर्मा कोर्ट जाने के लिए घर से निकले थे तभी उन्होंने कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के पास उन्हें अगवा कर लिया था। बाद में उनकी शॉल से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद अरुण के शव को लेकर अमेत, प्रियंक और साहिल पहले गुरुग्राम पहुंचे। वहां हितेश को अरुण का शव दिखाने के बाद उसके कहने पर वे शव को झांसी ले गए और उसे वहां एक नहर में ठिकाने लगा दिया और गुरुग्राम वापस लौट आए।

विजिलेंस के हत्थे चढ़ा मेडिकल कॉलेज का करोड़पति स्टेनो

जागरण संवाददाता, कटक : आय से अधिक संपत्ति को लेकर विजिलेंस की टीम ने बुधवार को ओडिशा के कटक में श्रीराम चंद्र भंज (एससीबी) मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक कार्यालय के स्टेनो प्रमोद कुमार सामंतरा के कई ठिकानों पर छापेमारी की। विजिलेंस पांच टीमों ने प्रमोद के कार्यालय, सरकारी क्वार्टर सहित अन्य ठिकानों और उसके एक रिश्तेदार के घर पर एक साथ छापेमारी की।

इस दौरान जांच टीम को करीब 1.40 करोड़ की संपत्ति का पता चला है। विजिलेंस के सूत्रों के अनुसार जगतपुर नीमपुर में प्रमोद का दो मंजिला भवन मिला है, जिसकी कीमत करीब 11 लाख होने का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह चंपती गांव में 8 लाख रुपये की दो इमारत होने की बात जांच में पता चली है। कटक में 5 लाख रुपये के दो प्लॉट, साढ़े चार लाख रुपये की एक कार, बुलेट, एक्टिवा स्कूटर, विभिन्न बैंक एवं बीमा कंपनी के जमा राशि, करीब साढ़े पांच लाख रुपये के सोने के आभूषण, एक लाख 34 हजार रुपये नकद, करीब पांच लाख रुपये के घरेलू सामान आदि का पता विजिलेंस की टीम ने लगाया है।

पंजाब में अब मंत्रियों ने कहा नहीं सुन रहे अधिकारी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

गुस्सा

- रंधावा ने उठाया मन्ना का मामला, कांग्रेसियों की खामोशी पर साधा निशाना
- पावरकॉम चेयरमैन उनकी नहीं सुनता है मेरी : कांगड़
- एसएसपी मुक्तसर बता रहा कांग्रेस पार्षद के बेटे को गैंगस्टर : रंधावा
- डीएसपी सेखों दे रहा है धमकियां : आशू

अब तक तो पंजाब के विधायकों की ही शिकायतें थीं कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, लेकिन अब धीरे-धीरे मंत्री भी इससे नाराज नजर आने लगे हैं। मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में राजस्व मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने साफ तौर पर कहा कि पावरकॉम का चेयरमैन उनकी नहीं सुनता। यही नहीं, जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा तो बैठक में अपनी ही पार्टी और सरकार के नेताओं से कुछ ज्यादा ही नाराज दिखे।

रंधावा ने जमकर भड़ास निकाली और कहा कि मुक्तसर के एसएसपी राजबचन सिंह संधू कांग्रेसी पार्षद के बेटे मनप्रीत सिंह मन्ना को गैंगस्टर बता रहे हैं, जबकि 14 केसों में से वह सात में बरी हो चुका है और किसी में वह भगोड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने उसके हक में आवाज नहीं उठाई, जबकि दूसरी ओर अकाली दल के लोग उनके हलके में मारे गए पूर्व सरपंच को शहीद बता रहे हैं।

रंधावा ने कहा कि उन पर गैंगस्टरों के साथ मिले होने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन हमारी अपनी ही सरकार के किसी मंत्री ने उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। उन्होंने बैठक में बिक्रम मजीठिया की गैंगस्टरों के साथ फोटो भी दिखाए। उन्होंने अपना विभाग तक छोड़ने की धमकी दी। मंत्री भारत भूषण आशू भी अपनी सरकार से नाराज दिखे। उन्होंने डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों पर आरोप लगाए कि वह उन्हें धमकियां दे रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को भी हमारी सरकार ने अहम पदों पर लगा रखा है।

शिअद ने कहा, गैंगस्टर की तारीफ दुर्भाग्यपूर्ण : शिरोमणि अकाली दल ने जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान एक कांग्रेसी गैंगस्टर की सराहना पर हैरानी और दुख व्यक्त किया गया है। शिअद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एंव प्रमुख प्रवक्ता डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने कहा जेल मंत्री रंधावा द्वारा मंत्रिमंडल बैठक में किए व्यवहार की खबर सार्वजनिक होने के बाद समाज को धक्का लगा है। ऐसे व्यवहार के लिए मंत्री को बर्खास्त किया जाए। डॉ. चीमा ने कहा कि दुख की बात है कि जेल मंत्री ने एक कांग्रेसी गैंगस्टर के पक्ष में न बोलने के लिए अपने कैबिनेट साथियों का न सिर्फ मजाक उड़ाया, बल्कि यह सवाल भी किया कि मुक्तसर के एसएसपी ने मारे जा चुके बदमाश (मनप्रीत मन्ना) को गैंगस्टर क्यों कहा? कहा कि इस गैंगस्टर के खिलाफ 14 आपराधिक मामले दर्ज थे। उन्होंने कहा कि यहां मंत्री पुलिस अधिकारियों के काम में दखल देते हैं तथा उन्हें सही तरीके से अपनी ड्यूटी करने से रोकते हैं।

मौसम विशेष

दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा व पंजाब में ठंडी सुबह में कुहासा व धुंध के साथ कुछ स्थानों पर कोहरा छाया रहेगा। दिन सुहावना बना रहेगा। जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क व ठंडा बना रहेगा। कश्मीर घाटी में सुबह में तापमान में गिरावट के साथ कंपकंपाती ठंड जारी रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	33/23/व	अहमदाबाद	32/16/व
कोलकाता	27/17/सा	बड़ौदा	32/19/आंबा
चेन्नई	30/22/व	नागपुर	30/13/व
हैदराबाद	28/20/सा	इन्दौर	29/18/आंबा
बंगलूरू	28/19/सा	राँची	28/16/व
त्रिवेन्द्रम	31/24/सा	पटना	28/18/आंबा
गुवाहाटी	24/16/आंबा	जमशेदपुर	29/21/व
गंगटोक	08/-1/आंबा	पुणे	30/20/आंबा

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 6 दिसंबर 2019
आजकल
16
www.jagran.com

मंगल ग्रह पर पानी की निशानियों का दुनिया को पता चला

2006 में आज ही नासा के अंतरिक्ष यान मार्स ग्लोबल सर्वेयर ने मंगल ग्रह की ऐसी तस्वीरें भेजी थीं, जिनमें इस लाल ग्रह पर पानी होने की निशानियां मिली थीं। मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए इस अंतरिक्ष यान को 7 नवंबर, 1996 को लांच किया गया था।

स्पेन ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए मतदान किया

1978 में आज ही स्पेन के नागरिकों ने राजशाही की जगह लोकतंत्र की स्थापना के लिए मतदान किया था। इस चुनाव में 91.8 फीसद जनता ने नये संविधान के पक्ष में मतदान किया था। बाद में स्पेन के राजा जुआल कार्लोस ने भी इस पर अपनी सहमति जताई।

यरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मिली मान्यता

2017 में आज ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीन और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के विरोध के बीच यरुशलम को इजरायल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने की घोषणा की थी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के ज्यादातर देश पूरे यरुशलम पर इजरायल के दावे को मान्यता नहीं देते। 1948 में इजरायल ने आजादी की घोषणा की थी और एक साल बाद यरुशलम का बंटवारा हुआ था। बाद में 1967 में इजरायल ने 6 दिनों तक चले युद्ध के बाद पूर्वी यरुशलम पर कब्जा कर लिया था।

इधर-उधर की

दुनिया की पहली फ्लाई एंड ड्राइव कार

वाशिंगटन, एजेंसी : दुनिया की पहली फ्लाई एंड ड्राइव कार को मियामी में लांच किया गया। इसे पायनियर पर्सनल एयर लैंडिंग व्हीकल नाम दिया है। इसमें रिट्रैक्टेबल ओवरहेड और रियर प्रोपेलर लगाए गए हैं, जिसकी मदद से यह 12500 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है। कार हवा में 321 किमी प्रति घंटा और सड़क पर 160 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ और दौड़ने में सक्षम है। टू-सीटर इस कार में 230 हॉर्स पावर का इंजन लगा है। इसकी कीमत लगभग 4.30 करोड़ रुपये है। अभी तक इसकी 70 बुकिंग हो चुकी हैं। इसकी पहली डिलीवरी 2021 में की जाएगी। कंपनी ने इसके लिए एक शर्त रखी है, जिसके तहत खरीदार के पास ड्राइविंग लाइसेंस के साथ पायलट लाइसेंस भी होना चाहिए। इसका वजन 680 किलो है।

दो अरब जानें लेने के लिए काफी हैं सौ परमाणु मिसाइलें

मिशिगन टेक यूनिवर्सिटी और टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जोशुआ एम पीयर्स और डेविड सी डेनकेबर्गर की जर्नल सेफ्टी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर परमाणु युद्ध हुआ तो दुनिया में मौजूद 13,865 परमाणु हथियारों में से केवल 100 परमाणु मिसाइलें ही आधी दुनिया को तबाह करने के लिए काफी होंगी। इससे दुनिया की आधी ओजोन परत बर्बाद हो जाएगी, आधी दुनिया से सर्दी-गर्मी का मौसम ही खत्म हो जाएगा। वनस्पतियों और पेड़-पौधों का निशान तक मिट जाएगा। दुनिया के दो अरब लोग भूख, रेडिएशन और तपिश से मारे जाएंगे।

कृषि उत्पादन में आएगी कमी

इससे कृषि उत्पादन में 10 से 20 फीसद की कटौती होगी और औद्योगिक आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होगा।

अन्य चीजों पर पड़ेगा प्रभाव

इसका असर चिकित्सा आपूर्ति पर भी पड़ेगा। प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा। मनोवैज्ञानिक तनाव बढ़ेगा। बीमारियों और महामारियों के साथ-साथ बढ़े हुए यूवी विकिरण के कारण त्वचा कैंसर की दर भी बढ़ेगी।

खो देंगे आधी आबादी

रिपोर्ट के मुताबिक, नौ में से छह परमाणु संपन्न देश यदि सौ मिसाइल लांच करते हैं, तो वे स्वयं को नष्ट कर लेंगे। भारत, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, उत्तर कोरिया, इजरायल और चीन इसके कारण भुखमरी से अपनी आधी आबादी खो देंगे।

भयावह होगा नजारा : इन मिसाइलों के विस्फोट से निकलने वाली सात ट्रिलियन ग्राम राख वायुमंडल में फैल जाएगी और सूरज को ढक लेगी। इसके कारण सूर्य की 20 फीसद किरणें पृथ्वी पर पहुंच ही नहीं पाएंगी और पृथ्वी का तापमान इतना कम हो जाएगा जितना धरती ने पिछले 1000 सालों में अनुभव नहीं किया है। यही नहीं इससे वैश्विक वर्षा में 19 फीसद गिरावट आएगी। दुनिया भर के करीब दो अरब लोग काल के मुंह में समा जाएंगे।

फिल्म रिव्यू

मराठा योद्धा का साहसी सफर

★★★

पानीपत : द ग्रेट बिट्रेल

प्रमुख कलाकार : संजय दत्त, अर्जुन कपूर, कृति सैनन, मोहनीश बहल
निर्देशक : आशुतोष गोवारिकर
अवधि : 2 घंटे 53 मिनट

कहावत है- घर का भेदी लंका ढाए। इतिहास गवाह रहा है कि हिंदुस्तान के शासकों की मैदान-ए-जंग में शिकस्त की वजह अपनों का धोखा भी रहा है। 14 जनवरी, 1761 को मराठा योद्धाओं और अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा योद्धा की पराजय में अपनों का धोखा देना शामिल भी था। पानीपत की तीसरी लड़ाई भले ही मराठा हार गए, लेकिन अब्दाली उनकी बहादुरी का कायल हो गया और कभी हिंदुस्तान वापस नहीं आया। युद्ध की इस गाथा को आशुतोष गोवारिकर ने 'पानीपत : द ग्रेट बिट्रेल' में दर्शाया है। कहानी पेशवा बाजीराव के भतीजे सदाशिव राव भाऊ के हिंदुस्तान को एकजुट करने के उनके जांबाज इरादों के संबंध में है।

कहानी 18वीं सदी की है। उस समय उत्तर-पश्चिमी अफगान सीमा पर अटक के किले तक मराठा साम्राज्य फैला हुआ था। वह अपने पड़ोसी उदगिर के निजाम पर जीत हासिल करने में नाकाम रहे थे। उसे नाना साहेब पेशवा के चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सैनिक घेर लेते हैं। विजय हासिल करने के बाद सदाशिव मराठा साम्राज्य की राजधानी शनिवार वाड़ा लौटते हैं। वहां कहानी उनकी निजी और पेशवर जिंदगी के पहलुओं को छूती है। सदाशिव राव के परिवार में उनकी मां हैं। वैद्य पार्वती बाई उनसे बचपन से प्यार करती है। दोनों की शादी हो जाती है। अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली नजीबउद्दौला के न्योते पर हिंदुस्तान आता है। उसे रोकने के लिए नाना साहेब सदाशिव के नेतृत्व में चालीस हजार सैनिकों की सेना भेजते हैं। उसके इस सफर में उनकी पत्नी भी साथ आती हैं। अब्दाली और उसकी एक लाख सेना को रोकने के लिए सदाशिव बाकी राज्यों के राजाओं से मदद मांगते हैं। वहां से कहानी युद्ध के मैदान में आमना-सामना होने के उनके सफर पर ले जाती है।

आशुतोष गोवारिकर की 'पानीपत : द ग्रेट बिट्रेल' में काफी तथ्य हैं। कहानी के केंद्र में युद्ध है, लेकिन सदाशिव और पार्वती बाई के बीच की प्रेमकहानी भी है। मराठा साम्राज्य की कहानी में वास्तविकता लाने के लिए कुछ जगहों पर मराठी भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसे गैर मराठीभाषियों को समझने में दिक्कत पेश आ सकती है। उस दौर की वास्तुकला, युद्धकला, वेशभूषा, सामाजिक व्यवहार, राजनीतिक और पारिवारिक मर्यादाओं का कहानी में समावेश है। उन्होंने ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ कल्पना का योग किया है। कहानी सैनिकों के युद्ध के सफर पर निकलने की है, पर सफर की मुश्किलों की गहराई में लेखक-निर्देशक नहीं जाते हैं। फिल्म का वीएफएक्स कहीं-कहीं कमजोर है।

मुख्य पात्र सदाशिव राव भाऊ की भूमिका में अर्जुन कपूर हैं, जो मराठी योद्धा के रूप में जमते हैं। युद्ध के मैदान में उनकी स्फूर्ति, घुड़सवारी, तलवारबाजी और आक्रामकता देखने योग्य है। भावनात्मक उथल-पुथल के घमासान को भी वह अपेक्षित भाव देने का प्रयास करते हैं, हालांकि कुछ जगह कमजोर पड़ते हैं। पार्वती बाई की भूमिका में कृति सैनन सुंदर लगी हैं। फिल्म का खास आकर्षण संजय दत्त हैं। वह अब्दाली के खौफ को उकेरने में सफल रहते हैं।

आशुतोष ने सदाशिव राव भाऊ के समय के सामाजिक, वैचारिक और धार्मिक मुद्दों को स्पर्श किया है। संवादों और प्रसंगों के माध्यम से आशुतोष ने लड़ाई में हार के कारणों का पक्ष रखा है। फिल्म का संगीत पक्ष साधारण है। क्लाइमेक्स से थोड़ी निराशा होती है। उन दृश्यों को गढ़ने में बारीकियों पर काम करने की गुंजाइश थी। बहरहाल, इतिहास के उन साक्ष्यों को दर्शाती 'पानीपत' मराठा योद्धा की बहादुरी को सलाम करती है।

स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

प्राकृतिक गैसें भी बढ़ा रहीं कार्बन उत्सर्जन

चिंताजनक ▸ ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने सालाना विश्लेषण में कहा- उत्सर्जन में हुई रिकॉर्ड वृद्धि

इस साल वातावरण में बढ़ा है 0.6 फीसद कार्बन

पेरिस, एएफपी : प्राकृतिक गैसों का उपयोग बढ़ने से इस वर्ष वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। यह हालात तब हैं जब कई देशों ने कोयले की खपत कम करने के साथ-साथ जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। एक नए अध्ययन में यह दावा किया गया है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने अपने सालाना विश्लेषण में कहा कि रसोई और वाहनों में प्रयुक्त होने वाली प्राकृतिक गैसों के कारण इस साल कार्बन का उत्सर्जन 0.6 फीसद बढ़ा है। हालांकि पिछले साल की तुलना में यह आंकड़ा कम है लेकिन हमें ग्लोबल वार्मिंग के प्रति सचेत रहने की जरूरत है।

तीन वैश्विक अध्ययनों में लेखकों ने उत्सर्जन में वृद्धि के लिए प्राकृतिक गैस और तेल को जिम्मेदार ठहराया है। इसका एक अर्थ यह भी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में कोयले के उपयोग में गिरावट आने लगी है। कार्बन बजट रिपोर्ट के लेखक और ईस्ट एंग्लिया यूनिवर्सिटी के कॉरिन ले क्वेर ने कहा, 'यह तो सब जानते हैं कि कोयले के उपयोग में उतार-चढ़ाव से वैश्विक स्तर पर जलवायु में परिवर्तन आते हैं, लेकिन तेल और विशेष रूप से प्राकृतिक गैस का उपयोग बढ़ने भी कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हुई है।' उन्होंने कहा कि हाल के दशकों में वायुमंडलीय में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर तेजी से बढ़ा है, इस वर्ष औसतन 410 पीपीएम (पाट्र्स पर मिलियन) फैलने का अनुमान है। यह स्तर 80 लाख साल में सबसे उच्चतम है।

वातावरण में कार्बन के स्तर में वृद्धि होने से गर्मी भी बढ़ने लगती है। प्रतीकात्मक

उत्सर्जन को 7.6 फीसद कम करने की जरूरत : क्वेर ने कहा, 'यह रिपोर्ट मैड्रिड में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की जलवायु वार्ता में एकत्रित होने वाले प्रतिनिधियों को असहज कर सकती है। दुनिया के शीर्ष जलवायु वैज्ञानिकों की चेतावनी पर हमें समय रहते काम करने की जरूरत है। पिछले सप्ताह यूएन ने कहा था कि वैश्विक उत्सर्जन को हर साल 7.6 फीसद कम करने की जरूरत है। ताकि वर्ष 2030 तक तापमान को 1.7 डिग्री सेल्सियस (2.6 फॉरनहाइट) तक स्थिर किया जा सके।

2010 में दर्ज की गई थी रिकॉर्ड गर्मी : औद्योगिक क्रांति के बाद अब तक एक डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है। इसके कारण भीषण तूफान, सूखा, जंगलों में आगजनी और बाढ़ की घटनाएं बढ़ गई हैं और जलवायु परिवर्तन और ज्यादा तेज हो गया है। यूएन ने कहा कि 21 सदी के पहले दशक में वर्ष 2010 में रिकॉर्ड गर्मी दर्ज की गई थी और इस साल गर्मी से लगभग 2.2 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं।

लो कार्बन टेक्नोलॉजी का बढ़ावा देने की जरूरत : इस अध्ययन के लेखकों ने बताया कि 2019 में हुई उत्सर्जन में वृद्धि पिछले दो वर्षों की तुलना में धीमी है। फिर भी ऊर्जा की मांग इस बात की ओर इशारा करती है कि पवन और सौर ऊर्जा जैसी लो कार्बन टेक्नोलॉजी के प्रयोग को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। वर्ष 2015 की तुलना में इस साल चार फीसद अधिक उत्सर्जन हुआ है। तापमान में वृद्धि को सीमित करने के लिए 195 देशों ने पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बाद में इस समझौते से अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया था।

शोध अनुसंधान

मां को डायबिटीज होने से बच्चे के दिल को खतरा

जिन बच्चों की मां डायबिटीज का शिकार होती है, उनमें दिल की बीमारियों का खतरा अन्य की तुलना में ज्यादा रहता है। यह खतरा और बढ़ जाता है अगर मां को दिल से जुड़ी कोई बीमारी हो। ऐसे लोगों में काफी कम उम्र से ही दिल की बीमारियों का खतरा रहता है। इस अध्ययन के लिए डेनमार्क में 1977 से 2016 के बीच जन्मे 24 लाख से ज्यादा लोगों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इन सभी की मां की उम्र, दिनचर्या और डायबिटीज से संबंधित जानकारियां भी जुटाई गईं। 40 साल के अध्ययन के बाद पाया गया कि जिन बच्चों की मां को डायबिटीज था, उनमें दिल की बीमारियों का खतरा 29 फीसद तक बढ़ गया। ये नतीजे बताते हैं कि मां बनने की उम्र वाली महिलाओं के लिए डायबिटीज व दिल की बीमारियों से सतर्क रहना ज्यादा जरूरी है। इस उम्र में अनदेखी खतरनाक हो सकती है। -आइएएनएस

फेफड़े पर घाव बना देती है ई-सिगरेट

ई-सिगरेट पीने वालों के फेफड़े पर खास किस्म का घाव बन जाता है। इस तरह के घाव अमूमन कोबाल्ट या टंगस्टन जैसी कठोर धातुओं के कारखाने में काम करने वालों के फेफड़ों पर दिखते हैं। इसे हार्ड मेटल न्यूमोकोनियोसिस कहा जाता है। ई-सिगरेट से यह खतरा हालिया शोध में सामने आया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस बीमारी में फेफड़े की क्षतिग्रस्त कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं के साथ मिलकर बड़ी कोशिकीय संरचना बना लेती हैं, जिसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। इससे सांस लेने में परेशानी होती है और व्यक्ति को बहुत ज्यादा खांसी आती है। फेफड़े के इन घावों को ठीक नहीं किया जा सकता है। हालांकि स्टेरॉयड लेने से स्थिति में कुछ सुधार होता है। ई-सिगरेट से सेहत को होने वाले नुकसान पर वैज्ञानिक पहले भी चिंता जता चुके हैं। इस नए खतरे ने चिंता को और बढ़ा दिया है। -प्रेट्र

ऑस्ट्रेलिया में आग से छाई धुंध

ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स क्षेत्र में 50 से अधिक स्थानों पर लगी आग की वजह से आसमान में धुआं और धुंध के बादल छाए हुए हैं। यह परिवार प्रदूषित वातावरण में सिडनी के समुद्र तट पर छुट्टी मनाने पहुंचा है। अधिकारियों का कहना है कि जहरीले धुएं की वजह से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। एएफपी

फ्रांस से तस्करी कर लाई गई हार्ले डेविडसन बाइक

इंडोनेशिया में नई एयरबस ए 330-900 के जरिये बीते दिनों हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल को फ्रांस से तस्करी कर लाया गया था। कस्टम विभाग ने मामला संज्ञान में आते ही उसे जब्त कर लिया था। गुरुवार को इंडोनेशिया के वित्त मंत्री मुलानी इंद्रावती (दाईं ओर से तीसरी) और राज्य के उद्यम मंत्री एरिक थोहर (दाएं से दूसरे) ने सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ मोटरसाइकिल का निरीक्षण किया। इस मौके पर आयोजित एक प्रेसवार्ता में एरिक थोहर ने कहा कि अब एयरलाइन के प्रमुख के खिलाफ तस्करी का मुकदमा चलाया जाएगा। एपी

स्क्रीन शॉट

बालाकोट एयरस्ट्राइक पर बनने वाली फिल्म का वीएफएक्स होगा जबर्दस्त

हिंदी सिनेमा में लगातार वास्तविक घटनाओं पर फिल्में बन रही हैं। इस साल की शुरुआत में फिल्म 'उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक' रिलीज हुई थी। मुंबई में 26 नवंबर को हुए आतंकी हमले पर 'होटल मुंबई' फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। अभिनेता विवेक ओबेरॉय बालाकोट हमले पर फिल्म बनाने की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। विवेक के मुताबिक, यह फिल्म बड़े पैमाने पर बनने वाली है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी वीएफएक्स कंपनी को फिल्म से जोड़ा है, जिसने पांच ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। फिल्म में काम करने वाले कलाकारों को लेकर वह कहते हैं कि फिल्म की कास्टिंग अभी होना बाकी है। फिल्म कई भाषाओं में बनेगी, ऐसे में हर भाषा में बड़े स्टार को कास्ट किया जाएगा। कास्टिंग के बाद फिल्म के कलाकारों की ट्रेनिंग शुरू होगी। ट्रेनिंग को लेकर विवेक कहते हैं कि इसके लिए भारतीय वायुसेना से बातचीत चल रही है। तकनीकी पहलुओं को फिल्म में कैसे दर्शाना है, इसे लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। पुलवामा में इस वर्ष 14 फरवरी को आंतकियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया था, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद जवाबी कार्यवाही करते हुए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयरस्ट्राइक की थी और वहां मौजूद आंतकी अड्डों को निशाना बनाकर खत्म किया था।

रिचा चड्ढा भी उठाएंगी आय में समानता का मुद्दा

अभिनेता के मुकाबले अभिनेत्रियों की कम आय को लेकर कई बार बॉलीवुड के गलियारे में आवाजें उठी हैं। अब यह आवाज रिचा चड्ढा उठा रही हैं अपनी आगामी वेबसीरीज 'इनसाइड एज 2' में। पहले सीजन की ही तरह दूसरे सीजन में क्रिकेट की दुनिया दिखाई जाएगी। क्रिकेट को अक्सर लड़कों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इस शो में ऐसा नहीं होगा। मेकर्स ने इसे संतुलित करने की कोशिश की है। महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले पारिश्रमिक कम क्यों दिया जाता है, इसे तर्क के साथ शो में दिखाने की कोशिश की जाएगी। 'इनसाइड एज 2' की लीड रिचा चड्ढा शो में सशक्त किरदार में हैं। उनका कहना है, 'पिछले काफी वक्त से हम पुरुषों और महिलाओं को मिलने वाले मेहनताने के बीच विसंगतियों पर चर्चा करते आए हैं, लेकिन दोनों के बीच के फासले को कम करने में काफी वक्त लग गया। वैश्विक स्तर पर फिल्म व्यवसाय के अलावा भी कई व्यवसाय हैं, जहां महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम मेहनताना दिया जाता है। लेकिन धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है। खासकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह देखने को मिल रहा है। इस मंच पर ऐसी कहानियां लिखी जा रही हैं, जिसमें इन मुद्दों पर चर्चा और बहस हो रही है। 'इनसाइड एज 2' में हमने इस मुद्दे को उठाया है। मेरे किरदार के व्यक्तित्व का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।' रिचा का कहना है कि वह ऐसे लोगों के साथ काम करके खुश हैं, जो मेहनताना देने के लिए योग्यता को सबसे ऊपर रखते हैं।

'शर्माजी नमकीन' में नजर आएंगे ऋषि

अभिनेता ऋषि कपूर कैंसर को हराकर अमेरिका से लौटने के बाद अब लगातार हिंदी फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं। उनकी आगामी फिल्म 'द बॉडी' होगी। 13 दिसंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म में वह एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म के बाद वह 'शर्माजी नमकीन' फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म की घोषणा फिल्ममेकर रितेश सिधवानी ने की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी देते हुए एक तस्वीर साझा की है। जिसमें ऋषि कपूर नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर लिखा, 'ऑफ स्क्रीन मीठे, ऑन स्क्रीन नमकीन। जब ऐसी प्रतिभाएं मिलती हैं, तो उत्सुकता बढ़ जाती है।' इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ अभिनेत्री जूही चावला भी होंगी। यह जोड़ी 'बोल राधा बोल', 'दरार', 'ईना मीना डीका', 'साजन का घर' जैसी फिल्मों में काम कर चुकी है। फिल्म अगले साल रिलीज होगी।

अध्ययन

पार्कर यान सूर्य के उतने करीब है, जितना अब तक कोई यान नहीं पहुंचा, सूरज के वातावरण को समझने में अहम साबित होंगे यान के डाटा

नासा के पार्कर यान ने खोले सूर्य के कई राज

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यान 'पार्कर सोलर प्रोब' ने सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। पार्कर सूर्य के उतने करीब पहुंच चुका है, जितना अब तक कोई मानव निर्मित यान नहीं पहुंच सका है। अब इसने वहां से कुछ ऐसे डाटा भेजे हैं, जिनसे सूर्य के कई रहस्य सामने आए हैं। यान ने यह पता लगाने में कामयाबी पाई है कि सूर्य का वातावरण 'कोरोना' उसकी सतह से सैकड़ों गुना ज्यादा गर्म क्यों होता है। साथ ही सौर हवा के चलने का कारण भी इसने खोजा है।

पार्कर को अगस्त, 2018 में लांच किया गया था। नासा ने इसके जरिये सूर्य के वातावरण के 24 ऐसे पड़ाव पार करने की योजना बनाई है, जहां अब तक कोई यान नहीं पहुंचा है। पार्कर ने अब तक इनमें से तीन पड़ाव पार कर लिए हैं। यान पर इस तरह के अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, जो इसके चारों ओर के वातावरण का अध्ययन करेंगे। नासा ने बताया कि इस यान की मदद से सूर्य से बाहर की ओर निकलने वाले विभिन्न पदार्थों एवं कणों की प्रकृति के बारे में जानकारी मिली है। इससे वैज्ञानिकों को सूर्य की भौतिकी को समझने में मदद मिलेगी। इससे मिले डाटा की मदद से धरती के चारों ओर अंतरिक्ष के वातावरण का ज्यादा सटीक अनुमान लगाना संभव होगा। इससे अंतरिक्षयात्रियों व यानों की सुरक्षा के बेहतर कदम उठाए जा सकेंगे। नासा में एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर साइंस थॉमस जुर्बुचेन ने कहा कि बहुत दूरी के बजाय करीब से सूर्य को जानना महत्वपूर्ण है।

सतह के मुकाबले सूरज का वातावरण (कोरोना) कई गुना गर्म होता है। प्रतीकात्मक

तारों के बारे में मिलेंगी नई जानकारियां : जुर्बुचेन ने कहा, 'पार्कर के इस डाटा से सूर्य और तारों के बारे में नई और आश्चर्यजनक जानकारियां मिली हैं।' उन्होंने कहा कि सूर्य का अवलोकन करने के बजाय हम महत्वपूर्ण सौर घटनाओं का विश्लेषण कर यह पता लगा सकते हैं कि ये पृथ्वी को कैसे प्रभावित करते हैं। इसके अलावा यह डाटा हमें आकाशगंगाओं में सक्रिय तारों के बारे में भी नई जानकारियां देता है।

कोरोनल छिद्रों से निकलती हैं सौर हवाएं : इस शोध के प्रमुख लेखक और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टुअर्ट बेल ने कहा, 'इन आंकड़ों का विश्लेषण कर हम कोरोना की चुंबकीय संरचना को देख सकते हैं, जो हमें यह बताता है कि सौर हवाएं छोटे कोरोनल छिद्रों से निकल रही हैं।'